उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त
विश्वविद्यालय, प्रयागराज

MAGO-111

जनसंख्या भूगोल

इकाई 1 : भूगोल में जनसंख्या अध्ययन, जनसंख्या भूगोल की परिभाषा, एवं विषय–क्षेत्र 3

इकाई 2 : जनसंख्या भूगोल के उपागम, जनसंख्या भूगोल का विकास 13

इकाई 3 : जनसंख्या भूगोल और अन्य सामाजिक शास्त्र, भारत में जनसंख्या भूगोल 22

इकाई 4 : जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक 30

इकाई 5 : जनसंख्या का विश्व–वितरण–अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र, अल्प तथा अत्यल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र, जनरिक्त क्षेत्र 40

इकाई 6 : जनसंख्या घनत्व–प्रकार, जनसंख्या घनत्व का विश्व वितरण 53

इकाई 7 : विश्व में जनसंख्या वृद्धि, भारत में जनसंख्या वृद्धि 69

इकाई 8 : प्रजननता का अर्थ, प्रजननता के निर्धारक कारक 83

इकाई 9 : मर्त्यता का अर्थ, मृत्युदर में भिन्नता के कारण 99

इकाई 10 : लिंगानुपात के परिकलन की विधियाँ, लिंगानुपात के प्रकार 111

इकाई 11 : साक्षरता का अर्थ, साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारण 125

इकाई 12 : विश्व में साक्षरता प्रतिरूप, भारत में साक्षरता दर में वृद्धि पुरूष तथा स्त्री साक्षरता में अंतर 136

इकाई 13 : नगरीयकरण का अर्थ, नगरीयकरण के प्रभाव, भारत में नगरीयकरण 149

इकाई 14 : माल्थस का जनसंख्या सिद्धान्त, नव माल्थसवाद, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त 164

इकाई 15 : जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएँ, भारत में जनसंख्या की समस्याएँ 177

इकाई 16 : जनसंख्या नीति का अर्थ, आवश्यकता एवं उद्देश्य, भारत की जनसंख्या नीति, नई जनसंख्या नीति 189

mÙkj izns'k jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky; mÙkj izns'k iz;kxjkt

lja{kd ,oa ekxZn'kZd

izks0 lR;dke	dqyifr m-iz- jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt
fou; dqekj	dqylfpo m-iz- jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt

fo'k"kK lfefr

izks0 lrh"kk dqekj	vkpk;Z] bfrgkl] funs'kd] lekt foKku] fo|k'kk[kk] m-iz- jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt
izks- lat; dqekj flag	vkpk;Z] Hkwxksy lekt foKku fo|k'kk[kk m-iz- jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt
Mk- vfHk"kd flag	lgk- vkpk;Z lekt foKku fo|k'kk[kk m-iz- jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt
izks- ,u-d- jkuk	vkpk;Z] Hkwxksy foHkkx ch-,p-;w-] okjk.klh
izks- ,-vkj- flnnhdh	vkpk;Z] Hkwxksy foHkkx byksgkckn fo'ofo|ky;] iz;kxjkt
izks- v:.k dqekj flag	vkpk;Z] Hkwxksy foHkkx ch-,p-;w- okjk.klh

ys[kd

Mk- cztss'k ;kno	lgk;d vkpk;Z] Hkwxksy jk"Vªh; ih-th- dkyst tegkbZ tkSuiqj

lEiknu

izks- lat; dqekj flag	lgk;d vkpk;Z] Hkwxksy lekt foKku fo|k'kk[kk m-iz- jktf"kZ V.Mu eqDr fo-fo-] iz;kxjkt

leUo;d

izks- lat; dqekj flag	lgk;d vkpk;Z] Hkwxksy lekt foKku fo|k'kk[kk m-iz- jktf"kZ V.Mu eqDr fo-fo-] iz;kxjkt

lg&leUo;d

Mk- vfHk"kd flag	lgk;d vkpk;Z] Hkwxksy lekt foKku fo|k'kk[kk m-iz- jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt

izdk'kd

2024 ¼eqfnzr½
© m0iz0 jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt 2024
ISBN-978-81-976126-5-7

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठ्यसामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

नोट : पाठय सामग्री में मुद्रित सामग्री के विचारों एवं आकड़ों आदि के प्रति विश्वविद्यालय, उत्तरदायी नहीं है।

प्रकाषन : उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, प्रयागराज

प्रकाषक : कुलसचिव, विनय कुमार उ0प्र0 राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, प्रयागराज – 2024

मुद्रक :–चंद्रकला यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड, 42/7 जवाहरलाल नेहरू रोड, प्रयागराज– 211006

इकाई–1 भूगोल में जनसंख्या अध्ययन, जनसंख्या भूगोल की परिभाषा एवं विषय–क्षेत्र

इकाई की रूपरेखा

1.0 प्रस्तावना

1.1 उद्देश्य

1.2 जनसंख्या भूगोल की परिभाषा

1.3 जनसंख्या भूगोल की प्रकृति

1.4 जनसंख्या भूगोल का विषय क्षेत्र

1.5 सारांश

1.6 स्वमूल्यांकन प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

1.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1.8 अभ्यास प्रश्न (सत्रांत परीक्षा की तैयारी)

1.0 प्रस्तावना

प्राचीन काल से ही भूगोल में जनसंख्या वितरण एवं उसकी प्रकृति के साथ संबंध का भूगोलवेत्ताओं एवं मानव वैज्ञानिकों के आकर्षण का क्षेत्र रहा है। यद्यपि जनसंख्या का अध्ययन भूगोलवेत्ताओं के साथ – साथ सभी सामाजिक एवं मानव वैज्ञानिकों के अध्ययन का विषय क्षेत्र रहा है। वुड्स (1979) ने अपने अध्ययन में बताया है कि विभिन्न विषयों की अध्ययन विधा और विषय क्षेत्र भिन्न – भिन्न है, फिर भी प्रत्येक विषय का जनसंख्या के ऐतिहासिक और क्षेत्रीय प्रतिरूप में महत्वपूर्ण योगदान है। परंपरागत रूप से भूगोल का अध्ययन दो भागों में विभक्त है भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल। अध्ययन के क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि भौगोलिक विश्लेषण में मानव का स्थान क्या है। इस प्रश्न पर भूगोलवेत्ताओं के साथ ही मानव वैज्ञानिकों में अत्यधिक मतभेद है। जनसंख्या का अध्ययन मानव भूगोल का अभिन्न अंग है। मानव भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1932 ई. में प्रकाशित फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता कैनिल वैल्यूक्स की पुस्तक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस में मिलता है। इसी अवधि में ब्लाश, बूंश एवं डिमांजिया आदि ने मानव भूगोल की पुस्तक लिखी और प्रकाशित कराई । एस. डी. मौर्य ने अपनी पुस्तक जनसंख्या भूगोल में वर्णित किया है कि भूगोल जिसे मूलतः क्षेत्रीय भिन्नता का विश्लेषण करने वाला विज्ञान समझा जाता है, जनसंख्या के विविध लक्षणों के क्षेत्रीय प्रतिरूप की सकारण व्याख्या करता है।

1.1 उद्देश्य

जनसंख्या भूगोल अध्ययन की नवीन शाखा जिसके कारण इसके अध्ययन का दृष्टिकोण भी प्राचीन विषयों से अलग होगा। प्रस्तुत अध्याय के उद्देश्य निम्नलिखित है –

1. भूगोल में जनसंख्या का अध्ययन।
2. जनसंख्या भूगोल की परिभाषा को स्पष्ट करना।
3. जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र – क्षेत्र को स्पष्ट एवं निर्धारित करना।

प्राचीन काल में भूगोलवेत्ता में प्रमुख स्ट्रेबो ने जनसंख्या अध्ययन में विशेष योगदान दिया है। प्राचीन काल की सभी संस्कृतियों में भूगोल का अध्ययन किया जाता रहा है, लेकिन उसका स्वरूप वर्तमान भूगोल से अलग नहीं था । तब भूगोल एक नए विषय के रूप में स्थापित नहीं हुआ था और न ही अलग अध्ययन होता था । प्राचीन

काल की सभी सभ्यताओं में ऋषि, मुनियों द्वारा प्रकृति के विविध तत्वों की व्याख्या अपने लेखों, व्याख्यानों में समय – समय पर की गई है। उन लोगों ने अलग से किसी भौगोलिक सिद्धान्त अथवा संकल्पना का प्रतिपादन नहीं किया था, फिर भी उनके द्वारा दिये गए ज्ञान के आधार पर ही आधुनिक भूगोल की नींव टिकी हुई है। प्राचीन भारत वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, स्मृतियों, बौद्ध एवं जैन धर्म की पुस्तकों में ऐसे प्रसंग मिलते है, जो आधुनिक भौगोलिक ज्ञान से समकक्ष है। मध्य एशिया में होमर द्वारा लिखी गई पुस्तक इलियड एवं ओडिसी ऋग्वेद के समकालीन है। इन दोनों पुस्तकों में पवनों के प्रवाह, मार्ग एवं दिशा के साथ उनसे प्रभावित होकर जनसंख्या के वितरण का वर्णन मिलता है।

वर्तमान काल से लगभग कुछ शताब्दी पूर्व तक भूगोल का अध्ययन भौतिक विज्ञान के अधिक निकट माना जाता था और इसके अध्ययन क्षेत्र की विषय वस्तु में मानव की अपेक्षा भूक्षेत्र, प्रादेशिक अध्ययन एवं यात्रा वृतांत को अधिक प्राथमिकता दी जाती थी। बाद के समयों में कुछ विद्वानों द्वारा मानव को भी भौगोलिक अध्ययन में शामिल करने की वकालत की जाने लगी थी। इस प्रकार भौतिक एवं मानवीय तथ्यों की प्रधानता के आधार पर परंपरागत भौगोलिक अध्ययन की पद्धति दो प्रमुख शाखाओं में विभक्त हुई है। इन दोनों शाखाओं के नाम भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल हैं। भौतिक भूगोल में प्रकृति प्रदत्त तत्वों का अध्ययन किया जाता है जबकि मानव भूगोल में मानव और उसके पर्यावरण के मध्य अंतर्संबंधों तथा उनके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले क्षेत्रीय प्रतिरूपों का विश्लेषण किया जाता है। इसकी विषय वस्तु में जनसंख्या सहित अनेक सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन सम्मिलित होता है। अध्ययन की उपयोगिता में होने वाली वृद्धि का प्रभाव यह हुआ कि अब सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा है। क्षेत्रीय अध्ययनों में मानवीय तथ्यों का बढ़ता प्रभाव मुख्य रूप से 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक से प्रारम्भ होने वाली संभववादी विचारधारा का परिणाम रहा है। इसके विकास में फ्रांस के संभाववादी विचारकों ब्लाश, बूंश, डिमांजिया आदि ने सहयोग किया था । इस प्रकार भौगोलिक अध्ययनों में मानव को केंद्रीय स्थान प्राप्त हुआ है साथ ही भूगोलवेत्ताओं की रुचि जनसंख्या के अध्ययन में बढ़ने लगी । बढ़ते मानवीय महत्त्व के फलस्वरूप पिछले चार से पाँच दशकों में भूगोल को एक सामाजिक विज्ञान का स्थान प्रदान किया जाने लगा। ऐसी स्थिति में भौगोलिक अध्ययन की विषय वस्तु में भूक्षेत्र के स्थान पर मानव और उससे जुड़े तथ्यों को प्रासंगिकता दी जाने लगी।

जनसंख्या और उससे जुड़ी समस्याओं की सार्थकता एवं व्यापकता के सार्थक अध्ययन के उद्देश्य से भूगोल में विशिष्टीकरण की प्रवृत्ति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई और मानव भूगोल की अनेक शाखाएँ एवं उपशाखाएँ विकसित हुई। इन शाखाओं में जनसंख्या भूगोल भी एक महत्त्वपूर्ण शाखा है जो भूगोल की एक नई शाखा है, जिसका विकास 1960 के दशक से प्रारम्भ हुआ था। जनसंख्या भूगोल के आधुनिक काल के लेखकों में संयुक्त राज्य अमेरिका के बेकर (1928), आरूषों (1923) और जैफरसन (1909) के साथ ही ब्रिटेन के आर्थर गैडिस (1941) ने भी विशेष कार्य किया है। भौगोलिक अध्ययन में जनसंख्या की दृष्टि से वर्ष 1953 ई. का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसी वर्ष ट्रिवार्था ने अलग से जनसंख्या भूगोल की नीव रखी थी। उन्हें अमेरिकी भूगोल परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने जनसंख्या भूगोल को एक क्रमबद्ध स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। इसके पश्चात जनसंख्या भूगोल एक अलग शाखा के रूप में पढ़ा और पढ़ाया जाने लगा। कालांतर में जनसंख्या से संबंधित अनेक शोध भी किया और कराए गए। ट्रिवार्था ने अमेरिकी भूगोल संघ की पत्रिका में प्रकाशित अपने एक लेख के द्वारा जनसंख्या भूगोल की रूप रेखा प्रस्तुत की थी। इसके बाद अमेरिका के साथ विश्व के अनेक देशों में जनसंख्या के अध्ययन एवं अध्यापन की प्रेरणा मिली। ट्रिवार्था के पश्चात क्लार्क, मैलेजीन, जैलिन्सकी, डैम्को, गार्नियर आदि ने जनसंख्या भूगोल की विषय वस्तु के साथ इसके अध्ययन क्षेत्र को निर्धारित करने का प्रयास किया। इसके पश्चात विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययन एवं शोध के लिए विभाग स्थापित किए गए थे।

1.2 जनसंख्या भूगोल की परिभाषा

जनसंख्या भूगोल, भूगोल की नवीनतम शाखाओं में से एक है। इसको स्थापित करने एवं वर्तमान स्वरूप प्रदान करने का श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिका के जी. टी. ट्रिवार्था को जाता है। ट्रिवार्था ने इसे सर्वप्रथम स्वतंत्र एवं क्रमबद्ध शाखा के रूप में स्थापित किया, इसी कारण इनको जनसंख्या भूगोल का पिता भी कहा जाता है। उनके अनुसार जनसंख्या, जनसंख्या भूगोल का मूल तत्व, जनसंख्या द्वारा आवासित पृथ्वी के प्रादेशिक विभिन्नताओं को समझने में निहित है।

ट्रिवार्था ने जनसंख्या भूगोल की परिभाषा देते समय भूगोलवेत्ताओं का ध्यान निम्नलिखित बिंदुओं की ओर आकर्षित किया है –

1. भौगोलिक अध्ययन के केंद्र में जनसंख्या का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए।
2. सभी विषयों के अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या एक प्रमुख घटक है, जबकि भूगोल में इसे अभी तक वह मान्यता नहीं प्राप्त हो सकी है।
3. भूगोलवेत्ताओं ने अब तक अपने अध्ययन में जनसंख्या को वह स्थान नहीं दिया है जो देना चाहिए था।
4. उन्होंने बताया की जनसंख्या भूगोल का मुख्य उद्देश्य भू–दृश्य पर असमान रूप से वितरित जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों के प्रादेशिक अंतर का अध्ययन करना।

इन्हीं संदर्भों को समेकित करते हुए ट्रिवार्था ने वर्ष 1969 ई. में जनसंख्या भूगोल पर पहली पुस्तक 'A Geography of Population : World Patterns' लिखी जो दो खण्डों में विभाजित है। इसके पहले भाग में उन्होंने भूतकालीन जनसंख्या का विश्लेषण किया है जबकि दूसरे भाग में जनसंख्या के जैविक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पक्षों का विश्लेषण किया है।

ट्रिवार्था ने जनसंख्या भूगोल को स्थापित करने के साथ ही इसके अध्ययन क्षेत्र, विषय वस्तु एवं उद्देश्य को भी निर्धारित किया ताकि भविष्य में इसका स्थायित्व बना । बिना उद्देश्य के किसी विषय में अध्ययन, अध्यापन एवं शोध जैसे कार्य नहीं हो सकते हैं । ट्रिवार्था द्वारा जनसंख्या भूगोल के लिए निर्धारित दो उद्देश्य निम्नलिखित है –

अ) जनसंख्या के सभी तथ्यों को समझना – इसके अंतर्गत जन्म, मृत्यु, लिंग, संघटन, आयु, प्रजननता, वितरण, घनत्व, वृद्धि, प्रवास, आदि का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है।

ब) जनसंख्या की कालिक भिन्नता एवं क्षेत्रीय भिन्नता को समझना तथा जानना – इसके अंतर्गत जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। किसी स्थान की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के दो स्वरूप होते है। कालिक भिन्नता से तात्पर्य होता है किसी स्थान की जनसंख्या प्रवृत्ति का दो या दो से अधिक काल अवधियों में होने वाला परिवर्तन । यह परिवर्तन दो प्रकार का होता है धनात्मक एवं ऋणात्मक । इसी प्रकार क्षेत्रीय भिन्नता का अर्थ होता है दो या दो से अधिक स्थानों पर जनसंख्या की वृद्धि, वितरण, विकास एवं जनसंख्या के प्रक्षेपण का अध्ययन करना ।

ए. मेलेजिन – मेलेजिन रूस के निवासी थे, उनके विचारों तथा अध्ययन की विधि तंत्र पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव देखा जाता है। वे मार्क्स के विचारों से ज्यादा प्रभावित थे । उन्होंने जनसंख्या के उत्पादक पक्ष को महत्त्व प्रदान किया है। जनसंख्या के वितरण स्वरूप के लिए भी उन्होंने आर्थिक एवं उत्पादक पक्ष को ही उत्तरदायी बताया है। उन्होंने अपने अध्ययन में जनसंख्या भूगोल को आर्थिक भूगोल की एक शाखा के रूप में मान्यता प्रदान की है। अन्य रूसी भूगोलवेत्ताओं के साथ मिलकर जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र को आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर निर्धारित करने का प्रयास किया है। इसमें विभिन्न उत्पादक सम्बन्धों की प्रधानता एवं प्रभाविता के आधार पर आर्थिक क्रियाकलापों को ग्रामीण एवं नगरीय में विभाजित किया है।

उनके अनुसार जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या के वितरण तथा विभिन्न जनसंख्या समूहों में विद्यमान उत्पादक संबंधों और अधिवास तंत्र के साथ समाज के उत्पादक उद्देश्य के लिए उसकी उपयुक्तता, उपयोगिता और प्रभावशीलता का अध्ययन है। रूस के निवासी इस भूगोलवेत्ता ने मार्क्सवादी विचारधारा का अनुसरण किया और समजवादी मान्यता का पालन भी करते हैं । उन्होंने जनसंख्या के वितरण प्रतिरूप का अध्ययन करने हेतु इसके उत्पादक पक्ष को स्वीकार किया है।

विल्वर जेलिन्सकी एक प्रमुख जनसंख्या भूगोलविद है। जनसंख्या भूगोल पर उनकी पुस्तक 'A Prologue to Population Geography' वर्ष 1966 ई. में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उन्होंने जनसंख्या भूगोल को जनसंख्या का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया है। उन्होंने एक विस्तृत परिभाषा प्रस्तुत की है। उनके अनुसार जनसंख्या भूगोल वह विज्ञान है जो उन सभी रीतियों की व्याख्या करता है, जो स्थलों की भौगोलिक प्रकृति को निर्मित करते हैं। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप जनसंख्या तत्वों का एक समूह उत्पन्न होता है, जो क्षेत्र एवं समय दोनों के संदर्भ में परिवर्तनशील होता है। दूसरे शब्दों में जेलिन्सकी लिखते हैं कि जनसंख्या भूगोल वह विज्ञान है जो उन तरीकों और विधितंत्रों की व्याख्या करता है जिनमें किसी स्थान की भौगोलिक प्रकृति निर्मित होती है। इन सभी का संयुक्त

परिणाम यह होता है कि जनसंख्या तत्वों का एक विशाल जन समूह निर्मित होता है जो काल एवं क्षेत्र दोनों के संदर्भ में परिवर्तनशील होता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि ये तत्व आपस में एवं अनेक अजैविक तत्वों के साथ अंतर्क्रिया करते हुए अपने व्यावहारिक नियमों के अनुसार कार्यों का सम्पादन करते हुए एक दूसरे को प्रभावित करते है तथा प्रभावित भी होते है।

उपर्युक्त सन्दर्भ के अनुसार जनसंख्या भूगोल कि यह परिभाषा तीन तथ्यों का बोध कराती है जो निम्नलिखित है –

1. जनसंख्या के विविध घटकों एवं तथ्यों का क्षेत्रीय वितरण किस प्रकार का है तथा पृथ्वी के धरातल पर कहाँ – कहाँ वितरित पाया जाता है।
2. इन तत्वों के वर्तमान क्षेत्रीय वितरण एवं स्वरूप के लिए जिम्मेदार कारण कौन से है।
3. वर्तमान समय में जो क्षेत्रीय स्वरूप दृष्टिगत हो रहा है, उसका यह स्वरूप किस प्रकार प्राप्त हुआ हुआ है।

इन सभी तथ्यों की सार्थक व्याख्या एक भूगोलवेत्ता के लिए अति आवश्यक हो जाती है। उसे उसके सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करना चाहिए । इसके अतिरिक्त जेलिन्सकी का मानना है कि जनसंख्या भूगोल किसी क्षेत्र की जनसंख्या को उस क्षेत्र की सम्पूर्ण प्रकृति के संदर्भ अध्ययन करता है।

जे. आई. क्लार्क ब्रिटिश भूगोलवेत्ता होने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय भूगोल संघ में जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष थे । वर्ष 1965 ई. में इन्होंने जनसंख्या भूगोल पर एक पुस्तक पापुलेशन ज्योग्राफी लिखी । इस पुस्तक में उन्होंने जनसंख्या के गुणात्मक एवं मात्रात्मक पक्षों का विश्लेषण करने के साथ ही साथ भूतल पर उनके वितरण एवं क्षेत्रीय असमानताओं के भौतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पक्षों की व्याख्या की है। उनके अनुसार जनसंख्या भूगोल की परिभाषा है जनसंख्या भूगोल इस बात की व्याख्या करता है कि जनसंख्या के वितरण, संगठन, वृद्धि एवं प्रवास में व्याप्त क्षेत्रीय विभिन्नताओं का स्थानों की प्रकृति में पाई जाने वाली क्षेत्रीय विभिन्नताओं से कैसे संबंधित है।

क्लार्क ने जनसंख्या भूगोल का संबंध क्षेत्रीय विभेदन से भी जोड़ कर भी व्याख्या की है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि किस प्रकार किसी स्थान की भौगोलिक अवस्थिति, भौतिक संरचना, सांस्कृतिक संगठन, राजनैतिक सरचना एवं आर्थिक घटक जनसंख्या को प्रभावित करते है। क्लार्क लिखते हैं कि जनसंख्या भूगोल का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के विभिन्न पक्षों की क्षेत्रीय विविधताओं की व्याख्या करना है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है क्लार्क एवं ट्रिवार्था की परिभाषाएँ लगभग समान हैं उनमें कोई विशेष अंतर नहीं है।

जे. बी. गार्नियर प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे । इनके द्वारा जनसंख्या की विशेषताओं को संदर्भित करते हुए फ्रांसीसी भाषा में एक पुस्तक 'Geography of Population' लिखी गई थी, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद वर्ष 1966 ई. सबके सामने आया । उनके अनुसार जनसंख्या भूगोल किसी पर्यावरण के संदर्भ में जनांकिकीय तथ्यों की मूल विशेषताओं तथा उनके संभव का सकारण अध्ययन करता है।

इसी पुस्तक में गार्नियर ने बताया है कि जनसंख्या भूगोल मुख्यतः तीन प्रश्नों का अध्ययन करता है –

1. पृथ्वी के धरातल पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई ?
2. मनुष्य का वर्तमान वितरण किस प्रकार हुआ है ?
3. वर्तमान में मानव का विकास स्तर क्या है ?

इन्होंने जनसंख्या भूगोल का वर्णन वर्तमान वातावरण के सन्दर्भ में जनांकिकीय से जोड़ कर किया है। साथ ही इस बात पर भी विशेष जोर दिया है कि आंकड़ों के संकलन हेतु प्रयुक्त विधियों में शुद्धता एवं स्पष्टता भी होनी चाहिए ताकि वास्तविकताओं की जानकारी पूर्ण रूप से हो सके। उनका मानना है कि अपने उद्भव स्थल से वर्तमान स्थिति तक पहुँचने में मानव सभ्यता को किन – किन चरणों से गुजरना पड़ा है, साथ वर्तमान में उसके वितरण में भिन्नता देखी जा रही है वह किस कारण से है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि एक जनसंख्या भूगोलवेत्ता के लिए आवश्यक है इसके तीन मूल प्रश्नों के उत्तर यथासंभव एवं तर्कपूर्ण ढंग प्रस्तुत करें तथा भविष्य के योजना एवं मानसिक मानचित्र भी प्रस्तुत करें।

जी. जे. डेम्को अमेरिका के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे। इनके अध्ययन प्रणाली पर तत्कालीन अमेरिकी भौगोलिक विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। उन पर नवनियतिवादी विचारधारा का अधिक प्रभाव पड़ा था। अमेरिका के अन्य भूगोलवेत्ताओं के साथ ही वह भी प्राकृतिक प्रभाव के अंतर्गत मनुष्य की क्रियाशीलता पर जोर देते हैं। इन्होंने वर्ष 1970 ई. में Population Geography : A Reader नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में इन्होंने जनसंख्या के जनांकिकीय लक्षणों के साथ ही सामाजिक – आर्थिक लक्षणों के क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन किया है। इन्होंने जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र को भी निर्धारित करने का कार्य किया है। जनसंख्या डेम्को के अनुसार जनसंख्या भूगोल, भूगोल की वह शाखा है, जिसमें किसी क्षेत्र विशेष की जनांकिकीय एवं अजनांकिकीय तथ्यों की मौलिक विशेषताओं एवं विभिन्नताओं का विश्लेषण किया जाता है। उन्होंने लिखा है कि जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या के वितरण, परिवर्तन, उत्पादकता, मर्त्यता, आवास, प्रवास के साथ खाद्य आपूर्ति एवं जनसंख्या नीति को सम्मिलित किया जाता है।

डेम्को ने जनसंख्या भूगोल में जनांकिकीय विशेषताओं के साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक लक्षणों की क्षेत्रीय विविधताओं के अध्ययन को भी सम्मिलित करने पर जोर दिया है। उनका यह भी मानना है कि जनसंख्या भूगोल में एक मॉडल विकसित किया जाना चाहिए जिसके आधार पर किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली समस्त जनसंख्या के लक्षण निर्धारक प्रक्रियाओं को अच्छी तरह से समझा जा सके।

जनसंख्या भूगोल को विषय के रूप विकसित करने में पाश्चात्य भूगोलविदों के साथ ही रूस के मार्क्सवादी विचारकों ने भी विशेष योगदान दिया था। इन दोनों के विचार, मान्यता एवं विधि तंत्र में पर्याप्त अंतर था। जहाँ पाश्चात्य भूगोलविदों ने जनसंख्या भूगोल को भूगोल की एक शाखा के रूप में विकसित किया था वहीं मार्क्सवादी विचारकों ने इसे आर्थिक भूगोल का प्रमुख घटक के साथ उसकी उपशाखा मानते है। जनसंख्या भूगोल को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने एवं अलग से एक विषय के रूप में स्थापित करने में विशेष योगदान अमेरिका, ब्रिटिश एवं अन्य पश्चिमी भूगोलवेत्ताओं का था। इस प्रकार सम्पूर्ण अध्ययन के पश्चात जनसंख्या भूगोल की निम्नलिखित परिभाषा दी जा सकती है जनसंख्या भूगोल, भूगोल की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जनसंख्या के संघटन, जनसंख्या के वितरण एवं परिवर्तन में पाई जाने वाली क्षेत्रीय विभिन्नताओं तथा किसी निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या और पर्यावरण के मध्य होने वाले अंतःक्रिया से उत्पन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है।

1.3 जनसंख्या भूगोल की प्रकृति

प्रत्येक विषय की अपनी कुछ खास विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर वह विषय अन्य विषयों से अलग होता है। साथ ही जो उस विषय के समग्र स्वरूप को प्रकट करती है अथवा स्पष्ट करती है या खोलती है। इन्हीं सभी विशेषताओं को एक साथ जोड़कर जब एक विशेष स्वरुप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे ही उस विषय की विषय वस्तु कहा जाता है। जनसंख्या भूगोल की प्रकृति के विषय में किसी विशेष प्रकार का कोई सिद्धांत प्रचलित नहीं है फिर भी अलग – अलग विद्वानों द्वारा इसके विषय क्षेत्र की अलग – अलग प्रकार से पहचान की गई है। जनसंख्या भूगोल की प्रकृति को चिन्हित करने के लिए विद्वानों द्वारा जो मत प्रस्तुत किए गए हैं उन्हें समग्र रूप से एक साथ अभिव्यक्त करने पर निम्नलिखित परिदृश्य प्रकट होते हैं –

(1) जनसंख्या भूगोल के अध्ययन का मूल केंद्र बिंदु स्थान, क्षेत्र के साथ – साथ जनसंख्या का होना ।

(2) जनसंख्या भूगोल का एक अंतरविषयक विज्ञान के रूप में पाया जाना ।

(3) जनसंख्या भूगोल का एक गतिशील विज्ञान होना ।

(4) जनसंख्या भूगोल विभिन्न जनांकिकीय तत्वों में व्याप्त अंतर्संबंधों की व्याख्या करता है।

(1) जनसंख्या भूगोल के अध्ययन का मूल केंद्र बिंदु स्थान, क्षेत्र के साथ–साथ जनसंख्या का होना : जिस प्रकार इतिहास के अध्ययन का केंद्र बिंदु समय, राजनीतिशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु राज्य, अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु धन और समाजशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु समाज होता है। इस प्रकार जनसंख्या भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु स्थान, क्षेत्र के साथ – साथ जनसंख्या भी होती है। जनसंख्या का संबंध पृथ्वी तल पर उसके वितरण से होता है, इसके बगैर जनसंख्या की कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः इसकी विषय वस्तु में जनसंख्या केंद्रीय स्थान रखती है। स्थान एक सापेक्ष तत्व होता

है जो धरातल पर अवस्थिति, धरातल की संरचना, जलवायु, वनस्पति एवं विभिन्न संस्कृति के साथ आर्थिक दशाओं से युक्त होती है। अतः प्रत्येक स्थान का एक विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। स्थान का यही व्यक्तित्व जनसंख्या को प्रभावित करता है तथा जनसंख्या के तत्वों के बीच अंतरसंबंधों को बनता है। इसके साथ ही जनसंख्या के जनसांख्यिकीय गुण एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न – भिन्न होते हैं । ऐसी स्थिति में जनसंख्या भूगोल के अध्ययन का प्रथम केंद्र बिंदु होती है, जहाँ वह यह पहचान करने का प्रयास करता है कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की जनसंख्या निवास करती है। साथ ही वह उस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले भौतिक एवं सांस्कृतिक कारकों को भी अभिव्यक्त करता है, जिनके आधार पर उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या वितरित पाई जाती है। इस प्रकार जनसंख्या भूगोल में क्षेत्र एवं जनसंख्या दोनों एक – दूसरे से अतःसंबंधित होते हैं और दोनों को एक – दूसरे से अलग करके अध्ययन नहीं किया जा सकता है।

(2) **जनसंख्या भूगोल एक अंतर विषयक विज्ञान है** : जनसंख्या भूगोल की प्रकृति का दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है उसका एक अंतरविषयक विषय के रूप में अस्तित्व क्योंकि जनसंख्या भूगोल का संबंध स्थान अथवा क्षेत्र के साथ – साथ जनसंख्या से भी है। अतः पृथ्वी तल से इसका प्रत्यक्ष जुड़ाव पाया जाता है। यह संबंध उसे अन्य प्राकृतिक विषयों से भी भली – भांति जोड़ता है जिन्हें प्राकृतिक नियमों के आधार पर वर्णित किया जा सकता है। इसी प्रकार पृथ्वी तल से संबंधित अन्य विषय या जनसंख्या से संबंधित अन्य विषयों के साथ इसका अंतरसंबंध बनता है। जनसंख्या का सीधा संबंध नगर अथवा ग्रामीण जनसंख्या के रूप में प्रकट होता है। अतः नगरीय भूगोल एवं ग्रामीण भूगोल के साथ – साथ अधिवास भूगोल भी प्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या भूगोल से संबंधित है। जनसंख्या भूगोल के विकास का जब अध्ययन किया जाता है, तो अर्थशास्त्र से भी इसका संबंध जुड़ जाता है क्योंकि अर्थशास्त्र का मूल बिंदु मानव द्वारा क्रियान्वित आर्थिक क्रियाकलाप एवं उससे उत्पन्न होने वाले विविध प्रकार के स्वरूपों से होता है। आर्थिक क्रियाएं मानव विकास का आधार होती हैं । यही कारण है कि उसके सभी क्रियाकलापों को आर्थिक उपार्जन के रूप में मापा जाता है। इन आर्थिक क्रियाओं का प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन के माध्यम से विनिमय करता है। इस प्रकार जनसंख्या भूगोल अर्थशास्त्र से भी बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है साथ ही इसकी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं मानव जीवन को खु"ा बनाने का प्रयास करती हैं । जब जनसंख्या के सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है तब जनसंख्या भूगोल समाजशास्त्र से जुड़ जाता है क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार के संबंधों से जुड़ा होता है और इन्हीं संबंधों के फलस्वरुप जो परिदृश्य उभर कर सामने आता है वही सामाजिक संरचना कहलाती है। सामाजिक संरचना व्यक्ति के संबंधों का जाल होती है जिसके आधार पर एक समाज अपने विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। सामाजिक संबंधों के साथ समाजशास्त्र से जुड़े होने की स्थिति में जनसंख्या भूगोल जनसंख्या के खान – पान, रहन – सहन, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन इत्यादि कार्यों का भी अध्ययन करता है। जनसंख्या भूगोल मानव के लिए कल्याणकारी कार्यों को भी प्रोत्साहन देता है। जब कल्याण को प्रोत्साहन दिया जाता है तब ऐसी स्थिति में जनसंख्या भूगोल स्वास्थ्य से भी जुड़ जाता है और स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधों का एक नया आयाम प्रस्तुत करता है। इस प्रकार यह देखा जाता है कि जनसंख्या भूगोल स्वयं भूगोल की अन्य शाखों के साथ – साथ सामाजिक विज्ञान और अन्य विषयों से काफी अंतर्संबंधित होता है। अतः ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि जनसंख्या भूगोल की प्रकृति अंतर विषयक होती है।

(3) **जनसंख्या भूगोल एक गतिशील विज्ञान है** : किसी विषय के उद्भव से लेकर वर्तमान समय तक उसकी विषय वस्तु में क्रमिक एवं निरंतर परिवर्तन होता रहता है। प्रारंभिक समय में किसी भी विषय का विषय वस्तु कुछ संकुचित रहता है लेकिन समय के साथ उसमें तीव्रता से परिवर्तन आता है और उसके विषय क्षेत्र में अन्य तत्वों का समागम होने लगता है। इस प्रकार वर्तमान समय तक प्राप्त होने वाली उसकी क्रमबद्धता ही उस विषय की गतिशीलता कहलाती है। जनसंख्या भूगोल अभी तक मात्र 6 दशक का जीवनकाल प्राप्त किया हुआ है। इसकी गतिशीलता को उतनी स्पष्टता से अभी रेखांकित नहीं किया जा सका है तथापि जो कुछ भी गतिशीलता अब तक दिखाई पड़ती है। वह उसके अध्ययन शैली में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या भूगोल का स्वरूप प्रारंभिक काल में गुणात्मक अधिक था जबकि अब उसमें मात्रात्मकता का प्रवेश हो चुका है। सांख्यिकी तकनीकियों के आधार पर जनसंख्या भूगोल के विभिन्न तत्वों की व्याख्या करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्हें आरेखीय माध्यमों से अभिव्यक्त करने पर भी

जोड़ दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उसके अध्ययन के तरीके तथा विषय वस्तु में काफी परिवर्तन हुआ है। अब जनसंख्या के विभिन्न तत्वों और घटकों को समझने के लिए मॉडल का भी प्रयोग किया जाने लगा है। मॉडलों के आधार पर विविध प्रकार की अध्ययन तकनीकियों का भी ईजाद हुआ है जिससे जनसंख्या भूगोल वर्तमान के समकालीन सामाजिक विज्ञान के विषयों के समक्ष खड़ा हो चुका है। जनसंख्या भूगोल में तंत्र विश्लेषण को भी समाहित किया जा चुका है, तंत्र विश्लेषण के माध्यम से जनसंख्या और उसके चारों तरफ आवृत्त तत्वों का एक साथ समग्र अध्ययन किया जाता है जो उसके बदले हुए परिदृश्य को प्रदर्शित करता है। जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र के अध्ययन क्रम में यह देखा जा सकता है कि किस प्रकार ट्रिवार्था से लेकर क्लार्क आदि ने तकनीकी आधार पर जनसंख्या भूगोल की विषय वस्तु को बढ़ाने का प्रयास किया है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या भूगोल को एक गत्यात्मक विषय के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

(4) जनसंख्या भूगोल जनांकिकीय तत्वों में व्याप्त अंतरसंबंधों की व्याख्या करता है : विभिन्न जनसंख्या तत्वों की व्याख्या में अंतरसंबंधों का वर्णन करना जनसंख्या भूगोल की एक प्रकृति है साथ ही साथ यह उसका एक स्वभाव भी बनता जा रहा है। जनसंख्या के तत्व ही जनसंख्या भूगोल के तत्व कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, नगरीकरण, जनसंख्या नियोजन आदि आते हैं। ये सभी घटक आपस में एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप से अतःसंबंधित भी हैं। इसी के साथ–साथ जनसंख्या जिस स्थान पर निवास करती है उसे स्थान के भौतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण से उसके अंतरसंबंध की व्याख्या जोड़कर करनी चाहिए। यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि सभी प्रकार के अध्ययन, कार्यक्रम आदि सिद्धांत पर आधारित होते हैं। जनसंख्या भूगोल की यही प्रकृति सबसे गहन होती है और इसे भूगोल से जोड़ती है। यह जनसंख्या से संबंधित किसी भी तत्व जैसे कहां, कैसे औ रक्यों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर आसानी से देने का प्रयास करती है। इस प्रकार जनसंख्या भूगोल की प्रकृति जनसंख्या के विभिन्न तत्वों की व्याख्या करने के साथ–साथ उनके अंतरसंबंधों को भी आसानी से अभिव्यक्त करती है।

1.4 जनसंख्या भूगोल का विषय क्षेत्र

भौगोलिक अध्ययन की दिशा में जनसंख्या भूगोल एक नवीनतम शाखा है जिसकी अवस्था अभी तक विकासमान है। इसी कारण अभी तक इसके अध्ययन क्षेत्र अथवा विषय वस्तु का पूर्ण रूप से निर्धारण नहीं हो सका है। इसकी गत्यात्मकता अधिक होने के कारण समय के साथ इसके विषय क्षेत्र में नए – नए पक्ष समाहित हो रहे हैं। यह सर्वमान्य है की जनसंख्या भूगोल के अध्ययन का केंद्रीय बिंदु मानव एवं उससे जुड़ी क्रियाएं हैं। इसी कारण जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र के निर्धारण में भूगोलविदों के विचारों में समानता नहीं पाई जाती है। प्रमुख भूगोलवेत्ताओं द्वारा निर्धारित जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र निम्नलिखित हैं –

अमेरिकी भूगोलवेत्ता जी. टी. ट्रिवार्था ने वर्ष 1953 ई. में जनसंख्या भूगोल को एक क्रमबद्ध रूप में स्थापित किया। उन्होंने भौगोलिक अध्ययन में जनसंख्या की महत्ता को बताया तथा यह मत व्यक्त किया कि जनसंख्या का अध्ययन किए बिना भौगोलिक अध्ययन आधारहीन है। ट्रिवार्था ने जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र को तीन भागों में विभाजित किया है –

अ. भूतकालीन जनसंख्या भूगोल : इसके अंतर्गत जनसंख्या के उद्भव, विकास एवं स्थानीय तथा वैश्विक वितरण के ऐतिहासिक काल का क्रमशः अध्ययन किया जाता है।

ब. मानव की संख्या : इसमें किसी प्रदेश विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या के वृद्धि, घनत्व, संगठन, प्रवास एवं वितरण के पक्षों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है।

स. जनसंख्या की विशेषताओं के वितरण का प्रादेशिक प्रतिरूप : ट्रिवार्था ने इसे दो उपखण्डों में विभाजित किया है –

1) **जनसंख्या का जैविक लक्षण** – इसके अंतर्गत जनसंख्या के उन पक्षों का अध्ययन किया जाता है, जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं जैसे आयु संरचना, जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात, स्वास्थ्य, प्रजाति आदि।

2) **सांस्कृतिक लक्षण** – इसके अंतर्गत उन पक्षों का अध्ययन करते हैं जो किसी जो किसी भौगोलिक प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या अपने कार्यात्मकता एवं क्रियाशीलता के फलस्वरुप निर्मित करती है। ये पक्ष हैं धर्म, भाषा, साक्षरता, आर्थिक स्तर, आवास, प्रवास, व्यावसायिक संरचना, जाति व्यवस्था, वैवाहिक स्थिति एवं राष्ट्रीयता इत्यादि है।

क्लार्क के अनुसार जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र – प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता क्लार्क ने जनसंख्या की सभी विशेषताओं का गहन अध्ययन करने के पश्चात उसके विषय क्षेत्र को तीन वर्गों में विभाजित किया है –

अ. **जनसंख्या की निरपेक्ष संख्या** –इसके अंतर्गत उन्होंने विश्व की संपूर्ण जनसंख्या की भौगोलिक विशेषताओं को समाहित किया है।

ब. **जनसंख्या के जैविक एवं सांस्कृतिक लक्षण** –अध्ययन की दृष्टिकोण से उन्होंने इसे तीन प्रमुख उपवर्गों में विभाजित किया है –

1) **भौतिक लक्षण** –इसके अंतर्गत जनसंख्या की जन्म दर, मृत्यु दर, आयु, लिंग एवं प्रजाति संबंधित विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है।

2) जनसंख्या के सांस्कृतिक एवं सामाजिक लक्षण – इसके अंतर्गत परिवार, अधिवास, भाषा, शिक्षा, साक्षरता, धर्म, जाति व्यवस्था, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है।

3) **आर्थिक लक्षण** –इसके अंतर्गत उद्योग, व्यवसाय एवं आय इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है।

स. **जनसंख्या की गतिशीलता** –इसके अंतर्गत उन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है जिनसे किसी स्थान विशेष की जनसंख्या में परिवर्तन होते हैं जैसे जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास ।

विल्बर जैलीन्सकी के अनुसार – जैलीन्सकी ने अपनी पुस्तक 'A Prologue to Population Geography' में वर्णन किया है कि जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या के उन सभी लक्षणों को समाहित करना चाहिए जिनके बारे में आंकड़े उपलब्ध हैं । इस प्रकार उन्होंने जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र को उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर प्रस्तावित किया है तथा तीन वर्गों में विभक्त किया है –

अ. **जनसंख्या के भौतिक लक्षण** – इसके अंतर्गत प्रजाति, आयु, लिंग, जन्म एवं मृत्यु से जुड़े तथ्यों का अध्ययन किया जाता है।

ब. **सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक लक्षण** –इसके अंतर्गत आय, व्यवसाय, आवास, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता एवं भाषा से जुड़े अध्ययन को प्राथमिकता दी जाती है।

स. **गत्यात्मक लक्षण** –इसके प्रमुख घटक जन्मदर, मृत्यु दर एवं प्रवास होते हैं ।

जनसंख्या भूगोल की प्रवृत्ति एक गत्यात्मक विज्ञान की है जिसकी विषय वस्तु एवं अध्ययन क्षेत्र की परिधि का निरंतर विस्तार हो रहा है। आधुनिक समय में जनसंख्या भूगोल में मात्रात्मक विधियों का प्रयोग होने लगा है तथा विषय के सामान्यीकरण हेतु तंत्र एवं माडल के निर्माण पर जोड़ दिया जाने लगा है। विषय की अधिक व्याख्या के लिए नवीनतम शोध, विधि तंत्र एवं तकनीकी क प्रयोग किया जा रहा है। इससे जनसंख्या भूगोल के अध्ययन को सार्थकता एवं प्रासंगिकता मिल रही है। उपरोक्त विद्वानों के जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र संबंधी विचारों का अध्ययन करने के पश्चात इसके विषय क्षेत्र को निम्नलिखित रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है –

1. **जनसंख्या भूगोल की प्रकृति** – इसके अंतर्गत जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र, परिभाषा, अध्ययन के उपागम, अन्य विषयों से इसके संबंध आदि का अध्ययन किया जाता है।

2. **जनसंख्या की निरपेक्ष संख्या** – जनसंख्या की निरपेक्ष संख्या में जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व का विश्लेषण सम्मिलित है।

3. **जनसंख्या की गत्यात्मकता** – गत्यात्मकता से तात्पर्य होता है निरंतर परिवर्तन से है। इसमें जन्मता, मर्तयता, प्रजननता, जनसंख्या में वृद्धि एवं प्रवास से संबन्धित मुद्दे सम्मिलित है।

4. **जनसंख्या के लक्षण** – जनसंख्या के लक्षणों क मुख्य रूप से तीन वर्गों में विभक्त किया जाता है –

अ) **भौतिक लक्षण** – इसके अंतर्गत जनसंख्या के प्रकृति प्रदत्त अवयवों को सम्मिलित किया है। इसमें आयु, लिंग एवं प्रजाति आते हैं।

ब) **आर्थिक लक्षण** – मानव के आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़ी क्रियाएँ इसमें सम्मिलित होती है, जिनके द्वारा व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसके घटक आय, कृषि, उद्योग एवं व्यवसाय आदि हैं।

स) **सामाजिक** – सांस्कृतिक लक्षण – मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनेकों सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों तथा नियमों को बनाया है। इन्हीं के माध्यम से वह अपने जीवन को सुखमय एवं समृद्ध बनाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से परिवार, ग्रामीण एवं नगरीय अवस्थिति तथा अनुपात, वैवाहिक स्थिति, जाति, धर्म, भाषा, साक्षरता एवं राष्ट्रीयता आदि सम्मिलित होते हैं।

5. **जनसंख्या एवं संसाधन में संबंध** – वे सभी वस्तुएँ जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम होती हैं संसाधन कहलाती है। इनके अभाव में मानव सभ्यता के सभी क्रियाकलाप ठप हो जाते है। इन्हीं के आधार पर जनसंख्या का वितरण संभव होता है। जनसंख्या की सघनता तथा विरलता संसाधनों की उपलब्धता पर ही निर्भर करती है। इसके अंतर्गत अनुकूलतम जनसंख्या, जनाधिक्य, जनअल्पता, जनसंख्या दबाव, जनसंख्या संसाधन प्रदेश आदि सम्मिलित होते है।

6. **जनसंख्या नीतियाँ और जनसंख्या नियोजन** – किसी भी देश की जनसंख्या सबसे महत्त्वपूर्ण संसाधन होती है। जब देश की जनसंख्या तथा उपलब्ध संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित हो जाता है तब उसे अनुकूलतम जनसंख्या कहते है। इस स्थिति में देश के सर्वोच्च विकास की संभावना होती है। उससे अधिक या कम होने पर विकास बाधिक होने लगता है। ऐसी स्थिति में देशों की सरकारों द्वारा जनसंख्या के वृद्धि अथवा ह्रास हेतु अनेकों जनसंख्या नीतियों एवं जनसंख्या नियोजन कार्यक्रमों को चलाया जाता है।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जनसंख्या भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के वर्गीकरण में उन सभी तथ्यों को समाहित करने का प्रयास किया गया है, जिनका उल्लेख 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक विभिन्न जनसंख्या भूगोलवेत्ताओं द्वारा किया गया है। अन्त में यह कहा जा सकता है कि विषय के विकास के साथ – साथ जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र के विकास की असीम संभावनाएँ विद्यमान हैं

1.5 सारांश

आपने इस इकाई में भूगोल में जनसंख्या अध्ययन, जनसंख्या भूगोल की परिभाषा एवं विषय – क्षेत्र का अध्ययन किया है। आप समझ गए होगें कि जनसंख्या भूगोल के विकास को प्रभावित करने में किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है। इससे विश्व या देश की जनसंख्या को गतिशीलता मिलती है तथा उसके विकास को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। वास्तव में किसी देश की जनसंख्या तथा वहाँ जनसंख्या भूगोल का अध्ययन उसकी भौगोलिक अवस्थिति, सरकारी नीतियों, सांस्कृतिक संगठन आदि से प्रभावित होता है।

इस इकाई में जनसंख्या भूगोल एवं उसके विषय क्षेत्र की उपयोगिता, क्षेत्रीय विभिन्नता के विविध आयाम तथा वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता को प्रस्तुत किया गया है। आपने देखा है कि जनसंख्या भूगोल, भूगोल की नवीनतम शाखा है। इसका अध्ययन भूगोल में बहुत बाद में शुरू हुआ जिसके कारण वैश्विक स्तर पर इसके अध्ययन के विविध स्वरूप प्रकट करते हुए है। किन्हीं देशों में इसके अध्ययन को ज्यादा महत्त्व दिया गया है तो किन्हीं देशों में कम। समय में होने वाले परिवर्तन के साथ ही जनसंख्या के अध्ययन की प्रासंगिकता में वृद्धि हुई है, जिसने जनसंख्या भूगोल के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान। इस प्रकार आपने जनसंख्या भूगोल की परिभाषा एवं विषय – क्षेत्र का विस्तृत एवं सारगर्भित अध्ययन किया है।

1.6 स्वमूल्यांकन प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

1. जनसंख्या भूगोल का उद्भव कब हुआ था।

(क) 1905 ई. (ख) 1953 ई. (ग) 1967 ई. (घ) 1912 ई.

2. जनसंख्या भूगोल का विकास किस देश में हुआ था ।

(क) ब्रिटेन (ख) संयुक्त अमेरिका (ग) जर्मनी (घ) रूस

3. जनसंख्या भूगोल का पिता किसे कहा जाता है ।

(क) जी. टी. ट्रिवार्था (ख) जेलिन्सकी (ग) क्लार्क (घ) डेम्को

4. जनसंख्या भूगोल की प्रथम पुस्तक का 'A Geography of Population : World Patterns' किसके द्वारा लिखी गई है ।

(क) जेलिन्सकी (ख) जी. एस. गोसाल (ग) जी. टी. ट्रिवार्था (घ) क्लार्क

5. जी. टी. ट्रिवार्था ने जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र को कितने भागों में विभक्त किया है ।

(क) 5 (ख) 4 (ग) 3 (घ) 7

1.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

Bogue] D- J-] 1969] Principles of Demography] John Wiley] N-Y-

Clarke] John I-] 1973] Population Geography] Pergaman Press] Oxford-

Crook] Nigel] 1997] Principles of Population and Development] Pergaman Press] N- Y-

Garmier] J- B-] 1970] Geography of Population] Longman] London-

Mamoria] C- B-] 1981] India's Population Problem] Kitab Mahal] New Delhi-

Premi] M- K-] 1991] India's Population] Heading Towards a Billion] B- R- Publishing Corporation-

Blassoff] M- and Srinivasan K-] 2001] Population Development Nexus in India : Challenges for the New Millennium] Tata McGraw Hill] New Delhi-

Woods] R-] 1979] Population Analysis in Geography] Longman] London-

Zelinsky] W-] 1966] A Prologue to Population Geography] Prentice Hall-

चन्दना, आर. सी., 2022, जनसंख्या भूगोल – संकल्पना, नियंत्रक व विश्व प्रारूप, कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

चन्दना, आर. सी., 2022, भारत : जनसंख्या (जनसंख्या भूगोल – भाग 2), कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

मौर्या, एस. डी., 2005, जनसंख्या भूगोल, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद.

ओझा, आर. पी., 1984, जनसंख्या भूगोल, प्रतिभा प्रकाशन.

हीरा लाल, 2000, जनसंख्या भूगोल के मूल तत्व, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली.

तिवारी, राम कुमार, 2023, जनसंख्या भूगोल, प्रवालिका पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद.

1.8 अभ्यास प्रश्न (सत्रांत परीक्षा की तैयारी)

1. भूगोल में जनसंख्या के अध्ययन की विस्तृत व्याख्या कीजिए?
2. जनसंख्या भूगोल को परिभाषित कीजिए?
3. जनसंख्या भूगोल के विषय – क्षेत्र का वर्णन कीजिए?

इकाई–2 जनसंख्या भूगोल के उपागम, जनसंख्या भूगोल का विकास

इकाई की रूपरेखा

2.0 प्रस्तावना

2.1 उद्देश्य

2.2 जनसंख्या भूगोल के उपागम

2.3 जनसंख्या भूगोल का विकास

2.4 सारांश

2.5 स्वमूल्यांकन प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

2.6 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

2.7 अभ्यास प्रश्न (सत्रांत परीक्षा की तैयारी)

2.0 प्रस्तावना

उपागम से तात्पर्य किसी ऐसी विधि या प्रक्रिया से है, जिसके द्वारा उसके मौलिक प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया जाता है। जनसंख्या भूगोल, भूगोल की नवीनतम शाखा है। इसके अध्ययन का केंद्रीय विषय वस्तु जनसंख्या है। इसी कारण भौगोलिक अध्ययन हेतु प्रयुक्त विधि तंत्र इसके लिए भी उपयोगी होते हैं। भूगोल के अध्ययन हेतु सर्वप्रथम हम्बोल्ट एवं रिटर ने उपागम विधि का प्रयोग किया है। हम्बोल्ट ने जहाँ क्रमबद्ध उपागम का प्रयोग किया है वहीं रिटर ने क्षेत्रीय विविधता को समझने हेतु प्रादेशिक उपागम का सहारा लिया है। यह उपागम वर्तमान समय में जनसंख्या और उसकी विशेषताओं, उसके मुद्दे, उसकी समस्याओं एवं इतिहास को समझने हेतु वर्तमान समय में भी बहुत ही उपयोगी है।

2.1 उद्देश्य

समय में परिवर्तन के साथ विषयों के अध्ययन की प्रवृत्ति में भी परिवर्तन होता है। अध्ययन की इसी परिवर्तनशीलता को विभिन्न उपगमों के अंतर्गत समझा जाता है। प्रस्तुत अध्याय के उद्देश्य निम्नलिखित है –

1. जनसंख्या भूगोल के उपागम का अध्ययन करना।
2. जनसंख्या भूगोल के विकास का अध्ययन करना।

2.2 जनसंख्या भूगोल के उपागम

जनसंख्या भूगोल की अध्ययन के प्रमुख उपागम निम्नलिखित है –

2.2.1 क्रमबद्ध उपागम

भौगोलिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के धरातल पर विद्यमान विभिन्नताओं का विश्लेषण करना है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक जनसंख्या मानव भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल में एक भौगोलिक कारक के रूप में प्रयुक्त होती थी। जनसंख्या भूगोल नामक अध्ययन की कोई शाखा अस्तित्व में नहीं थी। जनसंख्या भूगोल की नीव जी. टी. ट्रिवार्था 1960 के दशक में रखी थी। इस प्रकार उन्होंने भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या भूगोल को एक अलग शाखा के रूप में स्थापित किया । भौगोलिक दृष्टिकोण से भूगोल का मुख्य उद्देश्य किसी प्रदेश की विशेषताओं को समझना है जो कि क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार जनसंख्या से संबंधित विभिन्न पक्षों का भौगोलिक अध्ययन क्रमबद्ध रीति से ही संभव है। क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत एक संपूर्ण क्षेत्र को एक भौगोलिक इकाई माना जाता है तथा वहाँ निवास करने वाली जनसंख्या की सभी विशेषताओं का क्रमबद्ध विश्लेषण करते हैं।

अध्ययन की इस विधा में मापनी का कोई विशिष्ट प्रभाव नहीं होता है। अतः छोटे – बड़े किसी भी इकाई का चयन अध्ययन हेतु किया जा सकता है। जनसंख्या भूगोल के क्रमबद्ध उपागम का तात्पर्य है जनसंख्या के विविध पक्षों जैसे संगठन, जन्म दर, मृत्यु दर, घनत्व, वृद्धि, प्रवास, जनसंख्या एवं संसाधन में संबंध, जनसंख्या से जुड़ी समस्याएं, नियोजन एवं जनसंख्या नीतियां इत्यादि का एक साथ क्रमबद्ध विश्लेषण करना है। इस प्रकार देखा गया है कि जनसंख्या भूगोल क्रमबद्ध उपागम के आधार पर एक विज्ञान का स्वरूप धारण कर चुका है।

2.2.2 प्रादेशिक उपागम

प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत एक विस्तृत क्षेत्र को अनेक उप प्रदेशों में विभक्त करके जनसंख्या के विभिन्न तत्वों का भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। यह उपागम किसी भी भौगोलिक प्रदेश के विस्तृत अध्ययन हेतु प्रयोग किया जाता है। 20वीं शताब्दी के मध्य तक जब तक जनसंख्या भूगोल अलग से विषय के रूप में स्थापित नहीं हुआ था तब तक यह भूगोल का एक अभिन्न अंग था । ऐसी स्थिति में किसी प्रदेश की संरचना की तीन प्रमुख घटकों स्थान, जनसंख्या एवं कार्य की व्याख्या की जाती थी।

भौगोलिक अध्ययन में प्रादेशिक उपागम की शुरुआत कार्ल रिटर द्वारा की गई थी। अन्य तथ्यों की अपेक्षा जनसंख्या के सभी पक्षों का विस्तृत अध्ययन प्रादेशिक उपागम के द्वारा ही सही से हो सकता है। मनुष्य एवं पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया का स्तर हर प्रदेश में अलग – अलग होता है। इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले किसी भौगोलिक प्रदेश को सुविधा के अनुसार अलग – अलग उपविभागों में विभाजित करते हैं। उसके पश्चात अलग – अलग प्रदेशों की जनसंख्या संबंधित विविध लक्षणों का अध्ययन करते हैं। जैसे अगर भारत की जनसंख्या के साथ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का अध्ययन करना है तो देश को पहले राज्यों में, राज्यों को जिलों में एवं जिलों को उपखंडों में विभाजित करके एक – एक पक्ष की विस्तृत व्याख्या की जाती है।

2.2.3 ऐतिहासिक उपागम

भौगोलिक अध्ययन का यह विकासात्मक उपागम है जिसमें सभी भौगोलिक तथ्यों की व्याख्या कालिक संदर्भ में की जाती है। यहाँ कालिक विश्लेषण मुख्यतः जनसंख्या के तत्वों का समय के सापेक्ष व्याख्या करता है। इसमें किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या के विविध तत्वों की व्याख्या उनके उद्भव काल से लेकर वर्तमान समय तक क्रमिक रूप से की जाती है। इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या तत्वों के ऐतिहासिक परिवर्तन को देखा जाता है। जनसंख्या अध्ययन की इस विधा में जनसंख्या विकास की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरती है। अतः किसी प्रदेश के संपूर्ण विकास का अध्ययन करने हेतु ऐतिहासिक उपागम की आवश्यकता होती है।

इसके अंतर्गत सामान्य रूप से अध्ययन की संपूर्ण अवधि को उनकी विशेषताओं के अनुसार प्रमुख कालिक उपवर्गों में विभाजित करते हैं, जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल एवं वर्तमान काल इत्यादि । इस प्रकार विभाजन करने के पश्चात प्रत्येक उप विभाजित काल अवधि को भी उस अवधि में घटित होने वाली घटनाओं के अनुसार पुनः कई वर्गों में विभक्त करते हैं जैसे प्राचीन काल को वैदिक काल, ब्राह्मण काल, मौर्य काल, गुप्त काल । इसी प्रकार मध्यकालीन काल को सल्तनत काल, मुगल काल उत्तर मुगल काल एवं आधुनिक भारत को स्वतंत्रता के पूर्व का काल एवं स्वतंत्रता के पश्चात का काल के रूप में विभक्त किया जाता है। इस प्रकार जनसंख्या के विकासक्रम को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक काल, चीरसम्मत काल, पुनर्जागरण काल एवं वर्तमान काल आदि में विभाजित कर उसकी विशेषताओं का क्रमवार अध्ययन करते हैं ।

2.2.4 व्यवहार परक अथवा आचार परक उपागम

मानव भूगोल की प्रमुख शाखा जनसंख्या भूगोल में भी इस उपागम का प्रमुख स्थान है। भूगोल में इस उपागम के प्रयोग से वैचारिक स्तर पर क्रांति की शुरुआत हुई है जिसने भौगोलिक चिंतन में क्रांतिकारी एवं गुणात्मक परिवर्तन की शुरुआत हुई । जनसंख्या भूगोल के इस उपागम में मनुष्य के व्यवहार को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है तथा तथ्यों का विश्लेषण करते समय मानव के व्यक्तिगत व्यवहार को प्राथमिकता दी जाती है। इस उपागम में यह देखा जाता है कि किसी काम को करने या नहीं करने की संदर्भ में मानव के निर्णय एवं प्रतिक्रिया को उसका व्यवहार किस सीमा तक तथा किस प्रकार प्रभावित करता है। परिवार नियोजन के क्षेत्र में यह उपागम सर्वाधिक उपयुक्त होता है। उदाहरणस्वरूप परिवार में बच्चों की संख्या कितनी होगी तथा एक बच्चे से दूसरे बच्चे में कितने समय का अंतराल होगा इस प्रकार के निर्णय पर मानव की व्यक्तिगत सोच एवं व्यवहार का

अधिक प्रभाव होता है। भौगोलिक अध्ययन का एक प्रमुख अवयव प्रवास भी है जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाले प्रवास पर मानव की सोच एवं व्यवहार का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। जनसंख्या के तत्वों के अध्ययन में मनुष्य के व्यक्तिगत व्यवहार पर अधिक ध्यान दिया जाता है। समान भौगोलिक पर्यावरण पाए जाने पर जहाँ एक व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारणों से प्रवास हेतु प्रेरित होता है वहीं दूसरी तरफ एक अन्य व्यक्ति विकट परिस्थितियों के होने पर भी व्यक्तिगत विचारों और धारणाओं के प्रभाव के कारण अपना स्थान नहीं छोड़ता है।

जनसंख्या भूगोल के विधिक घटक जैसे जन्मदर, मृत्युदर, व्यवसाय चयन, वैवाहिक स्थिति एवं स्थानांतरण आदि के क्षेत्रीय प्रतिरूपों की व्याख्या मानव की आवश्यकता, रुचि तथा जीवन के नैतिक एवं सांस्कृतिक दर्शन का महत्व होता है। सामान्यतः मानव के व्यवहार का आकलन अधिकतर आर्थिक कारकों से जोड़कर देखा जाता है जबकि लाभ एवं हानि के मापदंड के स्थान पर कार्यकुशलता, आवश्यकता एवं रुचि अधिक प्रभावित होती है।

2.2.5 कल्याणपरक उपागम

यह उपागम जनसंख्या भूगोल में मानव समूह के कल्याण पर विशेष ध्यान देता है। यह उपागम मानव पर्यावरण के अंतःसंबंध के उसे पक्ष की ओर ध्यान आकर्षित करता है जहाँ सामाजिक, आर्थिक एवं प्रादेशिक न्याय की संभावना अधिक होती है। इस उपागम के अंतर्गत एक भूगोलवेत्ता इस बात को खोजने का प्रयास करता है कि किस स्थान पर जनसंख्या एवं उसके तत्व की अधिकता है तथा किस स्थान पर अभाव है। इस प्रकार इस उपागम के दो उद्देश्य होते हैं पहला क्षेत्रीय विषमता को ज्ञात करना तथा दूसरा इस विषमता को दूर करने का प्रयास करना जो विद्यमान है। इसी प्रकार इसके दो चरण भी देखे जाते हैं जैसे पहला क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना तथा दूसरा प्रादेशिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करना । इस उपागम का मूल उद्देश्य यह होता है कि मानव और पर्यावरण की अंतःक्रिया से उत्पन्न संसाधनों को समाज के सभी वर्गों, व्यक्तियों एवं पिछड़े स्थान तक न्याय संगत ढंग से वितरित करना जिसके फलस्वरुप क्षेत्रीय एवं सामाजिक असमानता का निवारण हो और एक सुखमय समाज का निर्माण हो । कल्याणपरक उपागम सतत विकास की प्रक्रिया पर आधारित है इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, मनोरंजन, प्रतिव्यक्ति आय आदि की सभी व्यक्तियों तक पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है।

2.2.6 तंत्र उपागम

अध्ययन के क्षेत्र में तंत्र विश्लेषण की संकल्पना का उद्‌भव डार्विनवाद के सिद्धांत के बाद होता है। इसके द्वारा भूतल पर स्थित अनेक तत्वों एवं तथ्यों के बीच जटिल विन्यास को समझने का प्रयास किया जाता है।

जेम्स के अनुसार तंत्र वस्तुओं का एक ऐसा संयोजन है जिसमें वस्तुओं एवं उनके गुणों के मध्य कार्यात्मक सहसंबंध की व्याख्या करता है।

मिलर ने तंत्र को एक ऐसे समुच्चय के रूप में परिभाषित किया है जिनमें आपस में गूढ़ संबंध होता है। इसकी प्रत्येक इकाई एक दूसरे से जुड़ी होती है निर्भर होती है तथा उन्हें पूर्णतः एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है।

जिम्मेरमन के अनुसार तंत्र उपागम का भौतिक विज्ञानों के साथ – साथ भूगोल में भी महत्व है। यह वस्तुओं का ऐसा समुच्चय है जिनके अंग एवं उपांग आपस में संबंधित होते हैं साथ ही साथ क्रियाशील भी होते हैं।

जनसंख्या भूगोल के सभी तत्व आपस में अन्य पर्यावरणीय तत्वों से जुड़े होते हैं इसीलिए किसी छोटे तत्व के स्वरूप में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या हेतु समस्त में होने वाली अंतःक्रिया की जानकारी जरूरी है। किसी क्षेत्र या पर्यावरण के अंतर्गत तंत्र उपागम की संकल्पना पार्थिव एकता से जुड़ी हुई है। यह उपागम जनसंख्या की विविध घटकों के में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। रिटर, रेटजल, ब्लाश, बूंश एवं सावर जैसे विद्वानों ने भूगोल में तंत्र विश्लेषण की संकल्पना को स्वीकार किया है। इनका मानना है कि जिस प्रकार किसी तंत्र के संचालन के लिए उसके सभी घटकों का क्रियात्मक स्वरूप आवश्यक होता है, उसी प्रकार पृथ्वी पर पाए जाने वाली जनसंख्या अध्ययन में तंत्र की व्याख्या उसके समस्त घटकों की एक ऐसी व्याख्या है। जिसमें सभी घटक एक – दूसरे के साथ संयोजित हैं तथा एक के बिना दूसरे की समुचित व्याख्या नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में प्रत्येक

भूगोलवेत्ता के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि जनसंख्या और उससे जुड़े अतःसंबंधों की व्याख्या हेतु तंत्र मॉडल का प्रयोग अवश्य करें।

2.3 जनसंख्या भूगोल का विकास

जनसंख्या पृथ्वी के भूतल के सबसे सक्रिय कारकों में से एक है, जिसकी क्रियाकलापों का अध्ययन भूगोलवेत्ताओं की साथ – साथ अन्य मानव शास्त्रियों द्वारा प्राचीन काल से अब तक किया जा रहा है। जनसंख्या भूगोल और उनसे जुड़ी समस्याओं का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन माल्थस द्वारा 1798 ई. में सर्वप्रथम किया गया था । उसने जनसंख्या एवं उपलब्ध खाद्यान्नों के संबंधों को जोड़कर सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इसी दौरान यूरोप एवं अमेरिका के विभिन्न देशों में जनणनाओं का दौर भी प्रारंभ हुआ । 20वीं शताब्दी में भी कुछ कतिपय विद्वानों द्वारा इसका अध्ययन किया गया। प्रमुख वैज्ञानिक कर सौंडर्स ने अपनी पुस्तक 'The Population Problems & A Study in Human Evolution' में वर्ष 1911 ई. में जनसंख्या के विकास एवं उसके आकार की व्याख्या की है। वर्ष 1929 ई. में कार्ल मार्क्स ने जनसंख्या और उससे जुड़ी समस्याओं के अध्ययन हेतु समाजवादी दृष्टिकोण का प्रयोग किया। इस प्रकार प्रारंभिक अवधि में जनसंख्या से संबंधित अध्ययनों की प्रगति बहुत ही धीमी थी।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जनसंख्या से जुड़ी समस्याओं के समाधान खोजे जाने लगे । अमेरिका एवं यूरोप के अनेक देशों ने भावी जनसंख्या वृद्धि हेतु विशेष प्रावधान करना शुरू कर दिया । इस कार्य हेतु विविध वैश्विक संस्थाओं ने जनसंख्या से संबंधित आंकड़े एकत्र किया तथा उनका विश्लेषण करने के पश्चात रिपोर्ट प्रकाशित की । इन संस्थानों में British Royal Commission, Leage of Nations, United Nations of Organisation, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक – सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन और खाद्य एवं कृषि संगठन ने अपने शोधों एवं प्रशासन के माध्यम से जनसंख्या भूगोल के विकास में विशेष योगदान दिया । इससे पूर्व प्रमुख भूगोलवेत्ता ब्लाश, बूंश, डिमांजिया और सोरे आदि ने भी मानव के केंद्रीय अध्ययन को प्रोत्साहन दिया ब्लाश ने अपने अध्ययन में जनसंख्या को मानव भूगोल का केंद्रीय विषय वस्तु बताया।

भूगोलविदों द्वारा जनसंख्या अध्ययन के इतिहास को पूर्व से कुछ भिन्न रखा गया है। लगभग एक शताब्दी पहले तक भूगोल को मुख्यतः भौतिक विज्ञान के निकट माना जाता था और उसमें मनुष्य की तुलना में भू–क्षेत्र पर अधिक बल दिया जाता था। प्राकृतिक तत्वों, पर्यावरण और प्रकृति के प्रभाव का ज्यादा से ज्यादा अध्ययन भूगोल के विषय क्षेत्र में समाहित किया जाता था। स्थलस्वरूपों के विकास में पर्यावरण की भूमिका और साथ ही साथ पर्यावरण किस प्रकार विकसित होकर मानव सभ्यता के विकास एवं संचालन को निर्देशित करता है, ऐसे विषयों को भूगोल के मुख्य विषय वस्तु के रूप में समाहित किया जाता था। 20वीं शताब्दी पूर्वार्द्ध में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता सोरे, ब्लाश, बूंश, डिमांजिया एवं ब्लाँशार आदि ने भूगोल को मानव केंद्रित अध्ययन की प्रवृत्ति पर जोर दिया। ब्लाश ने जनसंख्या को मानव भूगोल में अध्ययन की प्राथमिक तत्व के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि जब तक हम जनसंख्या को मानव भूगोल की प्राथमिक विषय वस्तु नहीं मानेंगे तब तक भौगोलिक अध्ययन पूरी तरह से संभव नहीं हो सकता है। भूगोल में भू–क्षेत्र की तुलना में जनसंख्या की अध्ययन पर अधिक महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि प्राकृतिक कारकों से अधिक सक्रिय मानवीय कारक होते हैं, जो धरातल पर विविध प्रकार की परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऐसी स्थितियों में भूगोलवेत्ताओं को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि मानव का अध्ययन अधिक से अधिक हो। इस प्रकार कुछ अन्य यूरोपीय देशों में भी भूगोल के अध्ययन में जनसंख्या के अध्ययन को अधिक रुचिकर बनाया गया किंतु भूगोल की एक पृथक शाखा के रूप में जनसंख्या भूगोल का स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सामने आता है।

कुछ विद्वानों का मानना है कि जनसंख्या भूगोल का अध्ययन पूर्व सोवियत संघ में वर्ष 1947 ई. के आस – पास शुरू हो चुका था। वहाँ पर जनसंख्या भूगोल के पाठ्यक्रम बनाए गए तथा कुछ विश्वविद्यालय में उन्हें चलाया भी जाने लगा था परंतु इन विद्वानों द्वारा किए गए प्रयासों को अधिक प्रोत्साहन एवं सहयोग स्थानीय सरकारों द्वारा नहीं प्राप्त हो सका। प्रारंभिक अवस्था में तो इन विश्वविद्यालयों में भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या भूगोल की एक शाखा स्थापित की गई परंतु उचित सहयोग एवं क्रियात्मक क्रियाकलापों की अनुपस्थिति में यह प्रयास उतना सफल नहीं रह सका। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता पियरे जॉर्ज ऐसे अग्रणी व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम जनसंख्या भूगोल का एक मोनोग्राम प्रकाशित कराया था जिसका प्रकाशन कई खण्डों में 1951 ई. के आस – पास प्रकाशित हुआ किंतु अभी तक एक संगठित विषय के रूप में जनसंख्या भूगोल को मान्यता नहीं मिल सकी थी। ऐसी स्थिति में कुछ प्रयास तो किए गए परंतु सार्थक एवं सफल आधार जनसंख्या भूगोल की स्थापना में अभी तक नहीं हो सकी थी।

जनसंख्या भूगोल का उद्‌भव वर्ष 1953 ई. में अमेरिका में हुआ था। जनसंख्या भूगोल के जन्मदाता जी. टी. ट्रीवार्था माने जाते हैं। वर्ष 1953 ई. में विसकांसिन विश्वविद्यालय में आयोजित अमेरिका भूगोलवेत्ता संघ की वार्षिक अधिवेशन में ट्रीवार्था ने अपने अध्यक्षीय भाषण में भूगोल को एक स्वतंत्र शाखा के रूप में जनसंख्या भूगोल को प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा। इसी दौरान उन्होंने इसके अध्ययन हेतु पाठ्यक्रम भी प्रस्तुत किया और बताया कि जनसंख्या की विश्लेषणात्मक एवं मात्रात्मक व्याख्या आवश्यक है। वे लिखते हैं की जनसंख्या वह संदर्भ बिंदु है जहाँ से सभी अन्य तत्व देखे जाते हैं जिससे वे सभी अकाल? एवं सामूहिक रूप से सार्थकता प्रदान करते हैं। 1960 के दशक में यूरोप सहित अमेरिका के अनेक विश्वविद्यालय में जनसंख्या भूगोल के अलग से पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वर्ष 1954 ई. में ट्रीवार्था एवं जैलीन्सकी ने संयुक्त रूप से उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में जनसंख्या प्रतिरूप शीर्षक से एक लेख प्रकाशित कराया जिसने भूगोलवेत्ताओं को जनसंख्या की ओर आकर्षित किया। वर्ष 1954 ई. में पी. ई. जेम्स ने अपनी पुस्तक जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन में ट्रीवार्था के योगदानों का विश्लेषण एवं समीक्षा किया है। जनसंख्या भूगोल को लोकप्रिय बनाने एवं संगठित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय जॉन क्लार्क को जाता है वे जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष के रूप में अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ में भी काम कर चुके थे। उन्होंने जनसंख्या के अध्ययन हेतु विधि तंत्र भी विकसित किया। उनकी पुस्तक जनसंख्या भूगोल 1965 ई. में प्रकाशित हुई जिसमें उन्होंने जनसंख्या अध्ययन के गुणात्मक एवं परीणात्मक दोनों पक्षों का विश्लेषण किया है। क्लार्क ने स्पष्ट किया है कि जनसंख्या का वितरण, प्रवास, संगठन तथा विकास आपस में अन्तरूसंबन्धित है।

प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जे. बी. गार्नियर ने जनसंख्या के सभी पक्षों का तर्कसंगत विश्लेषण अपनी फ्रांसीसी भाषा में लिखी पुस्तक जनसंख्या भूगोल में 1957 ई. में किया। यह पुस्तक वर्ष 1966 ई. में अंग्रेजी अनुवाद के साथ प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उन्होंने पर्यावरणीय दशाओं के संदर्भ में जनांकिकीय तत्वों के विश्लेषण पर बल दिया है।

जनसंख्या भूगोल की विषय वस्तु, अध्ययन क्षेत्र एवं उसे लोकप्रिय बनाने में प्रमुख योगदान अमेरिकन भूगोलवेत्ता जैलीन्सकी को भी जाता है। उनकी पुस्तक 'A Prologue to Population Geography' का प्रथम संस्करण वर्ष 1966 ई. में प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने बताया है कि जनसंख्या भूगोल किसी भौगोलिक प्रदेश में जनसंख्या का अध्ययन वहाँ की प्राकृतिक दशाओं के संदर्भ में करता है। जैलीन्सकी ने जनसंख्या भूगोल के अध्ययन को उनके लक्षणों के आधार पर तीन वर्गों में विभाजित किया है –

- **जनसंख्या के जैविक लक्षण** – इसमें आयु, लिंग एवं प्रजाति को सम्मिलित किया जाता है।
- **जनसंख्या के आर्थिक लक्षण** – इसमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक लक्षण आवास, व्यवसाय, विवाह, शिक्षा, धर्म एवं अन्य सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है।
- **जनसंख्या के गत्यात्मक लक्षण** – इसमें मुख्यतःजन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास सम्मिलित होते हैं।

अध्ययन की दृष्टिकोण से सोवियत संघ के भूगोलवेत्ताओं का दृष्टिकोण पाश्चात्य देशों से अलग था। उन्होंने जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र को विस्तृत माना तथा मानव को एक सक्रिय एवं उत्पादक कारक के रूप में स्वीकार किया। सोवियत संघ के प्रमुख भूगोलवेत्ता ए. मैलेजीन ने जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या के विभिन्न समूहों के उत्पादक संबंध, जनसंख्या का वितरण, उनके अधिवास के साथ उनकी क्रियाशीलता एवं उपयोगिता को स्वीकार किया है। वर्ष 1970 में जी. जे. डेम्को एवं साथियों के सहयोग से संपादित पुस्तक 'Population Geography & A Reader' में जनसंख्या से जुड़े विभिन्न तथ्यों का वर्णन मिलता है। उन्होंने ऐसे मॉडल भी विकसित करने पर बल दिए हैं जिसमें जनसंख्या के सभी लक्षणों का वर्णन हो।

लारकिन एवं पीटर्स ने संयुक्त रूप से वर्ष 1979 ई. में जनसंख्या भूगोल पर एक पुस्तक 'Population Geography & Problems] Concept and Prospectus' शीर्षक से प्रकाशित किया। इस पुस्तक में उन्होंने साक्षरता के साथ जनसंख्या से जुड़े तथ्यों की व्याख्या प्रस्तुत की है। वर्ष 1979 ई. में रॉबर्ट वुड ने अपनी पुस्तक 'Population Analysis in Geography' को प्रकाशित कराया। इन्होंने जनसंख्या भूगोल के शोधकर्ताओं को मॉडल निर्माण एवं नवीन विधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस प्रकार उपर्युक्त भूगोलवेत्ताओं के साथ – साथ अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा समितियों ने जनसंख्या भूगोल के विकास में विशेष योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ एवं इसके द्वारा निर्मित जनसंख्या आयोग ने जनसंख्या के विस्तृत अध्ययन हेतु जनसंख्या भूगोल के विकास में विशेष योगदान दिया है।

जनसंख्या भूगोल के विकास में कुछ प्रसिद्ध भूगोलवेत्ताओं के विशेष योगदान

भौगोलिक अध्ययनों में जनसंख्या भूगोल एक नवीनतम शाखा है, जिसका विकास बहुत बाद में हुआ है। अनेक विद्वानों ने अपनी पुस्तकों, लेखों, शोध पत्रों, मोनोग्राम एवं व्याख्यानों के माध्यम से इसके विकास के मार्ग को प्रशस्त किया था। इनके अध्ययन एवं अध्यापन की एक वृहद श्रृंखला विकसित हुई, जो कालांतर में भूगोलवेत्ताओं के संघ में परिवर्तित हुई। इस प्रकार जनसंख्या भूगोल के विकास में योगदान देने वाले प्रमुख भूगोलवेत्ताओं एवं उनके योगदान को निम्नलिखित सारणी में सूचीबद्ध किया गया है –

सारणी 2.1 जनसंख्या भूगोल के क्रमबद्ध विकास में भूगोलवेत्ताओं के योगदान

क्र. सं.	विशेष वर्ष	प्रमुख व्यक्ति अथवा संस्थान	दिया गया विशेष योगदान
1.	1798 ई.	टी. आर. माल्थस	1. इनसे पूर्व जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन का अभाव। 2. पहली बार इन्होंने जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन की नीव रखी थी। 3. जनसंख्या वृद्धि तथा खाद्य संसाधनों की वहन क्षमता के संबंध का सिद्धान्त प्रतिपादित किया था।
2.	1911 ई.	कार सैंडर्स	1. जनसंख्या अध्ययन की शुरुआत की तथा जनसंख्या पर एक पुस्तक लिखी। 2. उस पुस्तक का नाम था The Population Problems % A Study in Human Evolution- 3. इन पुस्तक में उनके द्वारा जनसंख्या के विकास तथा आकार का अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है।
3.	1929 ई.	कार्ल मार्क्स	1. समाजवादी दृष्टिकोण से जनसंख्या का अध्ययन। 2. जनसंख्या की सभी समस्याओं का जड़ गरीबी को बताया।
4.	1951 ई.	पियरे जार्ज	1. फ्रांस के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे। 2. जनसंख्या भूगोल का प्रथम मोनोग्राम प्रकाशित कराया। यह मोनोग्राम कई खण्डों में उपलब्ध है।
5.	1953 ई.	जी. टी. ट्रिवार्था	1. जनसंख्या भूगोल के पिता कहे जाते हैं। 2. विसकांसिन विश्वविद्यालय में भूगोल के प्राध्यापक नियुक्त हुए थे। 3. अमेरिकी भूगोलवेत्ता संघ के वार्षिक अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष चुना गया था। इसी अध्यक्षीय भाषण इनके द्वारा भूगोल की स्वतंत्र शाखा के रूप में जनसंख्या भूगोल को विकसित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूरी मिल गई। 4. इसी अधिवेशन में स्नातक स्तर के अध्ययन हेतु जनसंख्या भूगोल का पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया था।
6.	1954 ई.	पी. ई. जेम्स	1. एक पुस्तक का सम्पादन किया जिसका शीर्षक था – The Geographic Study of Population

			2. इस पुस्तक में इनके द्वारा जी. टी. ट्रिवार्था के कार्यों की समीक्षा की गई थी। 3. इसी वर्ष जी. टी. ट्रिवार्था एवं जैलिन्स्की द्वारा उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में जनसंख्या प्रतिरूप शीर्षक से शोध पत्र प्रकाशित हुआ
7.	1965 ई.	जॉन आई. क्लार्क	1. अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ के जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष बने। 2. जनसंख्या भूगोल नामक पुस्तक लिखी और प्रकाशित कराई। 3. इन्होंने जनसंख्या भूगोल के अध्ययन एवं विधि तंत्र पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया था।
8.	1966 ई.	जे. बी. गार्नियर	1. जनसंख्या पर एक पुस्तक वर्ष 1957 ई. में फ्रांसीसी भाषा में लिखी। 2. बाद में इस पुस्तक का अँग्रेजी भाषा में अनुवादित खण्ड प्रकाशित हुआ। 3. इनके द्वारा जनांकिकीय तथ्यों का अध्ययन पर्यावरणीय दृष्टिकोण से किया गया था।
9.	1966 ई.	डब्ल्यू. जैलिन्स्की	1. इनका मानना है कि जनसंख्या भूगोल किसी क्षेत्र की जनसंख्या का अध्ययन उसकी प्रकृति के अनुसार करता है। 2. जनसंख्या भूगोल पर उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक A Prologue to Population Geography थी। 3. इन्होंने जनसंख्या के तीन प्रमुख लक्षणों की पहचान की है, जो निम्न हैं – अ) जनसंख्या के जैविक लक्षण। ब) जनसंख्या के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक लक्षण। स) जनसंख्या के गत्यात्मक लक्षण।
10.	1970 ई.	जी. जे. डैम्को	1. इनके द्वारा जनसंख्या भूगोल पर एक प्रसिद्ध पुस्तक Population Geography & A Reader संपादित एवं प्रकाशित की गई थी। 2. इस पुस्तक में उस समय के कई भूगोलवेत्ताओं के लेख एवं शोध पत्र प्रकाशित हुए थे।
11.	1979 ई.	पीटर्स एवं लारकिन	1. इनके द्वारा संयुक्त रूप से जनसंख्या भूगोल पर एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका शीर्षक था Population Geography & Problems] Concepts and Prospect-
12.	1979 ई.	बुड्स	1. इनकी एक पुस्तक Population Analysis in Geography इसी वर्ष प्रकाशित हुई थी। 2. उन्होंने जनसंख्या की संरचना को समझने के लिए माडल एवं तंत्र के विकास को प्रोत्साहन दिया। 3. जनसंख्या भूगोल में होने वाले शोध के लिए यह पुस्तक बाद में बहुत सहयोगी साबित हुई है।

स्त्रोतः तिवारी (2023), जनसंख्या भूगोल.

2.4 सारांश

आपने इस इकाई में जनसंख्या भूगोल के उपागम एवं जनसंख्या भूगोल के विकास का अध्ययन किया है। आप समझ गए होगें कि जनसंख्या भूगोल के उपागम में किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है। इससे विश्व या किसी देश की जनसंख्या की गत्यात्मकता की विस्तृत जानकारी मिलती है तथा उसके विविध को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। वास्तव में किसी देश की जनसंख्या तथा वहाँ जनसंख्या भूगोल के उपागम का विश्लेषण उसकी भौगोलिक अवस्थिति, सरकारी नीतियों, सांस्कृतिक संगठन आदि के आधार पर होता है।

इस इकाई में ही जनसंख्या भूगोल के विकास का विस्तृत प्रस्तुत किया गया है। आपने देखा है कि जनसंख्या भूगोल, भूगोल की नवीनतम शाखा है। इसका अध्ययन भूगोल में बहुत बाद में शुरू हुआ। प्राचीन काल से जनसंख्या का अध्ययन विद्वानों द्वारा विविध स्वरूप प्रकट किया गया था। जनसंख्या और उनसे जुड़ी समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन माल्थस द्वारा 1798 ई. में सर्वप्रथम किया गया था। ब्रिटिश रायल सोसाइटी द्वारा भी जनसंख्या के अध्ययन को महत्त्व दिया गया है। अंत में अमेरिका में इसका उद्‌भव वर्ष 1953 ई. में हुआ और वहीं से इसका विस्तार विश्व के अन्य देशों में हुआ है। समय में होने वाले परिवर्तन के साथ ही जनसंख्या भूगोल के अध्ययन की प्रासंगिकता में वृद्धि हुई है, जिसने जनसंख्या भूगोल के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान। इस प्रकार आपने जनसंख्या भूगोल के उपागम एवं जनसंख्या भूगोल के विकास की विस्तृत तथा सारगर्भित अध्ययन किया है।

2.5 स्वमूल्यांकन प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

1. भूगोल के अध्ययन हेतु क्रमबद्ध उपागम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था।

   (क) हम्बोल्ट (ख) रिटर (ग) जी. टी. ट्रिवार्था (घ) जेलिन्सकी

2. जनसंख्या से जुड़ी समस्याओं का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था।

   (क) माल्थस (ख) कार्ल मार्क्स (ग) कान्ट (घ) रूसो

3. जनसंख्या भूगोल के अध्ययन हेतु कितने उपागम है।

   (क) 5 (ख) 4 (ग) 6 (घ) 7

4. जनसंख्या और उससे जुड़ी समस्याओं के अध्ययन हेतु वर्ष 1929 ई. में समाजवादी दृष्टिकोण का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था।

   (क) जेलिन्सकी (ख) जी. एस. गोसाल (ग) कार्ल मार्क्स (घ) माल्थस

5. जनसंख्या भूगोल का विकास किस देश में सर्वप्रथम हुआ था।

   (क) ब्रिटेन (ख) जर्मनी (ग) फ्रांस (घ) अमेरिका

2.6 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

Bogue] D- J-] 1969] Principles of Demography] John Wiley] N-Y-

Clarke] John I-] 1973] Population Geography] Pergaman Press] Oxford-

Crook] Nigel] 1997] Principles of Population and Development] Pergaman Press] N- Y-

Garmier] J- B-] 1970] Geography of Population] Longman] London-

Mamoria] C- B-] 1981] India's Population Problem] Kitab Mahal] New Delhi-

Premi] M- K-] 1991] India's Population] Heading Towards a Billion] B- R- Publishing Corporation-

Blassoff] M- and Srinivasan K-] 2001] Population Development Nexus in India : Challenges for the New Millennium] Tata McGraw Hill] New Delhi-

Woods] R-] 1979] Population Analysis in Geography] Longman] London-

Zelinsky] W-] 1966] A Prologue to Population Geography] Prentice Hall-

चन्दना, आर. सी., 2022, जनसंख्या भूगोल – संकल्पना, नियंत्रक व विश्व प्रारूप, कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

चन्दना, आर. सी., 2022, भारत : जनसंख्या (जनसंख्या भूगोल – भाग 2), कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

मौर्या, एस. डी., 2005, जनसंख्या भूगोल, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद.

ओझा, आर. पी., 1984, जनसंख्या भूगोल, प्रतिभा प्रकाशन.

हीरा लाल, 2000, जनसंख्या भूगोल के मूल तत्व, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली.

तिवारी, राम कुमार, 2023, जनसंख्या भूगोल, प्रवालिका पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद.

2.7 अभ्यास प्रश्न (सत्रांत परीक्षा की तैयारी)

1. जनसंख्या भूगोल के उपगमों की विस्तृत व्याख्या कीजिए?
2. जनसंख्या भूगोल के विकास का वर्णन कीजिए?
3. जनसंख्या भूगोल के विकास में अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं के योगदान का वर्णन कीजिए?

इकाई–3 जनसंख्या भूगोल और अन्य सामाजिक शास्त्र, भारत में जनसंख्या भूगोल

इकाई की रूपरेखा

3.0 प्रस्तावना

3.1 उद्देश्य

3.2 जनसंख्या भूगोल का अन्य विषयों से संबंध

3.3 भारत में जनसंख्या भूगोल

3.4 सारांश

3.5 स्वमूल्यांकन प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

3.6 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

3.7 अभ्यास प्रश्न (सत्रांत परीक्षा की तैयारी)

3.0 प्रस्तावना

जनसंख्या भूगोल, भूगोल की नवीनतम शाखा है। 20 में शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक इसका अध्ययन मानव भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता था। इसको अलग अध्ययन की शाखा के रूप में वर्ष 1953 ई. में जी. टी. ट्रिवार्था ने स्थापित किया। चूँकि समाज का निर्माण जनसंख्या अर्थात विभिन्न मानव समूहों से होता है अतः सभी सामाजिक विज्ञानों द्वारा जनसंख्या के विविध पक्षों का विश्लेषण अपने – अपने अध्ययन और आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। भूगोल में जनसंख्या के विविध पक्षों का अध्ययन स्थान एवं क्षेत्रीय वितरण के संदर्भ में किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय असमानता एवं विभिन्नता को प्रकट करना है। इस प्रकार देखा जाता है कि सभी सामाजिक विज्ञानों एवं जनसंख्या भूगोल के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है जिसका विश्लेषण करना जनसंख्या भूगोल के सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक हो जाता है।

3.1 उद्देश्य

अध्ययन की दृष्टिकोण से जनसंख्या भूगोल का विकास बहुत बाद में हुआ है। इससे पूर्व जनसंख्या का अध्ययन अन्य विषयों में उसकी उपयोगिता के अनुसार होता था। जनसंख्या से जुड़ी सभी विशेषताओं, उपगमों, गत्यात्मकता, वितरण आदि अब जनसंख्या भूगोल का विषय क्षेत्र हो गया है, फिर अन्य विषयों से यह घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। इस अध्याय के प्रमुख उद्देश्य निम्न है –

1. जनसंख्या भूगोल का अन्य विषयों से संबंध का अध्ययन करना।
2. भारत में जनसंख्या भूगोल के विकास का विश्लेषण करना

3.2 जनसंख्या भूगोल का अन्य विषयों से संबंध

20वीं शताब्दी के मध्य तक मानव भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत ही जनसंख्या का अध्ययन विशेष रूप से किया जाता था, तब तक जनसंख्या भूगोल नामक अलग से कोई विषय अस्तित्व में नहीं था। वर्ष 1953 ई. में पहली बार अमेरिका के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जी. टी. ट्रिवार्था ने जनसंख्या भूगोल की रूपरेखा प्रस्तुत किया। उसके

पश्चात जनसंख्या भूगोल को भूगोल की एक अलग शाखा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। किसी भी समाज का निर्माण जनसंख्या अथवा मानव समूहों से होता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव समाज का अधिक से अधिक कल्याण करना होता है। भूगोल सहित सभी सामाजिक विज्ञान किसी न किसी न किसी रूप में समाज का अध्ययन करते है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्पष्ट होता है कि सभी सामाजिक विज्ञान जनसंख्या के विविध पक्षों का अध्ययन अपने – अपने विषय के उद्देश्य के अनुरूप करते है। सामाजिक विज्ञान में अंतर्गत जनांकिकी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं मानव शास्त्र आदि आते हैं, जो जनसंख्या और उसके विभिन्न तत्वों – घटकों का अध्ययन अपने – अपने दृष्टिकोण से करते हैं। भूगोल में जनसंख्या के विविध पक्षों का अध्ययन क्षेत्रीय वितरण, स्थान एवं परिवर्तनीयता के संदर्भ में किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय भिन्नता को प्रकट करना होता है। शिवदास मौर्य अपनी पुस्तक जनसंख्या भूगोल में लिखते हैं कि सभी सामाजिक विज्ञानों से जनसंख्या भूगोल का घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इस संबंध का ज्ञान जनसंख्या भूगोल के सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होता है। जनसंख्या भूगोल एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों के मध्य संबंधों को निम्नलिखित प्रकार से वर्णित किया गया है –

3.2.1 जनसंख्या भूगोल एवं जनांकिकी

जनांकिकी को परिभाषित करते हुए पीटर आर. काक्स लिखते हैं कि जनांकिकी मानव संख्या का सांख्यिकीय विश्लेषण है। यह मुख्यतःकिसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के विकास, आकार एवं वृद्धि – ह्रास का अध्ययन है। यह जन्म – मरण के अनुपात के साथ – साथ प्रजननता, मृत्यु एवं विवाह जैसे अवयवों के कारणों एवं परिणामों की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। जनांकिकी में जनसंख्या की गतिशीलता एवं उससे संबंधित कारकों का विश्लेषण होता है जबकि जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या की गतिशीलता एक अध्याय के रूप में होती है। जहाँ जनांकिकी जनसंख्या का अध्ययन एक वैज्ञानिक की तरह करता है वहीं भूगोल में इसका अध्ययन समाज वैज्ञानिक के रूप में होता है जो की जनांकिकी सिद्धांतों पर आधारित होता है। अध्ययन की दोनों शाखों में समानता यह है कि दोनों जनसंख्या का विश्लेषण एक ही समान करते हैं परंतु भूगोल अपने अध्ययन में स्थानिक, कालिक भिन्नता के साथ – साथ प्रकृति एवं मानव के अंतःसंबंधों का भी अध्ययन करता है। जनांकिकी मुख्य रूप से संख्या और सांख्यिकीय विधियों तक ही अपने अध्ययन को सीमित रखता है जबकि जनसंख्या भूगोल जनसंख्या के वितरण की क्षेत्रीय एवं कालिक विभिन्नता के अंतःसंबंधों के अध्ययन पर बल देता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जनांकिकी एवं जनसंख्या भूगोल में गहरा संबंध होता है परंतु जनसंख्या भूगोल एक विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करता है।

प्राचीन काल से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि तक भूगोल की प्रकृति व्याख्यात्मक प्रवृत्ति की थी। इसमें किसी भी प्रकारा के सांख्यिकी आँकड़ों का प्रयोग नहीं किया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1950 – 60 के दशक में भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का प्रयोग होने लगा। अब इसमें तथ्यों, सिद्धांतों एवं संकल्पनाओं की व्याख्या हेतु वर्णनात्मक विधि के साथ ही सांख्यिकी का भी प्रयोग होंने लगा। जनसंख्या भूगोल में इसकी उपयोगिता सर्वाधिक है क्योंकि इस विषय की मूल आत्मा ही आंकड़ों के विश्लेषण पर केन्द्रित है। जनसंख्या भूगोल मुख्य रूप से जनांकिकी तत्व के क्षेत्रीय वितरण का अध्ययन करता है और जनसंख्या के मात्रात्मक अध्ययन के लिए जनांकिकी आधारित विश्लेषण की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार जनांकिकी में जनसंख्या संबंधित आँकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकी विधियों के आधार पर किया जाता है, इस प्रकार भूगोल में भी क्षेत्रीय विभिन्नता की व्याख्या के लिए आँकड़ों तथा मात्रात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार दोनों विषयों के अध्ययन विधि एवं तकनीकी में लगभग समानता पाई जाती है, परंतु इसमें कुछ गुणात्मक अंतर भी दर्ज किए जाते हैं। जैसे एक जनांकिकीवेत्ता जनसंख्या के बौद्धिक, भौतिक, चारित्रिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के मध्य पाए जाने वाले संबंधों के विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसके लिए गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार की विधियां समान रूप से उपयोगी होती है। इन विधियो का प्रयोग करके जनसंख्या और उसके घटकों में होने वाले परिवर्तनीयता को आसानी से समझा जा सकता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जब तक तथ्यों के विश्लेषण तार्किक एवं सार्थक तथ्यों के आधार पर नहीं होगा तब तक अध्ययन की उपयोगिता अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाती है। ऐसी स्थिति में मात्रात्मक विधि का प्रयोग करते हुए तथ्यों को सारणी के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ ही उन तथ्यों की विस्तृत व्याख्या करके विविधताओं एवं भिन्नताओं को वक्र, आरेख, सरल दण्ड आरेख, चक्र आरेख, आयात चित्र, वर्ग चित्र इत्यादि माध्यमों से व्यक्त किया जाता है ताकि विषय की मूल विषय वस्तु को स्पष्टता के साथ समझा जा सके।

जनांकिकी एवं जनसंख्या भूगोल में मुख्य अंतर यह है कि जनांकिकी मुख्यतः संख्या और सांख्यिकी विधियों पर केंद्रित होती है जबकि जनसंख्या भूगोल जनसंख्या के लक्षणों को क्षेत्र एवं क्षेत्रीय विभिन्नता के संदर्भ में प्रकट करने का प्रयास करता है। जनांकिकीय तथ्यों का क्षेत्र के संदर्भ में विश्लेषण जनसंख्या भूगोल की मूल विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। इसीलिए जनसंख्या भूगोल के विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह जनांकिकीय विधियों का अनुसरण अपने जनसंख्या भूगोल के तत्वों, सिद्धांतों आदि को समझने के लिए करें। इस प्रकार देखा जाता है कि जनांकिकी और जनसंख्या भूगोल एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं।

3.2.2 जनसंख्या भूगोल एवं इतिहास

जनसंख्या भूगोल एवं इतिहास दोनों जनसंख्या का अध्ययन अलग – अलग विधियों एवं दृष्टिकोण से करते हैं। इतिहास जहाँ जनसंख्या की कहानी है वहीं जनसंख्या भूगोल जनसंख्या के तत्वों का अध्ययन है इसका बृहद विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है कि इतिहास में समाज के व्यक्तियों का विश्लेषण होता है जबकि जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या के तत्वों जैसे जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, प्रवास, वितरण, संयोजन एवं नगरीकरण आदि की वैज्ञानिक व्याख्या होती है। सर्वविदित है कि इतिहास के अध्ययन का संबंध काल से होता है। इतिहास में समाज या जनसंख्या का अध्ययन समय सापेक्ष होता है जहाँ घटनाक्रम के अनुसार व्याख्या मिलती है जबकि जनसंख्या भूगोल के तत्वों की व्याख्या काल एवं स्थान के संबंध में होती है। ऐतिहासिक अध्ययन में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों का विश्लेषण समय के अनुसार की जाती है ठीक उसी प्रकार जनसंख्या भूगोल में इसकी व्याख्या समय एवं काल के सापेक्ष होती है। इस प्रकार कहा जाता है कि इतिहास एवं जनसंख्या भूगोल में घनिष्ठ संबंध देखा जाता है।

भूगोल और इतिहास दोनों विषय जनसंख्या का विश्लेषण अलग – अलग विधियों से करते है। दोनों का मूल अंतर इस बात से स्पष्ट होता है कि यदि इतिहास जनसंख्या की व्याख्या है तो जनसंख्या भूगोल जनसंख्या का विवेचन है। एक इतिहासकर जनसंख्या का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि अथवा काल के सन्दर्भ में और घटना क्रम के अनुसार करता है। इतिहास में मनुष्य के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक आदि लक्षणों का अध्ययन का पूर्व के समय के सन्दर्भ में किया जाता है। जनसंख्या भूगोल में इन्हीं तथ्यों का अध्ययन स्थान या देश के सन्दर्भ में किया जाता है। किसी भूखण्ड या देश की जनसंख्या की विकास या वृद्धि की प्रवृत्ति का अध्ययन दोनों ही विषयों के लिए समान प्रकार से महत्त्वपूर्ण है। इस प्रकार जनसंख्या भूगोल इतिहास से भी संबन्धित है।

3.2.3 जनसंख्या भूगोल एवं राजनीति विज्ञान

राजनीति विज्ञान में किसी क्षेत्र विशेष के मानव समुदाय की राजनीतिक गतिविधियों, संगठनों एवं दशाओं का क्रमबद्ध विश्लेषण किया जाता है। राजनीति का संबंध जनता द्वारा शक्ति प्राप्त करने एवं किसी स्थान विशेष पर मानव कल्याण करने की कला है। राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु राजनीतिक परिस्थितियों पर जनसंख्या के अनेक तत्वों की व्याख्या करना है। जनसंख्या भूगोल में भी जनसंख्या के विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक घटकों पर तत्कालीन राजनीति के प्रभाव का अध्ययन है। जहाँ राजनीति विज्ञान जनसंख्या का अध्ययन राजनीतिक दृष्टिकोण से करता है वहीं जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या का अध्ययन स्थान, काल एवं प्रकृति के साथ उनके अंतरसंबंध का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान एवं जनसंख्या भूगोल में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है।

राजनीति विज्ञान किसी देश या प्रदेश में ऐतिहासिक कालक्रम में राजनीतिक दशाओं, संगठनों के साथ गतिविधियों का क्रमबद्ध उल्लेख करता है। जनसंख्या के सभी घटकों एवं लक्षणों पर राजनीतिक परिस्थितियों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान जनसंख्या का अध्ययन राजनैतिक दृष्टिकोण से करता है। हीरालाल अपनी पुस्तक जनसंख्या भूगोल में लिखते हैं कि जनसंख्या के विभिन्न लक्षणों जैसे जनसंख्या की वृद्धि, वितरण, प्रवास, जनसंख्या नीति एवं कार्यक्रम आदि के विश्लेषण एवं क्रियान्वयन में किसी देश या प्रदेश की राजनीतिक दशाओं की भूमिका अधिक होती है। इस प्रकार जनसंख्या भूगोल एवं राजनीति विज्ञान के संबंध आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं।

3.2.4 जनसंख्या भूगोल एवं समाजशास्त्र

समाजशास्त्र की विषय वस्तु में मानव समाज के साथ – साथ मनुष्य जीवन की विविध पहलू शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत सामाजिक – राजनीतिक संरचना, सामाजिक वर्ग एवं स्थानीय संगठनों आदि के क्रियाकलापों का विश्लेषण सामाजिक दृष्टिकोण से किया जाता है। जहाँ जनसंख्या भूगोल के एक अध्याय में जनसंख्या की संरचना के अंतर्गत जाति, धर्म, भाषा, प्रजाति एवं विवाह का संश्लेषित अध्ययन किया जाता है वहीं ये सभी संदर्भ समाजशास्त्र के केंद्रीय अध्ययन का विषय वस्तु है। भूगोल में इन तथ्यों का अध्ययन क्षेत्रीय विषमताओं एवं प्रतिरूपों के संदर्भ में किया जाता है। जनसंख्या की क्रियात्मकता का अध्ययन दोनों विषय करते हैं, अतः कहा जा सकता है कि दोनों विषय एक – दूसरे से संबंधित हैं।

सामाजिक विज्ञान के अभिन्न अंग समाजशास्त्र के साथ ही जनसंख्या भूगोल दोनों ही जनसंख्या का अध्ययन करते हैं परंतु उनके दृष्टिकोण में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। समाजशास्त्र में मानव समाज का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है। समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना, सामाजिक वर्गों एवं सामाजिक संगठनों आदि के अध्ययन को प्रधानता दी जाती है क्योंकि इनके केंद्र में मुख्य रूप से जनसंख्या का अध्ययन शामिल होता है। समाजशास्त्र के गुणात्मक अध्ययन का महत्त्व अधिक होता है। इसके अंतर्गत प्रजाति, जाति, परिवार, भाषा, धर्म, सामाजिक संबंध एवं राष्ट्रीयता के सभी पहलुओं का अध्ययन जनसंख्या के संदर्भ में होता है। समाजशास्त्र में क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर अलग – अलग क्षेत्रीय एवं सामाजिक प्रतिरूप देखें जाते है। जिनका अध्ययन समाजशास्त्र एवं जनसंख्या भूगोल में समान रूप से किया जाता है। इस प्रकार यह कहा जाता है कि समाजशास्त्र एवं जनसंख्या भूगोल एक दूसरे के सहयोगी और पूरक विषय है।

3.2.5 जनसंख्या भूगोल एवं अर्थशास्त्र

अर्थशास्त्र के अध्ययन की केंद्रीय विषय वस्तु में जनसंख्या के आर्थिक क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है। अर्थशास्त्रियों द्वारा किए गए अध्ययन में जनसंख्या की जन्म दर, मृत्यु दर, वृद्धि, समाज की आर्थिक एवं सामाजिक संरचना, श्रम शक्ति, आय एवं जीवन स्तर का अध्ययन किया जाता है। उनके अध्ययन का मुख्य आकर्षण आर्थिक संदर्भ में होता है। जनसंख्या भूगोल में इन आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण काल एवं स्थान के संदर्भ में किया जाता है। अर्थशास्त्र जनसंख्या के अनेक पक्षों पर आर्थिक तत्वों के प्रभाव की व्याख्या करता है। जनसंख्या भूगोल में प्रयुक्त होने वाले अधिकांश सिद्धांत अर्थशास्त्र से संबंधित होते हैं और उनके मूल स्रोत अर्थशास्त्र ही होता है। इस प्रकार जनसंख्या भूगोल घनिष्ठ रूप से अर्थशास्त्र से संबंधित है।

जनसंख्या भूगोल एवं अर्थशास्त्र में भी आपसी सहसंबंध पाया जाता है। दोनों के केंद्रीय विषय वस्तु में जनसंख्या का महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक अर्थशास्त्री जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि, प्रवास, आर्थिक एवं व्यावसायिक संरचना, आय, श्रम शक्ति, जीवन स्तर एवं रोजगार के विभिन्न अवसरों का अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करता है। इसके साथ ही एक भूगोलवेत्ता इन तथ्यों का किसी क्षेत्र विशेष अथवा स्थान विशेष की भौगोलिक परिस्थितियों के संदर्भ में व्याख्या करता है। अर्थशास्त्र में जनसंख्या के विभिन्न आर्थिक तत्वों के प्रभाव को स्पष्ट करने का प्रभाव किया जाता है जबकि जनसंख्या भूगोल में पर्यावरण प्रभावों के साथ – साथ मानव की क्रियाशीलता को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। इस दृष्टिकोण से क्षेत्रीय प्रतिरूप स्पष्ट होता है साथ ही उसका अध्ययन का दृष्टिकोण भी प्रकट होता है। जहाँ तक जनसंख्या भूगोल का प्रश्न है, उसके अधिकांश संदर्भ, सिद्धांतों एवं अध्ययन विधियों को अर्थशास्त्र से ही लिया गया है क्योंकि इन सिद्धांतों संकल्पनाओं विधियों एवं तथ्यों का मौलिक स्रोत अर्थशास्त्र ही होता है। इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली जनसंख्या की आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण और उनके आपसी अंतःसंबंध की व्याख्या अर्थशास्त्र एवं जनसंख्या भूगोल दोनों में समान रूप से किया जाता है। अंतर सिर्फ यही होता है कि जहाँ अर्थशास्त्र में आर्थिक पशुओं पर अधिक जोर दिया जाता है, वहीं जनसंख्या भूगोल में किसी स्थान विशेष की क्षेत्रीयता, स्थानीयता एवं जनसंख्या की कार्यशीलता संबंधित बातों का विशेष ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार देखा जाता है कि अर्थशास्त्र एवं जनसंख्या भूगोल बहुत घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संबंधित है।

3.2.6 जनसंख्या भूगोल एवं मानव शास्त्र

मानव विज्ञान की विषय वस्तु में मानव प्रजाति का विकास, उसका शारीरिक गठन एवं प्रजातियों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। मानव वैज्ञानिक इस बात का अध्ययन करना चाहते हैं कि मानव प्रजाति का

उनके क्रियाकलापों का उनकी शारीरिक संरचना एवं उनके विकास का संबंध किस प्रकार पर्यावरण से जुड़ा है। जनसंख्या भूगोल में भी इन तत्वों की व्याख्या मानव शास्त्र की विधियों, सिद्धांतों एवं सामान्य नियमों के आधार पर की जाती है। जनसंख्या भूगोल में इन संदर्भों की एक सामान्य व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। इस प्रकार जनसंख्या भूगोल एवं मानव शास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं।

एक मानव वैज्ञानिक जनसंख्या के घटक मानव के अध्ययन के लिए जो दृष्टिकोण अपनाते हैं वह सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों से थोड़ा अलग होता है। मानव शास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति के विकास, शारीरिक गठन, संरचना, प्रजाति वर्गीकरण तथा उसके शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। वह इस बात को खोजने का प्रयास करते हैं कि मानव जाति के विकास में स्थानीय पर्यावरण ने किस प्रकार योगदान दिया है। जनसंख्या भूगोल में मानव प्रजातियां एवं अन्य मानव समूह के शारीरिक लक्षणों की व्याख्या मानव के क्रियाकलापों से जोड़कर देखा जाता है। मानव शास्त्र जनसंख्या के सामान्य सिद्धांतों, नियमों एवं तकनीकि की व्याख्या करता है। साथ ही वह इस बात को खोजने का प्रयास करता है कि वर्तमान समय में पाई जाने वाली मानव प्रजाति किस प्रकार प्राचीन काल की मानव प्रजाति से भिन्न है। इस प्रकार समय में होने वाले परिवर्तन के साथ उसकी सोच, क्रियात्मकता एवं कार्यात्मकता में परिवर्तन हुआ है जो समाज विज्ञान के अन्य विषयों के साथ मानव शास्त्र एवं जनसंख्या अध्ययन का केंद्रीय विषय वस्तु है। इस प्रकार जनसंख्या भूगोल एवं मानव शास्त्र का एक – दूसरे के ज्यादा समीप होना इस बात का बोधक है कि दोनों विषय एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जुड़े हुए हैं।

3.3 भारत में जनसंख्या भूगोल

जनसंख्या भूगोल का उद्भव एवं प्रसार पाश्चात्य देशों में पहले हुआ। वहाँ से इसका विसरण विश्व के अनेक देशों में हुआ । भारत में भूगोल का अध्ययन एवं अध्यापन तो पहले से ही शुरू हो चुका था परंतु वैज्ञानिक तरीके से एक स्वतंत्र शाखा के रूप में जनसंख्या भूगोल 1960 के दशक में पल्लवित हुआ। भारत में जनसंख्या भूगोल को प्रारंभ करने का श्रेय गुरुदेव सिंह घोषाल को जाता है। गुरदेव सिंह घोषाल ने विस्कान्सिन विश्वविद्यालय के आचार्य जी. टी. ट्रिवार्था के निर्देशन में वर्ष 1956 ई. में अपना शोध प्रबंध पूर्ण किया। उनके शोध प्रबंध का विषय था 'A Geography Analysis of India's Population' अर्थात भारत की जनसंख्या का भौगोलिक विश्लेषण। घोषाल पंजाब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर कार्यरत थे। उनके प्रयास के फलस्वरुप ही पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में वर्ष 1960 ई. में स्नातकोत्तर स्तर पर जनसंख्या भूगोल का पठन – पाठन शुरू हुआ। इस दृष्टिकोण से जी. एस. घोषाल भारत में जनसंख्या भूगोल के पिता कहलाते हैं।

जनसंख्या भूगोल की शाखा स्थापित करने के पश्चात घोषाल ने भारत में जनसंख्या पर शोध को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने अपने शोध निर्देशन में गोपाल कृष्ण को 1968 ई. में, आर. सी. चांदना को 1969 ई. में एवं एस. मेहता को 1970 ई. में शोध की उपाधि प्रदान कराई। इन तीनों व्यक्तियों ने अलग – अलग क्षेत्र की जनसंख्या से जुड़ी विशेषताओं पर अपने शोध प्रबंध प्रस्तुत किए। गोपाल कृष्ण के शोध का शीर्षक था 'Changes in the Demographic Characters in the Punjab Border Districts of Amritsar and Gurudaspur'] आर. सी. चांदना का शीर्षक था 'Changes in Demographic Characters of Rohatak and Gurugaon District' तथा एस. मेहता का शोध प्रबंध Some Aspects of Changes in Demographic Characters of Bist Doab' शीर्षक से जमा हुआ। उन्होंने जनसंख्या भूगोल के सभी पहलुओं जैसे जनसंख्या वृद्धि, संगठन, जन्म दर एवं मृत्यु दर, वितरण, प्रवास और नगरीकरण की प्रवृत्तियों से जुड़े मुद्दों का क्रमबद्ध विश्लेषण किया। इनसे जुड़े शोध पत्रों को देश – विदेश के भौगोलिक पत्रिकाओं में भी प्रकाशित कराया।

आर. सी. चांदना एवं सिद्धू ने मिलकर वर्ष 1980 ई. में पंजाब विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम हेतु एक पुस्तक लिखी जिसका अंग्रेजी संस्करण 1986 ई. में एवं हिंदी संस्करण 1987 ई. में प्रकाशित हुआ। पंजाब विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के भारतीय जनसंख्या भूगोलवेत्ता संघ ने 'Population Geography' नामक एक पत्रिका भी शुरू कराई जो आज भी प्रकाशित होती है।

कालांतर में अनेक विद्वानों ने जनसंख्या से संबंधित लेखो, शोध पत्रों, निबंधों एवं शोध प्रबंधक द्वारा जनसंख्या भूगोल के विकास का मार्ग को प्रशस्त किया। इसमें से प्रमुख हैं ए. बी. मुखर्जी, बी. पी. राव, इनायत अहमद, एस. एल. कायस्थ, ए. एस. जौहरी, अमृतलाल चंद्रशेखर, बी. एन. सिंह, आशीष बोस, बी. के. राय, पी. वी.

देसाई, जसवीर सिंह, एम. ई. हार्वे, एस. एम. भारद्वाज, राजबाला एवं माया बैनर्जी। इसके अतिरिक्त ओम प्रकाश (1973), सांत्वना घोष (1973), दीनानाथ (1981) एवं रामदुलारे (1982) ने अपने शोध प्रबंधों में जनसंख्या भूगोल को विशेष महत्व प्रदान किया। कुछ विद्वानों ने जनसंख्या और उसके अधिवासों की अंतःक्रिया, उनके विकास, कार्यकाल जैसे विषयों पर भी शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। इन सभी लेखों एवं शोधों ने भारत में जनसंख्या भूगोल के विकास में मील के पत्थर का काम किया है।

भारत के जनगणना विभाग ने भी यहाँ जनसंख्या भूगोल के विकास में विशेष योगदान दिया है। यह विभाग अपने संगणकों के द्वारा संपूर्ण देश से जनसंख्या संबंधित आँकड़ों का संग्रह करता है। उसका संश्लेषण एवं विश्लेषण करने के पश्चात विभिन्न विभागों द्वारा प्रकाशन करता है। भारत की प्रथम जनगणना 1872 ई. से 2011 ई. तक के सभी आँकड़े इस विभाग के पास उपलब्ध हैं, जिसके कारण लेखकों एवं शोधकर्ताओं को भारत की जनसंख्या की विशेषता, गतिशीलता एवं परिवर्तनशीलता से जुड़ी समस्त जानकारी उपलब्ध हो जाती है। यह विभाग जनसंख्या के विभिन्न लक्षणों से संबंधित जानकारी अनेक मापकों पर ग्राम, खण्ड, तहसील, नगर, जिला, राज्य एवं देश के संदर्भ में प्रकाशित करता है। इस प्रकार अनेकों शोधकर्ताओं ने देश के अलग – अलग हिस्सों से जुड़ी जानकारी एकत्र करके जनसंख्या भूगोल में शोध प्रबंध प्रस्तुत किया है।

सारणी 3.1 भारत में लिखी गई जनसंख्या भूगोल की प्रमुख पुस्तकें

क्र. सं.	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशन वर्ष	प्रकाशन का नाम
1.	Principles of Population Geography	A- A- Bhande and Tara Kanitkar	1978 ई.	Himalaya Publishing House] Mumbai
2.	Introduction to Population Geography	R- C- Chandana	1980 ई.	Kalyani Publishers] New Delhi
3.	Atlas to Scheduled Cast Population	R- C- Chandana	1985 ई.	Kalyani Publishers] New Delhi
4.	A Geography of Population : Concept] Determinants and Patterns	R- C- Chandana	1986 ई.	Kalyani Publishers] New Delhi
5.	Population	R- C- Chandana	1988 ई.	Kalyani Publishers] New Delhi
6.	Spatial Diamensions of Scheduled Cast in India	R- C- Chandana	1989 ई.	Kalyani Publishers] New Delhi
7.	An Introduction to Study of Population	B- D- Mishra	1982 ई.	South Asian Publishers Pvt- Ltd- New Delhi
8.	Fundamentals of Population Geography	B- N- Ghosh	1985 ई.	Sterling Pub- House] Delhi
9.	Geography of Population	S- L- Kayasth	1988 ई.	Rawat Pub-] Jaipur
10.	Population Geography	M- Izhar Hassan	1998 ई.	Rawat Pub-] Jaipur
11.	जनसंख्या भूगोल	हीरालाल	1986 ई.	वसुंधरा प्रकाशन, गोरखपुर

12.	जनसंख्या भूगोल	आर. पी. ओझा	1987 ई.	प्रतिभा प्रकाशन
13.	जनसंख्या भूगोल	बी. पी. पांडा	1988 ई.	मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
14.	जनसंख्या भूगोल	आर. डी. त्रिपाठी	1990 ई.	वसुंधरा प्रकाशन, गोरखपुर
15.	जनसंख्या भूगोल	के. के. दुबे एवं एम. बी. सिंह	1994 ई.	रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर
16.	भारत का जनसंख्या भूगोल	विजय कुमार तिवारी	1997 ई.	हिमालया पब्लिशिंग हाउस, मुंबई
17.	जनसंख्या भूगोल	एस. डी. मौर्य	2005 ई.	शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद
18.	भारत का जनसंख्या भूगोल	अनुपम पाण्डेय	2007 ई.	डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
19.	जनसंख्या भूगोल	राम कुमार तिवारी	2013 ई.	प्रवालिका पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद

स्त्रोत : तिवारी, (2023), जनसंख्या भूगोल.

यद्यपि भारत में जनसंख्या भूगोल का विकास बाद में हुआ परंतु वर्तमान में उसका स्तर पाश्चात्य देशों के समक्ष हो गया है। जनसंख्या के जिन लक्षणों के आँकड़े जनसंख्या रिपोर्ट में उपलब्ध है, उन पर यहाँ अधिक काम हुआ है, जबकि जनगणना विभाग के पास जो आँकड़े नहीं है, उन पर काम कम हुआ है। यही कारण है कि जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात और नगरीकरण जैसे विषयों पर अधिक काम हुआ है। जनसंख्या की गत्यात्मकता अर्थात जन्मता, मर्त्यता एवं प्रवास जैसे विषयों पर लेखकों एवं शोधकर्ताओं ने कम ध्यान दिया है।

3.4 सारांश

आपने इस इकाई में जनसंख्या भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध एवं भारत में जनसंख्या भूगोल के विकास का अध्ययन किया है। आप समझ गए होगें कि जनसंख्या भूगोल का अन्य विषयों से घनिष्ट संबंध है। इससे अन्य विषयों जनसंख्या के अध्ययन और तकनीकियों की विस्तृत जानकारी मिलती है तथा जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या के विविध पक्षों के अध्ययन को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। वास्तव में किसी देश की जनसंख्या तथा वहाँ का सबसे बड़ा संसाधन होती है जो उसकी भौगोलिक अवस्थिति, सरकारी नीतियों, सांस्कृतिक संगठन आदि के आधार पर होता है।

इस इकाई में ही भारत जनसंख्या भूगोल के विकास का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। आपने देखा है कि जनसंख्या भूगोल, भूगोल की नवीनतम शाखा है। इसका अध्ययन भूगोल में बहुत बाद में प्रारम्भ हुआ। अमेरिका में इसका उद्‌भव वर्ष 1953 ई. में हुआ और वहीं से इसका विस्तार विश्व के अन्य देशों में हुआ है। इसके पश्चात भारत से अनेक लोग जनसंख्या भूगोल का अध्ययन के लिए अमेरिका प्रवास किए। उन्हीं में से एक थे, जी. एस. घोषाल जिन्होंने ट्रिवार्था के निर्देशन में अपना शोध प्रबंध पूर्ण किया। अंत में भारत आने के पश्चात 1960 के दशक में उन्होंने भारत में जनसंख्या भूगोल की नीव रखी। समय में होने वाले परिवर्तन के साथ ही जनसंख्या भूगोल के अध्ययन की प्रासंगिकता में वृद्धि हुई है, जिसने भारत में जनसंख्या भूगोल के विकास एवं प्रसार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार आपने जनसंख्या भूगोल के भारत में विकास का विस्तृत तथा सारगर्भित अध्ययन किया है।

3.5 स्वमूल्यांकन प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

1. भारत में जनसंख्या भूगोल पिता किसे कहा जाता है।

(क) आर. एल. सिंह (ख) इनायत अहमद (ग) ए. एस. जौहरी (घ) जी. एस. घोषाल

2. भारत में जनसंख्या भूगोल का विकास किस दशक में शुरू हुआ था।

(क) 1930 (ख) 1950 (ग) 1960 (घ) 1980

3. भारत में जनसंख्या भूगोल का विकास किस विश्वविद्यालय से प्रारम्भ हुआ था।

(क) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय , वाराणसी,

(ख) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय , नई दिल्ली,

(ग) पंजाब विश्वविद्यालय , चंडीगढ़,

(घ) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय , अलीगढ़,

4. जनसंख्या और उससे जुड़ी समस्याओं के अध्ययन हेतु वर्ष 1929 ई. में समाजवादी दृष्टिकोण का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था।

(क) जेलिन्सकी (ख) जी. एस. गोसाल (ग) कार्ल मार्क्स (घ) माल्थस

5. जनसंख्या भूगोल का विकास किस देश में सर्वप्रथम हुआ था।

(क) ब्रिटेन (ख) जर्मनी (ग) फ्रांस (घ) अमेरिका

3.6 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

Bogue] D- J-] 1969] Principles of Demography] John Wiley] N-Y-

Clarke] John I-] 1973] Population Geography] Pergaman Press] Oxford-

Crook] Nigel] 1997] Principles of Population and Development] Pergaman Press] N- Y-

Garmier] J- B-] 1970] Geography of Population] Longman] London-

Mamoria] C- B-] 1981] India's Population Problem] Kitab Mahal] New Delhi-

Premi] M- K-] 1991] India's Population] Heading Towards a Billion] B- R- Publishing Corporation-

Blassoff] M- and Srinivasan K-] 2001] Population Development Nexus in India : Challenges for the New Millennium] Tata McGraw Hill] New Delhi-

Woods] R-] 1979] Population Analysis in Geography] Longman] London-

Zelinsky] W-] 1966] A Prologue to Population Geography] Prentice Hall-

चन्दना, आर. सी., 2022, जनसंख्या भूगोल – संकल्पना, नियंत्रक व विश्व प्रारूप, कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

चन्दना, आर. सी., 2022, भारत : जनसंख्या (जनसंख्या भूगोल – भाग 2), कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

मौर्या, एस. डी., 2005, जनसंख्या भूगोल, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद.

ओझा, आर. पी., 1984, जनसंख्या भूगोल, प्रतिभा प्रकाशन.

हीरा लाल, 2000, जनसंख्या भूगोल के मूल तत्व, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली.

तिवारी, राम कुमार, 2023, जनसंख्या भूगोल, प्रवालिका पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद.

3.7 अभ्यास प्रश्न (सत्रांत परीक्षा की तैयारी)

1. जनसंख्या भूगोल के अन्य विषयों से संबंध की व्याख्या कीजिए?
2. जनसंख्या भूगोल के विकास में अन्य विषयों योगदान का वर्णन कीजिए?
3. भारत में जनसंख्या भूगोल के विकास का समीक्षात्मक विश्लेषण कीजिए?

इकाई–4 जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक

इकाई की रूपरेखा

4.0 प्रस्तावना

4.1 उद्देश्य

4.2 जनसंख्या का वैश्विक वितरण

4.3 जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक

4.4 प्राकृतिक कारक

4.5 मानवीय कारक

4.6 सारांश

4.7 स्वमूल्यांकन प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

4.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

4.9 अभ्यास प्रश्न (सत्रांत परीक्षा की तैयारी)

4.0 प्रस्तावना

पृथ्वी के धरातल पर जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान है। कहीं पर इसका संकेंद्रण अधिक है तो कहीं अल्प है। इसके वितरण एवं घनत्व में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक अनेकों परिवर्तन हुए हैं। इस परिवर्तन की गति समय, काल, परिस्थिति, स्थान एवं प्रदेश के अनुसार भिन्न – भिन्न रही है। प्रकृति ने भी इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कुछ स्थानों के उच्चावच एवं संसाधनों दृष्टिकोण समृद्ध बनाया है। इसके कारण वहाँ विकास के अवसंरचनाओं का निर्माण आसान हो जाता है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर मानव के जीवन यापन के संसाधन सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। वे स्थान मानव के निवास हेतु प्रयुक्त होते हैं तो वहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण एवं घनत्व अधिक पाया जाता है। इसके विपरीत जिन स्थानों पर भौगोलिक परिस्थितियां प्रतिकूल होती है, जैसे विषम उच्चावच, पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र, सघन वनीय भाग, दलदलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र इत्यादि जगहों पर जनसंख्या न्यून पाई जाती है। कभी – कभी ऐसे प्रदेश अति न्यून जनसंख्या या जनरिक्त प्रदेश रूप में भी पाए जाते हैं। इन दोनों परिस्थितियों के मध्य कुछ क्षेत्र ऐसे भी पाए जाते है जो न तो मानव निवास हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होने है और न ही अनुपयुक्त। ये स्थान अत्यधिक जनसंख्या के पोषण हेतु सक्षम तो नहीं होते हैं परंतु ऐसे भी नहीं होते है कि कोई जनसंख्या निवास नहीं कर सके। ऐसी स्थिति में यहाँ मध्यम जनसंख्या का वितरण पाया जाता है।

4.1 उद्देश्य

मनुष्य धरातल का सबसे सक्रिय प्राणी है, जिसने अपनी क्रियाशीयता के आधार पर महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना है।

4.2 जनसंख्या का वैश्विक वितरण

जनसंख्या भूगोल के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है पृथ्वी के धरातल पर वितरित जनसंख्या के स्थानिक वितरण प्रतिरूप का अध्ययन करना। अपने अध्ययन के दौरान ट्रिवार्था एवं फ्रिंच ने यह मत व्यक्त किया है कि जनसंख्या वह केंद्रीय बिंदु है जिसके कारण भूगोलवेत्ता पर्यावरण के अन्य तत्वों एवं तंत्रों का अध्ययन करता है। इसका अर्थ एवं महत्व मानव कल्याण में ही निहित होता है। पृथ्वी के किसी भूभाग या उसके संपूर्ण क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले व्यक्तियों के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य किसी निश्चित भूभाग के क्षेत्रफल तथा वहाँ निवास करने वाली जनसंख्या के अनुपात से है। जनसंख्या घनत्व यह व्यक्त करती है कि पृथ्वी के धरातल के किस भाग में जनसंख्या का बसाव अधिक है तथा कहां पर वह कम संख्या में बसी हुई है, कहां पर उसका बसाव बिखरा हुआ पाया जाता है और किस भाग में जनसंख्या जन शून्य है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि जनसंख्या के वितरण एवं जनसंख्या घनत्व की समता एवं सहसंबंध का अध्ययन किया जाए । जनसंख्या वितरण के मानक के रूप में जनसंख्या घनत्व का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर जनसंख्या अधिक अधिवासित होती है, वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है और जहाँ जनसंख्या कम आदिवासी होती है वहाँ जन घनत्व भी कम पाया जाता है। ऐसी स्थिति में कभी – कभी जनसंख्या वितरण एवं जनसंख्या घनत्व एक – दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार देखा जाता है कि जनसंख्या वितरण एवं जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक ही उत्तरदायी होते हैं।

भूगोलवेत्ताओं के एक समूह का मानना है कि विश्व की 90% जनसंख्या मात्र 10% भूखण्ड पर वितरित पाई जाती है जबकि 90% भूभाग पर मात्र 10% जनसंख्या ही प्रसारित है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वि"व की आधी जनसंख्या मात्र 5% भूभाग में ही केंद्रित है। फ्रांस के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता ब्लाश का मत है कि विश्व की दो तिहाई जनसंख्या संपूर्ण स्थल खण्ड के सातवें भाग पर ही निवास करती है। महाद्वीपों पर वितरित जनसंख्या का यदि अवलोकन करें तो स्पष्ट होता है कि एशिया महाद्वीप में लगभग दो तिहाई जनसंख्या निवास करती है, जबकि अंटार्कटिका महाद्वीप एवं ग्रीनलैंड के भूभाग प्रतिकूल पर्यावरण परिस्थितियों के कारण जनरिक्त हैं। इस प्रकार संपूर्ण विश्व का जनसंख्या वितरण की दृष्टि से सामान्य अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि इस आसमान वितरण हेतु प्राकृतिक एवं मानवीय कारक जिम्मेदार होते हैं।

4.3 जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक

भौगोलिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने पर दो पहलू सामने आते हैं। नियतिवादी विचारधारा के समर्थकों का मानना है कि धरातल पर जनसंख्या के वितरण को सबसे ज्यादा प्राकृतिक कारक ही निर्धारित करते हैं जबकि संभववादियों का मानना है कि मानव एक क्रियाशील प्राणी है, और वह अपनी क्रियाशीलता से पर्यावरण प्रभाव का सामना कर सकता है इसलिए मानवीय कारक ज्यादा प्रभावशाली होंगे। इस वैचारिक द्वैतवाद से यही स्पष्ट होता है कि जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व के निर्धारण में अकेले किसी एक घटक को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। दोनों ही कारक अपने – अपने स्तर पर प्रभावशाली होते हैं। किसी एक की अनदेखी करके दूसरे की सर्वोच्चता नहीं स्थापित की जा सकती है। अतः जनसंख्या पारिस्थितिकी की संकल्पना को आधार मानते हुए इसके कारकों को दो वर्गों में विभक्त किया जाता है –

सारणी 4.1 जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक

प्राकृतिक कारक	1. जलवायु कारक
	2. स्थलस्वरूप कारक
	3. मृदा कारक

	4. खनिज पदार्थ एवं शक्ति संसाधन कारक
	5. जल संसाधन की उपलब्धता कारक
	6. क्षेत्रीय संबंध एवं अभिगम्यता कारक
मानवीय कारक	1. सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक
	2. राजनीतिक कारक
	3. आर्थिक कारक
	4. जनांकिकीय कारक

स्त्रोत : तिवारी, (2023), जनसंख्या भूगोल.

4.4 प्राकृतिक कारक

इन कारकों के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त समुच्चय को सम्मिलित किया जाता है। एक कारक जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। भौगोलिक चिंतन की जर्मन विचारधारा ने भी प्रकृति की प्रधानता को स्वीकार किया है और पर्यावरण नियतिवाद की संकल्पना को प्रतिपादित किया है, प्रमुख प्राकृतिक कारक निम्नलिखित हैं –

4.4.1 जलवायु

मानव के दैनिक क्रियाकलाप निवास स्थान, स्वास्थ्य एवं आर्थिक क्रियाकलापों को सबसे ज्यादा जलवायु ही प्रभावित करती है। मानव के समस्त क्रियाकलापों एवं क्रियाशीलता को नियंत्रित करने वाले घटकों में प्रचलित पवन एवं उनकी परिवर्तनीयता तापमान, आर्द्रता एवं वर्षा की मात्रा प्रमुख है। जहाँ स्वास्थ्य वर्धक जलवायु जनसंख्या को आकर्षित करके जनसंख्या जमघट का निर्माण करती है, वहीं विषम जलवायु प्रकरण जल क्षेत्र के साथ जेनेरिक प्रदेशों के विकास को प्रोत्साहन देती है। प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैटिंगटन का मानना है कि मानसिक कार्य के लिए 3 अंश से 4 अंश सेल्सियस तापमान एवं शारीरिक कामों हेतु 15 अंश से 18 अंश सेल्सियस तापमान सबसे अधिक उपयुक्त होता है। वर्षा भी जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करती है। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु मानव के आर्थिक क्रियाकलापों एवं स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है। यही कारण है कि

वर्षायुक्त मानसूनी जलवायु जनसंख्या को सदैव आकर्षित करती है। संसार के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश इसी पेटी में स्थित है जैसे चीन भारत, जापान, कोरिया, वियतनाम, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश आदि। पर्याप्त वर्षा एवं जलवायु की विविधता इस प्रदेश में अनेकों प्रकार के फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देती है जिसके कारण ये प्रदेश अधिक जनसंख्या के भरण – पोषण में सक्षम हो जाते हैं। एशिया के अतिरिक्त यूरोप अमेरिका की शीतोष्ण कटिबंधीय एवं तटीय क्षेत्रों में भी अधिक जनसंख्या संकेंद्रण पाया जाता है। मानव के निवास हेतु 4 अंश सेल्सियस से 21 अंश सेल्सियस तक तापमान अधिक अनुकूल होता है। इसके विपरीत अत्यधिक न्यूनतम तापमान एवं अधिक तापमान की स्थितियां भी मानव बसाव हेतु प्रतिकूल होती है। तापमान की न्यूनता एवं हमेशा हिमाच्छादित रहने के कारण ग्रीनलैण्ड एवं अंटार्कटिका जैसे विशाल स्थलखण्ड जनशून्य बने हुए हैं । साथ ही टुंड्रा एवं शीत मरुस्थल में भी कम ही जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार अत्यधिक तापमान वाले उष्णकटिबंधीय प्रदेश तथा मरुस्थल मानव अधिवास हेतु विषम दशाएं प्रस्तुत करते हैं।

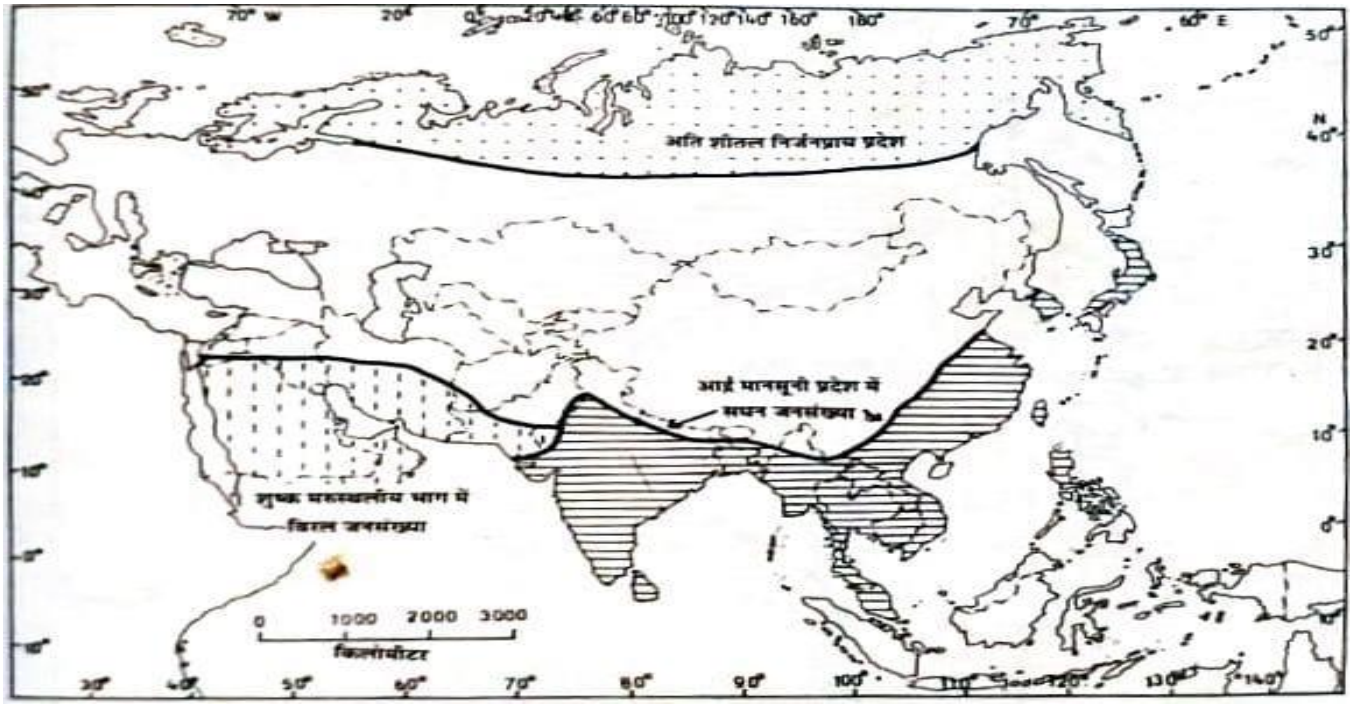

चित्र 4.1 जलवायु कारकों से प्रभावित होकर विश्व जनसंख्या का वितरण.

आर्द्रता एवं तापमान के संयुक्त प्रतिफल ही किसी स्थान पर मनुष्य एवं वनस्पति के विकास को निर्धारित करते हैं। अत्यधिक शुष्कता और आर्द्रता की दोनों ही स्थितियां कृषि एवं वनस्पति उत्पादन को प्रभावित करती है। कृषि एवं वनस्पति की उत्पादकता किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या की संकेंद्रण को निर्धारित करते हैं। अत्यधिक उष्ण एवं आर्द्र जलवायु वाले भूमध्या रेखीय प्रदेश जैसे अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन एवं द्वीप समूह प्रदेशों में वर्ष पर्यंत वर्षा एवं उमस का मौसम बना होता है। इसके फलस्वरुप यहाँ अल्प मात्रा में जनसंख्या निवास करती है। इसी तरह अत्यधिक शुष्कता के कारण मरुस्थली प्रदेशों में भी नगण्य जनसंख्या पाई जाती है। इन क्षेत्रों में एशिया के थार मरुस्थल, अफ्रीका के सहारा एवं कालाहारी मरुस्थल, दक्षिणी अमेरिका का अटाकामा मरुस्थल एवं दक्षिण – पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के भाग में स्थित मरुस्थल आते हैं। इन अधिकांश मरुस्थली भाग में जनसंख्या घनत्व एक प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त व्याख्या के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्षा के वितरण एवं जनसंख्या घनत्व में सीधा संबंध पाया जाता है। यह दोनों प्रकार की अधिकता अर्थात उष्णता एवं शीत के मध्य वाले क्षेत्रों में अधिकांशतः वितरित पाई जाती है

4.4.2 स्थलस्वरूप

पृथ्वी के धरातल के बाह्य स्वरूप में दृष्टिगत विविध प्रकार के विविधता को स्थलस्वरूप कहा जाता है। इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, अपवाह तंत्र आदि को सम्मिलित किया जाता है। जहाँ स्थल स्वरूप की समानता अधिक होती है अत्यधिक जनसंख्या का वास स्थान होती है वहीं विषम स्थलाकृति वाले क्षेत्रों में कम जनसंख्या

निवास करती है। जनसंख्या वितरण एवं घनत्व का भौगोलिक अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि मैदानी भाग में अधिक जनसंख्या निवास करती है जबकि पठारी भाग में उससे कम तथा पर्वतीय भाग में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। समतल मैदानी भाग कृषि हेतु सबसे उपयुक्त दशाएं उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ सिंचाई, यातायात, व्यापार एवं उद्योग से जुड़े अवसंरचनात्मक ढांचे को आसानी से खड़ा किया जा सकता है। यही कारण है कि विश्व की प्राचीन संस्कृतियाँ नदी घाटियों में ही विकसित हुई है। सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों का भारतीय मैदान, पाकिस्तान का सिंधु मैदान, चीन के पूर्वी भाग में स्थित हवांगहो, या यांगटीसिक्यांग एवं पीली नदी क्षेत्र, अमेरिका, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया के नदी घाटी क्षेत्र में जनसंख्या का अधिक वितरण एवं घनत्व पाया जाता है। रूसी भूगोलवेत्ता स्तासजवेसकी की ने अपने अध्ययनों में बताया है कि 500 मीटर से ऊंचाई वाले भागों में विश्व की लगभग 20% जनसंख्या निवास करती है। इसी तरह का अध्ययन क्लार्क ने भी किया है और बताया है कि हर पांच में से तीन व्यक्ति 200 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निवास करता है। अपवाह तंत्र भी मानव बसाव को प्रभावित करता है। अपरिपक्व अपवाह क्षेत्र में दलदल तथा काई मानव अधिवास के विकास में बहुत बड़े बाधक माने जाते हैं। इसलिए प्रमुख नदी डेल्टा क्षेत्र में बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। बहुमूल्य धातु उत्खनन क्षेत्र भी जनसंख्या को आकर्षित करते हैं ऐसे क्षेत्र लोगों को आजीविका का संसाधन उपलब्ध कराते हैं। ऐसी अनुकूलता वाले प्रदेशों में अधिक जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है साथ ही यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक देखा जाता है।

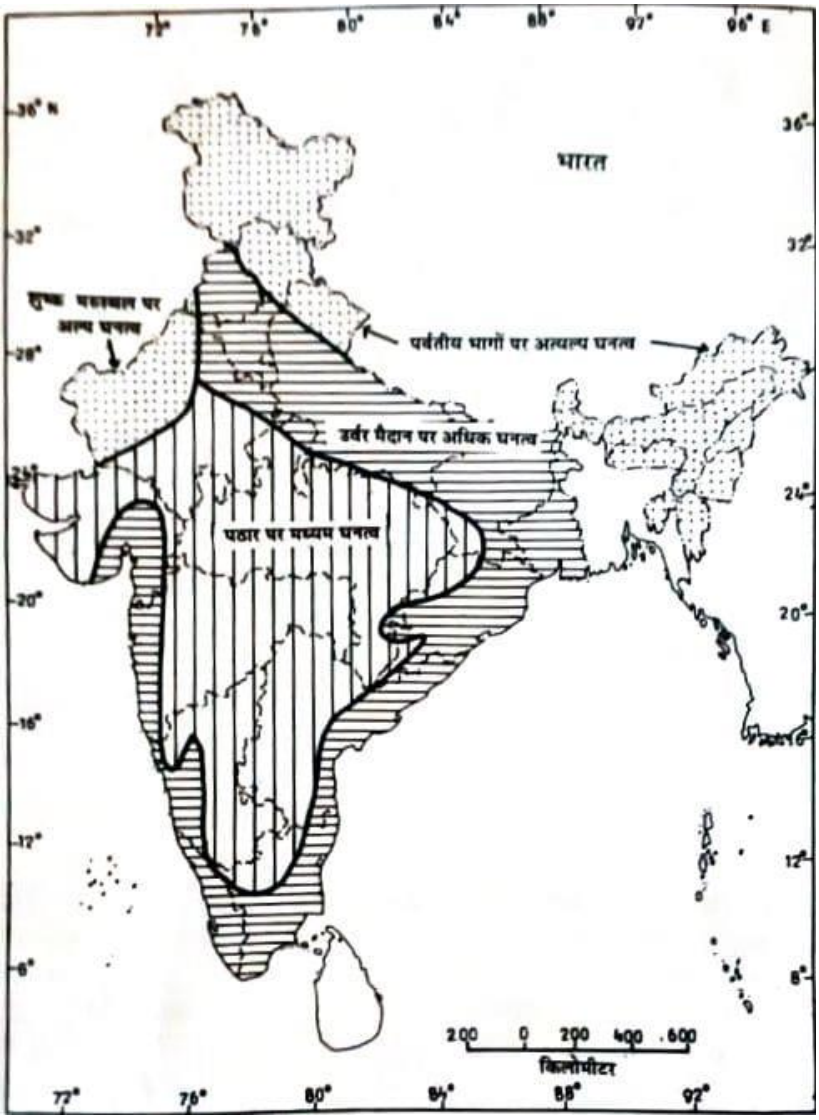

चित्र 4.2 स्थलाकृति एवं उच्चावच कारकों से प्रभावित होकर भारत की जनसंख्या का वितरण.

4.4.3 मृदा

पृथ्वी के धरातल पर असंगठित चट्टानों के संचयन को मृदा कहते हैं। मृदा मूल चट्टानों एवं प्राकृतिक तथा मानवीय कारकों का प्रतिफल होती है। किसी क्षेत्र में उपजाऊ मृदा की उपस्थिति एवं प्रसार वहाँ जनसंख्या संकेंद्रण को प्रभावित करती है। व्यक्ति की प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उसके संपूर्ण विकास का मृदा से ही जुड़ा होता है इसलिए मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास कहा जाता है (मौर्य, 2020)। मृदा ही वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के विकास का आधार होती है क्योंकि यह खाद्यान्न और जैविक उत्पाद का मुख्य स्रोत होती है। इस प्रकार इन सब के विकास के लिए उर्वरक एवं उपयोगी मृदा की आवश्यकता होती है। मानव के साथ ही सभी शाकाहारी प्राणियों का भोजन वनस्पति तथा अनाज के रूप में प्रत्यक्ष रूप से मृदा से ही प्राप्त होते हैं। मांसाहारी जीव जिन जंतुओं पर अपने भोजन हेतु निर्भर रहते हैं उन्हें भी मृदा से उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां एवं अनाज ही आधार प्रदान करते हैं। इस प्रकार शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के जंतुओं की भोजन की आपूर्ति का मुख्य स्रोत मृदा ही होती।

संसार के अलग – अलग भागों में वितरित मृदा के भौतिक एवं रासायनिक संगठन में अधिक भिन्नता पाई जाती है। नदियों द्वारा निर्मित नवीनतम खादर मिट्टियाँ पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं और उनकी उर्वरता अधिक होती है। इनमें सभी पोषक तत्वों का भरपूर समायोजन होता है जैसे जालोढ़ एवं काली मृदा। इन मृदाओं की उत्पादकता अधिक होती है तथा ये एक विशाल जन समूह के पालन – पोषण में सक्षम होती हैं। जिन मृदाओं में पोषक एवं रासायनिक तत्वों की कमी होती है उनमें कृत्रिम विधियों से पोषक का समिश्रण करके उनकी आपूर्ति की जाती है। इस प्रकार एक सीमा तक उनकी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। पर्वतीय एवं पठारी भागों में संरचनात्मक दृष्टि से कुछ अनुपजाऊ मृदाएँ पाई जाती हैं तथा स्थानीयता के आधार पर उनमें कुछ पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त होती है तो अधिकांश की कमी। इस स्थिति में उत्पादकता कम होती है। इसके अतिरिक्त औद्योगिककरण का विकास भी पर्याप्त नहीं हुआ है तो इसके कारण विश्व की अधिकांश जनसंख्या अपने जीवन यापन हेतु कृषि पर निर्भर होती है। यही कारण है कि संसार के जिन भागों में उपजाऊ मृदा पाई जाती है वहाँ जनसंख्या वितरण एवं घनत्व दोनों उच्चतम पाया जाता है।

4.4.4 खनिज एवं शक्ति संसाधन

वर्तमान समय में जनसंख्या के वितरण और खनिज एवं शक्ति संसाधनों के बीच संबंध के अध्ययन पर ज्यादा रुचि देखी गई है। मौर्य (2020) अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात खनिज संसाधनों की उपलब्धता ने जनसंख्या वितरण को अधिक प्रभावित किया है। जिन स्थानों पर इनकी उपलब्धता अधिक होती है वहाँ खनन एवं औद्योगिक उत्पादन जैसी क्रियाएं अत्यधिक संकेंद्रित पाई जाती हैं जो जनसंख्या का सबसे बड़ा आकर्षण तत्व है। इसके अतिरिक्त सोना, चांदी, हीरा एवं प्लैटिनम जैसे बहुमूल्य संसाधन उपयोगिता की दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन ये विश्व के कुछ भागों में ही सीमित पाए जाते हैं। ऊर्जा के संसाधनों की उपलब्धता जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, गैस, यूरेनियम एवं थोरियम सम्मिलित हैं कि सहयोग से ही आधुनिक संस्कृति गतिमान है। यूरोप में कोयला पेटी का विस्तार 40० से 60० उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। इस पेटी का विस्तार पूर्व में रूस की सीमा से लेकर पश्चिम में ग्रेट ब्रिटेन तक पाया जाता है। यहाँ लौह – अयस्क के निक्षेप में अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। इसके सहारे लौह – अयस्क उद्योग के साथ – साथ तांबा, जस्ता एवं अन्य खनिजों पर आधारित उद्योगों का भी विकास हुआ है। इन सभी का संयुक्त प्रभाव यह है कि उत्तरी एवं पश्चिमी यूरोप में जनसंख्या वितरण एवं घनत्व अधिक पाया जाता है।

दक्षिण पश्चिम एशिया के पेट्रोलियम संसाधनों से संपन्न क्षेत्र जनसंख्या के आकर्षण हेतु उत्तम दशाएँ प्रस्तुत करते हैं परंतु ये पर्यावरणीय दृष्टि से प्रतिकूल दशाएं भी उपलब्ध कराते हैं। ये क्षेत्र शक्ति संसाधनों की दृष्टिकोण से धनी हैं परंतु प्रकृति की प्रतिकूलता यहाँ के जनसंख्या संकेंद्रण एवं घनत्व को निम्न कर देती है।

भारत में जनसंख्या के वितरण को यहाँ की जलवायु एवं उच्चावच के साथ ही खनिज पदार्थ एवं शक्ति के संसाधनों का वितरण प्रभावित करता है। खनिज एवं शक्ति संसाधनों को आधुनिक सभ्यता का मेरुदण्ड कहा जाता है। यदि इन्हें किसी कारण हटा दिया जाए तो सम्पूर्ण मानवीय सभ्यता के सभी क्रियाकलाप अचानक ठप हो जाएंगे। भारत के विकास में भी इनका महत्त्व अतुलनीय है। कृषि के साथ ही सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला इन्हीं पर टिकी हुई है। जिन क्षेत्रों में इनकी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होती है वहाँ विकास के अवसर

अन्य क्षेत्रों के अपेक्षा अधिक होती है। जैसे भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र यहाँ उद्योगों के विकास हेतु कच्चा माल एक साथ उपलब्ध हो जाते है। इससे मालों को उद्योगों तक पहुँचाने तथा उनसे तैयार होने वाले उत्पादों को आसानी से उपभोक्ताओं तक पहुँचा दिया जाता है जिससे समय एवं धन दोनों का कम से कम व्यय होता है। दूसरी तरफ मैदानी भाग में समतल उच्चावच पाया जाता है, अनुकूल जलवायु, प्रचुर मात्रा में जल एवं कृषि योग्य भूमि भी पाई जाती है फिर इसका विकास प्रायद्वीपीय भारत की तुलना कम हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार कारकों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों के उद्‌गम स्त्रोत के अधिक दूरी पर अवस्थित है। नवीनतम खनिजों एवं ऊर्जा संसाधनों की खोज एवं विकास को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि भविष्य में कम लागत पर अधिक स्त्रोत प्राप्त हो जाए।

4.4.5 जल संसाधन की उपलब्धता

मानव जीवन के लिए जल एक अत्यंत ही आवश्यक पदार्थ है, जिसके बिना मानव जीवन संभव ही नहीं है। मानव निवास के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता पीने के लिए जल के स्रोत का उपलब्ध होना भी है। पीने के पानी के साथ – साथ सिंचाई, घरेलू आवश्यकताओं एवं औद्योगिक कार्यों को संपादित करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल आपूर्ति की व्यवस्था वाले क्षेत्रों में जनसंख्या की सघनता अधिक पाई जाती है। प्राचीन काल से ही नदियां यातायात का प्रमुख साधन हुआ करती थी, यही कारण है कि विश्व के अधिकांश महत्वपूर्ण नगरों का विकास नदियों के किनारे हुआ है। वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में विश्व व्यापार के दृष्टिकोण से समुद्री मार्गों का महत्व अधिक है। इसी का परिणाम था कि विश्व के अधिकांश बड़े – बड़े नगर समुद्र तटों पर ही स्थित है जैसे लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, शंघाई, सिंगापुर, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई इत्यादि।

शुष्कता से प्रभावित वातावरण के उन्हीं क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है जहाँ जल स्रोत एवं जलाशय पाए जाते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जलाशयों के पास ही पेड़ – पौधे एवं वनस्पतियों के उगने से कुछ हरियाली पाई जाती है और उसके आस – पास ही जनसंख्या निवास करती है। जब तक इन जलाशय में जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है, तब तक जन समुदाय उसके चारों तरह निवास करता है। इसके पश्चात वह प्रवास कर जाता है। इसी प्रकार पर्वतीय ढालों पर जनसंख्या का जमाव वहीं मिलता है जहाँ झीलों एवं प्राकृतिक जल स्रोतों के केंद्र पाए जाते हैं। यही कारण है कि जनसंख्या के वितरण एवं सघनता पर जल की उपलब्धता का प्रभाव अधिक देखा जाता है।

4.4.6 क्षेत्रीय संबंध एवं गम्यता

किसी स्थान विशेष की जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता और उनके सम्पूर्ण पोषण की क्षमता उस क्षेत्र की अवस्थिति एवं यातायात के साधनों के प्रसार से प्रभावित होती है। यही कारण है कि सभी महाद्वीपों में स्थित देशों में तटवर्ती क्षेत्रों में सघन जनसंख्या पाई जाती है जबकि दुर्गम एवं आंतरिक भागों में कम जनसंख्या होती है। किसी प्रदेश में यातायात की सुविधा जितनी अधिक होगी वह अपने चतुर्दिक क्षेत्र से अधिक जनसंख्या को आकर्षित करती है। समतल एवं मैदानी भागों में सड़क, रेलमार्ग एवं नहरों का विकास आसान होता है इसके विपरीत पर्वतीय एवं पठारी भागों में असमान उच्चावच के कारण इनका समुचित विकास नहीं हो पता है। अगर होता भी है तो वह अत्यधिक कीमत वाला होता है। ऐसी स्थिति में सरकारों पर अत्यधिक भार पड़ता है और वह ऐसे कार्यों में रुचि नहीं लेते हैं। मुख्य स्थल भूमि से जुड़े द्वीप समूह भी जनसंख्या हेतु आकर्षक होते हैं। यहाँ पर पर्यटन जैसे उद्योग को विकसित करके देश की अर्थव्यवस्था को अधिक सुदृढ बनाने का कार्य किया जा सकता है। इसी का परिणाम है कि विश्व के अधिकांश तटीय अवस्थित वाले देश पर्यटन की दृष्टिकोण से पर्याप्त विकसित हुए हैं जैसे जापान, इंडोनेशिया, वेस्टइंडीज एवं ब्रिटिश द्वीप समूह।

4.5 मानवीय कारक

मानव एक सक्रिय प्राणी है जो अपनी क्रियाशीलता के प्रभाव से पृथ्वी के भौतिक धरातल में परिवर्तन करके नए स्वरूपों का विकास करता है। मानव की क्रियाशीलता को संदर्भित करने वाला फ्रांसीसी भौगोलिक चिंतन का समुदाय मानता है कि कहीं पर भी कोई अनिवार्यता नहीं है। मानव संभावनाओं का स्वामी होता है और अपनी क्रियाशीलता के आधार पर वह विषम परिस्थितियों में भी कुछ ऐसा कर लेता है जिससे वह पर्यावरण अनुकूलता का सामना करने में सक्षम हो जाता है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि मानव द्वारा भी पृथ्वी पर तरह – तरह

के स्थलस्वरूपों का निर्माण किया जाता है जिन्हें सांस्कृतिक भूदृश्य के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार मनुष्य भी जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक होता है जो निम्नलिखित हैं –

4.5.1 सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक

किसी स्थान का सामाजिक संगठन, वर्ग व्यवस्था, प्रथाएं, रीति – रिवाज, परंपराएं, जीवन के मूल्य एवं धार्मिक विश्वास वहाँ पर जनसंख्या के संकेंद्रण एवं घनत्व को प्रभावित करते हैं। जहाँ पर उदारवादी प्रवृत्ति की सामाजिक संरचना पाई जाती है वहाँ पर सभी वर्गों एवं धार्मिक समुदाय के लोग बसना पसंद करते हैं। इसके विपरीत जहाँ धार्मिक एवं सामाजिक रूढ़िवादिता अधिक होती है तथा धार्मिक एवं सांप्रदायिक दंगों की आवृत्ति अधिक होती है। वहाँ कम लोग निवास करना पसंद करते हैं जैसे मुस्लिम एवं अविकसित देश। यहाँ के लोग बाहर की ओर प्रवास करने हेतु मजबूर होते हैं और जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। पश्चिमी देशों की संस्कृति आर्थिक संपन्नता हेतु जनसंख्या के प्रवास को प्रोत्साहन करती है। इसका परिणाम यह हुआ कि अधिक जनसंख्या वाले यूरोपीय देशों से अधिक मात्रा में लोग अफ्रीका, एशिया, अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रवास किए, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। एशिया एवं अफ्रीका के देशों में आर्थिक एवं सामाजिक गतिशीलता कम पाई जाती है। यहाँ के लोग कम संसाधन एवं सुविधाओं में जीवन यापन करके खुश रहते हैं एवं एक साथ रहते हैं। जिसका परिणाम यह होता है कि यहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है और जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। विकासशील एवं तीसरी दुनिया के देशों में वर्तमान नगरीकरण की प्रवृत्ति में तेजी आई है जिसके कारण निर्धन तथा व्यापक जनसंख्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नगरों की ओर आकर्षित हो रही है। इसके फलस्वरुप नगरीय जनसंख्या का आकार एवं घनत्व तेजी से बढ़ता चला जा रहा है।

4.5.2 राजनीतिक कारक

राजनीति से तात्पर्य होता है राजनीतिक एवं प्रशासनिक शक्ति को प्राप्त करना जिसके माध्यम से किसी देश विशेष के संपूर्ण शासन का संचालन किसी विशेष सिद्धांत, मान्यता एवं विचारों के मानने वाले लोगों में निहित हो जाता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाई जाती हैं, इन्हीं नीतियों में से जनसंख्या नीति भी एक है। जनसंख्या नीतियां किसी स्थान पर जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करती हैं। सभी देश अपनी सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार इनका निर्धारण एवं क्रियान्वयन करते हैं। इसी के माध्यम से प्रवास एवं जनसंख्या वृद्धि को भी नियंत्रित किया जाता है। 20वीं शताब्दी तक जनसंख्या के प्रवास पर सरकारों का नियंत्रण काम होता था जिसके कारण प्रवास में सुगमता होती थी। अनेकों आर्थिक संसाधनों की खोज तथा रोजगार के अवसरों ने एक देश से दूसरे देश में जाकर बसने हेतु लोगों को प्रोत्साहित किया। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात इस प्रवृत्ति में कमी देखी गई कुछ देशों ने बाहर से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया जैसे ऑस्ट्रेलिया सरकार ने श्वेत नीति के तहत अश्वेतों को नागरिकता देना बंद कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि एशिया एवं अफ्रीका के लोगों पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया जिससे मूल देश में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है जबकि ऑस्ट्रेलिया की संपूर्ण जनसंख्या भारत की जनसंख्या से भी बहुत कम है। युद्ध, अकाल, देश का विभाजन जैसे मानव निर्मित तत्व भी जनसंख्या के स्थानांतरण को प्रभावित करते हैं।

4.5.3 आर्थिक कारक

मानव एक सामाजिक प्राणी है उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आजीविका के संसाधनों की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। इस प्रकार किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या के निवास हेतु आजीविका के संसाधनों की उपलब्धता अनिवार्य होती है। अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के आधार पर मानव समुदाय द्वारा अनेकों आर्थिक क्रियाकलापों को संपादित किया जाता है। इन क्रियाकलापों में कृषि, पशुपालन, आखेटन, उद्योग – धंधे, व्यापार, कार्यालय, परिवहन के साथ अनेक सेवाएं सम्मिलित होते हैं। विश्व के वे सभी क्षेत्र जहाँ आजीविका के एक से अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं वह अन्य क्षेत्रों से जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विश्व के सभी कृषि प्रधान देश जहाँ उपजाऊ मिट्टी के साथ अन्य भौगोलिक परिस्थितियां कृषि हेतु उपलब्ध होती हैं वहाँ जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व उच्च पाया जाता है जैसे भारत का गंगा का मैदान, बांग्लादेश का डेल्टाई भाग एवं चीन के मैदान।

तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी के विकास भी जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। वर्तमान समय में नवीन उद्योगों, मशीनों, यातायात एवं संचार के साधनों का तीव्रता से विकास हो रहा है जिससे कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके कारण अन्य क्षेत्रों से जनसंख्या रोजगार एवं अन्य सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु इस क्षेत्र की ओर आकर्षित होती है। औद्योगिक ईकाइयां मुख्यतः शहरी क्षेत्र में ही स्थापित होती हैं, ऐसी स्थिति में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं हेतु ग्रामीण क्षेत्र से जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग नगरीय क्षेत्र की ओर प्रवास करता है। किसी भौगोलिक प्रदेश की आर्थिक प्रगति होने की दशा में उसमें रोजगार एवं खाद्य पदार्थों की उपलब्धि के रूप में अधिक जनसंख्या के पालन पोषण की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। इसके परिणामस्वरुप वहाँ अधिक जनसंख्या निवास करने लगती है। इसके साथ ही ऐसे विकसित प्रदेश जिनमें कुछ आवश्यक वस्तुएँ स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं होती हैं वे इनका अन्य क्षेत्रों से आयात कर लेते हैं जैसे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन एवं नीदरलैंड इत्यादि। जो प्रदेश औद्योगिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण से संपन्न होते हैं वह अधिकांश खाद्य सामग्रियों का आयात करते हैं बदले में उन देशों को निर्मित सामग्रियों एवं सेवाओं का निर्यात करते हैं। उदाहरण स्वरूप एशिया का जापान देश इन्हीं सभी आर्थिक क्रियाओं से प्रभावित होकर जनसंख्या वितरण एवं घनत्व निर्धारित होता है।

4.5.4 जनांकिकीय कारक

जनसंख्या के वितरण के जनांकिकीय कारकों में जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, स्थानांतरण और नगरीकरण सम्मिलित होते हैं। विगत कुछ वर्षों में यह प्रवृत्ति देखी गई है कि कुछ देशों द्वारा जनसंख्या स्थानांतरण पर प्रतिबंधात्मक अवरोध लगा दिए गए हैं। इसके कारण एशिया एवं अफ्रीका के देश जहाँ पहले से अधिक जनसंख्या अधिवासित है, प्रवासन नहीं होने के अभाव में प्राकृतिक वृद्धि के कारण जनसंख्या अधिक हो गई है। अधिकांश विकासशील देशों में अत्यंत प्रयत्नों के बावजूद भी जन्म दर में अपेक्षित कमी नहीं आ पाई है साथ ही चिकित्सा सुविधाओं में निरंतर विकास के कारण मृत्यु दर में अत्यधिक कमी देखी गई है, ऐसी स्थिति में प्राकृतिक वृद्धि की गति में तीव्रता देखी गई है।

विकसित देशों की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं जनांकिकीय संरचना विकासशील देशों से भिन्न होती है। विश्व के अधिकांश विकसित देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ पश्चिमी यूरोप के देशों ने जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों को नियंत्रित करके न्यूनतम स्तर पर ला दिया है। ऐसी स्थिति में दोनों में बहुत कम अंतर पाया जाता है इसके परिणामस्वरुप इन देशों की जनसंख्या वृद्धि लगभग रुक सी गई है और जनसंख्या घनत्व में स्थिरता आ गई है। नगरीकरण का भी जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व पर अधिक प्रभाव देखा गया है। नगरों के विकास से प्रभावित होकर ग्रामीण जनसंख्या रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सेवाओं को प्राप्त करने हेतु नगरों की ओर प्रवासित होती है। इसके फलस्वरुप नगरीय केन्द्रों में जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ने लगता है।

4.6 सारांश

आपने इस इकाई में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया है। आप समझ गए होगें कि जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व में किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है। इससे विश्व या किसी देश की जनसंख्या की गत्यात्मकता की विस्तृत जानकारी मिलती है तथा उसके विविध कारकों को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। वास्तव में किसी देश की जनसंख्या वितरण तथा वहाँ के जनसंख्या घनत्व पर उस स्थान भौगोलिक अवस्थिति, सरकारी नीतियों, सांस्कृतिक संगठन आदि का प्रभाव होता है।

आपने यह भी देखा है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक दो भागों में विभक्त होते है प्राकृतिक कारक तथा मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक प्रकृति प्रदत्त होते है तथा इनकी प्रभाविता सबसे अधिक होती है। कभी – कभी इनकी कठोरता एवं प्रभाविता से मानवीय विकास के सभी घटक नगण्य हो जाते है। मानवीय कारक मानव की क्रियाशीलता एवं प्रतिबद्धता से विकसित होते है। मानव के ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में जैसे – जैसे वृद्धि होती जाती है वह विविध प्रकार की तकनीकियों को विकसित करने में सक्षम हो जाता है। इससे वह उन क्षेत्रों को भी निवास योग्य बना देता है जो पहले मानव निवास के अनुकूल नहीं थे। फिर भी मानवीय कारकों की एक सीमा होती है।

4.7 स्वमूल्यांकन प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

1. विश्व की लगभग 90ः जनसंख्या का वितरण धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है।

   (क) 20% (ख) 50% (ग) 10% (घ) 30%

2. एशिया महाद्वीप में सम्पूर्ण विश्व की लगभग कितनी जनसंख्या निवास करती है।

   (क) दो तिहाई (ख) एक चौथाई (ग) आधा (घ) तीन चौथाई

3. सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है।

   (क) चीन (ख) भारत (ग) अमेरिका (घ) ब्राज़ील

4. निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों में नहीं है।

   (क) जलवायु कारक (ख) स्थलस्वरूप कारक (ग) आर्थिक कारक (घ) मृदा कारक

4.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

Bogue] D- J-] 1969] Principles of Demography] John Wiley] N-Y-

Clarke] John I-] 1973] Population Geography] Pergaman Press] Oxford-

Crook] Nigel] 1997] Principles of Population and Development] Pergaman Press] N- Y-

Garmier] J- B-] 1970] Geography of Population] Longman] London-

Mamoria] C- B-] 1981] India's Population Problem] Kitab Mahal] New Delhi-

Premi] M- K-] 1991] India's Population] Heading Towards a Billion] B- R- Publishing Corporation-

Blassoff] M- and Srinivasan K-] 2001] Population Development Nexus in India : Challenges for the New Millennium] Tata McGraw Hill] New Delhi-

Woods] R-] 1979] Population Analysis in Geography] Longman] London-

Zelinsky] W-] 1966] A Prologue to Population Geography] Prentice Hall-

चन्दना, आर. सी., 2022, जनसंख्या भूगोल – संकल्पना, नियंत्रक व विश्व प्रारूप, कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

चन्दना, आर. सी., 2022, भारत : जनसंख्या (जनसंख्या भूगोल – भाग 2), कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

मौर्या, एस. डी., 2005, जनसंख्या भूगोल, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद.

ओझा, आर. पी., 1984, जनसंख्या भूगोल, प्रतिभा प्रकाशन.

हीरा लाल, 2000, जनसंख्या भूगोल के मूल तत्व, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली.

तिवारी, राम कुमार, 2023, जनसंख्या भूगोल, प्रवालिका पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद.

4.9 अभ्यास प्रश्न (सत्रांत परीक्षा की तैयारी)

1. जनसंख्या के वैश्विक वितरण को प्रस्तुत करते हुए उसे प्रभावित करने वाले कारकों की विस्तृत व्याख्या कीजिए?
2. जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों का वर्णन कीजिए?
3. जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले मानवीय कारकों की समीक्षा कीजिए?

इकाई–5 जनसंख्या का विश्व – वितरण, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र अल्प तथा अत्यल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र, जनरिक्त क्षेत्र

इकाई की रूपरेखा

5.0 प्रस्तावना

5.1 उद्देश्य

5.2 जनसंख्या का वैश्विक परिदृश्य

5.3 जनसंख्या का वैश्विक वितरण

5.4 अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र

5.5 मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र

5.6 अल्प तथा अत्यल्प जनसंख्या वितरण वाले क्षेत्र

5.7 जनरिक्त जनसंख्या वितरण वाले क्षेत्र

5.8 सारांश

5.9 स्वमूल्यांकन प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

5.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

5.11 अभ्यास प्रश्न (सत्रांत परीक्षा की तैयारी)

5.0 प्रस्तावना

जनसंख्या भूगोल के भूगोलवेत्ताओं के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि संपूर्ण विश्व पर जनसंख्या किस प्रकार से वितरित है। जनसंख्या वितरण को बहुत हद तक संसाधन प्रभावित करते हैं। प्रत्येक देश हेतु प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संसाधनों की एक सीमा होती है। किसी देश का भौगोलिक क्षेत्रफल, खनिज, मिट्टी, जल संसाधन, वन संपदा, भूमि की उपजाऊ शक्ति, सिंचाई के साधन, उद्योग, परिवहन मार्ग, यातायात के साधन, शिक्षा का स्तर एवं बाजार की उपलब्धता जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में हैं।

5.1 उद्देश्य

प्रकृति के अन्य तत्वों के समान ही मानव का पृथ्वी के धरातल पर वितरण समान नहीं है। मानव जनसंख्या कहीं सघन पाई जाती है तो कहीं विरल। इस अध्याय में उसी वितरण का अध्ययन किया जाएगा, जो निम्नलिखित है –

1. अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र
2. मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र
3. अल्प तथा अत्यल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र
4. जनरिक्त क्षेत्र

5.2 जनसंख्या का वैश्विक परिदृश्य

जनसंख्या भूगोल के अध्ययन में जनसंख्या का वितरण अभिन्न अंग है। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या विभाग से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि विश्व की कुल जनसंख्या वर्ष 2001 में 600.31 करोड़ थी, जो बढ़कर वर्ष 2011 ई. में 682.38 करोड़ हो गई ।इस विस्तृत जनसंख्या का संपूर्ण विश्व में वितरण समान नहीं है। विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल के लगभग तीन चौथाई भाग पर जल का विस्तार है। इस प्रकार यहाँ जनसंख्या का पाया जाना नगण्य ही है। शेष एक चौथाई भाग पर 682.38 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। इस स्थलीय भूखण्ड पर जनसंख्या सर्वत्र नहीं पाई जाती है। वह कुछ भू–भाग में ही संकेंद्रित है। एक सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों से इस बात का बोध होता है कि लगभग 90% जनसंख्या 10% भू–भाग पर निवास करती है, जबकि 90% भू–भाग पर मात्र 10% जनसंख्या वितरित है (अलेक्सजेंडर, 1997)।

एक और तथ्य से बोध होता है कि विश्व के 10 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में संपूर्ण संसार की 60% जनसंख्या पाई जाती है। इन 10 अधिसंख्यक देशों में से 7 एशिया में स्थित हैं। विश्व के प्रत्येक पांच व्यक्ति में से एक व्यक्ति चीन में निवास करता है, वहीं प्रत्येक 6 व्यक्ति में से एक व्यक्ति भारत में रहता है। अगर गोलार्ध के आधार पर देखा जाए तो उत्तरी गोलार्द्ध में 88% जनसंख्या निवास करती है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में मात्र 12% जनसंख्या पाई जाती है।

सारणी 5.1 जनसंख्या का वैश्विक परिदृश्य

गोलार्धों के नाम	जनसंख्या प्रतिशत में
उत्तर – पूर्वी	80
दक्षिण – पूर्वी	7
दक्षिण – पश्चिम	5
उत्तर – पश्चिम	8

स्त्रोतः संयुक्त राष्ट्र संघ का जनसंख्या विभाग.

इसी प्रकार पूर्वी गोलार्ध में जहाँ 87% जनसंख्या निवास करती है, वहीं पश्चिमी गोलार्ध में मात्र 13% जनसंख्या के अधिवास हैं। आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि नई दुनिया में जहाँ 13% जनसंख्या पाई जाती है, वहीं पुरानी दुनिया में 87% जनसंख्या रहती है। ऐसी स्थिति में अलेक्सजेंडर ने वर्ष 1970 ई. में वितरण के दृष्टिकोण से पृथ्वी पर तीन प्रकार के प्रदेशों को सीमा सीमांकित किया है –

1. अधिवासित क्षेत्र – बसे हुए क्षेत्र
2. गैर आदिवासी क्षेत्र – बिना बसे हुए क्षेत्र
3. संक्रमण क्षेत्र

जनसंख्या के अध्ययन में क्लार्क ने भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। वह संयुक्त राष्ट्र में जनसंख्या विभाग के अध्यक्ष पद पर भी कार्य कर चुके हैं। उन्होंने जनसंख्या के वितरण के आधार पर विश्व को दो भागों में विभक्त किया है –

पहला– मानव पुंज के क्षेत्र

दूसरा– निर्जन क्षेत्र

5.3 जनसंख्या का वैश्विक वितरण

प्रकृति की परिवर्तनीयता उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है। समय, स्थान एवं परिस्थितियों के कारण उसमें भिन्नता देखी जाती है। यही भिन्नता ही धरातल पर जनसंख्या के वितरण को नियंत्रित करती है। कहीं पर जनसंख्या का अधिक जमाव पाया जाता है, तो कहीं पर कम।

सारणी 5.2 वैश्विक जनसंख्या का वितरण एवं परिवर्तन

क्र. सं.	महाद्वीप के नाम	जनगणना 1950	जनगणना 1990	जनगणना 2001	जनगणना 2004	जनगणना 2011
1.	एशिया	140.35	318.62	370.8	387.53	414.03
2.	अफ्रीका	22.41	63.35	73.88	88.50	99.45
3.	यूरोप	54.91	72.26	67.63	72.81	73.85
4.	उत्तरी अमेरिका	22.02	42.42	49.18	47.24	52.87
5.	दक्षिणी अमेरिका	11.23	29.32	35.73	36.51	38.57
6.	ओसेनिया	01.39	2.63	3.07	3.35	3.61
7.	अंटार्कटिका	–	–	–	–	0.0001
8.	सम्पूर्ण विश्व	252.1	528.4	600.31	635.8	682.38

स्त्रोतः संयुक्त राष्ट्र संघ का जनसंख्या विभाग.

कहीं – कहीं तो जनसंख्या एकदम नहीं पाई जाती है और संपूर्ण क्षेत्र जन शून्य वीरान दिखाई देता है। इस प्रकार जनसंख्या के बसाव, जमाव एवं वितरण की दृष्टिकोण से धरातल पर निम्न तीन स्वरूप देखे जाते हैं –

- अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र
- मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र
- अल्प तथा अत्यल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र

5.4 अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र

जनसंख्या के सघन बसाव के दृष्टिकोण से यदि अवलोकन किया जाए तो इस श्रेणी में मुख्यतः तीन क्षेत्र दृष्टिगत होते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में संपूर्ण विश्व की लगभग 90% जनसंख्या निवास करती है। ये क्षेत्र हैं एशिया, यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका। इन तीन वृहद क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या के सघन बसाव में भिन्नता देखने को मिलती है, जिसके फलस्वरुप निम्न धरातलीय स्वरूप दृष्टिगत होते हैं–

- एशिया में पूर्वी, दक्षिणी एवं दक्षिणी – पूर्वी क्षेत्र,
- यूरोप में उत्तरी – पश्चिमी के साथ मध्यवर्ती क्षेत्र,
- अमेरिका में उत्तर – पूर्वी क्षेत्र

5.4.1 एशिया में पूर्वी, दक्षिणी एवं दक्षिणी – पूर्वी क्षेत्र

एशिया विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यहाँ संपूर्ण विश्व की आधे से अधिक जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या के वितरण एवं सघनता के दृष्टिकोण से एशिया में तीन प्रतिरूप देखे जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं –

अ. पूर्वी एशिया : भौगोलिक विस्तार की दृष्टिकोण से पूर्वी एशिया के अंतर्गत चीन, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया एवं ताइवान इत्यादि देश सम्मिलित हैं। यहाँ विश्व की लगभग 22% जनसंख्या निवास करती है। जापान को छोड़कर यह संपूर्ण क्षेत्र कृषि प्रधान है। यहाँ की जलवायु मानसूनी प्रकार की है, जो कृषि हेतु सर्वाधिक अनुकूल होती है। मानसून की सफलता एवं असफलता इस क्षेत्र के विकास स्तर को प्रभावित करती है। इसके कुछ क्षेत्रों में पिछले कुछ दशकों में औद्योगिककरण हुआ है, फिर भी यहाँ की आधी से अधिक आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। पूर्वी एशियाई जन संकुल प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या मुख्यतःसिंचित मैदानों, नदी घाटियों, तटीय मैदानों एवं डेल्टाई भागों में पाई जाती है। यहाँ जनसंख्या संकेंद्रण का मुख्य कारण फसल के लिए उपजाऊ भूमि, सिंचाई के लिए जल के साथ उचित अवसंरचना का प्रबंध, प्रचुर एवंसस्ते श्रमिक की उपलब्धता तथा यातायात के साधनों की उपलब्धता है। इस प्रदेश की जलवायु भी मानव विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रस्तुत करती हैं जिसका प्रभाव यहाँ जनसंख्या संकेंद्रण पर पड़ता है।

ब. दक्षिण एशिया : दक्षिण एशिया भी विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या संकेंद्रण वाले क्षेत्रों में से एक है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका एवं बांग्लादेश सम्मिलित हैं। वर्ष 1947 ई. से पूर्व भारत, पाकिस्तान एवं बांग्ला देश एक ही देश के अंग थे । वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इन तीनों देशों को मिलाकर कुल आबादी 153 करोड़ है तथा श्रीलंका की दो करोड़ आबादी जुड़ जाने के पश्चात 155 करोड़ हो जाती है। इस प्रकार दक्षिणी एशिया में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 23% जनसंख्या निवास करती है। यह संपूर्ण क्षेत्र मानसूनी जलवायु से आच्छादित है, साथ ही साथ इसका अधिकांश भाग समतल मैदानी क्षेत्र है। इसके कारण यहाँ कृषि, रोजगार एवं आजीविका के अवसर प्रदान करती है।

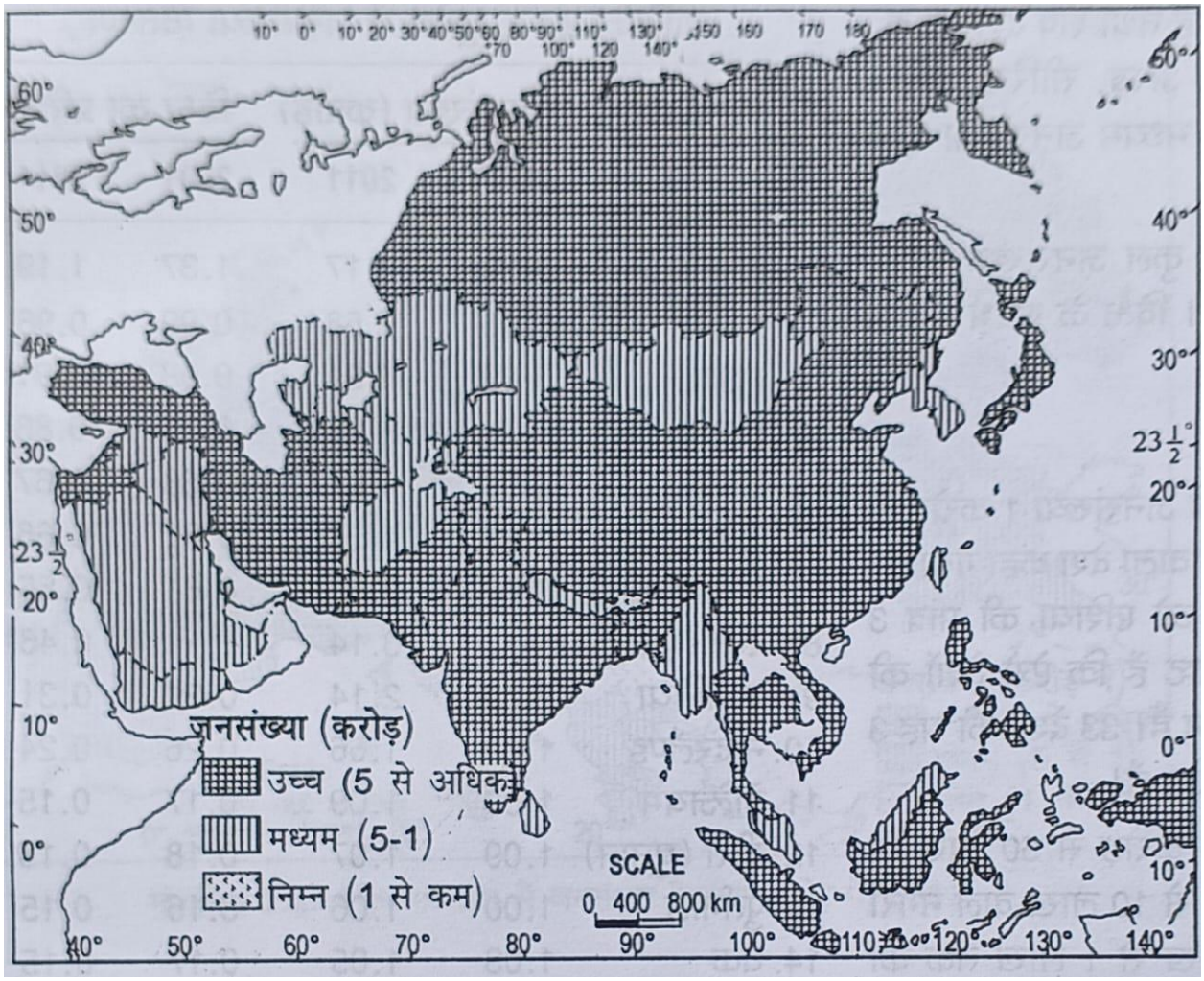

चित्र संख्या 5.1 एशिया में जनसंख्या का वितरण.

स. **दक्षिण – पूर्वी एशिया :** एशिया में जनसंख्या संकेंद्रण का एक महत्वपूर्ण संकुल दक्षिण – पूर्वी एशिया है। इसके अंतर्गत सम्मिलित देशों में थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, फिलिपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया एवं ब्रुनेई इत्यादि देश शामिल हैं। इस भौगोलिक प्रदेश की जनसंख्या 56 करोड़ है, जो विश्व की संपूर्ण जनसंख्या का 8% है। भौगोलिक दृष्टिकोण से यह छोटे – छोटे द्वीपों से मिलकर बना यह प्रदेश एशिया का सबसे छोटा जन समूह है।

भौगोलिक विस्तार की दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो एशिया के सघन बसे हुए तीनों क्षेत्र 0० से 40० उत्तरी अक्षांशों के मध्य केंद्रित हैं। इस प्रकार इस प्रदेश की जलवायु उष्ण एवं उपोष्ण प्रकार की है। मानसूनी वर्षा की पर्याप्त उपलब्धता के कारण पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली सदाबहार एवं मौसमी नदियों द्वारा विस्तृत उपजाऊ मैदान का निर्माण किया गया है। इस क्षेत्र में चावल की खेती अधिक होने के कारण इन्हें चावल सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इन क्षेत्रों में जापान ही एकमात्र विकसित देश है, बाकी सभी जनांकिकीय संक्रमण की अवस्था से गुजर रहे हैं और यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर विस्फोटक स्थिति में है।

5.4.2 यूरोप में उत्तरी – पश्चिमी के साथ मध्यवर्ती क्षेत्र

जनसंख्या समूहन की दृष्टिकोण से यह विश्व का दूसरा विशाल क्षेत्र है। इस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी – पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोप में स्थित ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, पोलैण्ड, यूगोस्लाविया, पुर्तगाल, रोमानिया, नीदरलैण्ड, हंगरी एवं बेल्जियम इत्यादि देश सम्मिलित हैं। इन देशों की संपूर्ण जनसंख्या लगभग 42 करोड़ है, जो विश्व के 6.2% भाग का प्रतिनिधित्व करती है। भौगोलिक विस्तार की दृष्टिकोण से यह संकुल 40० से 60० उत्तरी अक्षांशों के मध्य विस्तृत है, जबकि इसकी सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण 50० उत्तरी अक्षांश के आसपास है। इन्हीं अक्षांशों के बीच यूरोप का महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र भी स्थित है, जो औद्योगीकरण का आधार है। औद्योगीकरण से पूर्व यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या नदी घाटियों में निवास करती थी क्योंकि वहाँ कृषि कार्य से भोजन एवं आजीविका के स्रोत उपलब्ध हो जाते थे। औद्योगिक क्रांति के पश्चात विविध प्रकार के उद्योगों ने जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यहाँ प्रारंभ होने वाले औद्योगिक विकास सदी के अंत तक महाद्वीप को उद्योग प्रधान बना दिए । तटीय सुगमता के कारण उत्तरी – पश्चिमी यूरोप में सर्वाधिक नगरीय विकास हुआ है। इन देशों की जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि ये देश जनसंख्या संक्रमण की प्रथम अवस्था से आज से लगभग 200 वर्ष पहले ही मुक्त हो चुके हैं तथा वर्तमान समय में अंतिम अवस्था से गुजर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी है। यहाँ की जनसंख्या वृद्धि लगभग रुक गई है या फिर भी यहाँ उच्च जनसंख्या संकेंद्रण पाया जाता है।

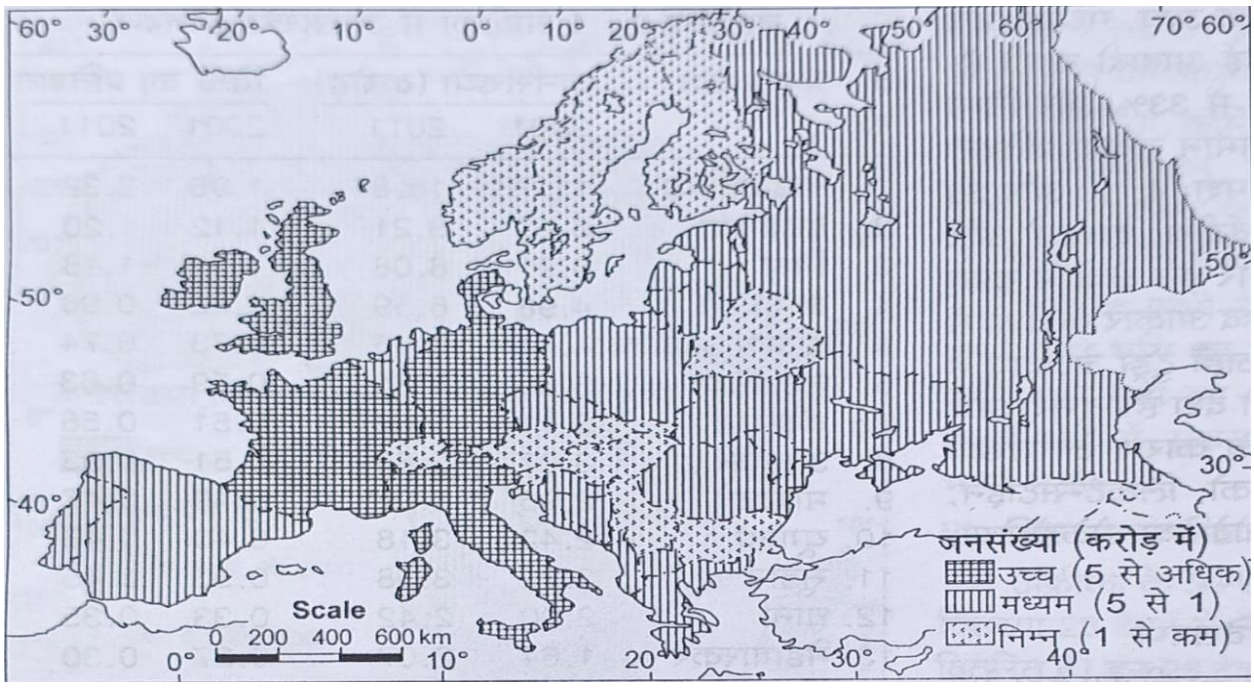

चित्र संख्या 5.2 यूरोप में जनसंख्या का वितरण.

5.4.3 अमेरिका का उत्तर – पूर्वी क्षेत्र

कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी तट विश्व का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या संकेंद्रण वाला संकुल है। भौगोलिक विस्तार की दृष्टिकोण से यह प्रदेश एशिया तथा यूरोपीय जन समूह क्षेत्र से छोटा है, परंतु यह प्रदेश नवीनतम है। इसका विकास नवीनतम संकल्पनाओं एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित है। यहाँ की सर्वाधिक जनसंख्या यूरोपीय मुल्क की है और प्रवास करके आयी है, जिसके कारण यहाँ की संस्कृति भी यूरोपीय है। अमेरिका के पूर्वी भाग में पाए जाने वाले कोयला एवं लौह अयस्क ने यहाँ औद्योगिक करण को आधार प्रदान किया है। नदियों, झीलों तथा तटीय अवस्थित के कारण परिवहन की सुविधा सुगम हो जाती है। भौगोलिक वितरण के आधार पर यदि देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या 100० पश्चिमी देशांतर के पूर्वी भाग में पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या संकेंद्रण के चार प्रमुख केंद्र हैं जो निम्नलिखित हैं –

1. मेन से मेरीलैण्ड तक अटलांटिक तटीय क्षेत्र।
2. पिट्सवर्ग से ओहायो तक का क्षेत्र।
3. प्रमुख झील प्रदेश जिसके अंतर्गत मिशीगन, ह्यूरन, इरी एवं ओंटारियो के तटीय भाग आते हैं।
4. कनाडा का सेंट लॉरेंस नदी घाटी प्रदेश

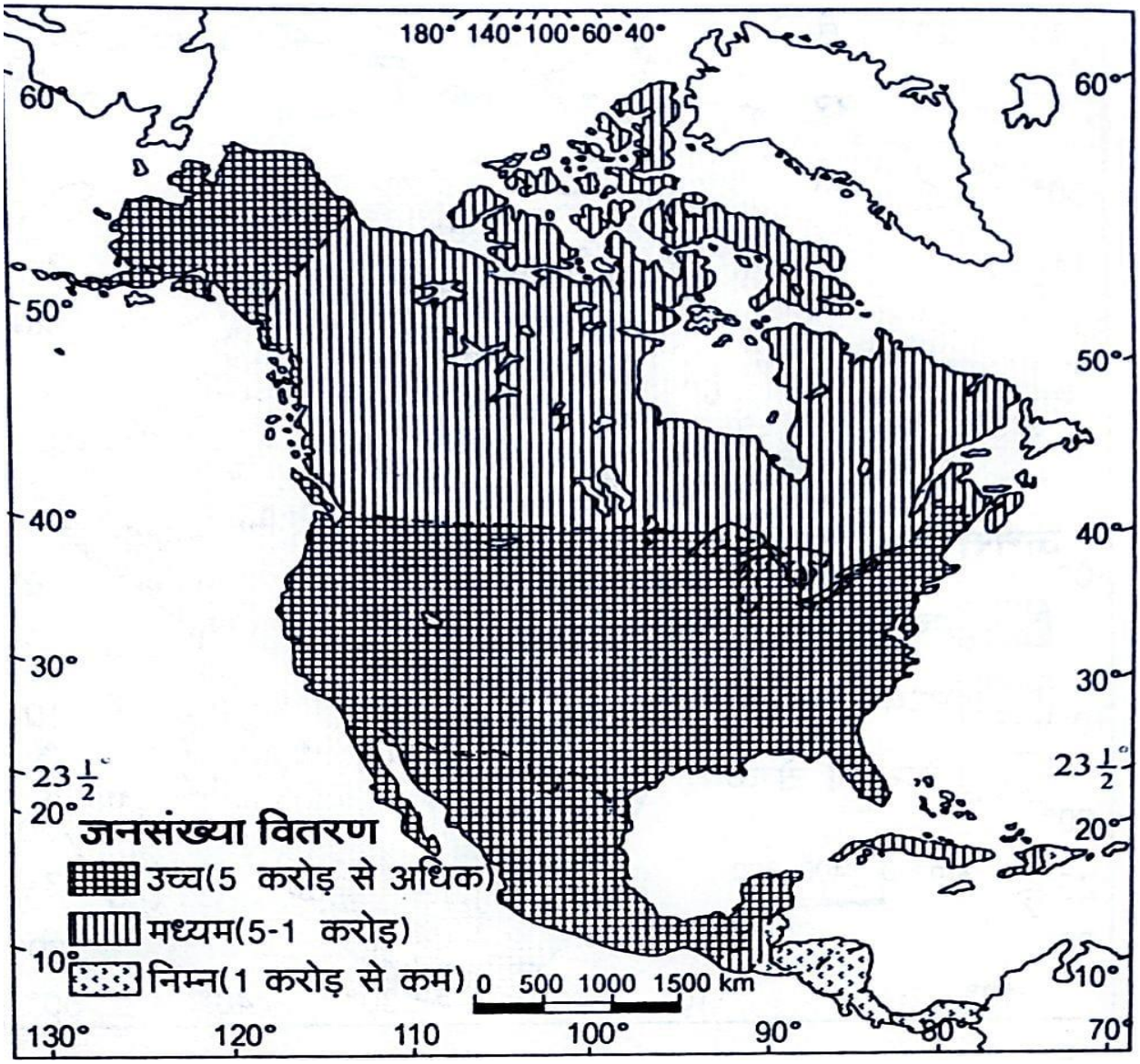

चित्र संख्या 5.3 उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या का वितरण.

संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा का यह प्रदेश न केवल औद्योगिक रूप से बल्कि कृषि के क्षेत्र से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कृषि उत्पादकता भी उच्च स्तरीय पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण सर्वाधिक पाया जाता है। अमेरिकी जन समूह की सांस्कृतिक विशेषताएं यूरोप से पूर्णतः मेल खाती हैं। इस कारण यहाँ के लोग आर्थिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण से संपन्न है। यहाँ का भी जनांकिकीय संक्रमण अंतिम अवस्था में है, जिसके कारण जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही नियंत्रित है। विदेशी प्रवासियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके कारण यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर नहीं के बराबर है।

5.5 मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र

पृथ्वी के धरातल का स्वभाव सभी जगह पर एक समान नहीं है। किन्ही क्षेत्र में समतल धरातल तथा प्रचुर मात्रा में उच्चावच मिलते हैं। संसाधनों से भरपूर भी होते हैं। इसके साथ ही साथ में अधिक मात्रा में आबादी को संभाल सकते हैं वहाँ अधिक जनसंख्या पाई जाती है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जो प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आधार पर अधिक जनसंख्या के वास योग्य नहीं होते हैं अर्थात अधिक आबादी को संभालने योग्य नहीं होते हैं, परंतु वे मानव अधिवास के लिए एकदम अनुपयोगी भी नहीं होते हैं। ऐसी दशाओं में ये क्षेत्र मध्य जनसंख्या बसाव के प्रतिरूप को अभिव्यक्त करते हैं। मध्यम जनसंख्या के वितरण वाले क्षेत्र सभी महाद्वीपों में विस्तारित हैं। भौगोलिक विस्तार की दृष्टिकोण से ये क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे होते है। भौगोलिक अवस्थित, प्राकृतिक दशाओं तथा मानव बसाव हेतु अधिक अनुकूल नहीं होने के कारण ये प्रदेश अधिक आबादी को संभालने योग्य नहीं है, परंतु मानव अधिवास के लिए पूर्णतः अनुपयोगी भी नहीं होते हैं। सभी महाद्वीपों में इनके वितरण को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है –

अ. एशिया : एशिया महाद्वीप में मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र का वितरण भूमध्य सागरीय प्रदेश के पूर्वी भाग के देशों में एक विस्तृत क्षेत्र पर पाया जाता है। प्राकृतिक स्वरूप की दृष्टिकोण से ये क्षेत्र पहाड़ी, पठारी एवं मरुस्थली प्रवृत्ति के हैं, जो जनसंख्या के बसाव हेतु सर्वोत्तम स्थितियों को प्रदर्शित नहीं करते। यह क्षेत्र संसाधनों की उपलब्धता एवं यातायात की साधनों की सुगमता के दृष्टिकोण से भी उतने सशक्त नहीं होते हैं। यहाँ मानव की आवश्यकता हेतु वस्तुओं की आपूर्ति आसानी से नहीं की जा सकती है।

ब. यूरोप : यूरोप के भूमध्यसागरीय प्रदेश के देशों में भी मध्यम जनसंख्या वितरण के क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ की भूमि कृषि के लिए उपजाऊ नहीं है क्योंकि अधिकांश उच्चावच पहाड़ी एवं पठारी है। यह क्षेत्र रसदार फलों के उत्पादन हेतु काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बागवानी कृषि का विस्तार पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ बड़े उद्योगों का विकास नहीं हुआ है और यह क्षेत्र मध्यम जनसंख्या के वितरण का स्वरूप प्रदर्शित करते हैं।

स. अफ्रीका : अफ्रीका महाद्वीप की भौगोलिक अवस्थिति ही उसे मानव बसाव हेतु अनुकूलता नहीं प्रदान करती है। यही कारण है कि यहाँ के लगभग 23 देशों में मध्यम जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। इस मध्यम जनसंख्या वितरण का कारण वहाँ का पहाड़ी, पठारी एवं मरुस्थलीय स्वरूप है। यहाँ के मध्यम बसाव वाले देशों में तंजानिया प्रमुख है जहाँ टैगानिका पठार उसके विस्तृत क्षेत्रफल को आच्छादित किया हुआ है। इसी प्रकार अन्य देशों जैसे कीनिया में किलिमंजारो पठार, मोरक्को में एटलस पर्वत श्रेणी, अल्जीरिया में सहारा मरुस्थल का विस्तार के साथ ही चाड से लीबिया तक के देशों में इस मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ अनेक छोटे – छोटे भौगोलिक प्रतिकूल दशाओं वाले देशों के नाम भी हैं, जहाँ मध्य जनसंख्या पाई जाती है।

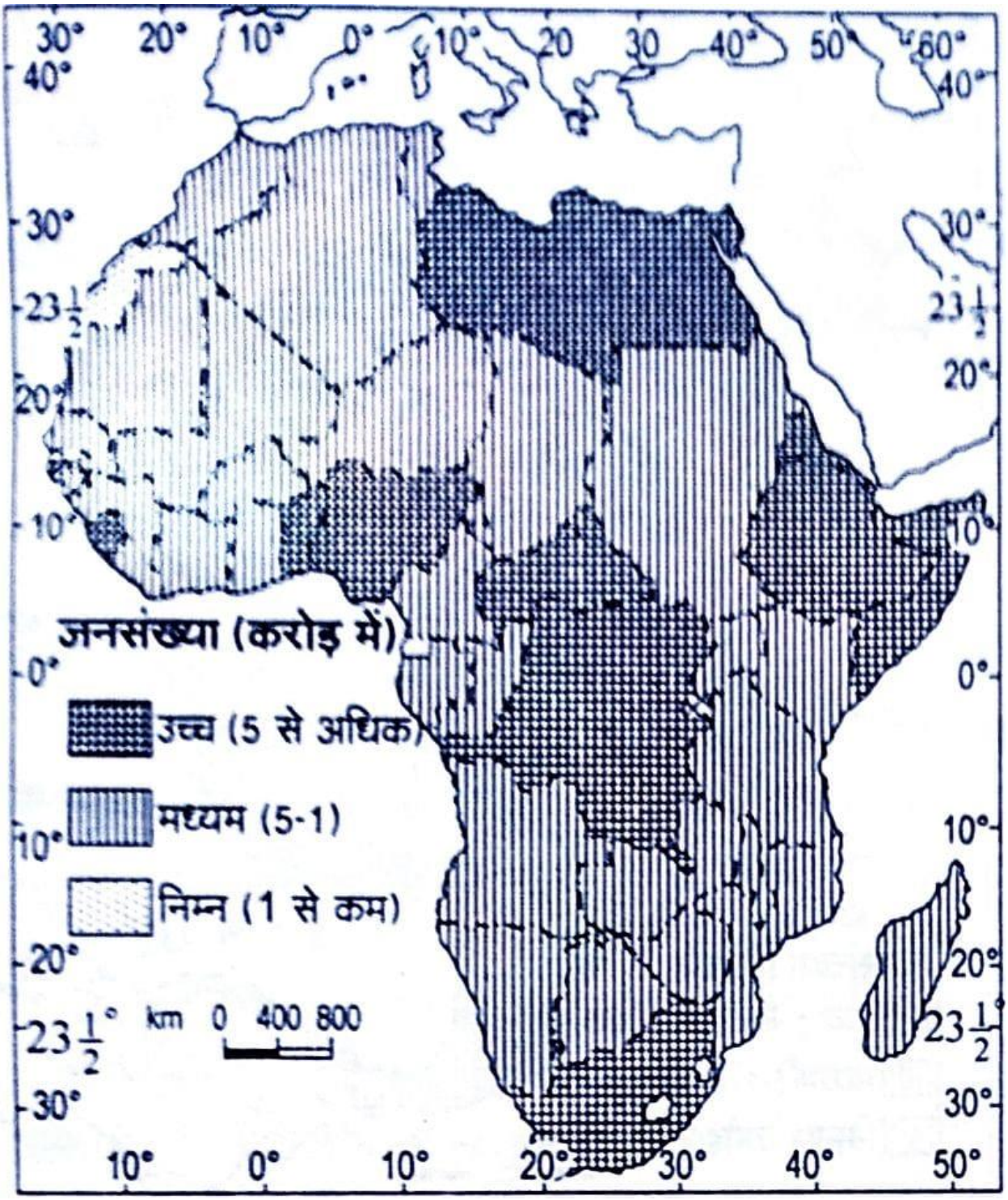

चित्र संख्या 5.4 अफ्रीका में जनसंख्या का वितरण.

द. **उत्तरी अमेरिका** : उत्तरी अमेरिका के मध्य पूर्व भाग में मध्यम जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। यहाँ पर मुख्यतः कृषि प्रदेश का विस्तार अधिकांश भागों पर पाया जाता है। इन प्रदेशों में कनाडा का सेंट लॉरेंस क्षेत्र, प्रेयरी का मैदानी भाग एवं पश्चिमी अमेरिका के प्रशांत महासागरीय क्षेत्र सम्मिलित हैं। जहाँ मध्यम जनसंख्या निवास करती है। इसके अतिरिक्त मध्य अमेरिका, मैक्सिको तथा पश्चिमी द्वीप समूह में भी मध्यम जनसंख्या का वितरण पाया जाता है।

य. **दक्षिण अमेरिका :** दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग की भौगोलिक स्थिति भी भूमध्यरेखीय है। शेष भाग के अधिकांश भू–भाग पर पर्वत एवं पठार का विस्तार पाया जाता है। यही कारण है कि दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों या देशों में मध्यम जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। यहाँ मध्यम जनसंख्या के वितरण वाले देशों में अर्जेंटीना, कोलंबिया, वेनेजुएला, पेरू, चिली, बोलिविया एवं इक्वेडोर आदि सम्मिलित हैं। उच्चावच वितरण के दृष्टिकोण से देखने पर मिलता है कि कोलंबिया की अवस्थिति एंडीज पर्वत पर है। अर्जेंटीना के पश्चिमी भाग पर पेंटागोनिया पठार का विस्तार पाया जाता है तथा पेरू का अधिकांश भू–भाग भी पर्वतीय है। इसके अतिरिक्त शेष अन्य देशों का भौगोलिक विस्तार एवं निवास हेतु परिस्थितियां प्रतिकूल पाई जाती हैं।

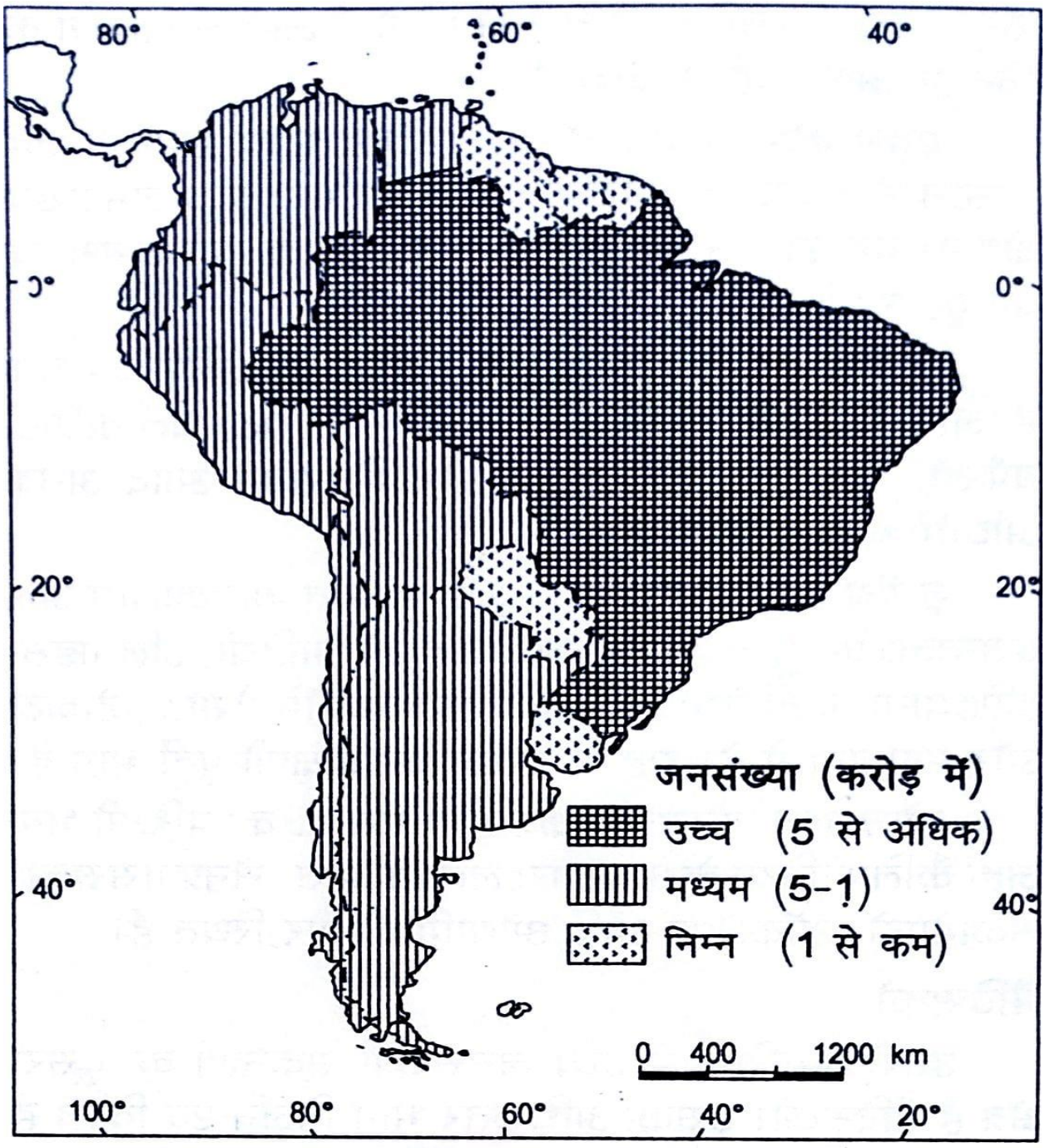

चित्र संख्या 5.5 दक्षिणी अमेरिका में जनसंख्या का वितरण.

र. **ऑस्ट्रेलिया** : आस्ट्रेलिया महाद्वीप के अधिकांश भू–भाग पर पहाड़ियों एवं मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। इसी का परिणाम है कि संपूर्ण आस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि पर मध्यम जनसंख्या का वितरण पाया जाता है।

5.6 अल्प तथा अत्यल्प जनसंख्या वितरण वाले क्षेत्र

अल्प जनसंख्या वितरण वाले क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे भू–भाग सम्मिलित होते हैं, जहाँ पर जनसंख्या का बसाव सघन एवं मध्यम क्षेत्र की तुलना में काम होता है। ये प्रदेश कभी भी जनशून्य नहीं होते है। यहाँ कुछ न कुछ जनसंख्या अवश्य पाई जाती है। यहाँ पर कम जनसंख्या पाए जाने का कारण है ऐसे क्षेत्रों का भू विन्यास, जलवायु, मिट्टी, कृषि, जलापूर्ति, संसाधनों का अभाव, विषम भौगोलिक परिस्थितियां इत्यादि जो मानव समूहों के निवास के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव बड़े समूह में न होकर छोटे – छोटे बिखरे समूह में पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों का वितरण प्रायः सभी महाद्वीपों में पाया जाता है। जहाँ निम्न जनसंख्या निवास करती है वे प्रदेश निम्नवत है –

अ. **एशिया** : क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की विशालता के कारण एशिया के संपूर्ण भाग पर जनसंख्या का एक समान वितरण नहीं पाया जाता है। यहाँ निम्न जनसंख्या वितरण वितरण छोटे क्षेत्रफल एवं आकार वाले देश उष्ण मरुस्थलीय एवं शीत मरुस्थलीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इत्यादि में पाई जाती है। यहाँ छोटे क्षेत्रफल वाले देशों में लाओस, इजराइल, कुवैत, लेबनान, जॉर्डन, बहरीन एवं कतर आते हैं। शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में तुर्कमेनिस्तान, ईरान एवं ओमान सम्मिलित हैं। इसी प्रकार शीत मरुस्थलीय क्षेत्र वाले देश में रूस, मंगोलिया, एवं कजाकिस्तान के भू–भाग सम्मिलित होते हैं।

ब. **यूरोप** : यूरोप महाद्वीप में निम्न जनसंख्या का वितरण पर्वतीय, अतिशीत, दलदली एवं वनीय क्षेत्र में पाया जाता है। इसी प्रकार यहाँ छोटे आकार वाले देश में भी कम जनसंख्या पाई जाती है। टुंड्रा प्रकार की जलवायु वाले देश में मुख्य रूप से उत्तरी रूस, फिनलैंड, नार्वे एवं स्वीडन के भू–भाग आते हैं। यहाँ की पर्यावरणीय दशाएं पूर्णतः मानव बसाव हेतु प्रतिकूल होती हैं। कुछ लघु आकार वाले देश जैसे मोनाको, एंडोरा, सानमेरिनों, स्लोवेनिया एवं आइसलैंड में भी कम जनसंख्या का वितरण देखने को मिलता है।

स. **अफ्रीका** : भू स्वरूप में अति विषमता, उबड़ – खाबड़ उच्चावच, प्रतिकूल जलवायु दशाएं एवं अत्यधिक भाग पर उष्णकटिबंधीय प्रदेश के विस्तार के कारण अफ्रीका महाद्वीप के लगभग आधे देशों में निम्न जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। इनमें से प्रमुख देश हैं रवांडा, गिनिया, चाड, जिम्बाम्बे, जांबिया, सेनेगल, इक्वेडोर, नाइजर मलावी एवं माले इत्यादि।

द. **उत्तरी अमेरिका** : उत्तरी अमेरिका का अल्प जनसंख्या वितरण का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कनाडा के उत्तरी भाग में पाया जाता है। यहाँ कम वितरण का मुख्य कारण विषम उच्चावच एवं शीत जलवायु है। इसके अतिरिक्त कुछ छोटे क्षेत्रफल वाले देश भी हैं जिनमें डोमिनिका, एंटीगुआ, क्रिस्टोफर, बरमूडा, सामोआ, बेलीज, जमैका, बहामा, एल साल्वाडोर, पनामा एवं कोस्टारिका इत्यादि सम्मिलित हैं। यहाँ भी जनसंख्या का वितरण निम्न स्तरीय पाया जाता है।

य. **दक्षिणी अमेरिका** : दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश भाग पर भूमध्य रेखीय जलवायु के विस्तार के कारण प्रतिकूल जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। यही कारण है कि ब्राजील के उत्तर एवं दक्षिण में स्थित अधिकांश छोटे – छोटे देशों में अल्प जनसंख्या वितरण पाया जाता है। इन देशों में सेंट विंसेंट, ग्रेनेडा, सेंट लूसियाना, गायना, मोंटेग्रो, सूरीनाम, बाराबडोस, त्रिनिडाड, उरुग्वे एवं पैराग्वे आदि देश सम्मिलित हैं। जहाँ एक तरफ उच्चावच पर्वतीय एवं पठारी होने के कारण कृषि हेतु अनुप्रयुक्त होता है, दूसरी तरफ इन क्षेत्रों में औद्योगिक करण एवं नगरीकरण का स्तर भी निम्न स्तरीय पाया जाता है। जिसके कारण जनसंख्या का वितरण अत्यंत निम्न अंकित किया जाता है।

5.7 जनरिक्त जनसंख्या वितरण वाले क्षेत्र

पृथ्वी के धरातल पर मानव का वितरण बहुत ही आसमान है। जनसंख्या किन्हीं भागों में सघन पाई जाती है तो किन्हीं भागों में विरल। पृथ्वी के धरातल पर कुछ ऐसे भी क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ जनसंख्या एकदम शून्य पाई

जाती है। ऐसे क्षेत्र जनशून्य के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि यहाँ पर मानव के निवास, विकास एवं प्रगति हेतु आवश्यक परिस्थितियां नहीं पाई जाती हैं। इसकी भौगोलिक दशाएं मानव विकास के लिए अनुकूल नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में यहाँ मानव सभ्यता का विकास नहीं हो पाया है। यह क्षेत्र अभी भी वीरान बने हुए हैं। वैज्ञानिक खोजों एवं प्रगति के बावजूद भी प्रकृति की प्रतिकूलता यहाँ पर इतनी अधिक पाई जाती है कि संपूर्ण क्षेत्र में जनसंख्या के लिए आवश्यक अनुकूल दशाएं निर्मित नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में संपूर्ण ब्रह्मांड में आठ ऐसे वृहद क्षेत्रों की पहचान की गई है, जहाँ जनसंख्या के निवास हेतु भौगोलिक परिस्थितियां विद्यमान नहीं है और यह क्षेत्र गैर अधिवास के नाम से जाने जाते हैं। इस विशाल भू–भाग पर शायद ही कोई जनसंख्या निवास करती हो । यह क्षेत्र निम्नलिखित हैं –

अ. **अफ्रीका एवं एशिया के मरुस्थलीय क्षेत्र** : यह क्षेत्र भौगोलिक विस्तार की दृष्टिकोण से उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक महासागर तट से लेकर पूर्व में हिंद महासागर के तट तक लगभग 10,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। इस वृहद मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत सहारा मरुस्थल, अरब मरुस्थल एवं पाकिस्तान – अफगानिस्तान होते हुए एशिया के मध्य तक विस्तृत प्रदेश पाए जाते हैं। इसके बीच में स्थित केवल नील घाटी में छोटे – छोटे समूह में वितरित जनसंख्या पाई जाती है, जहाँ मानव के निवास हेतु कुछ अनुकूल परिस्थितियां देखी जाती हैं। इस जनशून्य प्रदेश का विस्तार पृथ्वी के लगभग 20% भाग पर पाया जाता है। यह प्रदेश भौगोलिक दृष्टिकोण से अति उष्ण प्रकार का है, जिसके कारण यहाँ मानव के निवास हेतु अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां निर्मित नहीं हो पाती हैं और यह प्रदेश जनशून्य बना हुआ है।

ब. **उत्तरी साइबेरिया** : उत्तरी साइबेरिया का भौगोलिक विस्तार यूरोप एवं एशिया महाद्वीप में नार्वे के अटलांटिक महासागर तट से लेकर प्रशांत महासागर के कमचटका तक विस्तृत है। इस संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार लगभग 6,000 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। यह प्रदेश अतिशीत जलवायु विशेषताओं से आच्छादित है, जिसके कारण यहाँ मानव निवास हेतु प्रतिकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं और यह प्रदेश जनशून्य बना हुआ है।

स. **उत्तरी अमेरिका** : उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भू–भाग मानव अधिवास हेतु पूरी तरह से अनुपयुक्त है। इसी कारण यहाँ का क्षेत्र जनशून्य प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी अलास्का, उत्तरी ग्रीनलैंड एवं उत्तरी कनाडा के भाग सम्मिलित हैं। इस विस्तृत क्षेत्र की जलवायु अति विषम परिस्थितियां प्रस्तुत करती हैं जिसके कारण अमेरिका जैसे विकसित देश के समीप होने के बावजूद भी यहाँ जनसंख्या का अधिवास नहीं पाया जाता है और यह प्रदेश जनशून्य में परिवर्तित हो गया है।

द. **अंटार्कटिका** : अंटार्कटिका प्रदेश का विस्तार दक्षिणी ध्रुव के चतुर्दिक पाया जाता है। यह प्रदेश विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जाना जाता है इसका अधिकांश भाग वर्फ से ढका हुआ है, जिसके कारण यहाँ की जलवायु अतिशीत प्रकार की पाई जाती है। इस संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 13,720 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। प्राचीन समय से यह क्षेत्र जनशून्य बना हुआ है परंतु वर्तमान समय में वैज्ञानिक शोध कार्यों के कारण यहाँ अधिवास बनाए गए हैं परंतु यहाँ पर स्थाई अधिवास नहीं पाया जाता है।

य. **अमेजन बेसिन** : अमेजन बेसिन अपनी उष्णकटिबंधीय भौगोलिक परिस्थितियों के लिए जानी जाती है, जिसका विस्तार मुख्यतः दक्षिण अमेरिका में ब्राजील और उसके आस पास के देशों में पाया जाता है। यहाँ की जलवायु अति विषम प्रकार की है जिसमें मानव के निवास हेतु भौगोलिक परिस्थितियां बहुत कम पाई जाती हैं। यही कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर क्षेत्रफल वाले इस वृहद प्रदेश में जनसंख्या का वितरण बहुत कम पाया जाता है और यह क्षेत्र जनशून्य बना हुआ है।

र. **ओसिनिया** : ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग एक वृहद मरुस्थल है जहाँ मानव अधिवास हेतु परिस्थितियां लगभग नगण्य हैं। यह वृहद प्रदेश अपनी रेतीली भूमि के कारण जाना जाता है। इस मरुस्थल के अंतर्गत गिब्बन मरुभूमि एवं ग्रेट विक्टोरिया मरुभूमि का भाग सम्मिलित है। यह प्रदेश पूरी तरह से जनशून्य है। इसके अंतर्गत पापुआ न्यू गिनी का पर्वतीय क्षेत्र भी सम्मिलित होता है जो पूरी तरह से जनशून्य है।

ल. **दक्षिण पश्चिम अफ्रीका** : दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का क्षेत्र विषम परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। इसके अंतर्गत नामीबिया, बोत्सवाना क्षेत्र में विस्तृत कालाहारी मरुस्थल विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

उष्णकटिबंधीय प्रदेश की समीपता के कारण तथा ठंडी जल धाराओं के समीप होने के कारण यह प्रदेश एक विस्तृत मरुस्थल में परिवर्तित हो गया है, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या लगभग नहीं में पाई जाती है।

व. **दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी छोर** :यह प्रदेश दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना एवं उसके आसपास के देशों में विस्तृत है। इन देशों में एंडीज पर्वत श्रृंखला एवं पैटागोनिया पठार का विस्तार पाया जाता है। यह स्वरूप भौगोलिक परिस्थितियों की दृष्टिकोण से विषम स्थितियां उत्पन्न करता है जिसके कारण यहाँ जनसंख्या लगभग शून्य पाई जाती है।

5.8 सारांश

आपने इस इकाई में जनसंख्या का विश्व – वितरण, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र अल्प तथा अत्यल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र, जनरिक्त क्षेत्र का अध्ययन किया है। आप समझ गए होगें कि जनसंख्या के वैश्विक वितरण पर किसी स्थान विशेष की भौगोलिक परिस्थितियों से घनिष्ट संबंध है। जिन स्थानों पर जीवन यापन के साधन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं वहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक कारकों की उपलब्धता की प्रतिकूलता जैसे – जैसे बढ़ती जाती है जनसंख्या का संकेन्द्रण अथवा जमाव घटता जाता है। जहाँ मानव निवास हेतु प्रतिकूलता चरम पर होती है, वे क्षेत्र जनरिक्त होते है। वास्तव में किसी स्थान की जनसंख्या वहाँ का सबसे बड़ा संसाधन होती है जो उसकी भौगोलिक अवस्थिति, सरकारी नीतियों, सांस्कृतिक संगठन आदि के आधार पर वास्तविकता को प्राप्त करती है।

5.9 स्वमूल्यांकन प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

1. वर्ष 2011 में सम्पूर्ण विश्व की जनसंख्या कितनी थी ।

   (क) 600.31 करोड़ (ख) 682.38 करोड़ (ग) 700.00 करोड़ (घ) 785.32 करोड़

2. उत्तरी गोलार्द्ध में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है ।

   (क) 60% (ख) 75% (ग) 88% (घ) 94%

3. निम्न में से कौन विश्व का अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है ।

   (क) एशिया में पूर्वी, दक्षिणी एवं दक्षिणी – पूर्वी क्षेत्र,

   (ख) यूरोप में उत्तरी – पश्चिमी के साथ मध्यवर्ती क्षेत्र,

   (ग) मध्य एवं उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र,

   (घ) अमेरिका में उत्तर – पूर्वी क्षेत्र,

4. किस महाद्वीप के सम्पूर्ण भाग पर मध्यम जनसंख्या वितरण पाया जाता है ।

   (क) एशिया (ख) यूरोप (ग) अफ्रीका (घ) आस्ट्रेलिया

5. आमेजन बेसिन प्रदेश में किस प्रकार का जनसंख्या वितरण पाया जाता है ।

   (क) अधिक जनसंख्या (ख) मध्यम जनसंख्या (ग) न्यून जनसंख्या (घ) जनशून्य

5.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

Bogue] D- J-] 1969] Principles of Demography] John Wiley] N-Y-

Clarke] John I-] 1973] Population Geography] Pergaman Press] Oxford-

Crook] Nigel] 1997] Principles of Population and Development] Pergaman Press] N- Y-

Garmier] J- B-] 1970] Geography of Population] Longman] London-

Mamoria] C- B-] 1981] India's Population Problem] Kitab Mahal] New Delhi-

Premi] M- K-] 1991] India's Population] Heading Towards a Billion] B- R- Publishing Corporation-

Blassoff] M- and Srinivasan K-] 2001] Population Development Nexus in India : Challenges for the New Millennium] Tata McGraw Hill] New Delhi-

Woods] R-] 1979] Population Analysis in Geography] Longman] London-

Zelinsky] W-] 1966] A Prologue to Population Geography] Prentice Hall-

चन्दना, आर. सी., 2022, जनसंख्या भूगोल – संकल्पना, नियंत्रक व विश्व प्रारूप, कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

चन्दना, आर. सी., 2022, भारत : जनसंख्या (जनसंख्या भूगोल – भाग 2), कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

मौर्या, एस. डी., 2005, जनसंख्या भूगोल, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद.

ओझा, आर. पी., 1984, जनसंख्या भूगोल, प्रतिभा प्रकाशन.

हीरा लाल, 2000, जनसंख्या भूगोल के मूल तत्व, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली.

तिवारी, राम कुमार, 2023, जनसंख्या भूगोल, प्रवालिका पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद.

5.11 अभ्यास प्रश्न (सत्रांत परीक्षा की तैयारी)

1. जनसंख्या वितरण के वैश्विक परिदृश्य की व्याख्या कीजिए?
2. विश्व के अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों का वर्णन कीजिए?
3. विश्व के मध्यम जनसंख्या वितरण वाले क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए?
4. किसी क्षेत्र में अल्प तथा अत्यल्प जनसंख्या वितरण हेतु उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए?
5. जनरिक्त प्रदेशों में मानव निवास की संभावनाओं पर प्रकाश डालिए?

इकाई–6 जनसंख्या घनत्व – प्रकार, जनसंख्या घनत्व का विश्व वितरण

इकाई की रूपरेखा

6..0 प्रस्तावना

6.1 उद्देश्य

6.2 जनसंख्या घनत्व

6.3 जनसंख्या घनत्व के प्रकार

6.4 जनसंख्या घनत्व का विश्व वितरण

6.5 सारांश

6.6 स्वमूल्यांकन प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

6.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

6.8 अभ्यास प्रश्न (सत्रांत परीक्षा की तैयारी

6.0 प्रस्तावना

धरातल के किसी निश्चित भूभाग का क्षेत्रफल तथा उसके अंतर्गत निवास करने वाली जनसंख्या के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। सभी भूगोलवेत्ताओं ने जनसंख्या वितरण तथा जनसंख्या घनत्व का एक साथ अध्ययन किया है। सभी विद्वान इस बात से सहमत है कि जनसंख्या का वितरण और घनत्व आपस में अंतर्संबंधित होते हैं । जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व की व्याख्या करते हुए बी. पी. पांडा लिखते हैं कि जनसंख्या वितरण का अर्थ पृथ्वी पर जनसंख्या के विक्षेपण से है और जनसंख्या घनत्व जनसंख्या के केंद्रीयकरण का माप है। उनके अनुसार जनसंख्या के अध्ययन में भूमि एवं जनसंख्या दो घटक हैं, जिनका आपस में संबंध, वितरण एवं घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। हीरालाल ने अपनी पुस्तक जनसंख्या भूगोल में लिखा है वस्तुतः पृथ्वी पर मानव के वितरण संबंधी विभिन्नताओं की व्याख्या के लिए उपयोगी संक्षेपण के रूप में जनसंख्या घनत्व से विशेष सहायता मिलती है

6.1 उद्देश्य

सामान्य शब्दों में जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य किसी स्थान विशेष के क्षेत्रफल एवं वहाँ निवास करने वाली सम्पूर्ण जनसंख्या के अनुपात से होता है, जबकि वास्तविकता में जनसंख्या घनत्व उस क्षेत्र के सम्पूर्ण संसाधनों पर दबाव को अभिव्यक्त करता है। इस इकाई के उद्देश्य निम्नलिखित है –

1. जनसंख्या घनत्व की संकल्पना एवं जनसंख्या घनत्व के प्रकार को स्पष्ट करना।
2. जनसंख्या घनत्व के विश्व वितरण की व्याख्या करना।

6.2 जनसंख्या घनत्व

प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता के. ब्रूंस एवं न्यूहोल्ड लिखते हैं कि जनसंख्या वितरण का सामान्य मापन जनसंख्या घनत्व होती है। वास्तव में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व में विशेष अंतर्संबंध पाया जाता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से जनसंख्या का अध्ययन करने पर वितरण एवं घनत्व दो भिन्न – भिन्न तथ्य प्रकट होते हैं। जहाँ जनसंख्या वितरण जनसंख्या की स्थितिगत अध्ययन पर बोल देता है वहीं घनत्व अनुपातिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वितरण से जनसंख्या के क्षेत्रीय स्वरूप (केंद्रीय, जमघट, विकीर्ण, रेखीय) का बोध होता है तो घनत्व में जनसंख्या का संबंध क्षेत्रफल से जोड़कर देखा जाता है। जनसंख्या वितरण में जहाँ सिर्फ जनसंख्या की संरचना मुख्य होती है वहीं घनत्व में जनसंख्या और क्षेत्रफल के संबंध का अध्ययन किया जाता है।

किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल अथवा प्रदेश में जनसंख्या की मात्रा से जनसंख्या के वितरण की सार्थकता एवं सही जानकारी नहीं मिल पाती है। इसके लिए आवश्यक होता है भूमि और जनसंख्या के सही संबंधों को जानने के लिए क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की अनुपात का अध्ययन किया जाए । सामान्य शब्दों में जनसंख्या घनत्व का अर्थ जनसंख्या का जमाव ज्ञात करने का एक तरीके के रूप में प्रयोग किया जाता है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य जनसंख्या का जमाव नहीं बल्कि जनसंख्या का क्षेत्रफल पर दबाव है।

विजय कुमार तिवारी ने अपनी पुस्तक जनसंख्या भूगोल में लिखा है मानव और भूमि अंततः मानव समुदाय का जीवन तत्व है, जिसका अर्थ होता है कि एक निश्चित भूभाग के संपूर्ण क्षेत्रफल एवं उस पर निवास करने वाली संपूर्ण जनसंख्या का अनुपात क्या है। जनसंख्या घनत्व को प्रति हेक्टेयर, प्रति वर्ग किलोमीटर एवं प्रति वर्ग मील में ज्ञात किया जाता है। किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व वहाँ उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन तथा आर्थिक विकास के स्तर से प्रत्यक्षतः प्रभावित होता है।

आर. सी. चांदना ने अपनी पुस्तक जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या घनत्व की विस्तृत व्याख्या की है। वे मानते हैं कि जनसंख्या घनत्व एक विस्तृत संकल्पना है, जिसका अध्ययन करना प्रत्येक भूगोलवेत्ता का नैतिक कार्य होता है। उनका यह भी मानना है कि जनसंख्या की असमानता का अध्ययन और विश्लेषण तथा दो प्रदेशों की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन के साथ जनाधिक्य एवं जन अभाव के कारण और परिणाम क्या है। जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र के प्रादेशिक नियोजन में भी सहायक होते हैं। यह किसी स्थान की वर्तमान एवं भावी स्थिति एवं प्रगति का अध्ययन करने में सहायक होता है। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन सीमित होते हैं, जिनका उपयोग उसे क्षेत्र की जनसंख्या अपने जीवन निर्वाह हेतु करती है। इन्हीं संसाधनों के आधार पर उस क्षेत्र का जीवन स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय निर्धारित होती है।

6.3 जनसंख्या घनत्व के प्रकार

जनसंख्या अध्ययन के आधारभूत तत्वों में जनसंख्या घनत्व भी महत्वपूर्ण घटक है। यह जनसंख्या एवं भूमि का अनुपात होता है। इस अनुपात को अलग – अलग मानकों जैसे कुल जनसंख्या, कृषिगत जनसंख्या, ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या आदि आधारों पर ज्ञात किया जाता है। अतः इसके प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं –

6.3.1 अंकगणितीय घनत्व

किसी क्षेत्र या प्रदेश के कुल क्षेत्रफल तथा वहाँ निवासित कुल जनसंख्या का अनुपात अंकगणितीय घनत्व कहलाता है। इसके माध्यम से प्रति इकाई क्षेत्रफल (प्रति वर्ग किलोमीटर अथवा प्रति वर्ग मील) में अधिवासित लोगों की औसत संख्या का बोध होता है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो यह मनुष्य एवं भूमि का साधारण अनुपात होता है, जिसकी गणना निम्नलिखित सूत्र की सहायता से की जाती है –

अंकगणितीय घनत्व = प्रदेश कि कुल जनसंख्या / प्रदेश का कुल क्षेत्रफल

अंकगणितीय घनत्व की गणना विधि बहुत ही सरल है। इसे कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। जनसंख्या का यह घनत्व किसी क्षेत्र विशेष में व्यक्तियों की औसत संख्या का बोधक होता है, जिसे सामान्यतः पूर्णांक के रूप में लिखा जाता है। यह घनत्व कई उपवर्गों में भी विभक्त है, जो निम्नलिखित है –

सारणी 6.1 अंकगणितीय घनत्व के विविध मापन

क्र. सं.	अंकगणितीय घनत्व के उपवर्ग	ज्ञात करने के सूत्र
1.	मानव जातीय घनत्व	किसी क्षेत्र की कुल जातीय जनसंख्या / उस क्षेत्र का क्षेत्रफल
2.	लैंगिक घनत्व	किसी क्षेत्र की कुल स्त्री एवं पुरुष जनसंख्या / उस क्षेत्र का सम्पूर्ण क्षेत्रफल
3.	साक्षारता घनत्व	किसी क्षेत्र की कुल साक्षर जनसंख्या / उस क्षेत्र का सम्पूर्ण

		क्षेत्रफल
4.	ग्रामीण या नगरीय घनत्व	किसी क्षेत्र की कुल ग्रामीण या नगरीय जनसंख्या / उस क्षेत्र का सम्पूर्ण क्षेत्रफल
5.	गरीबी का घनत्व	किसी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे की कुल जनसंख्या / उस क्षेत्र का सम्पूर्ण क्षेत्रफल
6.	औद्योगिक घनत्व	किसी क्षेत्र की उद्योगों में लगी जनसंख्या / उस क्षेत्र का सम्पूर्ण क्षेत्रफल

स्त्रोतः जनसंख्या भूगोल (तिवारी, 2023).

यह सभी क्षेत्रों हेतु आसानी से उपलब्ध हो जाता है यही कारण है कि विश्व के देशों, देश के राज्यों, जिलों के ग्रामों का तुलनात्मक अध्ययन करने हेतु यह सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है।

सर्वाधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय होने के साथ – साथ ही इसमें कुछ कमियां भी हैं। यह किसी क्षेत्र में जनसंख्या की सघनता के क्षेत्रीय स्वरूप को उचित तरह से नहीं व्यक्त करता है बल्कि संपूर्ण क्षेत्रफल के घनत्व को दर्शाता है। इससे इस बात का बोध होता है कि संपूर्ण क्षेत्रफल में एक ही घनत्व पाया जाता है जबकि उस क्षेत्र विशेष में पर्वत, पठार, दलदल, जलाशय एवं मरुस्थल जैसे जनशून्य क्षेत्र भी पाए जाते हैं। भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि इसके द्वारा घनत्व की गणना कितने भी लघु इकाई हेतु की जाए वह यथार्थ एवं प्रमाणित नहीं होती। इसका कारण यह है कि यदि गांव का भी घनत्व इस विधि के द्वारा निकाला जाए तो वह यह बताता है कि संपूर्ण गांव में जनसंख्या सामान्य रूप से वितरित है जबकि गांव के एक छोटे हिस्से में ही जनसंख्या रहती है तथा शेष भाग पर या तो खेती होती है या निर्जन है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जनसंख्या घनत्व द्वारा वितरण नहीं बल्कि एक क्षेत्र विशेष पर मनुष्य का दबाव ज्ञात किया जाता है।

6.3.2 कायिक घनत्व

इस घनत्व को कृषि घनत्व भी कहा जाता है क्योंकि इस घनत्व में यह गणना की जाती है कि किसी क्षेत्र विशेष की कृषि योग्य भूमि पर उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या का दबाव कितना है। यह अंकगणित घनत्व का संशोधित स्वरूप है जो उसकी तुलना में अधिक उपयोगी एवं सार्थक होता है। इसकी गणना के लिए कुल क्षेत्रफल के बजाय कृषि योग्य भूमि को शामिल किया जाता है। इस घनत्व से इस बात का बोध होता है कि किसी प्रदेश की प्रति इकाई कृषि भूमि पर औसत रूप से कितने मनुष्यों का भार है। इसकी गणना निम्नलिखित सूत्र की सहायता से की जाती है –

कायिक घनत्व = प्रदेश की कुल जनसंख्या / प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि

भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि कायिक घनत्व अंकगणितीय घनत्व से ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि इसमें कुल क्षेत्रफल में से गैर कृषिगत भूमि को हटा दिया जाता है। इसमें संपूर्ण जनसंख्या का दबाव केवल कृषि योग्य भूमि से ज्ञात किया जाता है। इससे आसानी से यह ज्ञात किया जाता है कि जनसंख्या का अधिक दबाव किस क्षेत्र में है। कुछ आलोचकों का मानना है कि कृषि सभी लोगों की आजीविका नहीं होती, उन्हें यह तर्क दिया जाता है कि भले ही लोग रोजगार, व्यापार, उद्योग एवं सेवा आदि से आजीविका प्राप्त करते हैं परंतु प्रत्येक व्यक्ति के खाद्यान्न की जरूरत की आपूर्ति कृषि से ही होती है। अतः ऐसी स्थिति में कोई क्षेत्र जनाधिक्य वाला है या जनशून्य है, का आकलन कायिक घनत्व से ही संभव होता है। कुछ भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि यह संकल्पना केवल कृषि प्रधान देश के लिए ही सही हो सकती है, जहाँ सबकी आजीविका कृषि है जबकि ऐसे देशों की वास्तविकता से अधिक दूर है जिनका आर्थिक आधार द्वितीय एवं तृतीयक क्रियाकलाप हैं।

6.3.3 कृषि घनत्व

कृषि घनत्व कायिक घनत्व का संशोधित एवं परिष्कृत स्वरूप है, जिसमें कुल कृषि योग भूमि तथा कृषि कार्य में संलग्न जनसंख्या के पारस्परिक संबंध को प्रकट किया जाता है। इससे इस बात का बोध होता है कि

किसी निश्चित कृषिगत भूमि पर कृषि कार्य में संलग्न कितनी जनसंख्या का दबाव है। इसकी गणना प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि से कृषि कार्य में लगी संपूर्ण जनसंख्या में भाग देने से की जाती है। इसके परिणाम के दौरान प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या में से कृषि कार्य में लगी जनसंख्या को अलग किया जाता है जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि होता है। इस प्रकार कृषि घनत्व प्रति इकाई भूमि पर आधारित व्यक्तियों की औसत संख्या को दर्शाता है अर्थात यह स्पष्ट करता है कि किसी क्षेत्र विशेष में कृषिगत भूमि पर कितनी कृषिगत जनसंख्या का दबाव है। इसके परिणाम हेतु निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है –

कृषि घनत्व = कृषि कार्य में संलग्न कुल कृषिगत जनसंख्या / उस क्षेत्र की कुल कृषि योग्य भूमि

किसी क्षेत्र विशेष का कृषि घनत्व अधिक होने पर यह समझा जाता है कि कृषि पर भार अधिक है और कृषि से प्रति व्यक्ति आय घट जाती है। जिन देशों में कृषिगत भूमि अधिक होती है वहाँ कृषि घनत्व कम हो जाता है इसके विपरीत जहाँ कृषि पर आधारित जनसंख्या कम होती है वहाँ भी कृषि घनत्व कम पाया जाता है।

किसी क्षेत्र विशेष में कृषि कार्य में लगी जनसंख्या की मात्रा या कृषि योग्य भूमि दोनों चारों में से किसी में भी परिवर्तन होने पर कृषि घनत्व में परिवर्तन हो जाता है। शिवदास मौर्य अपनी पुस्तक जनसंख्या भूगोल में लिखते हैं कि कृषि प्रधान देशों या गैर कृषि प्रधान देशों हेतु कृषि भूमि पर जनसंख्या के वास्तविक दबाव को जानने के लिए कृषि घनत्व का प्रयोग किया जाता है। जिन देशों में कृषि कार्य में लगी जनसंख्या जितनी अधिक पाई जाती है वहाँ यह सूचकांक उतना ही अधिक होगा।

6.3.4 आर्थिक घनत्व

आर्थिक घनत्व के द्वारा किसी प्रदेश के पालन – पोषण की क्षमता की गणना की जाती है। इससे ही यह ज्ञात किया जाता है कि किसी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों पर जनसंख्या का वास्तविक दबाव कितना है। ऐसी स्थिति में उसे भौगोलिक क्षेत्र की परिसीमा में स्थित प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। इसके अध्ययन के दौरान उन सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है, जो मानव की आजीविका और भरण – पोषण करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होते हैं ।इसके अंतर्गत कृषि योग्य भूमि एवं मृदा की उर्वरता, जलीय उत्पाद, जलाशय वन संपदा, खनिज संसाधन, शक्ति एवं ऊर्जा के स्रोत, परिवहन के साधन, निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग, वाणिज्य एवं व्यापारिक क्रियाएं सेवाएं इत्यादि सम्मिलित होते हैं।

किसी देश की आर्थिक क्षमता के निर्धारण में वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसी स्थिति में भौगोलिक अध्ययन में सांस्कृतिक तत्वों के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ऐसे देश जहाँ पर या तो कृषि भूमि काम है या वहाँ की बहुत जनसंख्या कृषि कार्य पर आश्रित होती है, साथ ही अधिकांश लोग अपनी आजीविका उद्योग, व्यापार, परिवहन, सेवाओं एवं अन्य विविध कार्यों से अर्जित करते हैं ।ऐसी स्थिति में वहाँ की भूमि पर जनसंख्या के वास्तविक दबाव को कृषि घनत्व अथवा कायिक घनत्व से नहीं व्यक्त किया जा सकता है। ऐसे देश के अध्ययन हेतु आर्थिक घनत्व सर्वाधिक उपयोगी होते हैं। आर्थिक घनत्व किसी देश की संपूर्ण जनसंख्या तथा उसकी सीमा के अंदर स्थित संपूर्ण संसाधनों के मूल्यों का अनुपात होता है इसके गणना हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है –

आर्थिक घनत्व = देश की कुल जनसंख्या / देश के सम्पूर्ण संसाधनों का मूल्य

आर्थिक घनत्व की गणना अलग – अलग विद्वानों ने अनेक तकनीकियों का प्रयोग करके किया है। इनमें सबसे प्रमुख गणना साइमन की है। इन्होंने जनसंख्या एवं आर्थिक उत्पादकों हेतु अलग – अलग सूचकांक तैयार किया। साइमन के अनुसार जनसंख्या सूचकांक में उत्पादन सूचकांक से भाग देकर आर्थिक घनत्व को प्रतिशत के रूप में ज्ञात किया जा सकता है, जिसका सूत्र निम्नलिखित है –

आर्थिक घनत्व = जनसंख्या का सूचकांक / उत्पादन का सूचकांक * 100

नोट : * से तात्पर्य गुणा से है.

किसी देश के आर्थिक घनत्व की गणना हेतु उसके सभी संसाधनों का मूल्यांकन उस देश की मुद्रा इकाई में किया जाता है जैसे रुपया, डॉलर, पाउंड, येन इत्यादि । यद्यपि किसी देश के सभी भौतिक एवं सांस्कृतिक

संसाधनों की उत्पादकता एवं क्षमता का सही सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन कठिन काम है। यही कारण है कि सर्वाधिक सार्थक एवं उपयोगी होने के कारण भी वर्तमान समय में आर्थिक घनत्व की प्रासंगिकता कम है।

6.3.5 पोषण घनत्व

पोषण घनत्व के माध्यम से किसी प्रदेश में खाद्यान्नों के अंतर्गत प्रयुक्त प्रति इकाई भूमि पर मनुष्यों की औसत संख्या को व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि पोषण घनत्व समान्यतः खाद्यान्न भूमि एवं कुल जनसंख्या का आनुपातिक संबंध होता है। ऐसे कृषि प्रधान देश जहाँ की अधिकांश भूमि पर कोई एक प्रकार का ही खाद्यान्न उगाया जाता है। वैसे देश में कुल खाद्यान्न भूमि की जगह केवल प्रधान खाद्यान्न के अंतर्गत प्रयुक्त की गई भूमि के आधार पर पोषण घनत्व की गणना की जाती है। इस प्रकार का पोषण केवल उन्हीं देशों के लिए उपयुक्त होता है। जहाँ खाद्यान्न भूमि के अंतर्गत उसके अधिकांश क्षेत्र आच्छादित होते हैं। साथ ही साथ यह घनत्व उन देशों हेतु कम उपयोगी होता है, जहाँ कृषि उत्पादन नगण्य होता है या फिर खाद्यान्न की आपूर्ति आयात से करते हैं। पोषण घनत्व की गणना निम्न सूत्र से की जाती है –

पोषण घनत्व = प्रदेश की कुल जनसंख्या / उस प्रदेश की कुल खाद्यान्न भूमि

किसी निश्चित भूभाग की एक परिसीमित इकाई से जितने लोगों को आहार की प्राप्ति होती है उसे उस जनसंख्या का पोषण घनत्व कहते हैं। ऐसे देश जहाँ ग्रामीण जनसंख्या अधिक पाई जाती है और उसके अधिकांश लोगों की आय कृषि से होती है, उन देशों के लिए यह घनत्व अधिक महत्त्वपूर्ण होता है। ऐसे देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाइलैण्ड और कम्बोडिया समिलित है।

6.4 जनसंख्या घनत्व का विश्व वितरण

जनसंख्या वितरण की भांति जनसंख्या घनत्व के वैश्विक स्वरूप में भिन्नता देखने को मिलती है। जनसंख्या घनत्व का वैश्विक परिदृश्य अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों, समतल उच्चावच, जल की पर्याप्त उपलब्धता, संसाधनों की उपलब्धता, नगरीकरण एवं अन्य सेवाओं की उपलब्धता का अनुसरण करती है। जिन स्थानों पर इनकी उपलब्धता पर्याप्त होती है वहां जनसंख्या का घनत्व उच्च पाया जाता है। विश्व की जनसंख्या घनत्व को निम्नलिखित सारणी के माध्यम से दर्शाया गया है –

सारणी 6.2 जनसंख्या घनत्व का वैश्विक वितरण

क्र. सं.	महाद्वीप के नाम	क्षेत्रफल (हजार वर्ग किमी.)	जनगणना 1950	जनगणना 1990	जनगणना 2001	जनगणना 2004	जनगणना 2011
1.	एशिया	43820	32.09	72.7	84.6	88.4	94.4
2.	अफ्रीका	30370	7.35	20.8	24.3	29.1	32.7
3.	यूरोप	10180	53.91	70.9	66.4	71.5	72.5
4.	उत्तरी अमेरिका	24709	8.91	17.3	20.0	19.2	21.5
5.	दक्षिणी अमेरिका	17707	6.75	17.6	21.5	22.0	23.2
6.	ओसेनिया	9009	1.45	2.8	3.4	3.6	4.0
7.	अंटार्कटिका	13720	–	–	–	–	–
8.	सम्पूर्ण विश्व	149515	18.7	39.3	44.6	47.3	50.7

स्त्रोतः संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विभाग से प्राप्त आकड़ों के आधार पर परिगणित.

उपरोक्त सारणी की अवलोकन से स्पष्ट होता है कि एशिया महाद्वीप सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। इसके पश्चात दूसरे स्थान पर यूरोप महाद्वीप आता है। जनसंख्या के प्रारंभिक बसाव वाले क्षेत्र में से एक अफ्रीका का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से तीसरा स्थान है। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया क्रमशः चौथे, पांचवें एवं छठे स्थान पर हैं। जनसंख्या घनत्व की पर्याप्तता समय के साथ बदलती रहती है। वर्ष 1982 ई. में जनसंख्या घनत्व की दृष्टिकोण से यूरोप महाद्वीप पहले स्थान पर था, जबकि एशिया दूसरे स्थान पर। इस क्रम में परिवर्तन वर्ष 1990 ई. में देखा गया और एशिया विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप बन गया। इसी प्रकार वर्ष 1990 ई. से लेकर वर्ष 2011 ई. तक जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अफ्रीका तीसरे स्थान पर बना हुआ है। बढ़ती जनसंख्या के कारण उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका के जनसंख्या घनत्व में उतार – चढ़ाव देखा जाता है। यही कारण है कि कभी उत्तरी अमेरिका चौथे स्थान पर तो कभी पांचवें स्थान पर पाया जाता है। इसी प्रकार दक्षिण अमेरिका के स्थान में भी परिवर्तन होता रहता है और वह भी चौथे स्थान से पांचवें स्थान तक परिवर्तित होता रहता है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टिकोण से ऑस्ट्रेलिया हमेशा अंतिम पायदान पर बना हुआ है और जनसंख्या घनत्व की दृष्टिकोण से छठे स्थान पर पाया जाता है।

संपूर्ण विश्व को यदि एक इकाई मानकर भी जनसंख्या घनत्व का अध्ययन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या घनत्व का जो परिदृश्य उभर कर सामने आता है वह अलग है। उसने विश्व स्तर पर जनसंख्या घनत्व के वितरण को विविध स्वरूप में प्रदर्शित किया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जनसंख्या घनत्व के माध्यम से जनसंख्या के वितरण का अध्ययन नहीं होता है, बल्कि इससे इस बात का बोध होता है कि किसी स्थान विशेष की भूमि अथवा संसाधनों पर कितनी जनसंख्या का भार है। इसी संदर्भ में वैश्विक जनसंख्या घनत्व का अध्ययन भी किया जाता है। मानक के आधार पर संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का प्रथम आंकड़ा वर्ष 1650 ई. का प्राप्त होता है। इस अवधि में संपूर्ण पृथ्वी पर जनसंख्या का घनत्व 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो 1850 ई. में बढ़कर 9 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। इसके पश्चात जनसंख्या में वृद्धि दर तीव्र होती है और विश्व के अनेकों भागों में जनसंख्या की गत्यात्मकता देखी जाती है। ऐसी स्थिति में वर्ष 1900 ई. में संपूर्ण विश्व का जनसंख्या घनत्व 12 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर प्राप्त होता है। उसके पश्चात 1950 ई. में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1980 ई. में 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 2001 ई. में 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एवं सबसे नवीनतम आंकड़ा वर्ष 2011 ई. का प्राप्त होता है, जिसके अनुसार संपूर्ण विश्व का जनसंख्या घनत्व 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अंकित किया गया है।

विश्व स्तर पर जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि विश्व के कुछ भाग सर्वाधिक सघन है जबकि अधिकांश भाग पर जनसंख्या का घनत्व निम्न से निम्नतम पाया जाता है। वर्ष 2011 ई. की जनगणना से प्राप्त अंतिम आंकड़ों से विदित होता है कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 7,565 व्यक्ति निवास करते हैं, वहीं दूसरी तरफ विश्व का सबसे जनसंख्या कम जनसंख्या घनत्व वाला देश मंगोलिया है। जहाँ जनसंख्या घनत्व 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया है। इस प्रकार भूगोलवेत्ताओं द्वारा जनसंख्या के वैश्विक वितरण का अध्ययन करने हेतु अलग – अलग मानक प्रदान किए गए जिसके आधार पर इसका वर्गीकरण करके इनके स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से कुछ विद्वानों का मानना है कि वैश्विक दृष्टिकोण से जनसंख्या घनत्व को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है –

1. **उच्च जनसंख्या घनत्व** – 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक,
2. **मध्यम जनसंख्या घनत्व** – 100 व्यक्ति से कम तथा 10 व्यक्ति से अधिक प्रति वर्ग किमी. जनसंख्या का वितरण,
3. **निम्न जनसंख्या घनत्व** – 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या का वितरण।

कुछ विद्वानों द्वारा इस मत की आलोचना की जाती है तथा उनका मानना है कि जनसंख्या के वितरण का यह स्वरूप उतना सार्थक व्याख्या नहीं कर सकता जितनी होनी चाहिए । कुछ क्षेत्र सर्वाधिक सघन बसे हुए हैं। ऐसी स्थिति में विश्व के अधिकांश भाग अधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेशों के अंतर्गत आच्छादित हो जाते हैं। इसी संदर्भ में इन विद्वानों ने उच्च जनसंख्या घनत्व वाले भागों को पुनः तीन उपवर्गों में विभाजित किया है –

अ **उच्च जनसंख्या घनत्व** – 100 व्यक्ति से 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर,

इ. **अति उच्च जनसंख्या घनत्व** – 200 व्यक्ति से 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर,

ब. **उच्चतम जनसंख्या घनत्व** – 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक

एशिया में जनसंख्या घनत्व का वितरण

जनसंख्या के आकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण विश्व में वितरित आधी से अधिक जनसंख्या एशिया के मात्र आठ देशों में निवास करती है। भौगोलिक विस्तार की दृष्टिकोण से अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि इन देशों के अंतर्गत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 24% भाग पाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एशिया के एक चौथाई क्षेत्रफल पर विश्व की आधी जनसंख्या निवास करती है। इससे यह कह सकते हैं कि एशिया विश्व का सबसे सघन जनसंख्या वाला महाद्वीप है।

एशिया में जनसंख्या घनत्व के क्षेत्रीय वितरण का अध्ययन करने के लिए वर्ष 2001 ई. एवं वर्ष 2011 ई. के आकड़ों का प्रयोग किया गया है। इन आकड़ों से विदित होता है कि सिंगापुर एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है जहाँ वर्ष 2001 ई. एवं वर्ष 2011 ई. जनसंख्या घनत्व क्रमशः 6773 व्यक्ति/वर्ग किमी. एवं 7565 व्यक्ति/वर्ग किमी. है। इसी प्रकार जनसंख्या घनत्व की दृष्टिकोण से भारत का एशिया में छठा स्थान है जहाँ इन्हीं अवधियों में जनसंख्या घनत्व क्रमशः 324 व्यक्ति/वर्ग किमी. एवं 382 व्यक्ति/वर्ग किमी. है। एशिया में चार देश ऐसे भी हैं जिनके जनसंख्या घनत्व में कमी दर्ज की गई है। इन देशों के नाम जापान, कम्बोडिया, म्यानमार एवं ताइवान है। इनमें जापान एवं ताइवान में जहाँ जन्म दर मृत्यु दर से कम है वहीं कम्बोडिया एवं म्यानमार जन्म दर तो मृत्यु दर से अधिक है परन्तु प्रवास पर वर्तमान समय में सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। एशिया के जनसंख्या घनत्व को निम्नलिखित मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है।

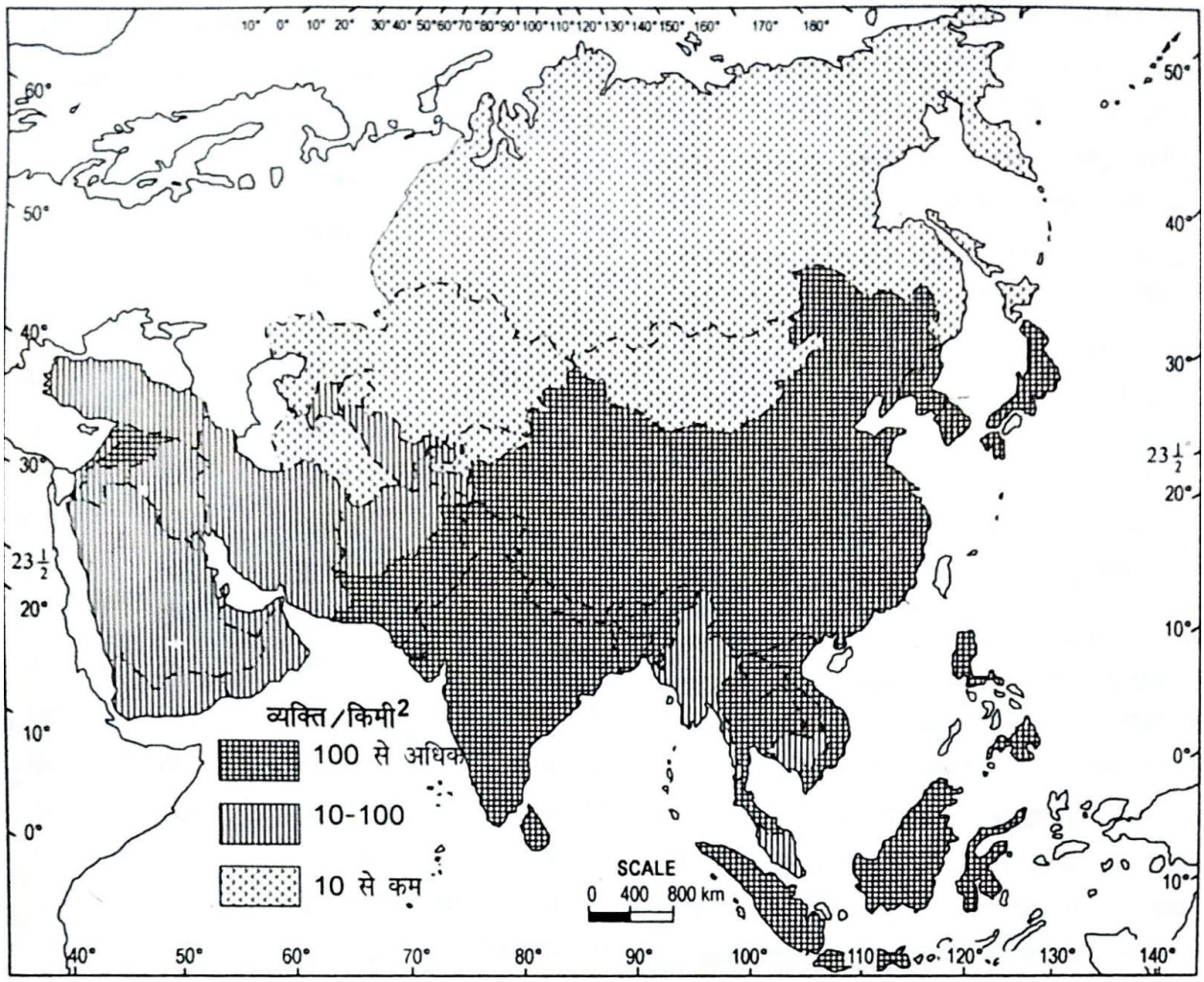

चित्र संख्या 6.1 एशिया में जनसंख्या घनत्व का वितरण.

यूरोप में जनसंख्या घनत्व का वितरण

वर्ष 2011 ई. की अनंतिम गणना से प्राप्त आकड़ों के अनुसार यूरोप की कुल जनसंख्या लगभग 73 करोड़ 85 लाख है तथा सम्पूर्ण महाद्वीप का क्षेत्रफल 10,180,000 वर्ग किमी. है। अतः इस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व 72 व्यक्ति/प्रतिवर्ग किमी. है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टिकोण से यूरोप एशिया के बाद दूसरे स्थान पर है। वर्ष 1950 ई. से पूर्व यूरोप सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व (53.9) वाला महाद्वीप था जबकि 1990 ई. से एशिया सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है तथा यूरोप दूसरे स्थान पर है। महाद्वीप में जनसंख्या वितरण की दृष्टिकोण से जर्मनी सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ की जनसंख्या 8.17 करोड़ दर्ज की गई है, परन्तु जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक 444 व्यक्ति/प्रतिवर्ग किमी. नीदरलैण्ड में दर्ज किया गया है। यह प्रथम स्थान पर है। नीदरलैण्ड कुल जनसंख्या की दृष्टि से 10वें स्थान पर है।

यूरोप सम्पूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का केवल 8% भाग आच्छादित करता है जबकि यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या की 11ः निवास करती है इसलिए यह जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2001 ई. एवं वर्ष 2011 ई. से प्राप्त आकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यहाँ के 26 प्रमुख देशों में से 10 देशों की जनसंख्या घटी है। ये देश हैं जर्मनी, पोलैण्ड, हंगरी, रूमानिया, सर्विया, ग्रीस, उक्रेन, बुल्गारिया, बेलारूस एवं नार्वे। यूरोप के प्रमुख देशों के जनसंख्या घनत्व को निम्नलिखित मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है।

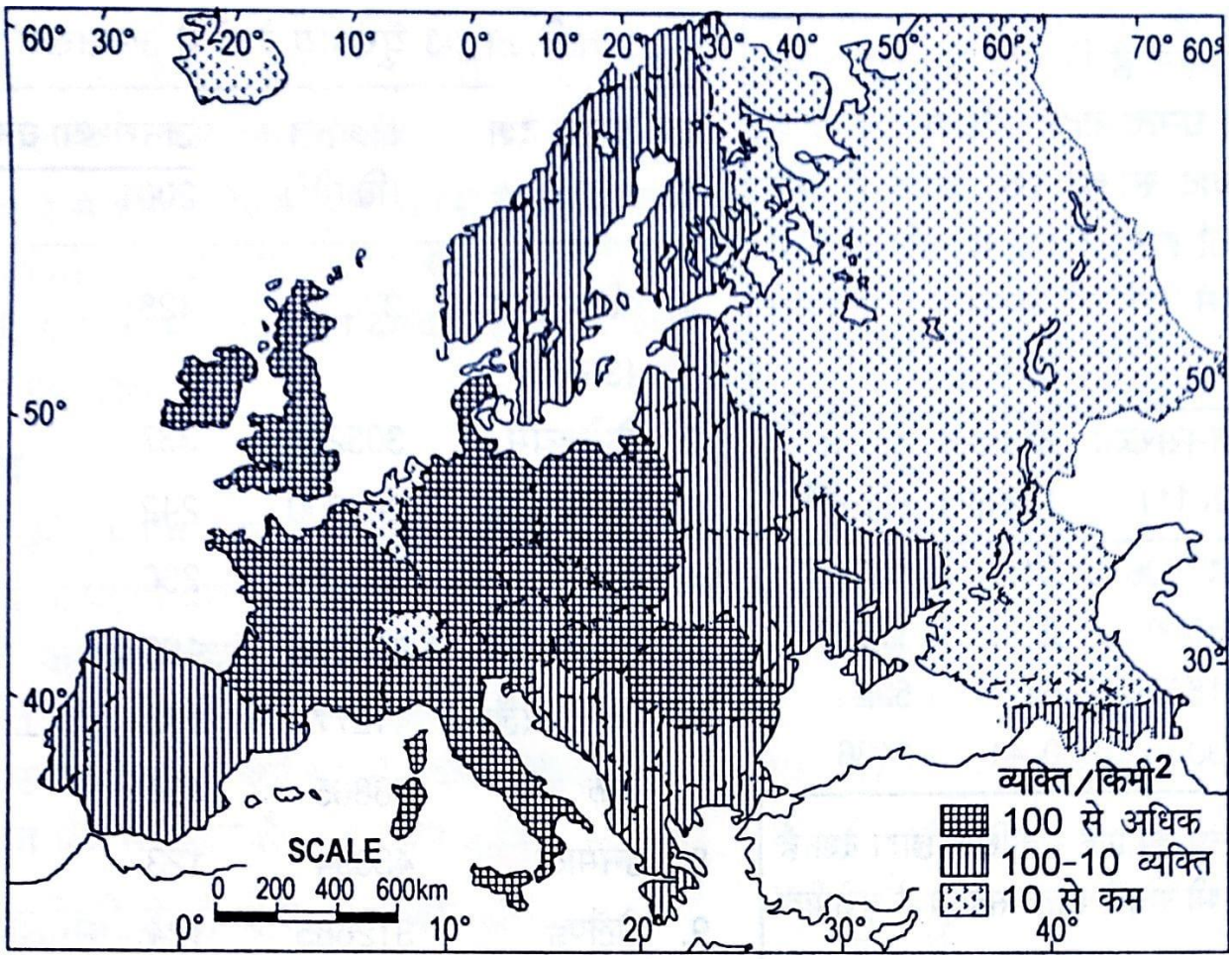

चित्र संख्या 6.2 यूरोप में जनसंख्या घनत्व का वितरण.

उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या घनत्व का वितरण

उत्तरी अमेरिका सम्पूर्ण स्थलीय भाग के 15% क्षेत्रफल पर विस्तारित है तथा इस पर विश्व की कुल जनसंख्या का मात्र 8% भाग ही निवास करती है। ऐसी स्थिति में यहाँ का जनसंख्या घनत्व 22 व्यक्ति/वर्ग किमी. दर्ज किया गया है जो वर्ष 1981 ई. में 20 व्यक्ति/वर्ग किमी. था। जनसंख्या घनत्व के वितरण के दृष्टिकोण से यह

पांचवें स्थान पर है। इस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व वर्ष 1950 ई. 8.9 व्यक्ति/वर्ग किमी. था जो वर्ष 1990 ई. में लगभग दोगुना बढ़ कर 17.3 व्यक्ति/वर्ग किमी. दर्ज किया गया था। बारबाडोस यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है जहाँ प्रति वर्ग किमी. 635 लोग निवास करते है। उत्तरी अमेरिका के सम्पूर्ण देशों के जनसंख्या घनत्व को निम्न मानचित्र द्वारा दर्शाया गया है।

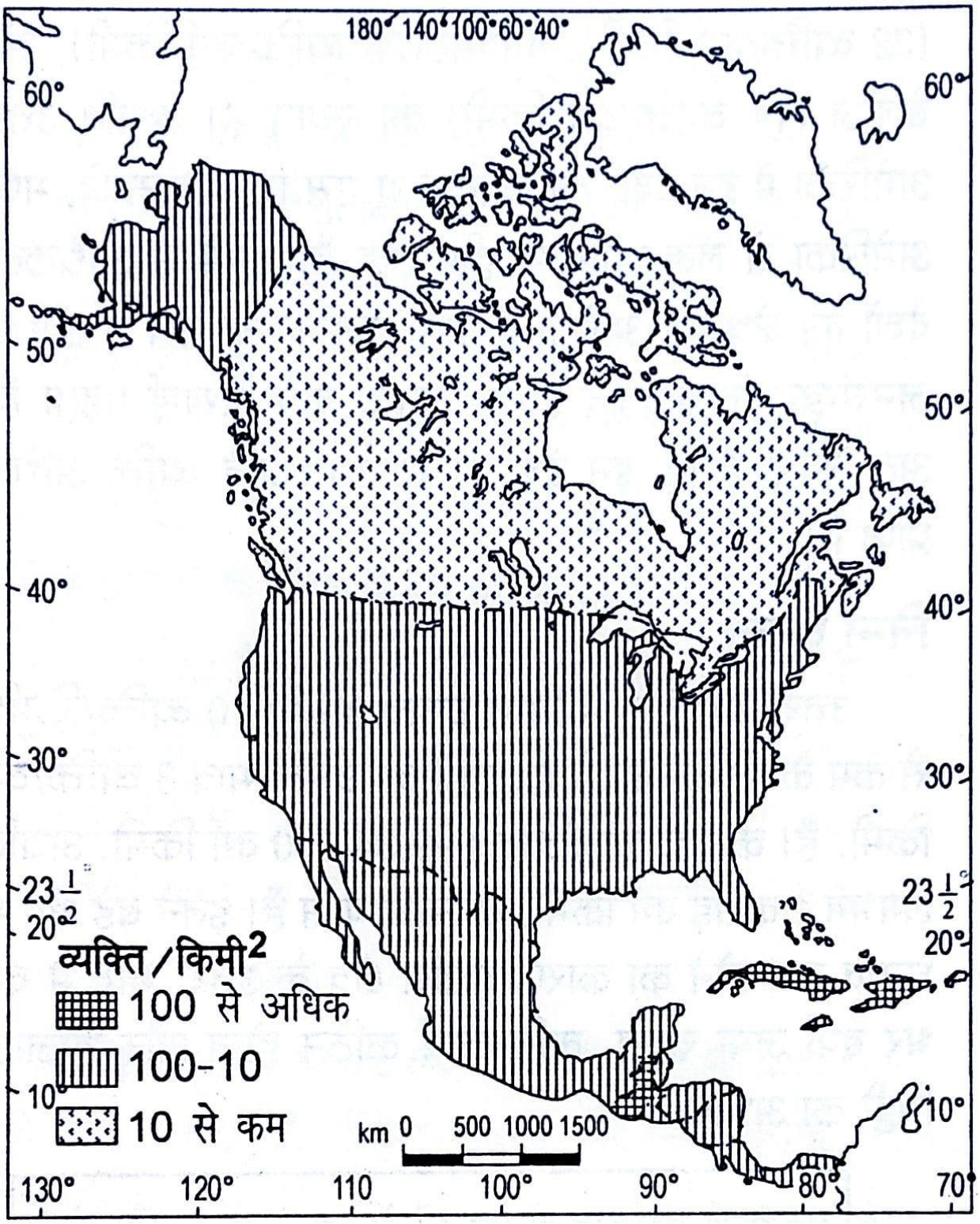

चित्र संख्या 6.3 उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या घनत्व का वितरण.

दक्षिणी अमेरिका में जनसंख्या घनत्व का वितरण

दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल सम्पूर्ण विश्व के 13% भाग को अभिव्यक्त करता है वहीं यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का मात्र 6% भाग निवास करती है। वर्ष 2011 ई. के प्राप्त आकड़ों के विश्लेषण से विदित होता है कि दक्षिण अमेरिका का औसत जनसंख्या घनत्व 23 व्यक्ति/वर्ग किमी. है। इस प्रकार जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से यह चौथे स्थान पर है। इस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व वर्ष 1950 ई. में 6.7 व्यक्ति/वर्ग किमी. था जो विगत चार दशकों में बढ़ कर 1990 ई. 17.6 व्यक्ति/वर्ग किमी. हो गया था ।इसी प्रकार यह वर्ष 2001 ई. में जहाँ 22 व्यक्ति/वर्ग किमी. दर्ज किया गया था वहीं वर्ष 2011 ई. में 23 व्यक्ति/वर्ग किमी. प्राप्त हुआ है। दक्षिण अमेरिका मध्यम जनसंख्या घनत्व वितरण को प्रस्तुत करने वाला महाद्वीप है। यहाँ इक्वेडोर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। दक्षिण अमेरिका के देशों जनसंख्या घनत्व के वितरण को निम्न मानचित्र द्वारा दर्शाया गया है।

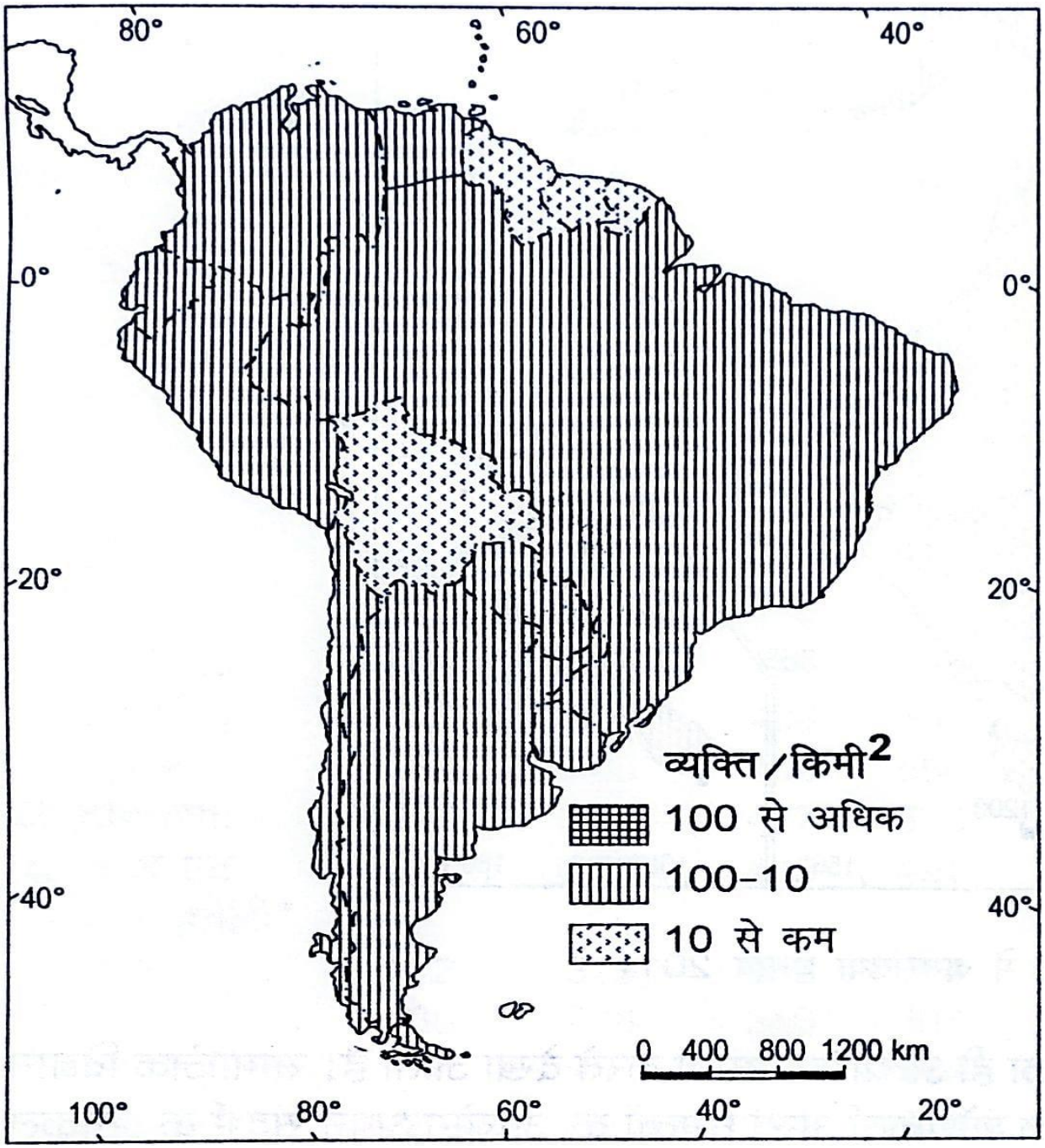

चित्र संख्या 6.4 दक्षिणी अमेरिका में जनसंख्या घनत्व का वितरण.

अफ्रीका में जनसंख्या घनत्व का वितरण

अफ्रीका महाद्वीप सम्पूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 22% भाग आच्छादित किया हुआ है परन्तु यहाँ विश्व की सम्पूर्ण जनसंख्या का मात्र 14.5% भाग ही निवास करती है। इस प्रकार सम्पूर्ण महाद्वीप का औसत जनसंख्या घनत्व 33 व्यक्ति/वर्ग किमी. है। वर्ष 1950 ई. में इस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व 7 व्यक्ति/वर्ग किमी. था जो बढ़ कर वर्ष 1990 ई. में 20 व्यक्ति/वर्ग किमी. हो गया। वर्ष 2001 ई. में इसका जनसंख्या घनत्व जहाँ 24 व्यक्ति/वर्ग किमी. था वहीं 2011 ई. में यह बढ़ कर 33 व्यक्ति/वर्ग किमी. हो गया। इस प्रकार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से इसका तीसरा स्थान है। अफ्रीका के कुल 59 देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मारिशस में प्राप्त होता है जहाँ प्रति वर्ग किमी. 639 व्यक्ति निवास करते है वहीं सबसे कम जनसंख्या घनत्व पश्चिमी सहारा में पाया जाता है। यहाँ प्रति वर्ग किमी. 2 व्यक्ति पाए जाते है। इस महाद्वीप के सभी देशों में जनसंख्या घनत्व के वितरण को निम्न मानचित्र द्वारा दर्शाया गया है।

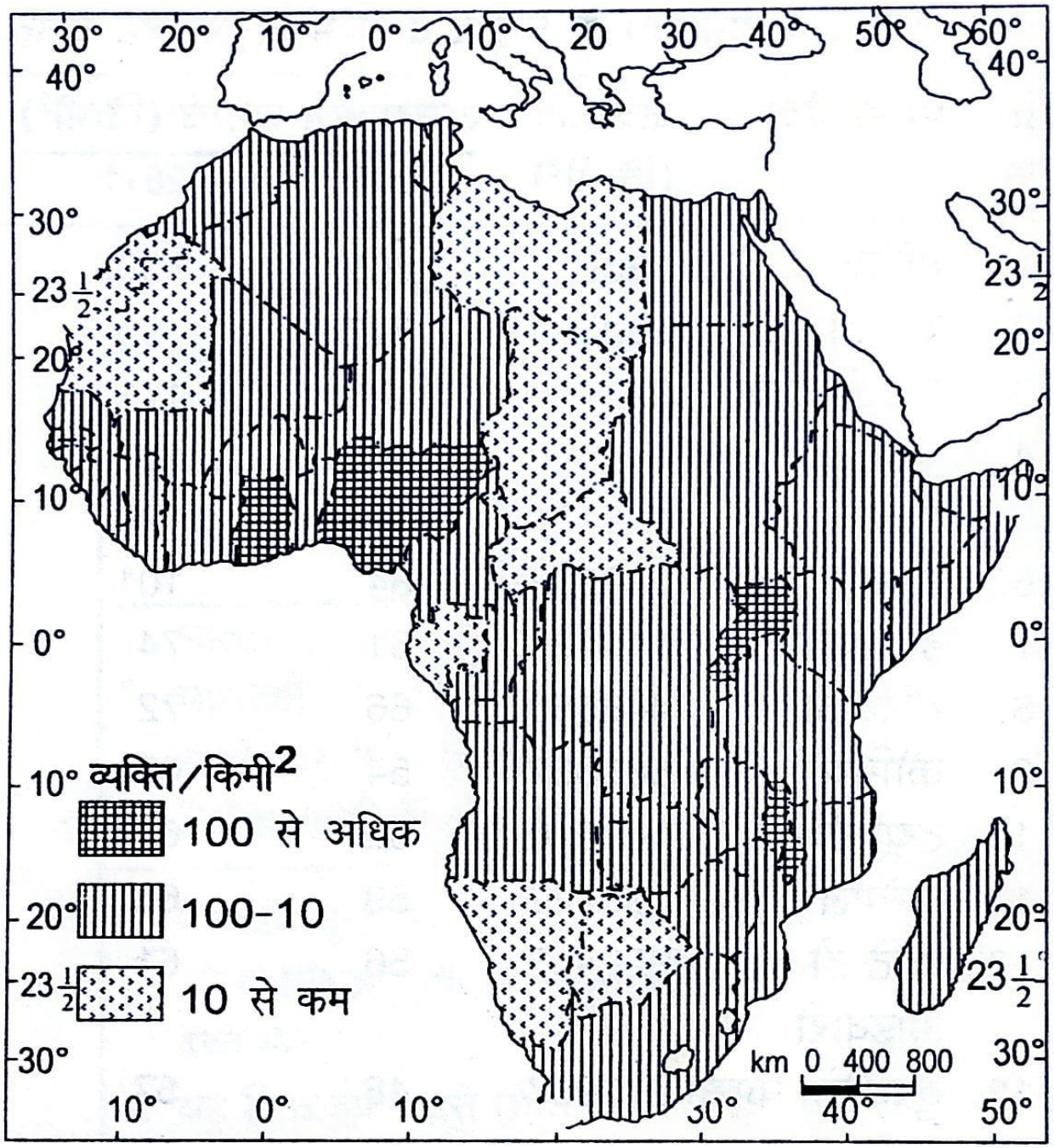

चित्र संख्या 6.5 अफ्रीका में जनसंख्या घनत्व का वितरण.

ओशिनिया में जनसंख्या घनत्व का वितरण

ओशिनिया एक ऐसा भौगोलिक प्रदेश है जिसमें दक्षिणी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के आस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा उसके आस – पास के क्षेत्र सम्मिलित होते है। इस क्षेत्र की सीमा में कुल 14 देश तथा 25 निर्भर क्षेत्र सम्मिलित है। आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, पापुआ न्यू गिनी और फिजी – टोंगा यहाँ के प्रमुख अधिवासित क्षेत्र है शेष भाग छोटे – छोटे द्वीपों से घिरा है। यह विश्व के सभी महाद्वीपों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। ओशिनिया विश्व के सम्पूर्ण स्थलीय भाग के मात्र 7% भू–भाग को आच्छादित करता है जबकि यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का मात्र 0.5% ही निवास करती है। इस प्रकार इस सम्पूर्ण भूखण्ड का औसत जनसंख्या घनत्व 4 व्यक्ति/वर्ग किमी. प्राप्त होता है अतः यह भी निम्न घनत्व वाला क्षेत्र होगा । अन्य महाद्वीपों की भाति इस भू–भाग में उच्च जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र नहीं पाया जाता है। इसके सम्पूर्ण भू–भाग पर मध्यम एवं निम्न जनसंख्या घनत्व क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। ओशिनिया महाद्वीप के सभी देशों में जनसंख्या घनत्व के वितरण में भिन्नता को निम्न मानचित्र द्वारा दर्शाया गया है।

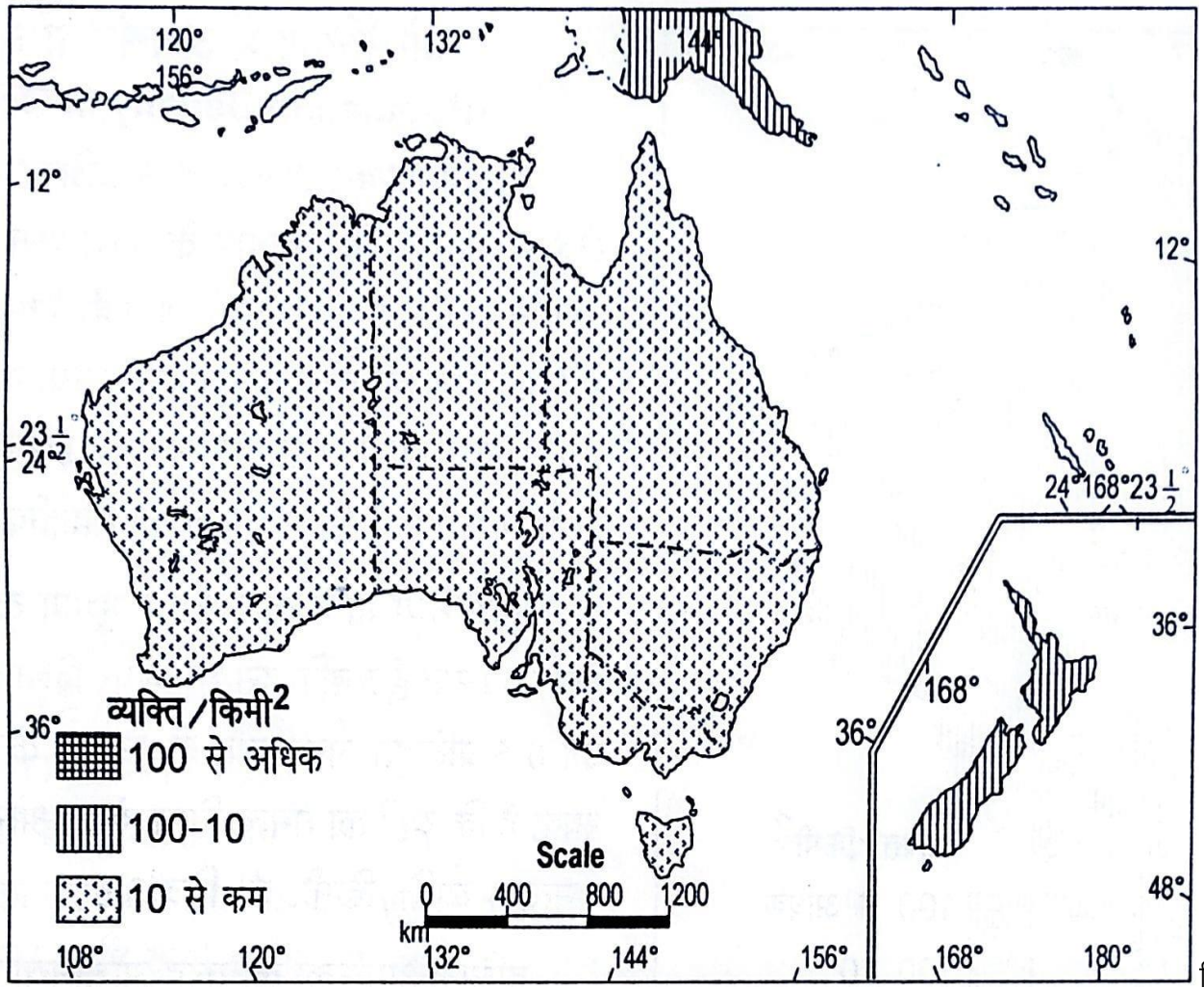

चित्र संख्या 6.6 ओशिनिया में जनसंख्या घनत्व का वितरण.

भारत में जनसंख्या घनत्व का वितरण

जनसंख्या घनत्व किसी निश्चित भू–भाग पर जनसंख्या के दबाव को दर्शाता है। इसके गणना की अनेक विधियाँ है जिनमें से सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली विधि अंकगणितीय विधि है। सामाजिक विज्ञान एवं अन्य विषयों के शोधकर्ताओं द्वारा भी इसी का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। भारत के संदर्भ में यदि इसका अवलोकन किया जाए तो वर्ष 1901 ई. में औसत जनसंख्या घनत्व 77 व्यक्ति/वर्ग किमी. था इसके पश्चात इसमें लगातार वृद्धि होती गई। जिसे निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है –

सारणी 6.3 भारत में जनसंख्या घनत्व (1901 ई. से 2011 ई.)

क्र. सं.	जनगणना वर्ष	औसत जनसंख्या घनत्व
1.	1901	77
2.	1911	82
3.	1921	81
4.	1931	90
5.	1941	103
6.	1951	117
7.	1961	142
8.	1971	198
9.	1981	221
10.	1991	267
11.	2001	324
12.	2011	382

स्त्रोतः जनगणना विभाग, लखनऊ.

उपरोक्त सारणी के आधार पर घनत्व में होने वाले दशकीय परिवर्तन का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि वर्ष 1901 से 1921 ई. के मध्य देश जनसंख्या घनत्व में परिवर्तन की दर सामान्य रही है। वर्ष 1931 ई. की जनगणना से इसमें वृद्धि की प्रवृत्ति शुरू होती है। वर्ष 1961 ई. की जनगणना तक इसकी दर मध्यम दर्ज की जाती है। उसके पश्चात तीव्र वृद्धि दर देखी जाती है और वर्ष 2001 तथा 2011 ई. की जनगणना में यह क्रमशः 324 एवं 382 प्राप्त होती है।

इस प्रकार जनसंख्या घनत्व के सम्पूर्ण देश को तीन वर्गों में विभक्त किया जाता है –

1. उच्च जनसंख्या घनत्व – 400 व्यक्ति/वर्ग किमी. से अधिक
2. मध्यम जनसंख्या घनत्व – 400 से 200 व्यक्ति/वर्ग किमी.
3. निम्न जनसंख्या घनत्व – 200 व्यक्ति/वर्ग किमी. से कम

भारत में राज्यवार जनसंख्या घनत्व के वितरण को निम्न मानचित्र द्वारा दर्शाया गया है –

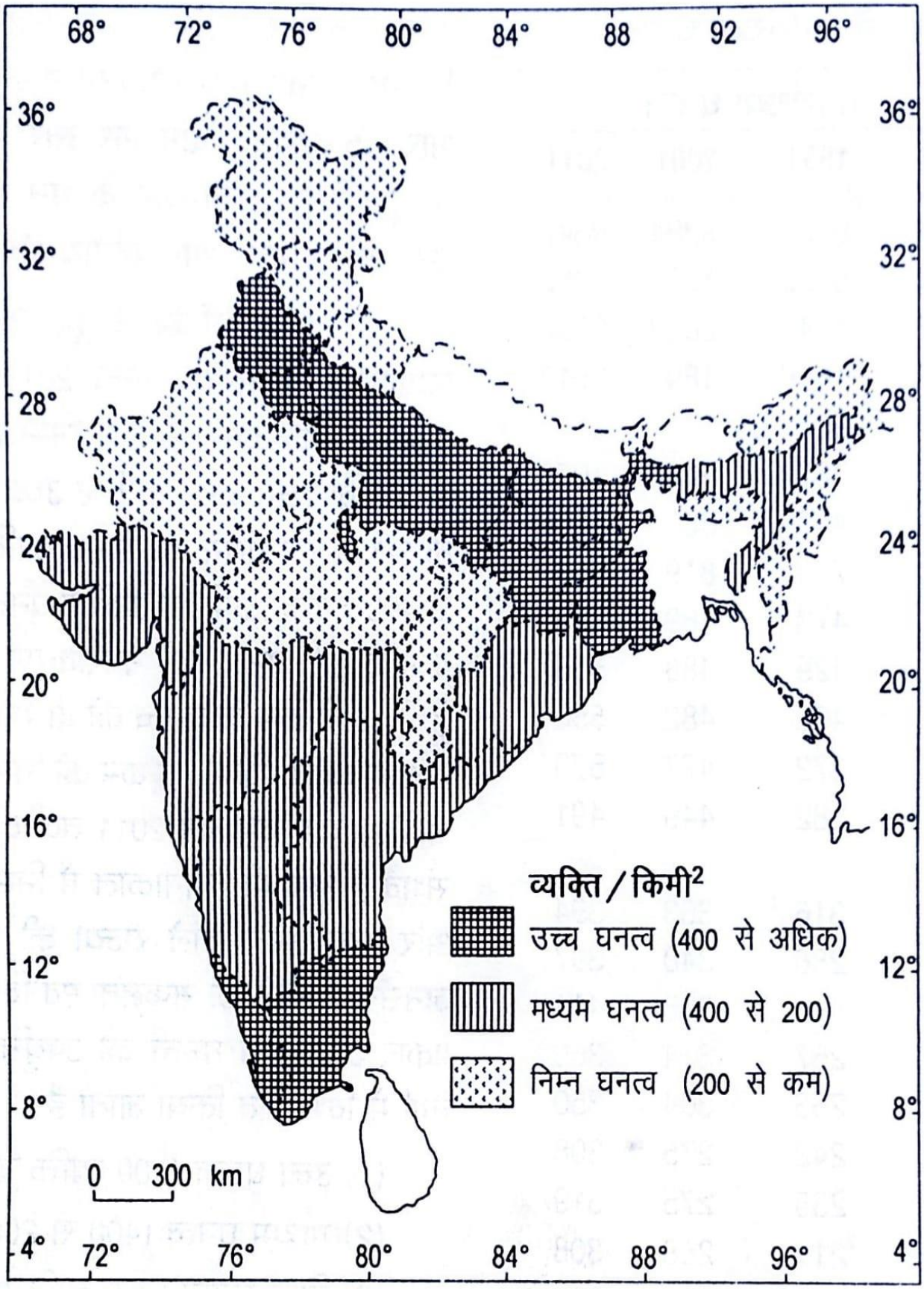

चित्र संख्या 6.7 भारत में जनसंख्या घनत्व का वितरण.

6.5 सारांश

आपने इस इकाई में जनसंख्या घनत्व, घनत्व के प्रकार, जनसंख्या घनत्व का विश्व वितरण का अध्ययन किया है। आप समझ गए होगें कि जनसंख्या घनत्व, घनत्व के प्रकार, जनसंख्या घनत्व का विश्व वितरण आपस में घनिष्ट संबंध पाया जाता है। सामान्य अर्थ में घनत्व का मतलब किसी स्थान की जनसंख्या तथा उसके क्षेत्रफल का अनुपात होती है जबकि अर्थ में यह उस क्षेत्र पर जनसंख्या के भार अभिव्यक्त करता है, जिसका वहाँ पोषण होता है। घनत्व के अध्ययन से किसी क्षेत्र के कल्याण को प्रोत्साहन प्राप्त होता है । वास्तव में किसी देश की जनसंख्या घनत्व तथा वहाँ के संसाधनों में सहसंबंध पाया जाता है जो उसकी भौगोलिक अवस्थिति, सरकारी नीतियों, सांस्कृतिक संगठन का प्रतिफल होता है। विश्व के सभी भागों में जनसंख्या घनत्व का वितरण समान नहीं है। कहीं पर यह सघन है तो कहीं विरल है।

6.6 स्वमूल्यांकन प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

1. किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली सम्पूर्ण जनसंख्या एवं उसके कुल क्षेत्रफल के अनुपात को कहा जाता है।

   (क) पोषण घनत्व (ख) अंकगणितीय घनत्व (ग) कायिक घनत्व (घ) आर्थिक घनत्व

2. किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली सम्पूर्ण जनसंख्या एवं उसके कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के अनुपात को कहा जाता है।

   (क) कायिक घनत्व (ख) पोषण घनत्व (ग) अंकगणितीय घनत्व (घ) उपरोक्त सभी

3. किसी क्षेत्र की कृषि कार्य में संलग्न सम्पूर्ण जनसंख्या एवं उसके कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के अनुपात को कहा जाता है।

   (क) अंकगणितीय घनत्व (ख) कृषि घनत्व (ग) कायिक घनत्व (घ) पोषण घनत्व

4. किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली सम्पूर्ण जनसंख्या एवं उसके कुल खाद्यान्न क्षेत्रफल के अनुपात को कहा जाता है।

   (क) अंकगणितीय घनत्व (ख) कायिक घनत्व (ग) कृषि घनत्व (घ) पोषण घनत्व

5. वर्ष 1650 ई. की अवधि में संपूर्ण पृथ्वी पर जनसंख्या का घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था ।

   (क) 10 (ख) 8 (ग) 4 (घ) 5

6.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

Bogue] D- J-] 1969] Principles of Demography] John Wiley] N-Y-

Clarke] John I-] 1973] Population Geography] Pergaman Press] Oxford-

Crook] Nigel] 1997] Principles of Population and Development] Pergaman Press] N- Y-

Garmier] J- B-] 1970] Geography of Population] Longman] London-

Mamoria] C- B-] 1981] India's Population Problem] Kitab Mahal] New Delhi-

Premi] M- K-] 1991] India's Population] Heading Towards a Billion] B- R- Publishing Corporation-

Blassoff] M- and Srinivasan K-] 2001] Population Development Nexus in India : Challenges for the New Millennium] Tata McGraw Hill] New Delhi-

Woods] R-] 1979] Population Analysis in Geography] Longman] London-

Zelinsky] W-] 1966] A Prologue to Population Geography] Prentice Hall-

चन्दना, आर. सी., 2022, जनसंख्या भूगोल – संकल्पना, नियंत्रक व विश्व प्रारूप, कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

चन्दना, आर. सी., 2022, भारत : जनसंख्या (जनसंख्या भूगोल – भाग 2), कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

मौर्या, एस. डी., 2005, जनसंख्या भूगोल, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद.

ओझा, आर. पी., 1984, जनसंख्या भूगोल, प्रतिभा प्रकाशन.

हीरा लाल, 2000, जनसंख्या भूगोल के मूल तत्व, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली.

तिवारी, राम कुमार, 2023, जनसंख्या भूगोल, प्रवालिका पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद.

6.8 अभ्यास प्रश्न (सत्रांत परीक्षा की तैयारी)

1. जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए?
2. जनसंख्या घनत्व के प्रकारों का वर्णन कीजिए?
3. जनसंख्या घनत्व के वैश्विक वितरण का विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए?

इकाई–7 विश्व में जनसंख्या वृद्धि, भारत में जनसंख्या वृद्धि

इकाई की रूपरेखा

7.0 प्रस्तावना

7.1 उद्देश्य

7.2 वैश्विक जनसंख्या वृद्धि के परिदृश्य

7.3 जनसंख्या वृद्धि के तत्व अथवा कारक

7.4 वैश्विक जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां

7.5 विश्व के महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि

7.6 भारत में जनसंख्या वृद्धि

7.7 भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति

7.8 सारांश

7.9 स्वमूल्यांकन प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

7.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

7.11 अभ्यास प्रश्न (सत्रांत परीक्षा की तैयारी)

7.0 प्रस्तावना

धरातल पर अन्य तत्वों के समान ही जनसंख्या में भी परिवर्तनशीलता के गुण पाए जाते हैं। पृथ्वी पर कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, सबकी एक निश्चित आयु होती है। इसके पश्चात उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसी प्रकार जनसंख्या में भी स्थायित्व के गुण नहीं पाए जाते है। समय में परिवर्तन के अनुसार इसमें कमी अथवा वृद्धि होती रहती है। किसी निश्चित अवधि में किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यह वृद्धि दो प्रकार की होती है धनात्मक जनसंख्या वृद्धि एवं ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। जब किसी स्थान की जनसंख्या एक निश्चित अवधि में बढ़ जाती है तो उसे धनात्मक वृद्धि कहते हैं। इसके विपरीत जब किसी स्थान विशेष की जनसंख्या एक निर्धारित अवधि में कम हो जाती है तब उसे ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं।

7.1 उद्देश्य

यद्यपि पृथ्वी के सम्पूर्ण भाग में जनसंख्या की वृद्धि दर एक समान नहीं है। कहीं पर तीव्र, कहीं पर मध्यम तो कहीं न्यून है । इस इकाई के उद्देश्य निम्नलिखित है –

1. विश्व में जनसंख्या वृद्दि का अध्ययन करना।
2. भारत में जनसंख्या वृद्दि का अध्ययन करना।

7.2 वैश्विक जनसंख्या वृद्धि के परिदृश्य

विश्व के विभिन्न भागों में अधिक समय तक उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर के कारण संतुलन बना रहा लेकिन इस पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं था। मृत्यु दर के उच्च पाए जाने के कारण उच्च उत्पादकता आवश्यक हो गई थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि 8,000 ईसा पूर्व कृषि कार्य के प्रारंभ के समय विश्व की जनसंख्या 80 लाख थी। विकास का क्रम एवं खाद्यान्नों में वृद्धि के कारण मानव जीवन में थोड़ा सुधार आया,

जिसका परिणाम यह हुआ कि जन्म दर में वृद्धि हुई तथा मृत्यु दर में गिरावट के कारण जन्म दर, मृत्यु दर से थोड़ा अधिक हो गई। इसके पश्चात लम्बे समय तक जनसंख्या मंद गति से बढ़ती रही और 4,000 ईसा पूर्व तक बढ़कर 8.6 करोड़ हो गई। जनसंख्याविदों का ऐसा मानना है कि आधुनिक काल के प्रारंभिक समय 18वीं शताब्दी के मध्य तक विश्व की जनसंख्या बढ़कर 80 करोड़ हो गई। इसी समय से जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने लगी। अब तक मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका था। जहाँ कृषि क्रांति से खाद्यसामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित हुई वहीं औद्योगिक क्रांति से आर्थिक समृद्धि तेज हुई। इसका परिणाम यह हुआ की मृत्यु दर में तेजी से ह्रास हुआ और जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर बढ़ने लगा। 20वीं शताब्दी के मध्य तक जनसंख्या तीन गुनी बढ़कर 250 करोड़ हो गई। वर्ष 1988 तक संपूर्ण विश्व की जनसंख्या 500 करोड़ हो गई थी। इस प्रकार देखा गया कि विश्व की कुल जनसंख्या को 100 करोड़ पहुंचने में 10 लाख वर्ष लगा तथा इस स्तर की प्राप्ति 1808 ई. में हुई। इसके पश्चात अगले 100 करोड़ की वृद्धि में मात्र 120 वर्ष लगे तथा 1928 ई. में विश्व की जनसंख्या 200 करोड़ हो गई। पुनः अगले 100 करोड़ बढ़ने में 32 वर्ष लगे तथा 1960 ई. में विश्व की संपूर्ण जनसंख्या 300 करोड़ हो गई। विश्व की संपूर्ण जनसंख्या के 400 करोड़ तक पहुंचने में फिर 15 वर्ष लगे और वर्ष 1975 ई. में विश्व की जनसंख्या 400 करोड़ हो गई। इसके पश्चात मात्र अगले 13 वर्षों में विश्व जनसंख्या में पुनः 100 करोड़ की वृद्धि हो जाती है और वर्ष 1988 ई. में विश्व की जनसंख्या 500 करोड़ हो गई।

7.3 जनसंख्या वृद्धि के तत्व अथवा कारक

किसी भी भौगोलिक क्षेत्र जिसमें विश्व, देश, राज्य, जिला, प्रखंड या गांव सम्मिलित होते हैं, में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि के लिए तीन कारकों को जिम्मेदार माना जाता है। इन्हीं कारकों को जनसंख्या वृद्धि का घटक भी कहा जाता है जो निम्न है –

- प्रजननता
- मर्त्यता
- प्रवास

7.3.1 प्रजननता

प्रजननता से तात्पर्य होता है किसी महिला या महिलाओं के समूह द्वारा एक निश्चित समय अवधि में कुल सजीव में बच्चों की वास्तविक संख्या। सामान्यतः प्रजननता की माप बच्चों की संख्या से होती है। रामकुमार तिवारी अपनी पुस्तक जनसंख्या भूगोल में लिखते हैं कि किसी समाज में एक नियत अवधि में सजीव बच्चों के जन्म की आवृत्ति ही प्रजननता की माप होती है। यही कारण है कि प्रजननता को बच्चों की संख्या से मापा जाता है। प्रजननता ही किसी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण होती है। जनसंख्या वृद्धि के इस घटक में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं, किसी वर्ष में कुल जन्म की संख्या, शिशु स्त्री अनुपात, पुनरुत्पादन आयु वर्ग की स्त्रियों की संख्या, निश्चित आयु वर्ग की स्त्रियों द्वारा प्रजननित बच्चों की संख्या, एक स्त्री अपना प्रजनन काल पुरा करके अपने स्थान पर कितने शिशुओं को प्रतिस्थापित करती है, कुल जन्म में शिशु कन्या का अनुपात, प्रजनन आयु काल में एक स्त्री कितनी महिला प्रतिस्थापित करती है और एक स्त्री अपने संपूर्ण प्रजनन काल में कितने शिशुओं को जन्म देती है। ये सभी तत्व किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या वृद्धि को निर्धारित करते हैं (तिवारी, 2023)।

7.3.2 मर्त्यता

किसी निश्चित समयावधि में घटित होने वाली मृत्यु की संख्या को मर्त्यता कहते हैं। कुछ स्थानों पर इसे मृत्यु तो कुछ स्थानों पर मृत्युक्रम भी कहा जाता है। मृत्यु एक अनिवार्य घटित होने वाली परिघटना है जिसके फलस्वरुप किसी स्थान के जनसंख्या आकार में ह्रास होता है और जनसंख्या वृद्धि प्रभावित होती है। मर्त्यता को जनसंख्या वृद्धि का दूसरा प्रमुख घटक भी कहा जाता है। इसके भी कुछ अनिवार्य घटक होते हैं जो निम्नलिखित हैं किसी वर्ष में संपूर्ण मृत्यु की संख्या, किसी आयु वर्ग में मृत्यु की संख्या, शिशु मृत्यु संख्या, मातृ मृत्यु संख्या और किस कारण से किसी स्थान पर मृत्यु जैसी घटना घट रही है। इन संपूर्ण कारकों का प्रभाव जनसंख्या वृद्धि पर पड़ता है।

7.3.3 प्रवास

किसी मानव समुदाय या व्यक्ति विशेष द्वारा अपने मूल स्थान से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जाना प्रवास कहलाता है। रामकुमार तिवारी के शब्दों में किसी व्यक्ति या समुदाय का बाहर से किसी समुदाय में आगमन या किसी समुदाय से व्यक्ति का बहिर्गमन करने की क्रिया को प्रवास कहा जाता है। प्रवास में आप्रवास एवं उत्प्रवास दोनों सम्मिलित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनांकिकीय शब्दकोश ने प्रवास की विस्तृत व्याख्या की है। उसने विशिष्ट अर्थ देते हुए प्रवास को अलग तरीके से परिभाषित किया है –

- अगर प्रवास देश की सीमा के भीतर हो रहा है तो बहिर्गमन की प्रक्रिया को बाह्य प्रवास एवं आगमन की प्रक्रिया को अंतर प्रवास के नाम से जाना जाएगा ।
- किसी देश की सीमा के बाहर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के संदर्भ में यह शब्दावली परिवर्तित हो जाती है किसी देश से बाहर जाने को बहिर्गमन तथा अंदर आने को अंतर्गमन कहा जाता है ।

प्रवास को स्पष्ट करते हुए जेलिन्सकी लिखते हैं कि प्रवास जन्म और मृत्यु की भांति जैविक परिघटना नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह भौतिक एवं सामाजिक कारकों से प्रेरित लेन – देन की प्रक्रिया है।

प्रसिद्ध विद्वान जोंस प्रवास के मापन की कठिनाइयों को संबोधित करते हुए लिखते हैं कि जन्म एवं मृत्यु की तुलना में प्रवास की सैद्धांतिक रूपरेखा प्रस्तुत करना और उसका मापन करना बहुत कठिन है।

किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि में इन तीनों कारकों का संयुक्त प्रभाव रहता है। अलग – अलग क्षेत्र के लिए इनकी प्रभाविता भी भिन्न – भिन्न होती है।

7.4 वैश्विक जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां

पृथ्वी पर प्रथम मानव का उद्‌भव एवं विकास कब तथा कहाँ हुआ यह आज भी विवाद का विषय है, फिर भी विद्वानों का मानना है कि आधुनिक स्वरूप में मानव अस्तित्व एक निरंतर जैविक विकास प्रक्रिया का प्रतिफल है जो आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ था । इस क्रम में मानव का विकास निम्न रूपों में हुआ है कपि मानव – जावा मानव – पैकिंग मानव – हाइडेल वर्ग मानव – अटलांटिक मानव – निएंडरथल मानव – क्रागमैन मानव – होमो सेपियंस मानव। इस प्रकार मानव जनसंख्या की वृद्धि के इतिहास को निम्नलिखित उपशीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है –

7.4.1 प्रागैतिहासिक काल (अज्ञात काल से 600 ई. पू. तक)

जनांकिकीय एवं जनसंख्याविदों का मानना है कि लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व मानव की जनसंख्या 1,000 से कम रही होगी। अध्ययन की दृष्टिकोण से इस अवधि को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। ईसा से 10,000 वर्ष पूर्व जिसे हिमयुग की समाप्ति के काल के नाम से जाना जाता है तब तक संपूर्ण विश्व की जनसंख्या बढ़कर 10 लाख हो गई होगी। ईसा से 8,000 वर्ष पूर्व यह 50 लाख रही होगी, जो बढ़कर 5,000 ईसा पूर्व तक 200 लाख हो गई थी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ईसा पूर्व 4,000 वर्ष तक विश्व की जनसंख्या 8.5 करोड़, 2,500 ईसा पूर्व तक 10 करोड़ एवं ईसा काल तक 25 करोड़ तक पहुंच गई थी।

जनसंख्या के इतिहास में 8,000 ईसा पूर्व शुरू होने वाली कृषि क्रांति का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसने मानव जीवन को स्थायित्व तो प्रदान किया। इससे पूर्व मानव द्वारा अपने जीवन यापन के लिए वन्य पदार्थों के एकत्रण, शिकार एवं मत्स्यन पर निर्भर रहना पड़ता था। इसके लिए एक विस्तृत भौगोलिक प्रदेश की आवश्यकता होती थी । कृषि के कारण इन क्रियाकलापों के क्षेत्र सीमित हुए। जनसंख्याविदों का मानना है कि उसे समय जीवन संघर्ष में होने के कारण जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों उच्च अवस्था में थी जिसके कारण लंबे अवधि तक जनसंख्या में संतुलन बना रहा। कृषि क्रांति के पश्चात उत्पादन में वृद्धि होने के कारण मानव जाति को पर्याप्त मात्रा में पोषण युक्त भोजन मिलने लगा, जिसके परिणामस्वरुप जन्म दर में वृद्धि हुई होगी। इस प्रकार यही से जनसंख्या में संगठित वृद्धि की परिघटना शुरू हुई होगी।

7.4.2 प्राचीन काल एवं मध्य ऐतिहासिक काल (ईसा पूर्व 600 से 1650 ई. तक)

ईसा काल के प्रारंभ में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या 25 करोड़ थी जो वर्ष 1650 ई. में बढ़कर लगभग 54 करोड़ हो गई। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या आयोग के एक विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि ईसा पूर्व 1455 वर्षों में जहाँ जनसंख्या दो गुनी हुई थी वहीं ईसा पश्चात 1650 वर्षों में जनसंख्या दोगुनी हुई। ईसा पूर्व जो जनसंख्या वृद्धि दर 0.05% थी वह ईसा पश्चात घटकर 0.04% प्रतिवर्ष हो गई। इससे स्पष्ट होता है कि ईसा पश्चात जनसंख्या वृद्धि में थोड़ा कमी आई है। इस प्रकार देखा जाता है कि विश्व में प्राचीन से मध्यकाल तक की अवधि (600 ईसा पूर्व से 1650 ई) के मध्य में जनसंख्या वृद्धि दर में थोड़ा उतार – चढ़ाव देखा गया है।

7.4.3 आधुनिक काल (1650 ई. के बाद)

17वीं शताब्दी के मध्यकल से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि की तीव्रता देखी गई है। ईसा काल की 25 करोड़ जनसंख्या को दोगुना होकर जहाँ 54 करोड़ होने में 1650 वर्ष लगे। वहीं यही जनसंख्या मात्र 158 वर्षों में 100 करोड़ हो गई। इस प्रकार अब जनसंख्या वृद्धि के तीव्र चरण की शुरुआत होती है। रामकुमार तिवारी अपनी पुस्तक जनसंख्या भूगोल में लिखते हैं कि 1650 ई. में जो जनसंख्या वृद्धि दर 0.04% थी, वह बढ़कर 1700 ई. में 0.36% तथा 1750 में घटकर 0.30% देखी जाती है। इसके पश्चात पुनः जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जाती है। 1800 ई. में जनसंख्या वृद्धि दर 0.56% दर्ज की गई है तथा 1808 ई. में यह वृद्धि दर घट करके 0.15% प्राप्त होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि में भले ही उतार – चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई, परंतु 158 वर्षों अर्थात 1808 ई. में जनसंख्या ने 100 करोड़ की सीमा को स्पर्श कर लिया।

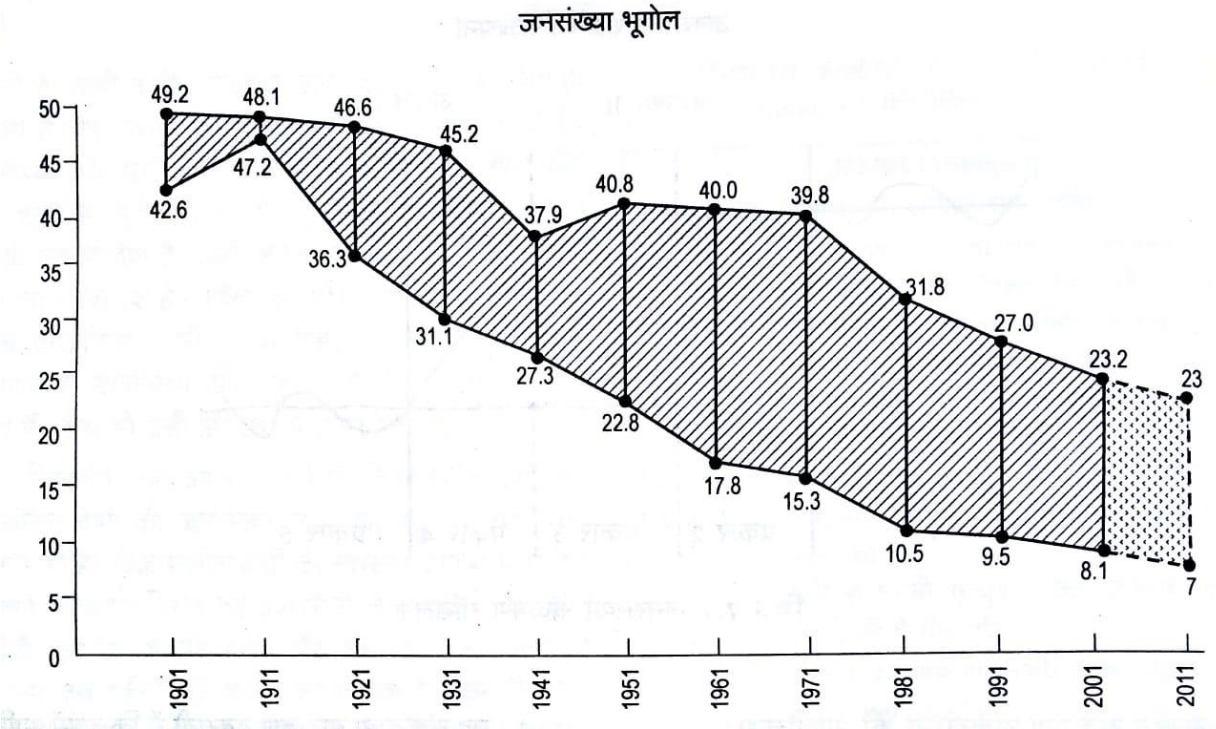

चित्र संख्या 7.1 विश्व जनसंख्या की जन्म दर एवं मृत्यु दर में समय के अनुसार परिवर्तन.

जनसंख्या में होने वाली वृद्धि सभी काल अवधियों में एक समान नहीं हुई है। कभी तीव्र हुई है तो कभी मंद। इसलिए इसमें होने वाले कालिक परिवर्तन को विभिन्न अवस्थाओं में विभक्त किया जाता है। इन्हीं अवस्थाओं जनसंख्या संक्रमण की अवस्था कहा जाता है। इसकी कई अवस्थाएँ पाई जाती है। प्रथम अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों उच्च होती है जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि की दर बहुत मंद होती है। द्वितीय अवस्था में मृत्यु दर में तीव्रता से कमी आती है जबकि जन्म दर यथावत बना रहता है जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि अत्यधिक

तीव्रता से होती है। जनसंख्या संक्रमण की तीसरी अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों में गिरावट आती है। इसका परिणाम यह होता है कि तीव्र गति से बढ़ने वाली जनसंख्या की वृद्धि दर में गिरावट आती है। साथ ही जनसंख्या में स्थायित्व की प्रवृत्ति देखी जाती है। जनसंख्या संक्रमण की सभी अवस्थाओं को निम्नलिखित चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।

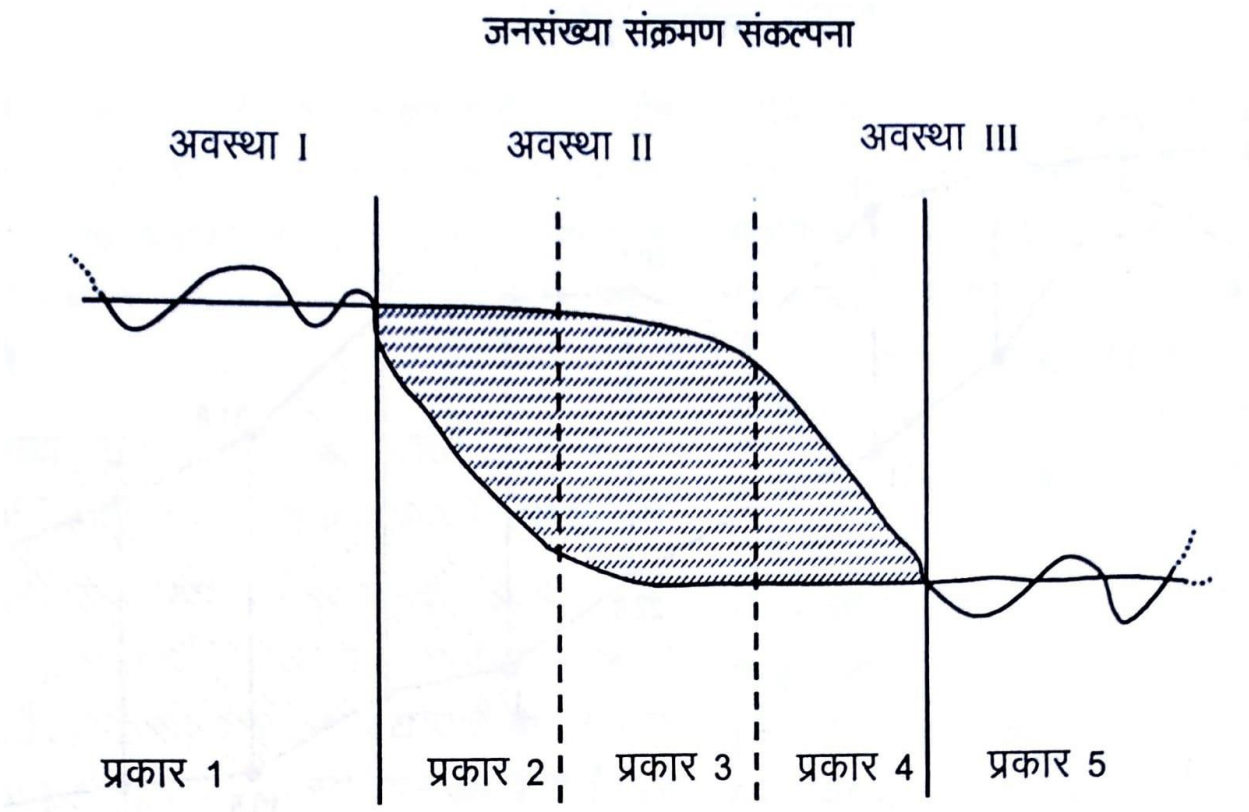

चित्र संख्या 7.2 विश्व जनसंख्या संक्रमण की अवस्था का आरेखीय प्रदर्शन.

आधुनिक काल में जनसंख्या वृद्धि के दो चरण देखे जाते हैं –

1. यूरोपीय खोज एवं उपनिवेशवाद का विस्तार
2. औद्योगिक क्रांति की शुरुआत

जनसंख्या वृद्धि के दृष्टिकोण से 20वीं शताब्दी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें जो जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई वह पूर्व में कभी नहीं थी । जनसंख्या के बढ़ने एवं घटने का क्रम 1650 ई. से शुरू होता है और 1920 तक जारी रहा। वर्ष 1920 के पश्चात जनसंख्या वृद्धि दर में घटने की प्रवृत्ति समाप्त हो गई। वर्ष 1920 से 1970 तक की अवधि में तीव्र वृद्धि दर दर्ज की गई है। वर्ष 1970 के पश्चात इसमें कुछ कमी आने लगी।

प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 10 लाख वर्षों के पश्चात वर्ष 1800 ई. में विश्व की जनसंख्या पहली बार 100 करोड़ के आंकड़े को छुई थी। इसके पश्चात 200 करोड़ होने में उसे 120 वर्ष लगे जबकि 200 करोड़ से 300 करोड़ होने में मात्र 32 वर्ष लगे थे । स्वास्थ्य सुविधाएं, पोषण आपूर्ति, जन कल्याण जैसी सुविधाओं में तेजी से वृद्धि होने के कारण यह वृद्धि दर और तीव्र हो जाती है तथा जनसंख्या के 300 करोड़ से 400 करोड़ होने में मात्र 15 वर्ष लगे। वैश्विक जनसंख्या वृद्धि का यह क्रम आगे भी जारी रहा जिसके कारण 400 करोड़ से 500 करोड़ होने में 13 वर्ष 500 करोड़ से 600 करोड़ होने में 12 वर्ष एवं 600 करोड़ से 700 करोड़ होने में मात्र 11 वर्ष का समय लगा है।

7.5 विश्व के महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि

जनसंख्या का वितरण संपूर्ण विश्व में एक समान नहीं है । कहीं पर उसका जमाव अधिक तो कहीं कम है। कोई क्षेत्र प्राचीन काल से अधिवासित है तो कहीं पर जनसंख्या का संकेंद्रण विगत कुछ वर्षों अथवा सदियों में हुआ। इस प्रकार वैश्विक स्तर पर जनसंख्या के वितरण, जमाव एवं वृद्धि के दृष्टिकोण से निम्न स्वरूप प्रकट होते हैं –

- एशिया एवं यूरोप मानव सभ्यता के उद्भव केंद्र माने जाते हैं। प्राचीन काल से ही ये क्षेत्र आबाद रहे हैं, इसलिए इन दोनों महाद्वीपों में जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है।
- अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अपनी विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अल्प बसाव वाले क्षेत्र हैं।
- उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका अन्वेषण यात्राओं के दौरान खोजे गए महाद्वीप हैं, इसलिए इन्हें नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अधिक मात्रा में प्रवासियों के आगमन के कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है।
- प्रत्येक महाद्वीप की अपनी – अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण जनांकिकीय, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विशेषताएं अलग – अलग हैं। इन सभी का प्रभाव वहाँ की जनसंख्या वृद्धि पर संयुक्त रूप से देखा जाता है।
- जनसंख्या वृद्धि के दृष्टिकोण से यूरोपीय देश, अमेरिका एवं जापान जैसे विकसित देश तथा एशिया, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका के विकासशील देशों में अंतर पाया जाता है। जहाँ विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि दर मंद है वहीं विकासशील देशों में यह प्रवृत्ति अति तीव्र है।

7.5.1 एशिया

एशिया विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। वर्ष 1650 ई. में एशिया की जनसंख्या 32.7 करोड़ थी, जो 361 वर्ष के पश्चात वर्ष 2011 ई. में 414 करोड़ हो गई। इससे स्पष्ट होता है कि इस अवधि में जनसंख्या में 1155 प्रतिशत की वृद्धि हुई है अर्थात संपूर्ण जनसंख्या 12.5 गुना बढ़ गई है। रामकुमार तिवारी अपनी पुस्तक जनसंख्या भूगोल में लिखते हैं कि वर्ष 1650 ई. में यहाँ विश्व की 60.6% जनसंख्या निवास करती थी, जो बढ़कर 1800 ई. में 66.4% तक हो गई। इसके पश्चात इसमें कुछ गिरावट आती है और वर्ष 2011 ई. में यह 60. 6% दर्ज की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि 360 वर्ष पहले भी एशिया सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप था और आज भी है।

एशिया महाद्वीप के कुछ देशों की जनसंख्या वृद्धि दर विस्फोटक स्थिति में है, जिसके कारण यह देश सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या जोड़ रहे हैं। इन देशों में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 3ः से अधिक है। इन देशों में अफगानिस्तान (6.3%), इजरायल (4.7%), सऊदी अरब (3.4%), ओमान (3.6%), इराक (3.2%) सम्मिलित हैं। इसके साथ ही कंबोडिया (2.5%), बांग्लादेश (2.4%), ईरान (2.7%), भारत (1.9%) एवं चीन (0.8%) प्रतिशत की दर से अधिक संख्या में जनसंख्या जोड़ रहे हैं ।

7.5.2 अफ्रीका

अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ प्रतिकूल प्राकृतिक दशाओं के साथ – साथ महामारी, विषम जलवायु, प्राकृतिक एवं मानवीय प्रकोप तथा चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण 50 व्यक्तिप्रति हजार जन्म दर थी तो इसी के कुछ ऊपर मृत्यु दर भी थी इसका प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँ की जनसंख्या वृद्धि पर देखा गया है । वर्ष 1650 ई. में इसकी जनसंख्या 10 करोड़ थी, इसके पश्चात 1750 ई. में यह घटकर 9.5 करोड़ हो गई तथा 1800 ई. में पुनः घटकर 9 करोड़ हो जाती है। वर्ष 1900 ई. तक यहाँ की जनसंख्या में अनेक उतार – चढ़ाव देखे गए और कुल जनसंख्या बढ़कर 12 करोड़ तक पहुंच गई। 19वीं सदी के प्रारंभ से लेकर मध्यकाल की अवधि तक एशिया एवं यूरोपीय देशों से अधिक संख्या में प्रवास अफ्रीका में हुआ। एशियाई लोग अफ्रीका के पूर्वी भाग में बसे जबकि अधिकांश यूरोपिय पश्चिमी भाग में बसे। इसमें अधिकांश लोग उपनिवेशों के बागानों में काम करने हेतु लाए गए थे। इन सभी का प्रभाव यह हुआ कि वर्ष 1950 ई. तक अफ्रीका की जनसंख्या लगभग 22.4 करोड़ तक

पहुंच गई थी। इसके पश्चात अधिकांश अफ्रीकी देश औपनिवेशिकता से आजाद हुए। इसके फलस्वरुप स्वास्थ्य एवं जीवन के अन्य सुविधाओं में विकास हुआ। इससे महामारियों एवं बीमारियों पर नियंत्रण पाया गया। जिससे जनसंख्या वृद्धि दर तेज हो गई और यह 1980 ई. में 48 करोड़ दर्ज की गई थी। इसके पश्चात भी यह वृद्धि जारी रही जिसके कारण अफ्रीका की संपूर्ण जनसंख्या बढ़कर 1990 में 64 करोड़ था 2001 में 73.58 करोड़ हो गई है।

जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारक जन्म दर एवं मृत्यु दर में भी परिवर्तन अधिक देखी गई है। अफ्रीका में वर्ष 1970 – 75 की अवधि में जन्म दर 46.5 प्रति हजार थी, जो घटकर 1990 – 95 में 41.9 प्रति हजार दर्ज की गई है। यह प्रवृत्ति आगे भी जारी रही और वर्ष 2004 में यह 38 दर्ज की गई है। इसी प्रकार मृत्यु दर में भी गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। वर्ष 1950 ई. में संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप में औसत मृत्यु दर 33 प्रति हजार थी, जो घटकर 1990 ई. में 16 प्रति हजार हो गई। इसी प्रकार 2004 में घटकर यह 14 प्रति हजार रह गई थी, इस प्रकार वर्ष 2004 में अफ्रीका की प्राकृतिक वृद्धि दर 24 प्राप्त होती है, जो एक तीव्र वृद्धि दर कही जाती है।

7.5.3 यूरोप

यूरोप की गिनती मानव के प्रारंभिक बसाव वाले स्थलों में की जाती है। वर्ष 1650 ई. में इसकी संपूर्ण जनसंख्या 10 करोड़ थी जो विश्व की कुल जनसंख्या का 18% थी। उपनिवेशवाद एवं औद्योगिक क्रांति ने यहाँ तीव्र जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन दिया इसी के फलस्वरुप वर्ष 1800 ई. में यूरोप की कुल जनसंख्या 18.7 करोड़ हो गई थी। 1850 ई. में 26.6 करोड़ 1920 में 40.01 करोड़ तथा 2001 तक यह बढ़कर 67.63 करोड़ तक पहुंच गई थी।

वैश्विक जनसंख्या में यूरोप की जनसंख्या की भागीदारी में गिरावट की प्रवृत्ति देखी जा रही है। वर्ष 1920 में इसकी भागीदारी जहाँ 24.9% थी, वहीं घटकर वर्ष 1950 में 21.7 प्रतिशत रह गई है। नवीनतम आंकड़ों में इसके और तीव्र ह्रास का प्रतिरूप देखा गया है। वर्ष 2001 में 11.2% थी तथा 2011 में घटकर संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का मात्र 10.5% रह गई है।

7.5.4 उत्तरी अमेरिका

उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका अन्वेषण पुनर्जागरण काल में खोजी यात्राओं के दौरान हुआ है। जनसंख्याविदों का मानना है कि वर्ष 1650 ई. में यहाँ की जनसंख्या 10 लाख थी, जिनमें अधिकांश लोग मूल निवासी थे और स्वतंत्र रूप से रह रहे थे। खोज के पश्चात यूरोपीय लोगों का अधिक संख्या में यहाँ आगमन हुआ, जिसके कारण यहाँ की जनसंख्या बढ़ने लगी वर्ष 1850 ई. में यहाँ की जनसंख्या बढ़कर 2.6 करोड़ हो गई। अमेरिका में अधिक संख्या में लोगों का प्रवास क्रम 18वीं सदी के प्रारंभ से शुरू होकर 20वीं सदी तक चलता है। इसी का परिणाम था कि वर्ष 1920 ई. में इसकी संपूर्ण जनसंख्या 8.1 करोड़ दर्ज की गई, वहीं 1950 ई. में यह बढ़कर 22 करोड़ हो गई । द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात अमेरिका एक महाशक्ति बन गया, जिसका प्रभाव वहाँ की जनसंख्या वृद्धि में भी प्रत्यक्ष रूप से देखा गया। वर्ष 2001 ई. में इसकी संपूर्ण जनसंख्या बढ़कर 49.18 करोड़ दर्ज की गई। जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में उत्तरी अमेरिका में दो स्वरूप देखे जाते हैं, कनाडा एवं मध्य अमेरिका के देशों में जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतराल अधिक होने के कारण वृद्धि दर तीव्र है।

उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या वृद्धि की प्रकृति का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि इसमें उतार – चढ़ाव अधिक है। वर्ष 1980 – 85 ई. में यहाँ वार्षिक वृद्धि दर 1.3% थी, जो 1990 – 95 में बढ़कर 1.4% हो गई थी। 2001 में इसमें भारी गिरावट आई और यह 0.5 प्रतिशत दर्ज की जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना में पुनः इसमें वृद्धि देखी जाती है और यह वृद्धि दर 0.7% वार्षिक दर्ज की जाती है।

7.5.5 दक्षिणी अमेरिका

दक्षिणी अमेरिका भी प्रारंभिक सभ्यताओं के केंद्र स्थल के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1650 ई. में यहाँ की कुल जनसंख्या मात्र 1.2 करोड़ थी। उत्तरी अमेरिका की तुलना में यहाँ प्रवासियों का आगमन कुछ समय बाद होता है। वर्ष 1750 ई. की जनगणना में ऋणत्मक वृद्धि देखी जाती है और कुल जनसंख्या 1.11 करोड़ दर्ज की गई। प्रवासियों के आगमन से इसमें तीव्रता की प्रवृत्ति देखी जाती है। इस प्रकार यह वर्ष 1800 ई. में बढ़कर 3.3 करोड़ हो गई, 1850 ई. में यह 6.3 करोड़ तथा वर्ष 1900 ई. में बढ़कर 17 करोड़ दर्ज की गई थी। इस अप्रत्याशित वृद्धि

का मूल कारण अधिक संख्या में यूरोपीय प्रवासियों का आगमन था। वर्ष 1950 ई. की जनगणना में इसमें कुछ गिरावट आती है और यह 11.2 करोड़ दर्ज की जाती है। इसके पश्चात पुनः वृद्धि का क्रम जारी रहा, जिसके फलस्वरुप वर्ष 2011 ई. में जहाँ यह 35.73 करोड़ थी वहीं 2011 की जनगणना में बढ़कर 38.557 करोड़ दर्ज की गई है। वर्ष 1950 ई. में अचानक गिरावट का कारण प्रवासियों के आगमन पर सरकारी प्रतिबंध था। दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर में भी परिवर्तन देखा गया है। वर्ष 1980 – 85 की अवधि में यह 2.1% वार्षिक था, जो घटकर 1990 – 95 ई. में 1.7% हो जाता है। इसके पश्चात भी यहाँ की जनसंख्या में गिरावट का क्रम जारी रहता है। वर्ष 2001 में यह घटकर 1.2% प्राप्त होता है जबकि 2001 में यह और घटकर 0.8% पर चला जाता है।

7.5.6 ओसिनिया

ओसिनिया महाद्वीप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पॉलिनेशन, माइक्रोनेशिया एवं मलेनेसिया आदि भूभाग सम्मिलित होते हैं। वर्ष 1650 ई. में इस संयुक्त महादेश की जनसंख्या 20 लाख थी। प्राकृतिक प्रकोप एवं महामारी के कारण 1800 ई. तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और यह स्थावत बनी रही। यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका से अधिक मात्रा में प्रवासियों के आगमन के कारण वर्ष 1850 में यहाँ की जनसंख्या बढ़कर 60 लाख हो गई, जो 1900 ई. तक बनी रही। 20वीं शताब्दी में यहाँ आने वाले प्रवासियों की संख्या में और अधिक वृद्धि देखी गई, जिसके फलस्वरुप वर्ष 1950 ई. में इसकी संपूर्ण जनसंख्या बढ़कर 1.3 करोड़ हो गई। इसी प्रकार वर्ष 2001 में 3.07 करोड़ तथा 2011 में 3.61 करोड़ दर्ज की गई। ओसिनिया में जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 1980 – 85 से 1990 – 95 के मध्य 1.5ः दर्ज की गई है। उसके पश्चात 2001 में इसमें गिरावट आती है और यह एक प्रतिशत दर्ज की जाती है, पुनः कुछ कारणों से इसमें वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई और 2011 में यह 1.6% प्राप्त होती है।

7.6 भारत में जनसंख्या वृद्धि

भारत प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का पालना रहा है। प्राचीन काल से वर्तमान समय तक यहाँ अनेकों प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँ की जनसंख्या पर पड़ा है। यहाँ की जनसंख्या में धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार की वृद्धि देखी गई है। जनसंख्या भूगोलविदों का मानना है कि भारत में प्रथम अनुमानित जनसंख्या का आंकड़ा वर्ष 1750 ई. में परिगणित किया गया था, परंतु आधुनिक पद्धति पर आधारित जनगणना की शुरुआत भारत में वर्ष 1872 ई. में लॉर्ड मेयो द्वारा शुरू की गई थी। नियमित जनगणना वर्ष 1881 से 2011 तक अनवरत रूप से चली है। 2020 में कोरोना महामारी के वैश्विक पर प्रसार के कारण 2021 की जनगणना नहीं हो पाई है इसी कारण हम जनसंख्या के अध्ययन हेतु वर्ष 2011 के आंकड़ों को ही आधार मानते हैं।

7.7 भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति

नियमित जनगणना प्रारंभ होने के पश्चात भारत का जनसंख्या इतिहास 20वीं शताब्दी में अधिक परिवर्तनशील रहा है। प्राप्त आंकड़ों से विदित होता है कि 20वीं शताब्दी में जनसंख्या में चार गुना वृद्धि हुई है। इस प्रकार भारत के जनांकिकीय इतिहास का वर्णन चार भागों में विभक्त करके किया जाता है –

1. स्थाई जनसंख्या वृद्धि का काल (1901 ई. से 1921 ई.)
2. धीमी जनसंख्या वृद्धि का काल (1921 ई. से 1951 ई.)
3. तीव्र जनसंख्या वृद्धि का काल (1951 ई. से 1981 ई.)
4. उच्च जनसंख्या वृद्धि के साथ घटती प्रकृति का काल (1981 ई. से 2011 ई.)

वर्ष 1901 ई. से 1921 ई. के बीच भारत की जनसंख्या स्थायी पाई जाती है। इस अवधि में यहाँ की जनसंख्या 23.6 करोड़ से बढ़कर 24.8 करोड़ होती है। इसके कारणों का अन्वेषण करने पर विदित होता है कि इस समय उच्च मृत्यु दर पाई जाती है, जो की उच्च उत्पादकता के लगभग बराबर थी। इस समय उत्पादकता दर एवं मर्त्यता दर दोनों 40 प्रति हजार से अधिक दर्ज की गई थी। आर. सी. चांदना लिखते हैं कि इस समय की उच्च मर्त्यता दर के मुख्य कारण महामारी, अकाल, खाद्य पदार्थों की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं की अपर्याप्तता इत्यादि थे।

इसका परिणाम यह हुआ कि जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों एक दूसरे को संतुलित किए हुए थे तथा जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत मंद भी थी। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत की जनसंख्या इतिहास में वर्ष 1921 ई. को जनसंख्या का महाविभाजक भी कहा जाता है। वर्ष 1921 ई. के पश्चात भारत की जनसंख्या में कभी भी ऋणात्मक वृद्धि नहीं हुई और उसके पश्चात वृद्धि दर में लगातार तीव्रता देखी गई है।

सारणी 7.1 भारत में जनसंख्या वृद्धि (1901 – 2011)

क्र. सं.	वर्ष	कुल जनसंख्या (करोड़ में)	जनसंख्या में वार्षिक औसत वृद्धि (प्रतिशत में)	वर्ष 1901 की तुलना जनसंख्या वृद्धि दर (प्रतिशत में)	पूर्ववर्ती दशक की तुलना में वृद्धि दर (प्रतिशत में)
1.	1901	23.62	–	–	–
2.	1911	24.91	0.56	5.75	5.75
3.	1921	24.81	0.03	5.42	–0.31
4.	1931	27.64	1.04	17.02	11.00
5.	1941	31.54	1.33	33.67	14.22
6.	1957	36.03	1.25	51.47	13.31
7.	1961	43.91	1.96	84.25	21.64
8.	1971	54.81	2.20	129.94	24.80
9.	1981	68.53	2.22	186.64	24.66
10.	1991	84.44	2.16	255.05	23.87
11.	2001	102.81	1.97	331.52	21.54
12.	2011	121.01	1.64	407.64	17.64

स्त्रोतः जनगणना विभाग, लखनऊ.

वर्ष 1921 ई. से वर्ष 1951 ई. तक की अवधि भारतीय जनगणना इतिहास में धीमी गति से अनवरत वृद्धि के काल के रूप में जाने जाती है। इस अवधि में भारत की कुल जनसंख्या 24.8 करोड़ से बढ़कर 36 करोड़ हो गई। इस प्रकार इस 30 वर्षों की अवधि में 11.02 करोड़ की वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता, साक्षरता में वृद्धि, अस्वाभाविक मृत्यु पर रोक, महामारी एवं अकाल पर नियंत्रण के कारण भारतीय जनसांख्यिकी के

दृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। देश के विभिन्न भागों में आपातकालीन स्थिति का सामना करने लिए सुदृढ़ वितरणतंत्र के साथ ही अवसंरचनात्मक विकास भी अधिक मात्रा में हुए थे। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता एवं अवस्थाओं में महत्वपूर्ण सुधार हुआ और मृत्यु दर में गिरावट आई है नीचे दी गई सारणी 7.01 से स्पष्ट होता है कि जहाँ वर्ष 1921 ई. में अनुमानित मृत्यु दर 47 प्रति हजार थी वह 1951 ई. में घटकर 27 प्रति हजार हो गई।

सारणी 7.2 भारत में जन्म – दर, मृत्यु – दर एवं प्राकृतिक वृद्धि दर

क्र. सं.	वर्ष	जन्म – दर (प्रति हजार)	मृत्यु – दर (प्रति हजार)	प्राकृतिक वृद्धि दर
1.	1911	49	43	6
2.	1921	48	47	1
3.	1931	46	36	10
4.	1941	45	31	14
5.	1951	40	27	13
6.	1961	42	23	19
7.	1971	37	15	23
8.	1981	34	12	22
9.	1991	31	11	20
10.	2001	25	08	17
11.	2011	22	7	15

स्त्रोतः जनगणना विभाग, लखनऊ.

इस प्रकार देखा जाता है कि वर्ष 1921 ई. से 1951 ई. के मध्य मृत्यु दर में तीव्रता से गिरावट आती है जबकि जन्म दर अभी भी 40 प्रति हजार पर ही बना था। इसके कारण भी जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि देखी गई है। कुछ जनसंख्या इतिहासकारो द्वारा वर्ष 1951 ई. को भी महत्वपूर्ण जनसंख्या विभाजन के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि 1951 ई. के पश्चात भारत की जनसंख्या में अप्रत्याशित गति से वृद्धि दर्ज की जाती है।

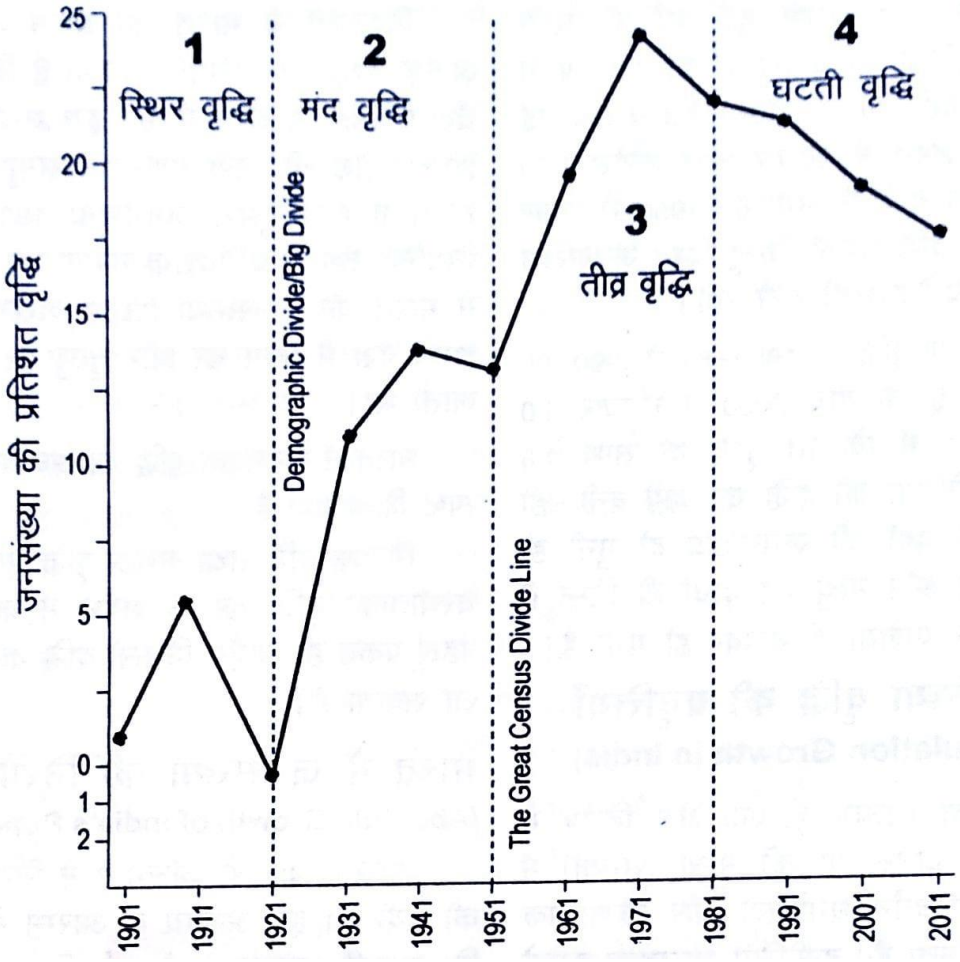

चित्र संख्या 7.3 भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति.

वर्ष 1951 ई. से 1981 ई. तक की अवधि भारतीय जनसंख्या इतिहास में तीव्र जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में जानी जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार द्वारा अनेकों कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर में और तीव्रता से कमी आई। जो मृत्यु दर वर्ष 1951 ई. में 27 प्रति हजार थी, वह गिरकर वर्ष 1981 ई. में 12 प्रति हजार रह गई थी। दूसरी तरफ जन्म दर में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ और वह अभी भी 34 प्रति हजार दर्ज किया गया था। ऐसी स्थिति में जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच में अंतराल बढ़ने से 1951 ई. से 1981 ई. के मध्य जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि दर्ज की गई थी। वर्ष 1951 ई. के पश्चात देश की जनसंख्या में अप्रत्याशित गति से वृद्धि हुई और वह 36 करोड़ से बढ़कर 68.5 करोड़ हो गई। इस प्रकार देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि भारत में विगत 100 वर्षों में यह सर्वाधिक वृद्धि वाली अवधी थी। आर. सी. चांदना लिखते हैं कि स्वतंत्रता उपरांत जहाँ एक ओर मृत्यु दर पर अंकुश लगाने का हर संभव प्रयास किया गया था, वहीं दूसरी ओर आर्थिक एवं सामाजिक विकास की प्रक्रिया को भी प्रारंभ किया गया। इन सभी प्रयासों का मृत्यु दर पर तो अनुकूल प्रभाव पड़ा और उसमें तीव्रता से गिरावट आई जबकि जन्म दर की प्रवृत्ति में कोई खास परिवर्तन नहीं देखा गया। जनसंख्या विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे विशाल देश में जहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विभिन्नताएं अधिक पाई जाती हैं वहाँ जन्म दर में गिरावट लाना बहुत कठिन काम है।

भारतीय जनसंख्या के इतिहास में वर्ष 1981 ई. एक और महत्वपूर्ण काल का प्रारंभ करता है, जिसे देश में जनसंख्या वृद्धि के ह्रास काल के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1981 ई. के पश्चात देश की जनसंख्या वृद्धि में पहली बार गिरावट देखी गई। वर्ष 1981 ई. से 1991 ई. की अवधि में भारत की जनसंख्या में 23.86 प्रतिशत की

दर से वृद्धि हुई है, जो पिछले दशक 1970 ई. से 1981 ई. की तुलना में 0.8% कम थी । वर्ष 1991 ई. से 2001 ई. की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर में और अधिक गिरावट देखी जाती है, जो वर्ष 2001 में 21.54% दर्ज की गई थी। इसी प्रकार यह वृद्धि दर पिछले दशक से 2.52% कम थी। इसी प्रकार 2001 ई. से 2011 ई. की अवधि में भी जनसंख्या वृद्धि दर की गिरावट में तीव्रता अधिक हुई और इस अवधि की वृद्धि दर 17.64% दर्ज की जाती है। इस दशक की वृद्धि दर पिछले दशक की तुलना में 3.9% कम प्राप्त होती है। सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन, बढ़ती शिक्षा तथा सीमित परिवार के प्रति लोगों के रुझान के कारण जनसंख्या में अत्यधिक गिरावट देखी गई है, दूसरी तरफ मृत्यु दर पहले से ही नियंत्रित थी। इस दौरान मृत्यु दर में और गिरावट आती है और अब यह 8 प्रति हजार तक पहुंच गई है। यह अपने आप में एक उपलब्धि से कम नहीं है। देश के विशाल आकार, बहुविध सामाजिक संरचना, धार्मिक मान्यताएं तथा कुछ व्यक्तिगत कारकों के कारण अभी भी देश में जन्म दर 22 प्रति हजार बनी हुई है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले दशकों में जन्म दर की गिरावट में और तीव्रता आएगी, जो देश की तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या पर अंकुश लगाने में सफल होगी।

भारत की ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में वृद्धि

भारत में जनसंख्या वितरण की असमानता का एक अन्य स्वरूप ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या की भिन्नता है। यह भिन्नता जनसंख्या के सभी घटकों वितरण, वृद्धि, संरचना एवं में देखी जाती है। सम्पूर्ण भारत की जनसंख्या के साथ ही भारत की ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्ति में अंतर अधिक पाया जाता है।

सारणी 7.3 भारत की ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्ति

क्र. सं.	वर्ष	कुल जनसंख्या में वृद्धि	ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि	नगरीय जनसंख्या में वृद्धि
1.	1901	——	——	——
2.	1911	5.75	6.41	0.35
3.	1921	−0.31	−1.29	8.27
4.	1931	11.00	9.96	19.13
5.	1941	14.22	11.82	31.97
6.	1951	13.31	8.80	40.43
7.	1961	21.64	20.49	26.41
8.	1971	24.81	21.86	38.23
9.	1981	24.67	19.32	46.15
10.	1991	23.88	20.01	36.46
11.	2001	21.54	18.34	31.13
12.	2011	17.63	12.20	31.80

स्त्रोतः जनगणना विभाग, लखनऊ.

7.8 सारांश

आपने इस इकाई में विश्व में जनसंख्या वृद्धि, भारत में जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन किया है। आप समझ गए होगें कि जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है चाहे वह विश्व की हो या भारत की हो। इससे उसके समय एवं काल विविध अवधियों में परिवर्तन की प्रवृत्तियों की विस्तृत जानकारी मिलती है तथा जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या वृद्धि के विविध पक्षों के अध्ययन को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। वास्तव में किसी देश की जनसंख्या तथा वहाँ का सबसे बड़ा संसाधन होती है जो उसकी भौगोलिक अवस्थिति, सरकारी नीतियों, सांस्कृतिक संगठन आदि के आधार पर होता है। विश्व हो या भारत जनसंख्या वृद्धि की दर सभी जगह समान नहीं रही है। कभी उसमें धनात्मक परिवर्तन हुआ है तो कभी ऋणात्मक। भारत की जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति भी निरंतर जारी है। वर्ष 1921 ई. की जनगणना को यदि छोड़ दिया जाए तो अभी तक सभी जनगणनाओं में धनात्मक वृद्धि हुई है। इसमें क्षेत्रीय असमानता देखी गई है, जहाँ उत्तरी राज्यों की वृद्धि दर तीव्र है वहीं दक्षिणी राज्यों की मंद है। इसी प्रकार घनत्व, साक्षरता, नगरीकरण आदि में भी भिन्नता देखी जाती है।

7.9 स्वमूल्यांकन प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

1. विश्व की कुल जनसंख्या 500 करोड़ कब हुई थी।

   (क) 1800 ई. (ख) 1950 ई. (ग) 1988 ई. (घ) 2000 ई.

2. ईसा पूर्व 8000 में कृषि क्रांति के प्रारम्भ के समय विश्व की जनसंख्या कितनी थी।

   (क) 130 लाख (ख) 150 लाख (ग) 60 लाख (घ) 80 लाख

3. वर्ष 1650 ई. विश्व की जनसंख्या कितनी थी।

   (क) 100 करोड़ (ख) 90 करोड़ (ग) 54 करोड़ (घ) 30 करोड़

4. विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है।

   (क) अफ्रीका (ख) एशिया (ग) यूरोप (घ) उत्तरी अमेरिका

5. भारतीय जनसंख्या इतिहास में महाविभाजक वर्ष के नाम से किसे जाना जाता है।

   (क) 1011 ई. (ख) 1951 ई. (ग) 1921 ई. (घ) 1981 ई.

7.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

Bogue] D- J-] 1969] Principles of Demography] John Wiley] N-Y-

Clarke] John I-] 1973] Population Geography] Pergaman Press] Oxford-

Crook] Nigel] 1997] Principles of Population and Development] Pergaman Press] N- Y-

Garmier] J- B-] 1970] Geography of Population] Longman] London-

Mamoria] C- B-] 1981] India's Population Problem] Kitab Mahal] New Delhi-

Premi] M- K-] 1991] India's Population] Heading Towards a Billion] B- R- Publishing Corporation-

Blassoff] M- and Srinivasan K-] 2001] Population Development Nexus in India : Challenges for the New Millennium] Tata McGraw Hill] New Delhi-

Woods] R-] 1979] Population Analysis in Geography] Longman] London-

Zelinsky] W-] 1966] A Prologue to Population Geography] Prentice Hall-

चन्दना, आर. सी., 2022, जनसंख्या भूगोल – संकल्पना, नियंत्रक व विश्व प्रारूप, कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

चन्दना, आर. सी., 2022, भारत : जनसंख्या (जनसंख्या भूगोल – भाग 2), कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

मौर्या, एस. डी., 2005, जनसंख्या भूगोल, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद.

ओझा, आर. पी., 1984, जनसंख्या भूगोल, प्रतिभा प्रकाशन.

हीरा लाल, 2000, जनसंख्या भूगोल के मूल तत्व, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली.

तिवारी, राम कुमार, 2023, जनसंख्या भूगोल, प्रवालिका पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद.

7.11 अभ्यास प्रश्न (सत्रांत परीक्षा की तैयारी)

1. विश्व जनसंख्या वृद्धि के परिदृश्य की व्याख्या कीजिए ?
2. वैश्विक जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए ?
3. भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए?

इकाई–8 प्रजननता का अर्थ, प्रजननता के निर्धारक कारक

इकाई की रूपरेखा

8..0 प्रस्तावना

8.1 उद्देश्य

8.2 प्रजननता का अर्थ एवं परिभाषा

8.3 प्रजननता के निर्धारक कारक

8.4 प्राकृतिक कारक

8.5 जैविक कारक

8.6 सामाजिक कारक

8.7 राजनीतिक कारक

8.8 धार्मिक कारक

8.9 आर्थिक कारक

8.10 प्रजननता का वैश्विक प्रतिरूप

8.11 प्रजननता का भारतीय प्रतिरूप

8.12 सारांश

8.13 स्वमूल्यांकन प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

8.14 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

8.15 अभ्यास प्रश्न (सत्रांत परीक्षा की तैयारी)

8.0 प्रस्तावना

जनसंख्या अध्ययन में प्रजननता, उत्पादकता एवं उर्वरता को प्रायः समानार्थी शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसी स्थान विशेष की जनसंख्या वृद्धि अथवा परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों में प्रजननता, मर्त्यता एवं प्रवास को सम्मिलित किया जाता है। यही कारक जनसंख्या में गतिशीलता लाने हेतु उत्तरदायी होते हैं। दूसरे शब्दों में जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य जनसंख्या की गतिशीलता से है। सभी भूगोलवेत्ता जो जनसंख्या का अध्ययन करना चाहते हैं किसी स्थान की जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण सूचकों में उस स्थान की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक उत्थान और आर्थिक प्रगति सम्मिलित होते हैं। आर. सी. चांदना इसी बात को संदर्भित करते हुए अपनी पुस्तक जनसंख्या भूगोल में लिखते हैं की प्रजननता जनसंख्या का वह तत्व जिससे जनसंख्या के अन्य तत्व गहन रूप से जुड़े होते हैं, इसीलिए भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि किसी प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि को समझना उसकी संपूर्ण जनसंख्या की संरचना को समझने की कुंजी है।

8.1 उद्देश्य

प्रजननता प्रकृति प्रदत्त एक जैविक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जीव अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाते है। जैव मण्डल को अबाध रूप से चलाने हेतु यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इस इकाई के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं –

1. प्रजननता अर्थ एवं परिभाषा को समझना।

2. प्रजननता को निर्धारित करने वाले कारकों की व्याख्या करना।

8.2 प्रजननता का अर्थ एवं परिभाषा

जनसंख्या वृद्धि की संकल्पना से तात्पर्य अधिकांशतः किसी क्षेत्र विशेष में किसी निश्चित अवधि में वहाँ निवास करने वाली जनसंख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन सकारात्मक अथवा नकारात्मक दोनों प्रकार से हो सकता है। इस प्रकार जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को कुल परिवर्तन और प्रतिशत परिवर्तन दोनों प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कुल संख्या में परिवर्तन की क्रियाविधि का मापन सरल होता है। संख्या में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए वर्तमान जनसंख्या में से पूर्ववर्ती जनसंख्या को घटा दिया जाता है। जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए वर्तमान जनसंख्या एवं पूर्ववर्ती जनसंख्या के अंतर में वर्तमान जनसंख्या से भाग देकर 100 से गुणा किया जाता है। प्रजननता से तात्पर्य महिलाओं के समूह अथवा किसी महिला द्वारा एक निश्चित समयावधि में कुल सजीव जन्में बच्चों की वास्तविक संख्या है। प्रजननता की माप जीवित जन्मों के आधार पर की जाती है –

जे. आई. क्लार्क के अनुसार प्रजनन एक निश्चित अवधि में जीवित जन्मों की घटना है तथा इसका संबंध भ्रामक रूप से प्रजनन क्षमता से नहीं जोड़ना चाहिए जिसका अर्थ होता है पुनरुत्पादक क्षमता अथवा शिशु धारण क्षमता।

थाम्पसन एवं लेवी के अनुसार प्रजननता का संबंध किसी एक महिला या महिलाओं के समूह द्वारा एक निश्चित समय अवधि में कुल सजीव जन्में बच्चों की संख्या से जोड़कर देखा जाता है।

बर्क द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार प्रजननता का मौलिक अर्थ है जनसंख्या का एक वास्तविक स्तर द्वारा किसी समय विशेष में जीवित जन्म लेने वाली शिशुओं की संख्या से है।

बर्नार्ड बेंजामिन ने प्रजननता को निम्न रूप में स्पष्ट किया है एक निश्चित अवधि में प्रजननता उस दर की माप होती है, जिसके फलस्वरुप कोई जनसंख्या जन्म द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करती है।

प्रजननता मुख्य रूप से विवाहित दंपतियों की संख्या अथवा पुनरुत्पादन आयु वर्ग की महिलाओं की संख्या से जुड़ा हुआ है। इसमें सामान्यतः जनसंख्या के एक निश्चित वर्ग से कुल जीवित प्रसवों की संख्या ज्ञात किया जाता है।

किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अधिवासित जनसंख्या की प्रजननता की माप के संदर्भ में भी भूगोलवेत्ता एकमत नहीं है। अध्ययन का उद्देश्य आंकड़ों की उपलब्धता तथा अध्ययन हेतु प्रयोग की गई तकनीक के अनुसार प्रजननता की माप हेतु निम्नलिखित सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है –

1. अशोधित जन्म दर
2. प्रजनन अनुपात
3. सामान्य प्रजनन दर
4. आयु विशिष्ट दर
5. कुल प्रजनन दर
6. मानक प्रजनन दर
7. पुनरुत्पादन दर

8.3 प्रजननता के निर्धारक कारक

यद्यपि प्रजननता एक प्राकृतिक क्रिया है, जो विपरीत लिंग वाले लोगों के संसर्ग से संपन्न होती है। यह अनेक प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। यह प्रत्यक्ष रूप से वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय आयु, वैवाहिक जीवन काल, प्रजनन क्षमता, मनोवैज्ञानिक अवधारणा एवं स्वास्थ्य पर निर्भर होती है। प्रजननता के प्रभावित होने के साक्ष्य वैश्विक एवं स्थानिक दृष्टिकोण से भिन्न – भिन्न होते हैं। भिन्न – भिन्न समाजों, अलग – अलग समुदायों एवं विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में यह उल्लेखनीय अंतर के साथ प्राप्त होती है। इस प्रकार प्राकृतिक,

जैविक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक कारक जनसंख्या की प्रजननता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं–

सारणी 8.1 प्रजननता को प्रभावित करने वाले कारक

क्र. सं.	कारक	कारकों का विभाजन
1.	**प्राकृतिक कारक**	1. जलवायु कारक
		2. प्राकृतिक साधन
2.	**जैविकीय कारक**	1. प्रजातीय भिन्नता
		2. प्रजनन क्षमता
		3. स्वास्थ्य
		4. जन्म नियंत्रण के उपाय
3.	**सामाजिक कारक**	1. विवाह की आयु
		2. वैवाहिक जीवन की अवधि
		3. लैंगिक चयन
		4. महिलाओं का समाज में स्थान
		5. ग्रामीण एवं नगरीय परिवेश
		6. सामाजिक सुरक्षा
		7. विधवा विवाह
		8. शिक्षा
4.	**राजनीतिक कारक**	1. युद्ध
		2. देशांतरण
		3. सांप्रदायिक राजनीति
		4. राष्ट्रीय अवहेलना
		5. जनसंख्या नीति
5.	**धार्मिक कारक**	1. धार्मिक मान्यताएँ

		2. धार्मिक संरचना
		3. संतान के प्रति दृष्टिकोण
		4. पुत्र की अनिवार्यता
		5. वर्ण एवं जाति
6.	**आर्थिक कारक**	1. आय स्तर
		2. व्यावसायिक संरचना
		3. जीवन स्तर
		4. खाद्यान्न आपूर्ति
		5. आर्थिक वैभव
		6. विकास की अवस्था

स्त्रोत : जनसंख्या भूगोल, तिवारी, (2023).

8.4 प्राकृतिक कारक

प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत उन सभी तत्वों को रखा जाता है, जिनकी उत्पत्ति एवं संचालन प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। इन क्रियाविधि में मनुष्य की भूमिका नगण्य होती है। प्रमुख प्राकृतिक कारक निम्नलिखित हैं –

8.4.1 जलवायु

प्रजननता को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण है। तापमान एवं वर्षा की प्रभाविता सबसे ज्यादा होती है। व्यक्ति का रहन – सहन, खान – पान और स्वास्थ्य के साथ उसकी जैविक संरचना प्रत्यक्ष रूप से जलवायु से प्रभावित होती है। इसी का परिणाम है कि उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में रहने वाली लड़कियां शीघ्र ही राजस्वला होती हैं, जबकि शीत कटिबंध में इसकी उम्र ज्यादा होती है। प्रजनन क्षमता का सीधा संबंध राजस्वला से जुड़ा हुआ है। शीत एवं उष्ण प्रदेशों में निवास करने वाले लोगों के यौनिक संबंध स्वभाव में भी अंतर पाया जाता है। इसके साथ ही सहवास की बारंबारता एवं गर्भधारण क्षमता में भी भिन्नता होती है। भूगोलवेत्ताओं एवं अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि जिन क्षेत्रों में राजस्वला की उम्र कम होती है, वहाँ शीघ्र ही विवाह का प्रचलन अधिक देखा जाता है। इससे प्रजननता पर उत्प्रेरक प्रभाव पड़ता है। अफ्रीका जैसे उष्णकटिबंधीय देशों के साथ मानसूनी प्रदेशों में निवास करने वाले भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में प्रजननता जलवायु से अत्यधिक प्रभावित होती है।

8.4.2 प्राकृतिक संसाधन

विश्व के सभी देशों में प्राकृतिक संसाधनों एवं मानवीय संसाधनों का वितरण सामान नहीं पाया जाता है। जीवन यापन हेतु आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता एवं प्रतिकूलता से प्रजननता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ जलवायु की विविधता, उपजाऊ भूमि, प्रचुर मात्रा में जल, सिंचाई के साधन, श्रम संसाधन, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। वहाँ प्रजननता अधिक पाई जाती है। इसके अभाव वाले क्षेत्रों में प्रतिकूल दशाओं में यह प्रभावित होती है। जैसे मानसूनी प्रदेशों में जहाँ प्रजननता अधिक पाई जाती है वहीं उष्णकटिबंधीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश तथा शीत कटिबंध में प्रजननता की दर न्यून होती है।

8.5 जैविक कारक

इसके अंतर्गत उन सभी कारकों को सम्मिलित किया जाता है, जो मनुष्य की दैहिक, प्रजातीय एवं मानसिक स्थितियों से जुड़े होते हैं। प्रमुख जैविक कारक निम्नलिखित हैं –

8.5.1 प्रजातीय भिन्नता

यद्यपि जनसंख्या का वितरण तो संपूर्ण विश्व में पाया जाता है, फिर भी वह अनेक प्रजातियों में विभक्त है। इसके कारण संपूर्ण वितरण में एकरूपता नहीं देखी जाती है। विश्व की प्रमुख प्रजातियां में नीग्रो, निग्रिटो, ऑस्ट्रेलाइड, नार्डिक, भूमध्यसागरीय, अल्पाइन एवं मंगोलिक सम्मिलित हैं। जिस प्रकार प्रत्येक प्रजाति मनोवैज्ञानिक शारीरिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अलग – अलग पहचान रखती है। ठीक उसी प्रकार उनके जैविकीय गुण भी विकसित हो जाते हैं। इन्हीं सभी कारकों के प्रभाव से उनकी प्रजनन क्षमता अलग – अलग होती है। साथ ही साथ किसी भौगोलिक प्रदेश का सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य भी प्रजननता को प्रभावित करता है। यही कारण है कि एक ही क्षेत्र में निवास करने वाली भिन्न – भिन्न प्रजातियों की प्रजनन क्षमता अलग – अलग होती है।

8.5.2 प्रजनन क्षमता

प्रजनन क्षमता पूरी तरह से प्रकृति प्रदत्त होती है। इसकी अनुपस्थिति की दशा के आधार पर ही किसी महिला को बंध्या और पुरुष को नपुंसक नाम से जाना जाता है। महिलाओं में प्रजनन क्षमता जन्म से नहीं होती है बल्कि यह 12 से 15 वर्ष की आयु के मध्य शुरू होती है और 45 से 50 वर्ष के मध्य समाप्त हो जाती है। जहाँ प्रजनन क्षमता की शुरुआत को राजस्वला कहते हैं, तो इसकी समाप्ति को रजोनिवृत्ति। राजस्वला एवं रजोनिवृत्ति के मध्य की उम्र में महिलाएं बच्चों को जन्म देने में सक्षम होती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिन महिलाओं का मासिक धर्म जल्दी प्रारंभ होता है, उनकी समाप्ति भी पहले होती है। प्रजनन की उम्र सभी महिलाओं में एक समान नहीं होती, वह अलग – अलग होती है।

पुरुषों में प्रजनन क्षमता का प्रारंभ 10 से 12 वर्ष की अवधि में होता है और उसके संपूर्ण जीवन काल तक बना रहता है। प्रजनन क्षमता की होने के बावजूद भी अनेकों ऐसे कारण होते हैं, जिनके कारण एक पुरुष या महिला बच्चों को जन्म देने में सक्षम नहीं होते है। जैसे विधवा अथवा विदुर होना, तलाक हो जाना नपुंसकता अथवा बांधता की स्थिति, कोई अन्य यौन संबंधी रोग या विकृति। इन सभी कारकों के कारण व्यक्ति की प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है।

8.5.3 स्वास्थ्य

किसी स्त्री अथवा पुरुष का स्वस्थ्य होना भी एक प्रमुख जैविक कारक है। इससे व्यक्ति की प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। स्वस्थ्य दंपति प्रजननता का अधिक से अधिक लाभ उठा पाते हैं। अस्वस्थ्य या बीमारियों के कारण कभी – कभी व्यक्तियों की प्रजनन क्षमता पूर्णतःया आंशिक रूप से खत्म हो जाती है। भारत में यदि जनसंख्या इतिहास पर दृष्टिपात किया जाए तो वर्ष 1901 ई. से 1931 ई. के मध्य बीमारियों, अकाल एवं महामारी के कारण मृत्यु दर अधिक देखी गई है। इस दौरान प्रजनन दर भी अपेक्षाकृत कम अंकित की गई। सामान्य सामाजिक नियमों के तहत यह देखा गया है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में उच्च मृत्यु दर की स्थिति बनी रहती है। इसका परिणाम यह होता है कि लोग परिवार छोटा रखने की वरीयता नहीं देते, जिसके कारण जन्म दर में वृद्धि हो जाती है। भारत में आजादी के पश्चात स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से प्रसार होने से लोगों का स्वास्थ्य एवं जीवन प्रत्याशा दोनों बढ़ गई, जिससे जनसंख्या विस्फोटक हो गई। बाद में जागरूकता बढ़ाने के साथ ही लोगों ने परिवार नियोजन कर विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया है।

8.5.4 जन्म नियंत्रण के उपाय

यद्यपि प्रजननता प्रकृति प्रदत्त क्षमता या क्रियाविधि है, फिर भी कृत्रिम उपाय का प्रयोग करके इसे नियंत्रित किया जाता है। प्रसिद्ध विद्वान डोनाल्ड जी. बोग ने इसे सामाजिक घटक के अंतर्गत सम्मिलित किया है। प्रजननता को नियंत्रित करने वाले कारकों पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो, कुछ को छोड़कर अधिकांश जैविक ही है। इन नियंत्रक उपाय में नसबंदी, निरोध, लूप, गर्भ – निरोधक गोलियां, गर्भपात एवं शिशु हत्या जैसी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। बदलते आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश के कारण समाज में इन अवरोध उपायों की स्वीकार्यता बढ़ी है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने परिवार नियोजन हेतु जो प्रोत्साहन दिया था, उसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है। भारत की जनसंख्या अब ह्रासमान वृद्धि के साथ बढ़ रही है। प्रसिद्ध जनांकिकीय विद्वान लॉन्ड्री ने निरोधक उपायों के प्रयोग को जनांकिकीय क्रांति के नाम से संबोधित किया है।

8.6 सामाजिक कारक

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो सामाजिक संबंधों से गिरा हुआ है। उसके सामाजिक क्रियाकलापों में प्रजननता भी एक प्रमुख अवयव है। प्रजननता को प्रोत्साहन एवं अवरोध को अनेक सामाजिक कारक प्रभावित करते हैं, जिनका विश्लेषण निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है –

8.6.1 विवाह की आयु

रामकुमार वर्मा तिवारी ने अपनी पुस्तक जनसंख्या भूगोल में लिखा है कि स्त्री एवं पुरुष की कामजन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विवाह एक पवित्र सामाजिक व्यवस्था है, जो सामाजिक रूप से अत्यधिक घनिष्ठ एवं आत्मीयता से पूर्ण होता है। संतुलित व्यवहार के साथ प्रजनन प्रक्रिया को स्वीकृति प्रदान करता है। विवाह की आयु व्यक्तियों की प्रजनन क्षमता के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे – जैसे विवाह की आयु बढ़ती जाती है, पुर्नउत्पादन आयु वर्ग की अवधि कम होती जाती है। महिलाओं में सामान्यतः 19 से 30 वर्ष की अवधि में प्रजनन क्षमता सर्वाधिक होती है। इस आयु वर्ग में विवाह होने से प्रजनन क्षमता निश्चित रूप से जोखिम मुक्त होती है। इसी कारण जनसंख्या नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के विवाह की आयु में वृद्धि करने का प्रोत्साहन दिया जाता है।

8.6.2 वैवाहिक जीवन की अवधि

किसी व्यक्ति की प्रजनन क्षमता को निर्धारित करने में आयु की भूमिका अधिक होती है परंतु जनांकिकीविदों का मानना है कि वैवाहिक जीवन की अवधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। आर. के. तिवारी लिखते हैं कि आयु विशिष्ट प्रजनन दर की एक परोक्ष विधि है, परंतु यदि आयु के स्थान पर वैवाहिक जीवन की अवधि को प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो इसके परिणाम अधिक सार्थक होंगे। किसी एक निश्चित वर्ष की अवधि में विवाहित स्त्रियों की संख्या तथा उनके पूरे प्रजनन काल में जन्मे बच्चों की संख्या के आधार पर इसकी गणना की जाती है। विभिन्न अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि वैवाहिक जीवन की प्रारंभिक अवधियों में बच्चों का अधिक जन्म होता है, जबकि बाद में यह क्रमशः घटता जाता है, इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रारंभिक अवधि में ही संतति निग्रह की आवश्यकता होती है।

8.6.3 लैंगिक चयन

अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारणों से गर्भस्थ शिशु के लिंग की जानकारी होते ही उसे नष्ट कर दिया जाता है। कभी – कभी कुछ अवांछित गर्भधारण की स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में या तो गर्भपात करा दिया जाता है या तो प्रसव के पश्चात ही अनिश्चित शिशु की हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार की क्रियाओं से भी प्रजननता प्रभावित होती है।

8.6.4 समाज में महिलाओं का स्थान

अधिकांश समाज में महिलाओं को घरेलू कार्यों एवं संतान उत्पादन तथा उनके पालन पोषण का साधन समझा जाता है। कुछ समाजों में अधिक बच्चा पैदा करने वाली महिलाओं को आदर भी दिया जाता है, जिन समाजों की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति निम्न स्तरीय होती है, वहाँ महिलाओं की स्थिति बेहद नाजुक होती है। ऐसी स्थिति में वहाँ की प्रजनन दर अधिक पाई जाती है।

8.6.5 ग्रामीण एवं नगरीय परिवेश

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों की प्रजननता की दर में विपरीतार्थक स्थितियां पाई जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत समाज पाया जाता है, जहाँ संतान उत्पत्ति को संसाधन के रूप में समझा जाता है। इसी कारण यहां अधिक संतान पैदा करने को प्रोत्साहन भी मिलता है। जैसे – जैसे नगरीकरण का स्तर बढ़ता जाता है। स्त्री एवं पुरुषों के मध्य अंतराल बढ़ता जाता है। नगरीय क्षेत्र में शिक्षा, रोजगार एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को प्राप्त करने

के लिए पुरुष जनसंख्या महिलाओं से अधिक आकर्षित होती है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव प्रजनन दर पर देखा जाता है। नगरीय क्षेत्र की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की तुलना में अधिक शिक्षित एवं जागरूक होती हैं जिसके कारण वह परिवार नियोजन के साधनों एवं निरोधकों का अधिक उपयोग करती हैं, जिसके कारण नगरीय क्षेत्रों में प्रजनन दर कम पाई जाती है।

8.6.6 सामाजिक सुरक्षा

वे समाज जिनमें महिलाओं को सामाजिक कल्याण की दृष्टि से अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, वहाँ प्रजनन दर अधिक पाई जाती है। कुछ ऐसे सामाजिक रीति – रिवाज भी हैं, जिनके कारण महिलाएं अधिक असुरक्षित रहती हैं, जैसे विधवा होना, परित्याग एवं तलाक का होना। इन स्थितियों में यदि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाती है तो वे प्रजननता में अधिक सहयोग करते हैं। शिक्षित समाज ऐसी कुरीतियों का सामना कुशलता पूर्वक कर लेता है, जिससे प्रजननता में स्वाभाविक वृद्धि देखी जाती है। यही कारण है कि जिन समाजों में महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा अधिक प्रदान किया जाता है वह समाज सामाजिक बुराइयों एवं कुरीतियों से दूर होता है।

8.6.7 विधवा विवाह

सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के पुनर्विवाह से उनकी प्रजनन शक्ति का प्रभाव देश की जन्म दर और जनसंख्या वृद्धि पर देखा जा सकता है। सामान्य मान्यता यह है कि जैसे ही कोई स्त्री विधवा होती है, वह अपनी प्रजनन क्षमता खो बैठती है। विधवा स्त्री के संरक्षण हेतु विश्व स्तर पर अलग – अलग प्रतिरूप दिखाई देते हैं। कहीं पर विधवा विवाह पुनः संपन्न होते हैं, तो कहीं पर पूर्णतःनिषेध है। पी. नाग ने विधवा विवाह पर किए गए अपने कार्य में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पितृ सत्तात्मक समाज में वंश पिता के नाम पर चलता है जबकि मातृ सत्तात्मक समाज में वंश परंपरा माँ अथवा मामा के अनुसार चलती है। पितृसत्तात्मक समाज में विवाह मातृसत्तात्मक विवाह की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होता है। इसी कारण पितृसत्तात्मक समाज में मातृसत्तात्मक समाज से प्रजननता अधिक पाई जाती है।

मातृसत्तात्मक समाज में पितृसत्तामक समाज की तुलना में विधवा पुनर्विवाह अधिक होते हैं, जिसके कारण प्रजननता की कमी पूर्ण हो जाती है। भारत एवं चीन जैसे देशों में पितृसत्तात्मकता एवं मातृसत्तात्मकता से अधिक विधवा विवाह पर आर्थिक प्रभाव पड़ता है। सर्वेक्षणों में पाया गया है कि जिन देशों की विधवा स्त्रियों की आर्थिक स्थिति निम्न होती है वहाँ विधवा विवाह के अवसर अधिक मिलते हैं, जबकि आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न समाजों में विधवा स्त्री को एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। यही कारण है कि आर्थिक रूप से संपन्न वर्गों की तुलना में पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में प्रजनन की प्रक्रिया अधिक होती है।

8.6.8 शिक्षा

प्रजननता को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य घटक शिक्षा है। इसका प्रजननता से ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। शिक्षा के प्रसार के साथ ही प्रजननता को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं – शिक्षा के विस्तार से विवाह के आयु में वृद्धि हो जाती है, लोगों के अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होने लगते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगता है, स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं का प्रसार होने लगता है, महिलाएं आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों में सहभागी बनने लगती हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों में उनकी सहभागिता बढ़ाने लगती है, निरोध सामग्रियों के प्रयोग की आपसी सहमति बढ़ने लगती है, परिवार में बच्चों के पालन – पोषण का दृष्टिकोण बदल जाता है। ऐसी स्थिति में यह सर्वमान्य है कि शिक्षा के प्रसार के साथ ही प्रजनन क्षमता प्रभावित होने लगती है।

8.7 राजनीतिक कारक

किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था वहाँ की जनसंख्या को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति के माध्यम से देश की सरकारें अपने समाज की स्थिति के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण अथवा प्रोत्साहन संबंधी नीतियों का निर्माण करते हैं। देश की जनसंख्या किस दशा में जाएगी यह निर्धारण वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियां ही करती हैं। प्रमुख राजनीतिक कारक निम्नलिखित हैं जो जन्म दर को प्रभावित करते हैं–

8.7.1 युद्ध

किसी एक देश की दूसरे देश से युद्ध की स्थिति दोनों देशों के लिए भय एवं आतंक की अवस्था प्रदान करती है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव वहाँ की प्रजनन क्षमता पर पड़ता है। ऐसी भयावह स्थिति का प्रभाव वहाँ की महिलाओं के गर्भधारण पर भी देखा जाता है। कभी – कभी ऐसी स्थितियां गर्भपात के लिए भी उत्तरदायी होती हैं। युद्ध की स्थिति में आक्रमण के दौरान सबसे अधिक महिलाएं एवं बच्चे प्रभावित होते हैं। कुछ स्थितियों में इनकी नृशंस हत्या भी कर दी जाती है। साथ ही गर्भवती महिलाएं भी इससे अधिक प्रभावित होती हैं, जिस कारण युद्ध की अवधि में प्रजनन दर निम्न हो जाती है।

8.7.2 देशांतरण

देशांतरण शब्द को प्रवास अथवा स्थानांतरण की पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत एक मानव समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि देशांतरण के दौरान परिवारों द्वारा प्रजनन क्रिया को स्थगित रखा जाता है, ताकि यात्रा के दौरान कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। असुरक्षित यात्रा में गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है।

8.7.3 सांप्रदायिक राजनीति

दो या दो से अधिक संप्रदायों के मध्य होने वाले संघर्षों को सांप्रदायिक दंगों के रूप में जाना जाता है। यह काफी भयावह स्थिति होती है, जिसमें एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों के खून के प्यासे हो जाते हैं। उनके क्रियाकलापों से एक – दूसरे के घर एवं परिवार नष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थितियां लोगों द्वारा अपने निहित स्वार्थ की आपूर्ति हेतु उत्पन्न की जाती है। ऐसी स्थिति में प्रजनन क्षमता का बहुत तीव्रता से ह्रास होता है।

8.7.4 राष्ट्रीय अवहेलना

प्रत्येक राष्ट्र की सरकारों का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह अपने नागरिकों के विकास का हर संभव प्रयास करें। इन्हीं प्रयासों में से एक है जनसंख्या नियंत्रण। जब सरकारें ऐसा करने में विफल हो जाती हैं तो उसका भयंकर परिणाम सामने आता है। परिवार नियोजन कार्यक्रमों को राजनीतिक संरक्षण प्रदान करना चाहिए। सरकारों को इस बात की निगरानी करनी चाहिए कि किस वर्ग या समाज द्वारा राष्ट्रीय नीतियों की अवहेलना की जा रही है। सरकारों को ऐसी स्थिति में विभिन्न राजनीतिक दलों एवं वर्गों के मध्य जनसंख्या नियंत्रण हेतु सामंजस्य बनाना चाहिए।

8.7.5 जनसंख्या नीति

किसी भी राष्ट्र द्वारा क्रियान्वित जनसंख्या नीति प्रत्यक्ष रूप से प्रजननता को प्रभावित करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत में देखा जाता है, जहाँ पहले से बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी परंतु बाद में सरकार द्वारा विवाह की उम्र में वृद्धि कर देने पर आज नियंत्रित है। कुछ वर्ष पहले 18 वर्ष से पूर्व विवाह दंडनीय था अब इसे बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। इस प्रकार विश्व के अनेकों देशों द्वारा अपनी जनसंख्या के नियंत्रण एवं प्रोत्साहन संबंधित नीतियों का पालन किया जाता है। जैसे चीन ने अपने यहां बढ़ती जनसंख्या के नियंत्रण हेतु वर्ष 1975 – 76 के लगभग में एक संतान की नीति को लागू किया और उसके लिए उसने वैधानिक तरिके से यह घोषित कर दिया कि प्रत्येक दंपति को एक ही संतान पैदा करना है। ऐसी स्थिति में वहाँ की तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण दिखाई दिया।

8.8 धार्मिक कारक

भारत सहित विश्व के सभी भागों में रहने वाले लोग किसी न किसी धार्मिक मान्यता से प्रभावित होते हैं। संबंधित धर्म की मान्यताओं एवं विश्वासों के अनुसार आचरण एवं व्यवहार करते हैं। इन्हीं में से एक शारीरिक संबंध एवं प्रजननता भी है, जिस पर धर्म का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जाता है। धार्मिक रूप से प्रजननता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं –

8.8.1 धार्मिक मान्यताएं

भारत जैसे परंपरागत समाज वाले देश में लोगों की मान्यता है कि लड़कियों का विवाह राजस्वला होने से पूर्व कर देना चाहिए। इसके समर्थन में संस्कृति के एक श्लोक में कहा गया है कि 8 वर्ष की लड़की गोरी होती है, 9 वर्ष की रोहिणी तथा 10 वर्ष की कन्या कहलाती है, तत्पश्चात वह राजस्वला होती है। अतः राजस्वला से पूर्व उनका विवाह कर देना चाहिए। ऐसी मान्यता के अनुसार किए गए विवाह ही बाल विवाह कहलाते हैं। इससे प्रजनन आयु में वृद्धि होने के साथ ही प्रजनन दर भी बढ़ जाती है। वर्तमान समय में ऐसे विवाह की परंपरा धीरे – धीरे कम हुई है और वर्तमान समय में नगण्य ही प्राप्त होती है। साथ ही सरकार द्वारा भी समय –समय पर विवाह की उम्र में वृद्धि कर दिया जाता है जिससे विस्फोटक रूप से होने वाली जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सके। वर्तमान समय में भारत में जनसंख्या नियंत्रण को देखते हुए इसकी उम्र सीमा को पुनः एक बार बढ़ाया गया है और यह 21 वर्ष कर दिया गया।

8.8.2 धार्मिक संरचना

हिंदू धर्म की मान्यता एवं विश्वास के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होनी चाहिए। इसी से वंश के वृद्धि होती है और वही पूर्वजों को पिण्ड देकर तर्पण करता है, जिससे उन्हें जन्म एवं मृत्यु के चरण से मुक्ति मिल जाती है। पुत्रहीन व्यक्ति को निर्वंश कहा जाता है। इस प्रकार देखा जाता है कि कई दंपतियों को पुत्र पाने की तलाश में अनेक कन्याएं पैदा हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में प्रजननता दर में वृद्धि हो जाती है।

8.9 आर्थिक कारक

व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की आवश्यकता की पूर्ति के माध्यम आर्थिक संसाधन ही होते हैं। इनकी उपलब्धता एवं अनुपलब्धता के आधार पर ही व्यक्ति की समस्त क्रियाएं संपन्न होती हैं। मानवीय जीवन की अभिन्न क्रिया प्रजननता पर भी आर्थिक कारकों का प्रभाव पड़ता है जो निम्नलिखित है –

8.9.1 आय स्तर

सामान्य मानता यह है कि व्यक्तियों की आय तथा जन्मदर में विपरीतार्थक संबंध पाया जाता है। अधिक संपन्न परिवारों में बच्चों की संख्या कम देखी जाती है जबकि कम आर्थिक आय वाले परिवारों में बच्चों की संख्या अधिक होती है। प्रसिद्ध विद्वान बोग अपने शोध से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब आय का स्तर निम्न होता है, तब प्रजनन दर उच्च होती है। जब आय का स्तर मध्यम होता है तब प्रजनन दर न्यून होती है और जब आय अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है तब प्रजननता पुनः बढ़ने लगती है। संपन्नता के कारण परिवारों के भरण – पोषण में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। ऐसी स्थिति में परिवारों के आकार बढ़ने लगते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्तमान समय में बड़े परिवारों की स्वीकार्यता बढ़ी है। प्रसिद्ध जनसंख्या शास्त्री हावले लिखते हैं कि सामाजिक, आर्थिक विकास के तीन चरण होते हैं। उनका मानना है कि पहले चरण में प्रजनन समता पाई जाती है, दूसरा चरण जिसे औद्योगिक समाज कहा जाता है, में प्रजननता का विलोम अनुपात देखा जाता है। तीसरा चरण जिसे विकसित देश कहा जाता है, में प्रजननता का सहसंबंध सीधा पाया जाता है।

8.9.2 व्यावसायिक संरचना

व्यावसायिक संरचना से तात्पर्य अपनी आजीविका को चलाने हेतु व्यक्तियों की विभिन्न क्रियाकलापों में सलंग्नता से है। सामान्यतः देखा जाता है कि घरेलू काम करने वाली महिलाओं की अपेक्षा नौकरी करने वाली महिलाओं की प्रजननता कम होती है। इसी प्रकार दूसरी तरफ यह भी देखा जाता है कि शारीरिक श्रम करने वाली महिलाओं में मानसिक श्रम करने वाली महिलाओं से प्रजननता अधिक पाई जाती है। ऐसी ही प्रवृत्ति पुरुषों में भी देखे जाते हैं। उच्च शिक्षित नौकरी पैसा जैसे लेखाकार, शिक्षक, अधिकारी, अधिवक्ता एवं इंजीनियर जैसे व्यवसायों में संलग्न पुरुषों के बच्चे कम होते हैं।

8.9.3 जीवन स्तर

जीवन स्तर का अर्थ लोगों के रहने के ढंग से है, जो मुख्यतः आय पर निर्भर करता है। इससे प्रजनन क्षमता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। जहाँ निम्न जीवन स्तर में आय एवं प्रजननता में ऋणात्मक संबंध पाया

जाता है, वहीं मध्यम स्तर में यह धनात्मक हो जाता है। पुनः आय में वृद्धि होने पर इसका स्वरूप ऋणात्मक हो जाता है।

8.9.4 खाद्यान्न आपूर्ति

जनसंख्या वृद्धि एवं खाद्यान्न आपूर्ति के सहसंबंध की विस्तृत व्याख्या माल्थस द्वारा की गई है। उन्होंने बताया है कि प्रकृति स्वतः जनसंख्या एवं खाद्यान्न आपूर्ति के मध्य संतुलन स्थापित करती है। खाद्यान्न आपूर्ति से प्रजननता प्रभावित होती है। आर्थिक रूप से संपन्न वर्गों द्वारा अधिक प्रोटीन युक्त पदार्थ का सेवन किया जाता है जिससे प्रजननता पर ऋणात्मक सहसंबंध पड़ता है।

8.9.5 आर्थिक वैभव

आर्थिक वैभव की संपन्नता प्रजनन दर को दो प्रकार से प्रभावित करती है। एक ओर व्यक्ति अपनी आर्थिक संपन्नता के कारण एक से अधिक शादियां कर लेता है, जिससे प्रजननता में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। सर्वसंपन्न आर्थिक वैभव से परिपूर्ण परिवार सभी प्रकार के निरोधक सामग्रियों के प्रयोग करने में सक्षम होता है, जिसके कारण वह प्रजननता को भी नियंत्रित कर सकता है। अधिक वैभवशाली परिवारों में बच्चों के पालन – पोषण पर अधिक व्यय होता है, इसीलिए ऐसे परिवार अधिक बच्चों को भार समझते हैं और प्रजननता को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं।

8.9.6 विकास की अवस्था

विकास की विभिन्न अवस्थाओं में प्रजननता की दर अलग – अलग पाई जाती है। जिन समाजों की अर्थव्यवस्था प्रारंभिक अवस्था में होती है, उनकी प्रजनन क्षमता सर्वाधिक होती है। जैसे – जैसे विकास का स्तर बढ़ता जाता है, प्रजननता की दर भी घटती जाती है। द्वितीय क्रियाकलापों से जुड़े नगरीय लोगों की प्रजननता अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। इसी प्रकार तृतीयक, चतुर्थक एवं पंचम क्रियाकलापों में सम्मिलित संपन्न वर्गों में प्रजननता सबसे कम पाई जाती है।

8.10 प्रजननता का वैश्विक प्रतिरूप

प्रजननता एक प्रकार का मानक होती है जिसका प्रयोग करके किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या संक्रमण की अवस्था, जनसंख्या वृद्धि एवं बच्चों की संख्या का पता लगाया जाता है। जनसंख्या में गत्यात्मकता देखी जाती है जिसके कारण उसमें कभी स्थायित्व, कभी वृद्धि एवं कभी ह्रास की परिघटना देखी जाती है। ऐसी स्थिति में इसका अध्ययन दो स्वरूपों में किया जाता है – अपरिष्कृत जन्म दर एवं कुल प्रजनन दर। अपरिष्कृत जन्म दर से इस बात का बोध होता है कि किसी जनसंख्या में जन्म का अनुपात क्या है, जबकि कुल प्रजननता दर से स्पष्ट होता है कि किसी देश में औसतन प्रति स्त्री बच्चों कि संख्या कितनी है। कभी – कभी इसे प्रतिस्थापन दर के नाम से भी जाना जाता है। एक आदर्श स्थिति में यह संख्या 2.0 अथवा 2.1 होती है। इससे कम होने पर जनसंख्या घटती है जबकि अधिक होने पर बढ़ती है। विश्व के प्रजननता प्रतिरूप को निम्नलिखित सारणी के माध्यम से दर्शाया गया है।

सारणी 12.2 महाद्वीपों के अनुसार भारत में अशोधित जन्म दर एवं कुल प्रजनन दर (1970 – 2011)

क्र. सं.	महाद्वीप के नाम	अशोधित जन्म दर (ब्ठत्)				कुल प्रजनन दर (ज्थ्त्)			
		1970	1990	2001	2011	1970	1990	2001	2011
1.	अफ्रीका	46.52	41.92	38.01	36.08	6.60	5.81	5.18	4.75
2.	एशिया	33.91	25.25	20.25	18.32	5.15	3.05	2.64	2.28
3.	दक्षिणी अमेरिका	32.93	24.81	21.22	17.32	4.62	3.01	2.52	2.17

4.	उत्तरी अमेरिका	22.81	20.26	14.54	13.52	3.15	2.55	2.00	1.91
5.	ओशिनिया	23.96	19.23	17.31	18.58	3.21	2.56	2.13	2.56
6.	यूरोप	15.62	11.66	10.12	11.65	2.12	1.67	1.42	1.64
7.	विश्व	30.91	25.05	21.00	20.01	4.50	3.16	2.85	2.51

स्त्रोतः विश्व जनसंख्या आकड़ा शीट.

8.10.1 अशोधित जन्म दर

अशोधित प्रजनन दर जनसंख्या प्रतिरूप दर्शाने की एक महत्त्वपूर्ण विधि है। इसके दस्तावेजों का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त आकड़ों के आधार पर होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त आकड़ों के अनुसार विश्व का अशोधित प्रजनन दर वर्ष 1971 ई. में 30.91 थी जो घटकर वर्ष 1990 ई. में 25.05 हो गई थी। विकास के साथ ही इसमें घटने की प्रक्रिया जारी रही जो वर्ष 2001 ई. में 21.00 तथा 2011 ई. में 20.01 प्राप्त हुई है। विकसित देशों में यह दर (11) कम जबकि विकासशील एवं अल्प विकसित देशों में यह दर (35) पाई जाती है। विश्व स्तर अगर इसके वितरण स्वरूप का अध्ययन किया जाए तो अलग प्रतिरूप प्राप्त होता है। अगर वर्ष 2011 ई. के आकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि एशिया में यह 18.32 एवं ओशीनिया में 18.58 के साथ लगभग बराबर है। इसी प्रकार अशोधित प्रजनन दर अफ्रीका में 36.08, दक्षिणी अमेरिका में 17.32, उत्तरी अमेरिका में 13.52 तथा यूरोप में सबसे कम 11.65 प्राप्त होता है। इन आकड़ों की परिवर्तनीयता के आधार पर कहा जा सकता है कि अफ्रीका एवं एशिया महाद्वीप अभी विकासशील अवस्था में हैं जबकि अन्य विकसित।

सम्पूर्ण विश्व के सभी देशों को अशोधित प्रजनन दर के आधार पर तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है–

- उच्च अशोधित प्रजनन दर – यहाँ जन्म दर 30 से अधिक होती है।
- मध्यम अशोधित प्रजनन दर – यहाँ जन्म दर 30 से 15 के बीच होती है।
- निम्न अशोधित प्रजनन दर – यहाँ जन्म दर 15 से कम होती है।

8.10.2 कुल प्रजनन दर

कुल प्रजनन दर का अर्थ है प्रति स्त्री कितने बच्चों का जन्म हुआ है। यह उत्पादकता को व्यक्त करने की सर्वोत्तम विधि है। राम कुमार तिवारी अपनी पुस्तक जनसंख्या भूगोल में लिखते हैं कि यदि कुल जन्म दर प्रति स्त्री औसतन दो बच्चे है तो इसका तात्पर्य है कि जनसंख्या वृद्धि दर शून्य है। इससे अधिक होने पर जनसंख्या वृद्धि होती है जबकि कम होने पर जनसंख्या में कमी होती है। वैश्विक जनसंख्या के आकड़े 2011 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि विश्व की कुल प्रजनन दर 2.5 बच्चे है। यह दर वर्ष 1970 ई. के आस – पास 4.5 थी। इसके पश्चात इसमें लगभग आधी की कमी आयी है। यह दर विकासशील एवं अल्प विकसित देशों में जहाँ 4.5 है वहीं विकसित देशों में 1.7 प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में दोनों प्रकार के देशों में यह अंतर चार गुना पाया जाता है।

विश्व के सभी देशों में प्राप्त प्रजनन दर के आधार पर देशों को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है –

- उच्च कुल प्रजनन दर – इसमें प्रति स्त्री बच्चों की संख्या 3 से अधिक होती है।
- मध्यम कुल प्रजनन दर – इसमें प्रति स्त्री बच्चों की संख्या 3 से 2 के बीच होती है।
- निम्न कुल प्रजनन दर – इसमें प्रति स्त्री बच्चों की संख्या 2 से कम होती है।

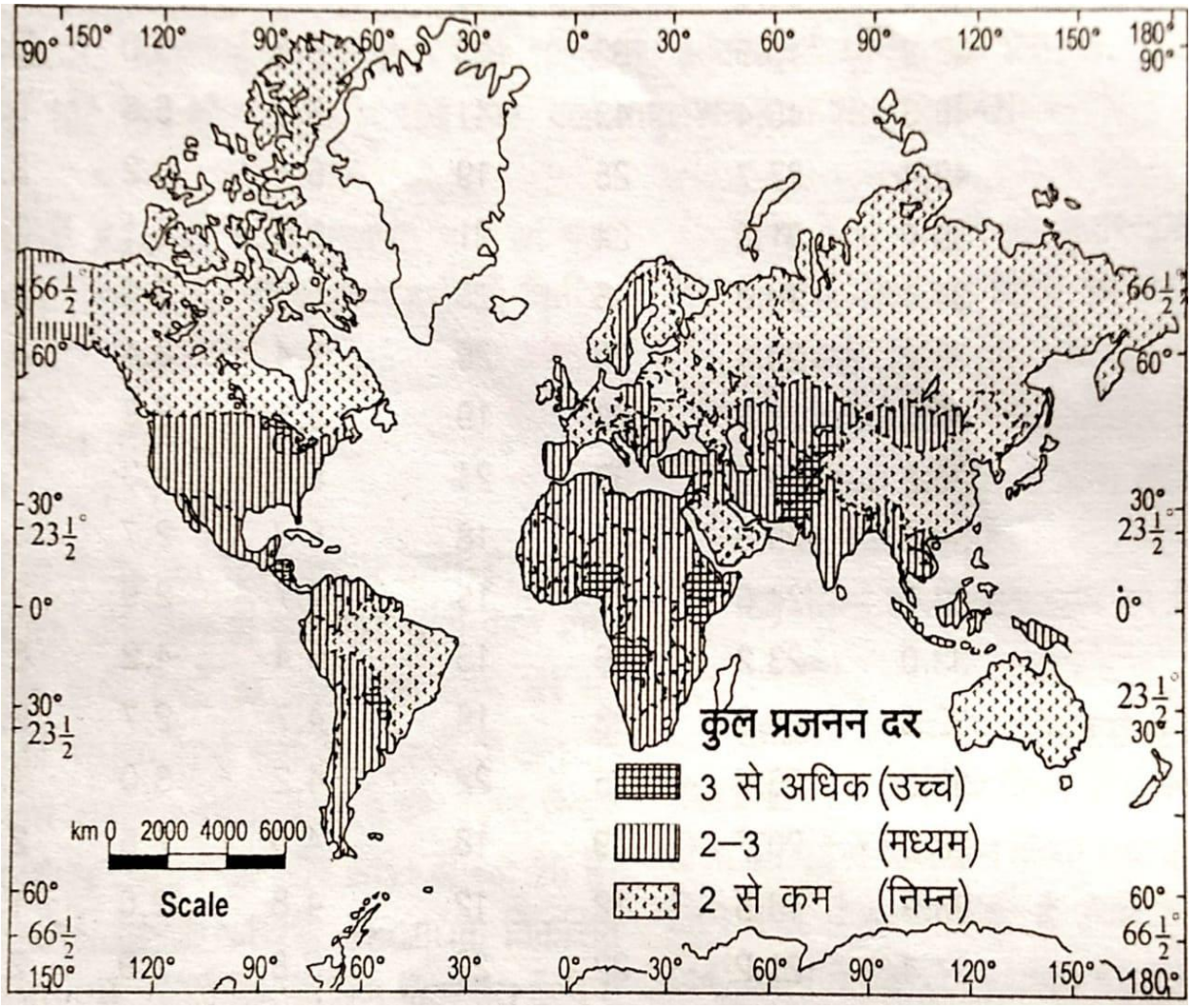

चित्र संख्या 12.1 वैश्विक जनसंख्या का कुल प्रजनन दर (2011)

8.11 प्रजननता का भारतीय प्रतिरूप

विश्व की भॉति ही भारत में भी जनसंख्या का वितरण बहुत ही आसमान है। यहाँ जन्म एवं मृत्यु से संबन्धित आकड़ें प्राप्त करने के दो स्त्रोत है – आम नागरिकों द्वारा निबंधन एवं नमूना निबंधन प्रणाली। इनमें सबसे अधिक लोकप्रिय विधि नमूना निबंधन प्रणाली है। भारत में प्रजननता के प्रतिरूप का अध्ययन करने हेतु दो विधियों अशोधित जन्म दर एवं कुल प्रजनन दर का प्रयोग किया जाता है।

सारणी 12.3 भारत में अशोधित जन्म दर एवं कुल प्रजनन दर (1901 – 2011)

क्र. सं.	जनगणना वर्ष	अशोधित जन्म दर (CBR)	कुल प्रजनन दर (TFR)
1.	1901	––	––
2.	1911	49.25	––

3.	1921	48.14	——
4.	1931	46.40	——
5.	1941	45.29	——
6.	1951	39.91	6.04
7.	1961	41.72	5.63
8.	1971	37.18	5.24
9.	1981	34.00	4.51
10.	1991	30.75	3.60
11.	2001	26.02	3.11
12.	2011	23.09	2.60

स्त्रोतः भारतीय जनगणना विभाग, लखनऊ.

8.11.1 अशोधित जन्म दर

विश्व के साथ भारत की जनसंख्या का सापेक्षिक अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि भारत की प्रजननता दर अधिक है। 19वीं सदी के अंतिम तथा 20वीं सदी के प्रारम्भिक कालों में भारत का अशोधित जन्म दर 50 बच्चे प्रति महिला थी। यह संख्या कुल जनसंख्या में बच्चों के अनुपात को दर्शाती है। इस अनुपात में निरंतर गिरावट की प्रवृत्ति देखी जा रही है। सारणी 12.3 के आकड़ों से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1901 ई. से 1961 ई. के मध्य यह अनुपात लगभग 40 के बराबर बना रहा। वर्ष 1970 ई. के पश्चात इसमें तीव्रता से गिरावट आयी है। इस प्रकार सबसे नवीनतम प्राप्त आकड़ों अर्थात वर्ष 2011 ई. की जनगणना में यह 23.09 अंकित किया गया है।

8.11.2 कुल प्रजनन दर

सामान्य अर्थ में कुल प्रजननता दर का तात्पर्य प्रति महिला बच्चों की संख्या होती है, जिसे कुछ विद्वानों द्वारा प्रतिस्थापन दर भी कहा जाता है। यह संकल्पना इस बात का बोध कराती है कि एक स्त्री यदि अपने जीवन काल में 2 बच्चों को जन्म देती है तब वह जनसंख्या का विस्तार नहीं करती है बल्कि स्वंय को प्रतिस्थापित करती है। ऐसी स्थिति में न तो जनसंख्या में वृद्धि होती है न ही कमी होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार वर्ष 2005 ई. में सम्पूर्ण विश्व की प्रजननता दर 2.7 शिशु प्रति स्त्री थी, जो विकसित देशों में 1.8 शिशु प्रति स्त्री तथा विकासशील देशों में 2.9 शिशु प्रति स्त्री प्राप्त होता है। इससे यह कहा जा सकता है कि अभी विश्व में जनसंख्या वृद्धि जारी है। भारत के संदर्भ में जब इस वृद्धि दर का अवलोकन कारते है तब ज्ञात होता है कि वर्ष 1951 ई. में कुल प्रजनन दर 6 शिशु प्रति महिला थी। बाद में प्राप्त होने वाले आकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है इसमें गिरावट की गति बहुत मंद थी। यह दर 1981 ई. में 4.5 शिशु प्रति महिला प्राप्त हुई है। इसके पश्चात इसमें गिरावट की गति तीव्र हुई और वर्ष 2011 ई. में यह 2.6 दर्ज की गई है।

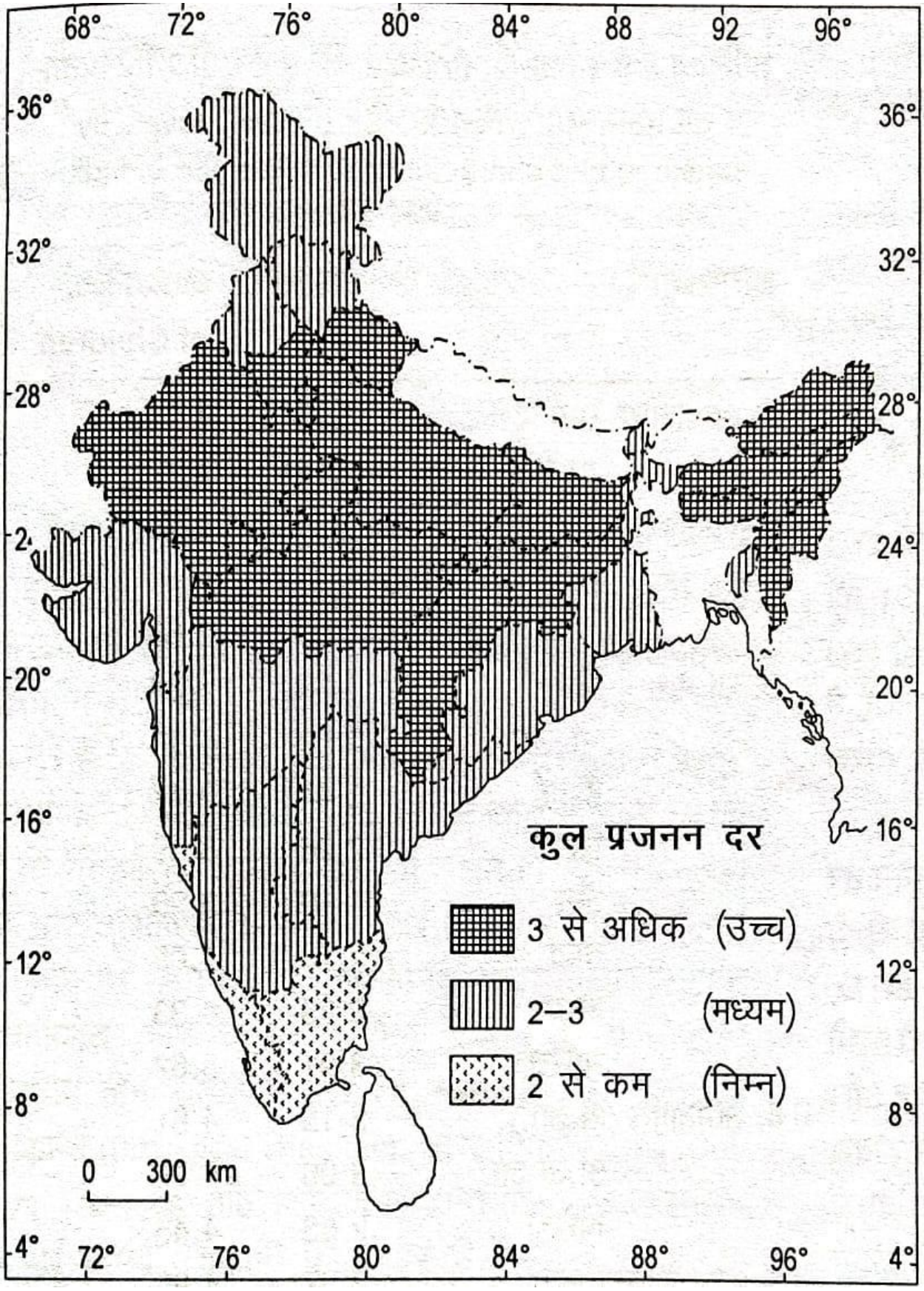

चित्र संख्या 12.2 भारत की जनसंख्या का कुल प्रजनन दर (2011).

8.12 सारांश

आपने इस इकाई में प्रजननता का अर्थ और प्रजननता के निर्धारक कारक का अध्ययन किया है। आप समझ गए होगें कि प्रजननता और उसके निर्धारक कारकों में घनिष्ट संबंध है। अन्य जनसंख्या तत्वों के समान प्रजननता की प्रवृत्तियों पर स्थानीय जलवायु, सामाजिक संरचना, जैविक क्षमता आदि का प्रभाव देखा जाता है। यही कारण है कि जनसंख्या भूगोल में प्रजननता के विविध पक्षों के अध्ययन को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। वास्तव में किसी देश की जनसंख्या तथा वहाँ का सबसे बड़ा संसाधन होती है, जो उसकी भौगोलिक अवस्थिति, सरकारी नीतियों, सांस्कृतिक संगठन आदि के आधार पर विकसित होता है। विश्व के साथ ही भारत के विभिन्न भागों में इन कारकों कि प्रभाविता में अंतर पाया जाता है। जहाँ विकासशील देशों कि प्रजननता दर तीव्र पाई जाती है वहीं विकसित देशों में मंद। भारत के उत्तरी राज्यों की तुलना में दक्षिणी राज्यों की प्रजननता दर निम्न पाई जाती है।

8.13 स्वमूल्यांकन प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

1. प्रजननता के माप हेतु निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है ।

   (क) अशोधित जन्म दर (ख) प्रजनन अनुपात (ग) कुल प्रजनन दर (घ) वैवाहिक स्थिति

2. महिलाओं में प्रजनन क्षमता का प्रारम्भ कब होता है ।

   (क) 8 से 10 वर्ष (ख) 12 से 15 वर्ष (ग) 15 से 18 वर्ष (घ) 21 से 24 वर्ष

3. प्रजननता को प्रभावित करने वाले जैविक कारकों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है ।

   (क) प्रजातीय भिन्नता (ख) विवाह की आयु (ग) व्यक्ति का स्वास्थ्य (घ) प्रजनन क्षमता

4. महिलाओं में समान्यत किस अवधि में प्रजनन क्षमता सर्वाधिक होती है ।

   (क) 19 से 30 वर्ष (ख) 15 से 21 वर्ष (ग) 32 से 39 वर्ष (घ) 35 से 45 वर्ष

5. चीन ने अपनी बढ़ती जनसंख्या जनसंख्या के नियंत्रण हेतु एक संतान की नीति कब लागू की थी ।

   (क) 1965 – 66 (ख) 1975 – 76 (ग) 1984 – 85 (घ) 1990 – 91

8.14 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

Bogue] D- J-] 1969] Principles of Demography] John Wiley] N-Y-

Clarke] John I-] 1973] Population Geography] Pergaman Press] Oxford-

Crook] Nigel] 1997] Principles of Population and Development] Pergaman Press] N- Y-

Garmier] J- B-] 1970] Geography of Population] Longman] London-

Mamoria] C- B-] 1981] India's Population Problem] Kitab Mahal] New Delhi-

Premi] M- K-] 1991] India's Population] Heading Towards a Billion] B- R- Publishing Corporation-

Blassoff] M- and Srinivasan K-] 2001] Population Development Nexus in India : Challenges for the New Millennium] Tata McGraw Hill] New Delhi-

Woods] R-] 1979] Population Analysis in Geography] Longman] London-

Zelinsky] W-] 1966] A Prologue to Population Geography] Prentice Hall-

चन्दना, आर. सी., 2022, जनसंख्या भूगोल – संकल्पना, नियंत्रक व विश्व प्रारूप, कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

चन्दना, आर. सी., 2022, भारत : जनसंख्या (जनसंख्या भूगोल – भाग 2), कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

मौर्या, एस. डी., 2005, जनसंख्या भूगोल, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद.

ओझा, आर. पी., 1984, जनसंख्या भूगोल, प्रतिभा प्रकाशन.

हीरा लाल, 2000, जनसंख्या भूगोल के मूल तत्व, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली.

तिवारी, राम कुमार, 2023, जनसंख्या भूगोल, प्रवालिका पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद.

8.15 अभ्यास प्रश्न (सत्रांत परीक्षा की तैयारी)

1. प्रजननता के अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट कीजिए?
2. प्रजननता को निर्धारित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए?
3. जन्म नियंत्रण के उपायों की व्याख्या कीजिए?

इकाई–9 मर्त्यता का अर्थ, मृत्यु दर में भिन्नता के कारण

इकाई की रूपरेखा

9.0 प्रस्तावना

9.1 उद्देश्य

9.2 मर्त्यता का अर्थ

9.3 मर्त्यता की माप

9.4 मर्त्यता के निर्धारक

9.5 मर्त्यता में भिन्नता के कारण

9.6 जनांकिकीय कारण

9.7 सामाजिक कारण

9.8 आर्थिक कारण

9.9 राजनीतिक कारण

9.10 प्राकृतिक कारक

9.11 सारांश

9.12 स्वमूल्यांकन प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

9.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

9.14 अभ्यास प्रश्न (सत्रांत परीक्षा की तैयारी)

9.0 प्रस्तावना

प्रत्येक मनुष्य एक मरणशील प्राणी है, अतः मर्त्यता एक शाश्वत सत्य है। इस धरातल पर मनुष्य एवं मनुष्यों के अतिरिक्त सभी प्राणियों के लिए प्रकृति का यह सर्वमान्य नियम लागू होता है कि जो भी जीव जन्म लेता है। किसी न किसी एक निश्चित दिवस पर उसकी मृत्यु अवश्य होगी। प्रत्येक प्राणी की मृत्यु होती है परंतु इस पर उसकी इच्छा का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है इसीलिए यह एक अनैच्छिक क्रिया है। किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या के गत्यात्मकता में मर्त्यता एक प्रमुख कारण है। इसके कारण किसी स्थान की जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जाती है। प्रजननता की ही भांति मर्त्यता भी जनसंख्या परिवर्तन का एक कारण है। यह अधिक स्थायी और अनुमन्य होती है तथा किसी विशिष्ट उतार एवं चढ़ाव से भी मुक्त होती है। मर्त्यता पर जैविक प्रभाव दिखाई देते हैं जबकि प्रजननता पर जनांकिकीय मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारकों का अधिक प्रभाव देखा जाता है। मर्त्यता पर अपनी उपलब्ध समर्थ के अनुसार विश्व के सभी देशों ने नियंत्रित करने का प्रयास किया है। इसी का प्रभाव है कि विश्व में मृत्यु दर काफी तीव्रता से घटी है।

9.1 उद्देश्य

मृत्यु सबके जीवन में घटित होने वाली एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इससे मनुष्य सहित सभी प्राणियों को गुजरना पड़ता है। इसके पश्चात जीव के सभी जैविक प्रमाण हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। इस इकाई के उद्देश्य निम्नलिखित है –

1. मर्त्यता के अर्थ को समझना।
2. मृत्यु दर में भिन्नता के कारणों की व्याख्या करना।

9.2 मर्त्यता का अर्थ

वर्तमान समय में जनांकिकीय जनसंख्या अध्ययन तथा जनसंख्या भूगोल में मर्त्यता के अध्ययन पर अधिक बल दिया जा रहा है, क्योंकि इन विषयों के अध्ययन के अनिवार्य तत्वों में से यह एक है। किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या के आकार में कमी मुख्य रूप से मर्त्यता से आती है। राम प्रसाद तिवारी अपनी पुस्तक जनसंख्या भूगोल में लिखते हैं कि मर्त्यता के कारण जनसंख्या की संरचना, वितरण, घनत्व एवं एक सीमा तक प्रजननता भी प्रभावित होती है। मर्त्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मरणशीलता। इसी से ही मर्त्यता अथवा मृत्यु जैसे शब्दों की व्युत्पत्ति होती है। सामान्य शब्दों में मर्त्यता का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या जंतु के जीवन का अंत हो जाना है। रामकुमार तिवारी के शब्दों में जीवित जन्म लेने के बाद किसी भी समय किसी जीव की जीवन समाप्त हो सकता है जिसे मृत्यु नाम से संबोधित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि भ्रूण मृत्यु तथा जन्म के समय की मृत्यु गणना मृत्यु में नहीं होती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जन्म के पश्चात किसी भी समय सदा के लिए पूर्णतः जीवन चिन्ह मिट जाने को मर्त्यता कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी गई परिभाषा सभी देशों द्वारा एक समान ही स्वीकार नहीं की जाती है। अलग – अलग देश में इसके अपने अलग मानक हैं। जहाँ सीरिया, गिनी एवं अल्जीरिया जैसे देशों में जन्म के बाद वे सभी शिशु जो पंजीकरण से पहले मर जाते हैं मृतक शिशु कहलाते हैं। वहीं दूसरी ओर मोरक्को जैसे देश में जन्म से 24 घंटे के अंदर मरने वाले बच्चों को मृतक शिशु कहा जाता है। मर्त्यता के आंकड़ों के संग्रह की विधियां भी सभी देशों में एक समान नहीं है। सामान्यतः इसका संग्रह एवं संकलन जन्म – मृत्यु पंजीकरण विधि के माध्यम से किया जाता है। विश्व में अनेक ऐसे भी देश हैं जहाँ वैधानिक रूप से जन्म – मृत्यु पंजीकरण अनिवार्य नहीं होता है। जब वहाँ वैधानिक अनिवार्यता नहीं है तब जन्म – मृत्यु पंजीकरण का कार्य पूर्ण नहीं हो पता है। वर्तमान जन्म – मृत्यु पंजीकरण का यदि विश्व स्तरीय विश्लेषण करें तो ज्ञात होता है कि कुछ पिछड़े देशों में यह अभी शुरू हुआ है, तो कुछ में इसका स्तर बहुत निम्न है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जीवित प्रसव के पश्चात ही मृत्यु होती है तथा प्रसव एवं मृत्यु के बीच की अवधि ही जीवन के नाम से जानी जाती है। मर्त्यता भी प्रजननता की भांति अनुपातिक होती है तथा मृत्यु की संख्या से ही मर्त्यता का मापन किया जाता है।

9.3 मर्त्यता की माप

किसी निश्चित भू–भाग पर निवास करने वाली जनसंख्या में किसी एक निश्चित समयावधि में मृतकों की संख्या को प्रति हजार के अनुपात में अभिव्यक्त किया जाता है इसे ही मृत्यु दर अथवा मर्त्यता की माप के नाम से भी जाना जाता है। रामकुमार तिवारी अपनी पुस्तक जनसंख्या भूगोल में लिखते हैं कि मृत्यु की संभाविता को ध्यान में रखकर यह बताने का प्रयास किया जाए कि एक निश्चित आयु वर्ग में मृत्यु का जोखिम कितना है तो यह संभाव्यता की मृत्यु दर कहलाती है। मर्त्यता दर को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। मर्त्यता दर की गणना के लिए किसी एक वर्ष की मृत्यु की कुल संख्या तथा उस निश्चित वर्ग की कुल जनसंख्या के आंकड़ों की आवश्यकता होती है। मर्त्यता की माप हेतु निम्नलिखित सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है–

9.3.1 अशोधित मृत्यु दर

मृत्यु दर के मापन हेतु इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। यह विधि एक वर्ष की अवधि में होने वाली कुल मृत्यु एवं कुल जनसंख्या के अनुपात को अभिव्यक्त करती है। इसकी गणना के लिए एक नियत समयावधि जो सामान्यतः एक वर्ष होती है, में होने वाली मृत्युओं को एक वर्ष के प्रारम्भ की जनसंख्या अथवा वर्ष के मध्य की जनसंख्या से भाग देकर उसमें 1000 से गुणा करके की जाती है। इस प्रकार इस विधि से प्रति हजार जनसंख्या पर मृत्युओं की संख्या प्राप्त की जाती है। इसकी परिगणना के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है–

अशोधित मृत्यु दर = मृत्युओं की कुल संख्या / मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या * 1000

नोटः* से तात्पर्य गुणा से है.

विश्व के अनेकों देशों में कुल जनसंख्या एवं कुल मृत्यु के आकड़ें आसानी से प्राप्त होने तथा सर्वसुलभ होने के कारण अशोधित मृत्यु दर अधिक प्रचलित होने के साथ लोकप्रिय भी है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस

विधि से होने वाली गणना सर्वाधिक सार्थक होती है। जिन क्षेत्रों में समान संरचना, समान आयु, जाति एवं लिंग की जनसंख्या पाई जाती है वहाँ यह विधि सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में इसमें असमानता देखी जाती है उन क्षेत्रों के लिए यह विधि उपयोगी नहीं होती है।

भारत का विशाल आकार एवं जनसंख्या के असमान वितरण के कारण देश में अशोधित मृत्यु दर में विविधता पाई जाती है। क्षेत्रीय वितरण के आधार पर इसके तीन प्रकार पाए जाते है जो निम्नलिखित है –

अ) उच्च अशोधित मृत्यु दर – 8 व्यक्ति प्रति हजार से अधिक।

ब) मध्यम अशोधित मृत्यु दर – 8 से 6 व्यक्ति प्रति हजार के मध्य।

स) निम्न अशोधित मृत्यु दर – 6 व्यक्ति प्रति हजार से कम।

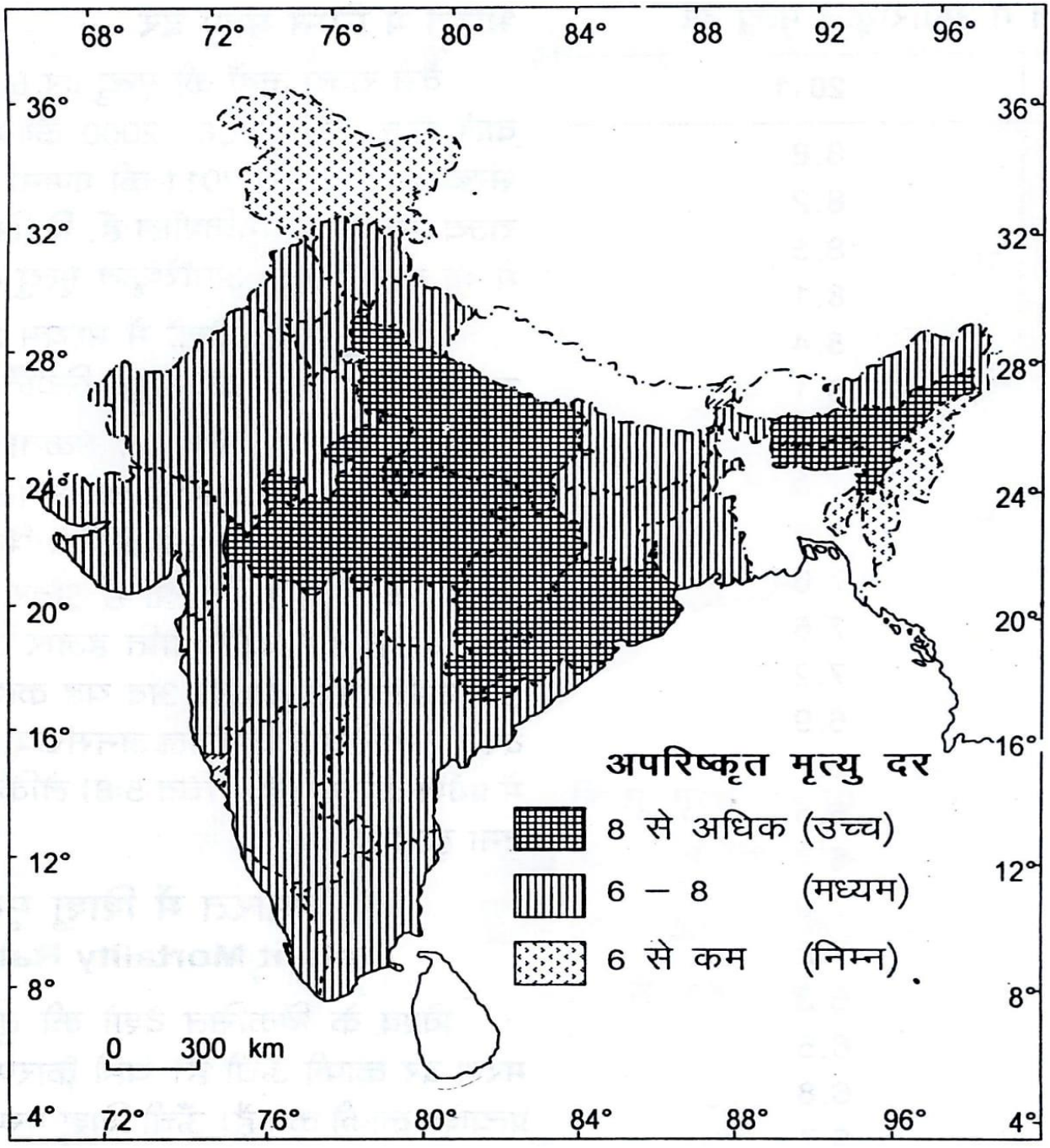

चित्र 9.1 भारत में अशोधित मृत्यु दर का वितरण.

9.3.2 शिशु मृत्यु दर

इस वर्ग के अंतर्गत आयु के प्रथम वर्ष में होने वाली शिशु मृत्यु को सम्मिलित किया जाता है। इस अनुपात के माध्यम से किसी वर्ष में एक वर्ष से कम आयु वर्ग वाले शिशुओं के मृत्यु की संख्या और उसी वर्ष में जन्म लेने वाले सभी शिशुओं की संख्या को अभिव्यक्त किया जाता है। इस अनुपात की गणना के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है –

शिशु मृत्यु दर = किसी वर्ष में एक वर्ष से कम आयु के मृतक शिशु / उसी वर्ष जन्में कुल जीवित शिशु * 1000

नोटः * से तात्पर्य गुणा से है.

इस अनुपात की गणना करते समय कुल शिशुओं में नर शिशु एवं मादा शिशु दोनों को सम्मिलित किया जाता है। इन दोनों प्रकार की मृत्यु दर में अंतर पाया जाता है। शिशु मृत्यु दर के सार्थक अध्ययन हेतु नर शिशु मृत्यु एवं बालिका शिशु मृत्यु के अलग – अलग आंकड़ों की आवश्यकता होती है। किसी भी क्षेत्र में नर शिशु मृत्यु दर की गणना के लिए केवल नर शिशुओं की मृत्यु संख्या को कुल नर जन्मों से विभाजित किया जाता है। इसी प्रकार महिला शिशु मृत्यु दर का परिकलन किया जाता है और प्राप्त होने वाले परिणाम में 1000 से गुणा कर दिया जाता है।

जनसंख्या अध्ययन के दौरान पाया जाता है कि जीवन सारणी को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला वर्ष जीवन का प्रथम वर्ष होता है। इसमें मृत्यु की संख्या की तुलना जीवन के किसी आयु वर्ग से अधिक पायी जाती है। शिशु मृत्युओं की संख्या अधिक होने पर सम्पूर्ण मृत्यु में इसकी सहभागिता अनुपात अधिक पाया जात है। ऐसी स्थिति समाज में कुपोषण, पिछड़ापन, अशिक्षा, निम्न जीवन स्तर एवं चिकित्सा सुविधाओं के अभाव की स्थिति का बोधक होती है। किसी देश में निम्न शिशु मृत्यु दर का पाया जाना अधिकांशतः जन स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति, चिकित्सा सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, उच्च जीवन स्तर आदि का बोधक होती है।

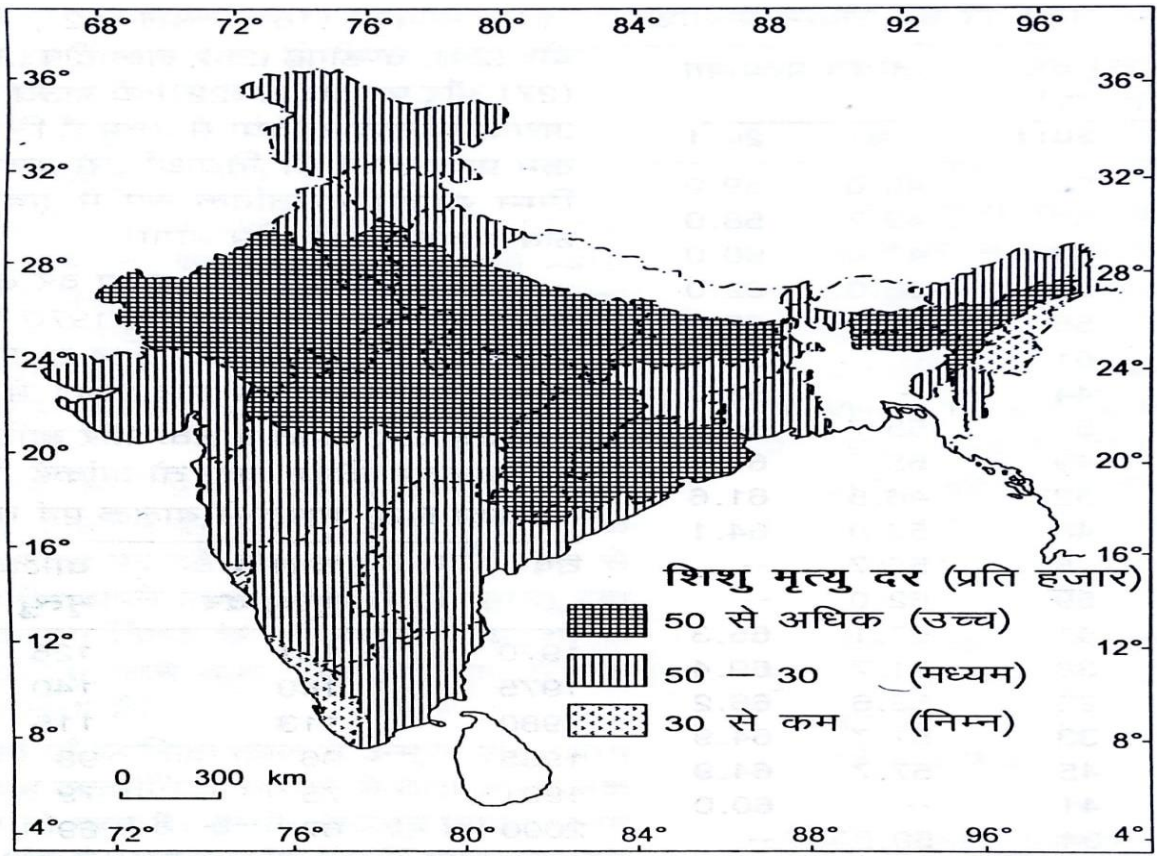

चित्र 9.2 भारत में शिशु मृत्यु दर का वितरण.

9.3.3 मातृ मृत्यु दर

यह एक निश्चित अवधि जिसे सामान्यतः एक वर्ष में लिया जाता है, में माताओं की मृत्यु की संख्या एवं कुल जीवित जन्मों के अनुपात का बोधक होता है। इसकी गणना के लिए गर्भावस्था, संतानोत्पत्ति के समय अथवा शिशु जन्म से संबन्धित कारणों से होने वाली माताओं की कुल संख्या को कुल जीवित जन्मों से विभाजित करके उसमें 10,000 से गुणा किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रति दस हजार जीवित जन्मों पर प्रसव कारणों से होने वाली माताओं की मृत्यु की संख्या का परिकलन किया जाता है। इसके आकलन हेतु निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है–

मातृ मृत्यु दर = प्रसव कारणों से माताओं की कुल मृत्यु संख्या / जीवित जन्मों की कुल संख्या * 10,000

नोटः * से तात्पर्य गुणा से है.

मातृ मृत्यु दर मुख्य रूप से माताओं की मृत्यु से जुड़ी हुई है। समाज में स्त्रियों की स्थिति, उनका पोषण स्तर, सामान्य स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं से मातृ मृत्यु दर को जोड़ कर देखा जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि मातृ मृत्यु दर के द्वारा सामान्य स्वास्थ्य, मातृत्व धारण करने की आयु, संतान वहाँ करने की आयु आदि के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक अवस्थाओं में पैदा परिवर्तन होने पर इसकी तीव्रता कम या अधिक हो सकती है।

9.3.4 आयु विशिष्ट मृत्यु दर

किसी विशिष्ट आयु वर्ग के लिए ज्ञात की जाने वाली मृत्यु दर को आयु विशिष्ट मृत्यु दर कहा जाता है। इसे अशोधित मृत्यु दर का एक रूप माना जाता है जिसकी गणना समाज के अलग – अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए भिन्न – भिन्न प्रकार से की जाती है। आयु विशिष्ट मृत्यु दर किसी समाज के विशिष्ट आयु वर्ग में होने वाली कुल मृत्यु तथा कुल जनसंख्या के अनुपात का बोधक होती है । इसकी गणना के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है –

आयु विशिष्ट मृत्यु दर = किसी विशिष्ट आयु वर्ग में कुल मृत्यु संख्या / उसी विशिष्ट आयु वर्ग में कुल जनसंख्या *10,000

नोटः * से तात्पर्य गुणा से है.

आयु विशिष्ट मृत्यु दर के आंकड़ों का सम्पूर्ण जनसंख्या के आंकड़ों के साथ अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है जीवन काल के प्रथम वर्ष में मृत्यु दर सबसे अधिक होती है जो अधिकांशतः दूसरे से आठवें – नौवें वर्ष तक तीव्रता से गिरती है। इसके पश्चात लगभग 40 वर्ष की आयु तक यह स्थिर रहती है। 40 वर्ष के बाद इसमें फिर से तीव्रता आने लगती है और 60 वर्ष के पश्चात उच्चता का स्तर प्राप्त कर लेती है। यही कारण आयु विशिष्ट मृत्यु दर का वक्रन्आकृति का होता है।

9.3.5 आयु एवं लिंग विशिष्ट मृत्यु दर

जनसंख्या अध्ययन के दौरान आयु विशिष्ट मृत्यु दर की गणना में स्त्री एवं पुरुष के सम्मिलित आंकड़े का प्रयोग किया जाता है, जिससे उनकी अलग – अलग मृत्यु दरों की गणना की जाती है। जनसंख्या अध्ययन की इस विधा को ही आयु एवं लिंग विशिष्ट मृत्यु दर कहा जाता है। इसकी गणना के लिए एक वर्ष में किसी विशिष्ट आयु वर्ग में पुरुषों अथवा स्त्रियों की कुल मृत्यु संख्या को उसी आयु वर्ग और लिंग की कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है और प्राप्त होने वाले परिणाम में 1000 से गुणा कर दिया जाता है। इसकी गणना हेतु प्रयुक्त होने वाला सूत्र निम्नलिखित है–

आयु एवं लिंग विशिष्ट मृत्यु दर = विशिष्ट आयु वर्ग में पुरुष अथवा स्त्री मृत्यु की कुल संख्या / विशिष्ट आयु वर्ग की कुल पुरुष अथवा स्त्री जनसंख्या * 1000

नोटः * से तात्पर्य गुणा से है.

इस तकनीकी का वर्तमान समय में बहुत कम प्रयोग किया जाता है क्योंकि मृत्यु संबंधी आंकड़े आसानी से उपलब्ध नही हो पाते है।

9.3.6 जीवन सारणी

यह अलग – अलग आयु वर्ग के बीच में मृत्यु दर को मापने की एक अप्रत्यक्ष विधि है। शिवदास मौर्य अपनी पुस्तक जनसंख्या भूगोल में लिखते हैं कि क्रमागत आयु विशिष्ट मृत्यु दर के समान ही जीवन सारणी को भी निर्मित किया जाता है। इसके लिए आवश्यक यह है कि पर्यवेक्षित मृत्यु दशाओं का ज्ञान हो। जीवन सारणी के द्वारा भिन्न – भिन्न आयु वर्ग में व्यक्ति के जीवित रहने तथा मृत्यु के संबंध में संभावनाओं की जानकारी मिलती है। विकासशील देशों में इस प्रकार के आंकड़ों के अभाव में जीवन सारणी का निर्माण कठिन काम होता है, इसीलिए यह शुद्ध एवं सार्थक नहीं होती है। जिन देशों में सामाजिक जागरूकता, उच्च शैक्षणिक स्तर तथा विकसित तकनीकी पाई जाती है ऐसे विकसित देशों के लिए यह सूचकांक अधिक उपयोगी होता है।

डी. बोग लिखते हैं कि जीवन सारणी एक अंकगणितीय मॉडल है जो एक निश्चित समय पर किसी जनसंख्या में मर्त्यता दशाओं को प्रकट करता है और साथ ही उत्तरजीविता के लिए आधार प्रस्तुत करता है।

9.3.7 कारण विशिष्ट मृत्यु दर

यह मृत्युदर कारण के अनुसार हों वाली मृत्यु के अनुपात को दर्शाती है। यह किसी निश्चित समयावधि जिसे अधिकतर एक वर्ष ही लिया जाता है। इस दौरान किसी विशेष कारण से एक वर्ष में होने वाली मृत्यु की संख्या कुल जनसंख्या के अनुपात में अति निम्न होती है। इस मृत्यु दर को प्रति 10 हज़ार या प्रति 1 लाख जनसंख्या के अनुपात में अभिव्यक्त किया जाता है। इसके परिकलन के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है –

कारण विशिष्ट मृत्यु दर = एक वर्ष में कारण विशेष से मृत्युओं की कुल संख्या / उसी वर्ष की औसत जनसंख्या * 1000

नोटः * से तात्पर्य गुणा से है.

कारण विशिष्ट मृत्यु दर की गणना आयु और लिंग के आधार पर भी की जा सकती है । विशेष आयु वर्ग के लिए किसी वर्ग की विशिष्ट कारण से होने वाली मृत्युओं और उसी आयु वर्ग की कुल जनसंख्या के अनुपात परिगणना किया जाता है । यदि विशिष्ट आयु वर्ग के पुरुष और स्त्री के कारण विशेष से होने वाली मृत्युओं की संख्या में उसी वर्ग के पुरुष और स्त्री की कुल संख्या से भाग दिया जाए एवं उसमें 10,000 से गुणा कर दिया तो उससे आयु और लिंग के अनुसार कारण मृत्यु दर प्राप्त हो जाएगी ।

9.4 मर्त्यता के निर्धारक

मर्त्यता के निर्धारकों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर और समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। भिन्न –भिन्न स्थानों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं प्रौद्योगिकी प्रगतियां अलग – अलग होती हैं इसलिए मर्त्यता के कारण प्रत्येक समाज में अलग – अलग पाया जाता है। मर्त्यता के कारणों में भिन्नता विश्व के विभिन्न भागों में अलग – अलग होती है। मर्त्यता के निर्धारक तत्वों को दो भागों में बांटा जाता है –

- आंतरिक कारक
- बाह्य कार

9.4.1 आंतरिक कारक

आंतरिक कारक मुख्य रूप से जैविक होते हैं। व्यक्ति की शारीरिक क्रियाशीलता में परिवर्तन होने के कारण उनकी जैविक शक्ति घटने लगती है और एक दिन ऐसा भी आता है, जब व्यक्ति मृत्यु को भी प्राप्त कर लेता है। इन कारकों के अंतर्गत आयु, लिंग, असाध्य रोग, अनुवांशिक रोग, एवं संचरण की बीमारियां सम्मिलित होती हैं।

9.4.2 बाह्य कारक

बाह्य कारकों के अंतर्गत पर्यावरण से जुड़े तत्व सम्मिलित होते हैं। पर्यावरण के प्रभावों से मृत्यु दर प्रभावित होती है। इसके अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण, ताप संबंधी परिवर्तनीयता, संक्रामक रोग, ज्वालामुखी, भूकंप एवं सुखा सम्मिलित होते हैं। बाह्य कारकों में इन प्राकृतिक तत्वों के अतिरिक्त अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक तत्व भी शामिल होते हैं, जो मर्त्यता हेतु उत्प्रेरक का कार्य करते हैं –

9.5 मर्त्यता में भिन्नता के कारण

मृत्यु व्यक्ति के जीवन में होने वाली एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जिससे वह बच नहीं सकता। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जो भी मनुष्य या जंतु जन्म लेता है, एक न एक दिन उसे अवश्य ही मरना पड़ता है। फिर भी प्रकृति के अंतर्गत कुछ ऐसी कारण पाए जाते हैं, जो मृत्यु जैसी परिघटना को नियंत्रित या उत्प्रेरित करने में सहायक होते हैं। ऐसे प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं –

सारणी 9.1 मर्त्यता के भिन्नता हेतु उत्तरदायी कारण

क्र. सं.	कारक	कारकों का विभाजन
1.	जनांकिकीय कारण	1. आयु कारक
		2. लिंग
2.	जैविकीय कारक	1. प्रजातीय भिन्नता
		2. प्रजनन क्षमता
		3. स्वास्थ्य
		4. जन्म नियंत्रण के उपाय
3.	सामाजिक कारक	1. विवाह की आयु
		2. वैवाहिक जीवन की अवधि
		3. लैंगिक चयन
		4. महिलाओं का समाज में स्थान
		5. ग्रामीण एवं नगरीय परिवेश
		6. सामाजिक सुरक्षा
		7. विधवा विवाह
		8. शिक्षा
4.	राजनीतिक कारक	1. युद्ध

		2. देशांतरण
		3. सांप्रदायिक राजनीति
		4. राष्ट्रीय अवहेलना
		5. जनसंख्या नीति
5.	धार्मिक कारक	1. धार्मिक मान्यताएँ
		2. धार्मिक संरचना
		3. संतान के प्रति दृष्टिकोण
		4. पुत्र की अनिवार्यता
		5. वर्ण एवं जाति
6.	आर्थिक कारक	1. आयस्तर
		2. व्यावसायिक संरचना
		3. जीवन स्तर
		4. खाद्यान्न आपूर्ति
		5. आर्थिक वैभव
		6. विकास की अवस्था

स्त्रोतः भारतीय जनगणना

9.6 जनांकिकीय कारण

9.6.1 आयु

मर्त्यता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में आयु का स्थान महत्वपूर्ण है। जनांकिकीय से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जीवन के प्रथम वर्ष एवं इसके अंतिम वर्षों में मर्त्यता की दर सर्वाधिक होती है। इसकी दर सबसे कम 15 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य अंकित की जाती है। जिन देशों में बच्चों एवं वृद्धो की संख्या अधिक होती है वहाँ मर्त्यता दर अधिक पाई जाती है दूसरी तरफ जिन देशों में युवा जनसंख्या अधिक होती है वहाँ मर्त्यता दर भी कम होती है।

9.6.2 लिंग

लिंग के आधार पर मर्त्यता दर का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है, कि जिंदगी के किसी भी आयु वर्ग में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जीवन संभाव्यता एवं रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। आंकड़ों में यह भी पाया गया है कि विकसित देशों में पुरुषों की मर्त्यता अधिक होती है, जबकि विकासशील देशों में महिलाओं की। विकसित देशों में पुरुषों की कृषि, व्यवसाय एवं सेवाओं में सलंग्नता अधिक होती है जिसके कारण उनकी मृत्यु दर

अधिक होती है। विकासशील देशों में महिलाओं की मर्त्यता दर अधिक होने के कारणों में अल्प आयु में विवाह एवं गर्भधारण, कुपोषण, समाज में स्त्रियों की दशा, शिक्षा का अभाव एवं चिकित्सा सुविधाओं आदि की कमी सम्मिलित होती है।

9.6.3 ग्रामीण एवं नगरीय भिन्नता

सामाजिक संरचना, जीवन स्तर, आवासीय सुविधा, चिकित्सकीय सुविधा एवं व्यावसायिक संरचना आदि में भिन्नता के कारण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में मर्त्यता दर अलग – अलग होती है। विकसित देशों में ग्रामीण एवं नगरीय भिन्नता का स्तर बहुत कम होता है, जबकि विकासशील एवं अल्पविकसित देशों में यह अंतर अधिक पाया जाता है। विकासशील एवं अल्पविकसित देशों में ग्रामीण जनसंख्या का विस्तार अधिक पाया जाता है। ऐसी स्थिति में इस जनसंख्या में निर्धनता, जागरूकता में कमी, अशिक्षा एवं निम्न स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं पाई जाती हैं। इस कारण यहां मर्त्यता दर अधिक दर्ज की जाती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ मर्त्यता दर 11 प्रति हजार है, वहीं नगरीय क्षेत्रों में यह 7 प्रति हजार दर्ज किया जाता है।

9.7 सामाजिक कारण

मर्त्यता को नियंत्रित करने वाले प्रमुख सामाजिक कारण निम्नलिखित हैं –

9.7.1 सामाजिक प्रथाएं

विश्व के अलग – अलग भागों में अलग – अलग प्रकार के धर्म एवं समुदाय के लोग रहते हैं। अपनी आस्था एवं विश्वास के अनुसार इनकी अपनी अलग – अलग प्रथाएं प्रचलित हैं जिनसे मर्त्यता दर प्रभावित होती है। ऐसी प्रथाओं में बाल हत्या, बाल विवाह एवं सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं प्रचलित हैं। अनेक देशों में ऐसी प्रथा है, जिसमें जनसंख्या में कमी लाने के लिए बच्चों की सामूहिक हत्या भी कर दी जाती है। कुछ समाज में लड़कियों को बोझ समझा जाता है। ऐसी स्थिति में उन्हें विभिन्न चिकित्सकीय विधियों से लिंग चयन करके या तो जन्म से पूर्व ही मार दिया जाता है या जन्म के पश्चात ताकि उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विवाह से होने वाले खर्च से परिवार को परेशानी न हो। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के कुछ भागों में डायन की प्रथा भी प्रचलित है, जिसके कारण कुछ महिलाओं को मार दिया जाता है।

9.7.2 अशिक्षा

अशिक्षा एक सामाजिक अभिशाप है जो अधिकांशतः पिछड़े समाजों में अधिक दिखाई देता है। यह प्रत्यक्ष रूप से मर्त्यता दर को उत्प्रेरित करती है। अशिक्षा के कारण ही समाज में अंधविश्वास, धर्मांधता, रूढ़िवादिता एवं कुप्रथा जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इन रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास के कारण लोग कई बीमारियों का समय पर इलाज नहीं कराते और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अशिक्षित समाजों में स्वच्छता पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है, जो बीमारियों का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है।

9.7.3 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं

वर्तमान समय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को विकास के एक मानक के रूप में देखा जाता है। इन सुविधाओं की पहुंच एवं अभाव मर्त्यता दर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जिन देशों या समाजों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रसार एवं स्थिति अच्छी पाई जाती है। वहाँ बीमारियां अपने आप ही नियंत्रित हो जाती हैं। विकासशील एवं अल्पविकसित देशों में अधिकांश भाग समुचित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहता है, जिसके कारण यहां मृत्यु अधिक होती है। कभी – कभी बीमारियां महामारियों का रूप भी धारण कर लेती है। समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होने पर स्वास्थ्य उत्तम रहता है, बीमारियां कम होती हैं और मृत्यु दर अपने निम्नतम स्तर पर होती है।

9.7.4 आवासीय स्थिति

स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं आवास मानव की मौलिक आवश्यकताएं हैं। इनकी उपलब्धता एवं अनुपलब्धता प्रत्यक्ष रूप से मर्त्यता को प्रभावित करती है। अधिकांश विकासशील एवं अल्पविकसित देशों के ग्रामीण एवं नगरीय भागों में आवास एक प्रमुख समस्या है। जहाँ ग्रामीण इलाकों में लोग झुग्गी –झोपड़ी, कच्चे मकान में रहते हैं, तो नगरीय

क्षेत्रों में अधिकांश जनसंख्या मलिन बस्तियों में रहने के लिए विवश हो जाती है। ऐसे दोनों स्थानों पर निर्धनता की अधिकता, आवासों की कमी, अशिक्षा एवं पारिवारिक व्यवस्था के कारण लोग बीमारियों से अधिक प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति में मर्त्यता दर बढ़ जाती है।

9.8 आर्थिक कारण

मानव समाज के कल्याण हेतु आर्थिक स्थितियां अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। यह मर्त्यता दर को अधिक प्रभावित करती है। इसके प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं –

9.8.1 आय

आय किसी भी देश की वर्तमान स्थिति का बोधक होता है। इसकी एक निश्चित सीमा होती है इससे कम कमाने वाला परिवार या व्यक्ति गरीब कहलाता है जिन देशों में आय का स्तर उच्च होता है। वहाँ समृद्धि का स्तर भी उच्चतम होता है। उनकी क्रय क्षमता भी अधिक होती है। ऐसी स्थिति में वह अपने दैनिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की आपूर्ति आसानी से कर लेते हैं। इसके विपरीत जिन समाजों या देश का आय स्तर निम्न होता है, वहाँ भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जरूरतों की आपूर्ति नहीं हो पाती है। इस कारण इन क्षेत्रों में मर्त्यता दर अधिक देखी जाती है।

9.8.2 गरीबी

गरीबी एक सामाजिक – आर्थिक दशा है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी तथा अपने परिवार की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असक्षम होता है। इसका स्वरूप अलग – अलग होता है। कभी – कभी यह स्वनिर्मित हो जाती है, तो कभी – कभी विरासत में भी प्राप्त होती है। गरीबों की स्थिति वहीं पाई जाती है, जहाँ आय एक सीमा से कम होती है। जिन समाजों में परंपरागत गरीबी विद्यमान है, अत्यधिक मात्रा में बीमार लोग वहीं मिलते हैं। कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो जन्मजात बीमार होते हैं, इनमें से कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है जबकि जो बचते हैं वह शारीरिक रूप से इतने कमजोर होते हैं कि गरीबी का सामना नहीं कर पाते हैं। इससे मर्त्यता दर में वृद्धि हो जाती है। वर्तमान समय में सरकारों द्वारा गरीबी का सामना करने हेतु कुछ कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं।

9.8.3 कुपोषण

कुपोषण का तात्पर्य होता है शरीर को जितनी मात्रा में पोषण की आवश्यकता होती है, उतनी मात्रा का नहीं मिल पाना। ऐसी स्थिति में व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। कुपोषण का मुख्य कारण गरीबी के साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय का कम होना भी है। इसके साथ ही कुछ संपन्न परिवारों में भी कुपोषण की स्थिति देखी जाती है, जिसका मुख्य कारण होता है रूढ़िवादिता एवं जानकारी का अभाव। ऐसी स्थितियों में कुपोषण बढ़ने से मर्त्यता की दर में वृद्धि हो जाती है।

9.9 राजनीतिक कारण

राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मर्त्यता को प्रभावित करने वाले दो ही महत्वपूर्ण कारण है। वह हैं युद्ध एवं आतंकवाद।

9.9.1 युद्ध

युद्ध की स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब दो परस्पर विरोधी राजनीतिक इकाइयों में अपने निहित स्वार्थ हेतु मतभेद हो जाता है। ऐसी स्थितियों में दोनों पक्षों से अपार जनधन की हानि के साथ हजारों सैनिक भी मारे जाते हैं। ऐसी स्थिति में सीमावर्ती इलाके में निवास करने वाली जनसंख्या भी मृत्यु का शिकार हो जाती है। इससे मृत्यु दर में अत्यधिक वृद्धि देखी जाती है।

9.9.2 आतंकवाद

कुछ अतिवादी संगठनों द्वारा अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति एवं जन सामान्य में भय उत्पन्न करने हेतु की गई हिंसक घटना को आतंकवाद कहते हैं। ये संस्थाएं लक्ष्य विहीन होती हैं, इनका उद्देश्य सिर्फ आतंक फैलाना

होता है। यह विश्व के किसी भी भाग या किसी देश के किसी भाग में गोलीबाजी एवं बमबाजी करके लोगों की हत्याएं कर देते हैं। ऐसी स्थिति में भी अनायास ही अधिक संख्या में लोग मारे जाते हैं। इस प्रकार आतंकवादी गतिविधियां मर्त्यता दर को उत्प्रेरित करती हैं।

9.10 प्राकृतिक कारक

प्रकृति द्वारा मानव समुदाय के सम्मुख उत्पन्न की गई, वे चरम दशाएं जिससे जन धन की हानि होती है प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। इनके प्रभाव से संपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था ही डगमगने लगती है इसके अंतर्गत भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा, अकाल एवं महामारियां सम्मिलित होती हैं। इनके बार – बार पुनरावृति से अधिसंख्यक लोगों की मृत्यु हो जाती है। वर्ष 2001 में भुज एवं 2015 में नेपाल में आने वाले भूकंप 21वीं शताब्दी के सबसे भयंकर थे। इसमें लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन, उनके मार्ग में प्राकृतिक अथवा मानवीय कारकों द्वारा उत्पन्न अवरोध, तली में गादों का जमाव जैसी स्थितियां नदियों के निचले भागों में बाढ़ का कारण बनती हैं। सुखा भी एक प्रकृति प्रदत्त घटना है, जो अल्प वर्षा के कारण उत्पन्न होती है। इस प्रकार देखा जाता है कि बाढ़ एवं सुखा के कारण अकाल जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं क्योंकि दोनों स्थितियों में फसले नष्ट हो जाती हैं। लोग खाद्यान्नों के अभाव में कुपोषण एवं अन्य बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और अधिक संख्या में लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये सभी कारक संयुक्त रूप से मर्त्यता दर को प्रभावित करते हैं।

उपरोक्त कारकों की व्याख्या करने के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि विश्व के कुछ भागों में मृत्यु दर अधिक पाई जाती है, तो कुछ भागों में कम। संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व जनगणना विभाग, विभिन्न देशों की संस्थाओं तथा स्थानीय स्तर पर प्राप्त होने वाले आंकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि विकासशील एवं अल्पविकसित देशों में मर्त्यता दर अधिक पाई जाती है। विकसित देशों एवं समाजों में इसकी मात्रा कम होती है। विकासशील एवं अल्पविकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं अभी विकसित नहीं हो पाई हैं जिसके कारण यहां शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं तथा सेवाओं का सभी जगह तक समुचित प्रसार नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ आर्थिक स्थितियां कमजोर होने के कारण इन देशों के निवासी बीमारियों एवं महामारियों का सामना ठीक ढंग से नहीं कर पाते, यही कारण है कि इन देशों में मृत्यु दर अधिक पाई जाती है।

विकसित देशों एवं समाजों की आर्थिक संपन्नता के कारण यहां शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का उचित ढंग से प्रसार हो जाता है। आर्थिक स्थितियां मजबूत होने के कारण इन समाजों में लोगों की जागरूकता एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचे अच्छी होती है जिसके कारण इन देशों अथवा समाजों में मर्त्यता दर न्यून पाई जाती है।

9.11 सारांश

आपने इस इकाई में मर्त्यता का अर्थ तथा एक समय से दूसरे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृत्यु दर में भिन्नता के कारण का अध्ययन किया है। आप समझ गए होगें कि मृत्यु एक अनिवार्य प्रक्रिया जो हर जीव को एक न एक दिन अवश्य प्राप्त होती है। इसके पश्चात व्यक्ति के समस्त जैविक चिन्ह नष्ट हो जाते है। वास्तव में किसी देश की जनसंख्या तथा वहाँ का सबसे बड़ा संसाधन होती है जो उसकी भौगोलिक अवस्थिति, सरकारी नीतियों, सांस्कृतिक संगठन आदि के आधार पर विकसित होती है। यदि किसी देश में मृत्यु दर तीव्र है तो निश्चित ही वहाँ के अधिकांश संसाधन इसका सामना करने में नष्ट हो जाते है। किसी भी देश के विकास की प्रारम्भिक अवस्था में मृत्यु दर तेज होती है परंतु जैसे – जैसे विकास का स्तर तीव्र होता मृत्यु दर घटने लगती है

9.12 स्वमूल्यांकन प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

1. मोरक्को में जन्म से कितने घण्टे के अंदर मरने वाले बच्चों को मृतक शिशु कहा जाता है।

   (क) 12 घण्टे (ख) 24 घण्टे (ग) 36 घण्टे (घ) 72 घण्टे

2. मर्त्यता दर को किसमें में व्यक्त करते हैं ।

   (क) प्रति हजार (ख) प्रति सौ (ग) प्रति दस हजार (घ) प्रति लाख

3. मर्त्यता की माप हेतु निम्नलिखित सूचकांकों में से किसका प्रयोग किया जाता है।

(क) अशोधित मृत्यु दर (ख) शिशु मृत्यु दर (ग) मातृ मृत्यु दर (घ) बीमारी

4. मर्तयता के एक कारणों में कुपोषण भी है, कुपोषण से तात्पर्य होता है।

(क) शरीर को जितनी मात्रा में पोषण की आवश्यकता होती है, उतनी मात्रा में नहीं मिल पाना।

(ख) शरीर को जितनी मात्रा में पोषण की आवश्यकता होती है, उससे अधिक मात्रा में मिल जाना।

(ग) शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाना।

(घ) शरीर में बसा की कमी हो जाना।

5. भारत में भुज का भूकम्प कब आया था।

(क) 2001 ई. (ख) 1972 ई. (ग) 2015 ई. (घ) 1983 ई.

9.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

Bogue] D- J-] 1969] Principles of Demography] John Wiley] N-Y-

Clarke] John I-] 1973] Population Geography] Pergaman Press] Oxford-

Crook] Nigel] 1997] Principles of Population and Development] Pergaman Press] N- Y-

Garmier] J- B-] 1970] Geography of Population] Longman] London-

Mamoria] C- B-] 1981] India's Population Problem] Kitab Mahal] New Delhi-

Premi] M- K-] 1991] India's Population] Heading Towards a Billion] B- R- Publishing Corporation-

Blassoff] M- and Srinivasan K-] 2001] Population Development Nexus in India : Challenges for the New Millennium] Tata McGraw Hill] New Delhi-

Woods] R-] 1979] Population Analysis in Geography] Longman] London-

Zelinsky] W-] 1966] A Prologue to Population Geography] Prentice Hall-

चन्दना, आर. सी., 2022, जनसंख्या भूगोल – संकल्पना, नियंत्रक व विश्व प्रारूप, कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

चन्दना, आर. सी., 2022, भारत : जनसंख्या (जनसंख्या भूगोल – भाग 2), कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

मौर्या, एस. डी., 2005, जनसंख्या भूगोल, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद.

ओझा, आर. पी., 1984, जनसंख्या भूगोल, प्रतिभा प्रकाशन.

हीरा लाल, 2000, जनसंख्या भूगोल के मूल तत्व, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली.

तिवारी, राम कुमार, 2023, जनसंख्या भूगोल, प्रवालिका पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद.

9.14 अभ्यास प्रश्न (सत्रांत परीक्षा की तैयारी)

1. मर्त्यता का अर्थ क्या है, इसकी माप हेतु प्रयुक्त सूचकांक को स्पष्ट कीजिए?
2. मर्त्यता के निर्धारकों का वर्णन कीजिए?
3. मर्त्यता में भिन्नता के लिए उत्तरदायी कारणों का विश्लेषण कीजिए

इकाई–10 लिंगानुपात के प्रकार एवं लिंगानुपात के परिकलन की विधियाँ

इकाई की रूपरेखा

10.0 प्रस्तावना

10.1 उद्देश्य

10.2 लिंगानुपात का अर्थ

10.3 लिंगानुपात के प्रकार

10.4 लिंगानुपात के परिकलन की विधियां

10.5 लिंगानुपात का वैश्विक वितरण

10.6 लिंगानुपात का वैश्विक प्रतिरूप

10.7 भारत में लिंगानुपात का वितरण

10.8 सारांश

10.9 स्वमूल्यांकन प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

10.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

10.12 अभ्यास प्रश्न (सत्रांत परीक्षा की तैयारी)

10.0 प्रस्तावना

लिंगानुपात जनसंख्या संघटन का एक प्रमुख अवयव है। क्लार्क के शब्दों में जनसंख्या संघटन उन पक्षों को व्यक्त करता है, जिनकी माप की जा सकती है। जनसंख्या से संबंधित वे सभी आंकड़े जिनको जनगणना या किसी अन्य माध्यम से संग्रहित किया जाता है, जनसंख्या के संघटन कहलाते हैं। जनसंख्या संगठन के आंकड़ों को गुणात्मक एवं मात्रात्मक दो पक्षों में विभक्त किया जाता है। गुणात्मक पक्षों में उन सामाजिक परंपराएं, मनोवैज्ञानिक सोच, रीति – रिवाज, खान – पान इत्यादि सम्मिलित होते हैं। मात्रात्मक पक्षों में राष्ट्रीयता, शैक्षणिक स्तर, भाषा, जाति, धर्म, परिवार का आकार, वैवाहिक स्थिति, व्यावसायिक क्रिया, आर्थिक क्रियाकलाप, ग्रामीण एवं नगरीय संरचनाएं इत्यादि सम्मिलित होते हैं।

10.1 उद्देश्य

लिंगानुपात जनसंख्या भूगोल का प्रमुख घटक है, जिसका अध्ययन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। इस इकाई के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है –

1. लिंगानुपात के अर्थ एवं प्रकार को समझना।
2. लिंगानुपात के परिकलन की विधियों की व्याख्या करना।

10.2 लिंगानुपात का अर्थ

जनसंख्या संघठन का प्रमुख अवयव लिंगानुपात होता है। लिंग संघठन अथवा लिंगानुपात का तात्पर्य किसी जनसंख्या में स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या से है। किसी देश या प्रदेश की सामाजिक स्थिति और अर्थव्यवस्था में स्त्री पुरुष अनुपात की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इन्हीं कारणों से एक जनसंख्या भूगोलवेत्ता के लिए आवश्यक हो जाता है, कि समाज में लिंगानुपात की वर्तमान दशा एवं दिशा का अध्ययन करें । स्त्री एवं पुरुषों के प्राकृतिक गुण,

स्वभाव, कार्य क्षमता एवं शारीरिक संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। इसके साथ ही वे अनेक विषयों में एक – दूसरे के पूरक भी होते हैं। ऐसी अवस्था में किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में लिंगानुपात की स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। लिंगानुपात किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास का सूचक होता है। इसमें होने वाली स्थानिक भिन्नता के कारणों का विश्लेषण जनसंख्या भूगोल की विषय वस्तु होती है।

ट्रिवार्था के अनुसार किसी भौगोलिक क्षेत्र की विश्लेषण के लिए लिंगानुपात एक मौलिक बिंदु होता है क्योंकि यह भू दृश्य का एक महत्वपूर्ण लक्षण ही नहीं बल्कि अन्य जनांकिकीय तत्वों को भी विशेष रूप से प्रभावित करता है।

जनसंख्या के विविध पक्षों के अध्ययन के दौरान अन्य जनसंख्या घटकों की तुलना में लिंगानुपात के आंकड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। स्पष्ट शारीरिक संरचना के कारण जनगणना के दौरान इनकी पहचान आसानी से हो जाती है तथा इसे छिपाया नहीं जा सकता । इसके विपरीत संपत्ति, व्यवसाय एवं आयु जैसे तत्वों को लोग आसानी से छुपा लेते हैं।

10.3 लिंगानुपात के प्रकार

लिंगानुपात जनसंख्या अध्ययन की एक महत्वपूर्ण धारणा है, जिसका मापन गर्भधारण की अवधि से लेकर मृत्यु तक किया जाता है। समय एवं अवस्था विशेष इसके नाम एवं गणना की विधियों में परिवर्तन होता रहता है। जनांकिकीय अवस्थाओं के आधार पर लिंगानुपात को मुख्यतः तीन वर्गों में विभक्त किया जाता है –

- प्राथमिक लिंगानुपात
- द्वितीय लिंगानुपात
- तृतीय लिंगानुपात

10.3.1 प्राथमिक लिंगानुपात

गर्भधारण के समय जिस लिंगानुपात की गणना की जाती है वह प्राथमिक लिंगानुपात कहलाता है। दूसरे शब्दों में प्राथमिक लिंगानुपात गर्भधारण के समय के लिंगानुपात को अभिव्यक्त करता है। कर्ट स्टर्न (1968) ने अपनी पुस्तक मानव अनुवांशिकता के सिद्धांत में स्पष्ट किया है कि सैद्धांतिक रूप में भी प्राथमिक लिंगानुपात 1:1 अनुपात में नहीं पाया जाता जबकि पुरुष भ्रूण की तुलना में स्त्री भ्रूण की संख्या कम पाई जाती है। सही सर्वेक्षण तथा आंकड़ों के अभाव में एक तथ्य अनुमानित होते हैं। कर्ट स्टर्न द्वारा व्यक्त विचार के अनुसार प्रति 100 बालिका वाले गर्भ की तुलना में 125 से 135 बालक गर्भ प्राप्त होते हैं। शिवदास मौर्य अपनी पुस्तक जनसंख्या भूगोल में लिखते हैं कि जन्म से पूर्व पुरुष भ्रूण अपेक्षाकृत अधिक नष्ट हो जाते हैं, जिससे इनका अनुपात उतना उच्च नहीं रहता जितना गर्भधारण के समय होता है।

वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि लिंग निर्धारण में पुरुष शुक्राणुओं का महत्व अधिक होता है। स्त्रियों के अंडाणु के साथ पुरुष के शुक्राणु से निषेचन के दौरान ही गर्भस्थ शिशु के लिंग का निर्धारण होता है। इसी दौरान यह निश्चित होता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की । इस संदर्भ में जीव वैज्ञानिकों द्वारा निम्नलिखित मत दिए गए हैं –

- पुरुषों के वीर्य में X तथा Y दो प्रकार के शुक्राणु पाए जाते हैं। इन दोनों की संख्या वृषण कोष एवं अण्डकोष में एक समान होती है।
- शारीरिक संबंध बनाने के दौरान जब स्त्री के प्रजनन अंग में पुरुष का वीर्य स्खलित होता है तब उसे दौरान भी वीर्य में X तथा Y शुक्राणुओं की संख्या समान होती है।
- शारीरिक संबंध स्थापित करने के पश्चात पुरुष का वीर्य स्त्रियों के प्रजनन अंग में कुछ समय के लिए ठहरता है। वहाँ पर स्त्री के अंडाणु से पुरुष एक अथवा शुक्राणु का संयोजन होता है जिसे निषेचन कहते हैं। ऐसी स्थिति में निषेचन के दौरान शुक्राणु की तुलना में शुक्राणु की सफलता दर अधिक होती है। इस संदर्भ में जीव वैज्ञानिकों ने तीन प्रकार की संभावनाएं व्यक्त की हैं –

1. पुरुष वीर्य में उपलब्ध X तथा Y दोनों प्रकार के शुक्राणुओं में से Y शुक्राणु के लिए महिलाओं के जननांग की आंतरिक संरचना एवं वातावरण ज्यादा सुरक्षित होता है।
2. X शुक्राणु की तुलना में Y शुक्राणु ज्यादा सक्रिय होता है, इसीलिए अंडाणु तक पहुंचने में वह अधिक सफल होता।
3. X शुक्राणु की तुलना में Y शुक्राणु से स्त्री का अंडाणु अधिक तीव्रता से प्रतिक्रिया करता है।

- मनोवैज्ञानिक सिद्धांत तथा प्रयोग के आधार पर सिद्ध है कि गर्भ का निर्धारण करने वाले शुक्राणु अधिक समय तक जीवित रहते हैं तथा हल्के भी होते हैं। इसके विपरीत X शुक्राणु स्थूल, मंद एवं अल्प अवधि वाले होते हैं। यह सर्व विदित है कि महिला के प्रजनन अंग अंदर से जब पुरुष का X शुक्राणु मिलता है तब उत्पन्न होने वाली भ्रूण महिला होती है, जबकि जब X अंडाणु से Y शुक्राणु मिलता है तब उत्पन्न होने वाला भ्रूण पुरुष होता है। ऐसी स्थिति में यह पाया गया है कि चूंकि शुक्राणु दीर्घाजीवी एवं तीव्र गामी होते हैं, अतः ऐसी स्थिति में गर्भावस्था में पुरुष भ्रूण की अधिकता पाई जाती है।

10.3.2 द्वितीय लिंगानुपात

महिलाओं के प्रसव के समय अथवा शिशु के जन्म के समय अंकित किए गए लिंगानुपात को द्वितीय लिंगानुपात कहा जाता है। इसे प्राकृतिक लिंगानुपात भी कहा जाता है। वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि गर्भावस्था की समय में पुरुष भ्रूण की अधिकता होती है। ऐसी स्थिति में जन्म के समय भी नर शिशुओं की संख्या अधिक पाई जाती है।

गर्भावस्था की अवस्था से शिशु जन्म तक आते – आते भ्रूण की संख्या में होने वाला यह परिवर्तन कुछ घट जाता है इसके निम्नलिखित कारण बताए गए हैं –

- बाडमर एवं सफोर्ज ने यह सिद्ध किया है कि अनुवांशिक तथ्य यह है कि प्रसव काल में से संयुक्त घटक जीन नर को साफ कर देता है, लेकिन मादा पर उसका कोई प्रभाव स्पष्ट नहीं होता । जैविक दृष्टि से मादा लिंग काफी सक्षम होता है क्योंकि इसमें दो प्रकार के क्रोमोजोम पाए जाते हैं, तथा नर में एक ही क्रोमोजोम होता है अतः कमजोर होते है। इस प्रकार यह देखा जाता है कि इन विविधताओं के बावजूद भी द्वितीयक लिंगानुपात में नर का जन्म अधिक होता है।
- कुछ प्राणी विज्ञानियों का मानना है कि द्वितीय लिंगानुपात 1:1 के अनुपात में नहीं होता है क्योंकि कभी – कभी मादा युग्मक स्वतः नर क्रोमोजोम में विकसित हो जाते हैं।

वैश्विक स्तर पर यदि द्वितीय लिंगानुपात का अध्ययन किया जाए तो प्राप्त होता है कि मैक्सिको, क्यूबा, ग्वाटेमाला, दक्षिण कोरिया एवं अर्जेंटीना में जहाँ यह अनुपात 120 पुरुष प्रति 100 स्त्री तक होते हैं वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका, चेक गणराज्य, जर्मनी एवं डेनमार्क में यह 105 पुरुष प्रति 100 स्त्री होते हैं। इसी प्रकार इसका परिदृश्य कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एवं रूस में प्रति 105 पुरुष पर 120 महिलाओं का अनुपात है।

10.3.3 तृतीय लिंगानुपात

तृतीय लिंगानुपात वह होता है, जो जनगणना के समय प्राप्त होता है। इसे मौलिक लिंगानुपात या वास्तविक लिंगानुपात के नाम से भी जाना जाता है। विश्व के सभी देशों द्वारा इसकी गणना प्रत्येक जनगणना काल में की जाती है। तृतीय लिंगानुपात मुख्य रूप से कुल स्त्री के संदर्भ में कुल पुरुषों की संख्या अथवा कुल पुरुषों के संदर्भ में कुल स्त्रियों की संख्या होती है। विश्व के अलग – अलग देश में इसकी गणना भिन्न प्रकार से की जाती है। भारत में इसकी गणना प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के अनुपात में की जाती है।

जनगणना काल में प्राप्त होने वाले लिंगानुपात के तीन मुख्य कारक होते हैं

1. जन्म का लिंगानुपात
2. मृत्यु का लिंगानुपात
3. प्रवासियों का लिंगानुपात

इन तीनों से संयुक्त रूप से प्राप्त होने वाला लिंगानुपात जनगणना काल के लिंगानुपात का परिणाम होता है। इन तीनों लिंगानुपात में समय के साथ परिवर्तनीयता देखी जाती है। लिंगानुपात गणना की यह प्रथम अवस्था प्राकृतिक होती है। ऐसी स्थिति में जन्म के समय पुरुष लिंगानुपात विश्व के सभी देशों में अधिक होता है। लिंगानुपात परिवर्तन का दूसरा कारक मृत्यु होती है। मृत्यु दर भी लिंगानुपात को प्रभावित करती है। इस संदर्भ में विद्वानों का मत है कि जैविक दृष्टि से स्त्रियां पुरुषों से सक्षम होती हैं। ऐसी स्थिति में यह देखा जाता है की जन्म से लेकर जीवन पर्यंत पुरुषों की मृत्यु अधिक होती है। व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक विकास की स्थिति मृत्यु दर पर प्रभाव डालती है। ऐसी समाज जहाँ बच्चों, स्त्रियों एवं वृद्धो के देखभाल, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता आदि लापरवाही देखी जाती है, वहाँ पर मृत्यु दर अधिक दर्ज की जाती है और तृतीय लिंगानुपात प्रभावित होता है।

लिंगानुपात में परिवर्तनीयता के प्रमुख कारकों में प्रवास अथवा जनसंख्या का स्थानीय स्थानांतरण भी महत्वपूर्ण है। आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास लिंग चयनित होता है। स्थानीय प्रवास में जहाँ स्त्री एवं पुरुष दोनों की सहभागिता देखी जाती है, वहीं लंबी दूरी के प्रवास में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष ही अधिक प्रवास करते हैं।

10.4 लिंगानुपात के परिकलन की विधियां

लिंगानुपात का परिकलन विश्व के अलग – अलग देश में भिन्न – भिन्न प्रकार से किया जाता है। कुछ देश इसका परिकलन प्रति हजार के अनुपात में करते हैं, तो कुछ 100 के अनुपात में इसकी गणना करते हैं। किन्हीं देश में इसकी गणना पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से की जाती है, तो किन्हीं देशों द्वारा स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या से की जाती है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या भूगोलवेत्ताओं के समक्ष इसके अध्ययन की चुनौती उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में इसके सहज, सरल और बाध्यता रहित परिकलन हेतु निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती हैं –

अ. प्रति 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की कुल जनसंख्या

सूत्र = कुल स्त्री * 1,000 / कुल पुरुष

नोट : * से तात्पर्य गुणा से है.

यह लिंगानुपात गणना हेतु सर्वाधिक प्रयोग होने वाला सूत्र है। दक्षिणी एशिया के साथ पूर्वी यूरोप में इसी सूत्र से लिंगानुपात की गणना की जाती है। भारत में भी इसी सूत्र का प्रयोग किया जाता है।

ब. प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की कुल जनसंख्या

सूत्र = कुल स्त्री * 100 / कुल पुरुष

नोट : * से तात्पर्य गुणा से है.

इस विधि से लिंगानुपात की गणना न्यूजीलैण्ड देश में की जाती है।

स. प्रति 1,000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या

सूत्र = कुल पुरुष * 1,000 / कुल स्त्री

नोट : * से तात्पर्य गुणा से है.

विश्व के अधिकांश देशों में इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है।

द. प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या

सूत्र = कुल पुरुष * 100 / कुल स्त्री

नोट : * से तात्पर्य गुणा से है.

यह सूत्र संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कुछ अन्य देशों में लिंगानुपात की गणना हेतु प्रयोग किया जाता है।

य. कुल 1,000 जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का अनुपात

सूत्र = कुल पुरुष * 1,000 / कुल जनसंख्या

नोट : * से तात्पर्य गुणा से है.

लिंगानुपात की गणना के लिए यह सूत्र रूस में प्रयोग रूस में किया जाता है।

र. कुल जनसंख्या में पुरुषाधिक्य की गणना

सूत्र = कुल पुरुष – कुल स्त्री / कुल जनसंख्या

नोट : * से तात्पर्य गुणा से है.

यह सूत्र वर्तमान समय में वेनेंजुएला में प्रचलित है।

10.5 लिंगानुपात का वैश्विक वितरण

जनसंख्या से जुड़े वैश्विक आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वैश्विक स्तर पर सामान्यतः पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक होती है। वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 984 है। इसका मुख्य कारण पुरुष संख्या का अधिक होना है। महाद्वीपों के आधार पर यदि विश्लेषण किया जाए तो ज्ञात होता है कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं अफ्रीका में स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है जबकि लैटिन अमेरिका, एशिया एवं ओसिनिया महाद्वीपों में स्त्रियों की संख्या कम पाई जाती है। आर. सी. चांदना अपनी पुस्तक जनसंख्या भूगोल में लिखते हैं यूरोप में लिंगानुपात उच्चतम है। इसके बाद क्रमशः उत्तरी अमेरिका एवं अफ्रीका का स्थान आता है। एशिया में लिंगानुपात सबसे कम पाया जाता है। रूस में लिंगानुपात प्रति 1167 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। वैश्विक स्तर पर प्रमुख देशों का लिंगानुपात निम्नलिखित है चीन (926), भारत (943), इंडोनेशिया (988) एवं बांग्लादेश (978)।

लिंगानुपात के वैश्विक परिदृश्य की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है –

- वैश्विक स्तर पर पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक है, विश्व का सामान्य लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 984 है।
- लिंगानुपात के परिदृश्य पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो दो प्रतिरूप मिलते हैं पहला वह क्षेत्र जहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है, दूसरा परिदृश्य वह है जहाँ पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है।
- पूर्वी यूरोप के साथ रुस एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से काफी कम है। इसका कारण विश्व युद्ध से जोड़कर देखा जाता है।
- उत्तरी अमेरिका एवं अफ्रीका के देशों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक पाई जाती है। इन दोनों क्षेत्रों में पुरुषों की मृत्यु महिलाओं से अधिक होती है। इसका कारण जहाँ अमेरिका की जीवन शैली एवं कुछ दुर्घटनाएं हैं वहीं अफ्रीका में जातीय एवं काबीलियाई संघर्ष हैं।
- चीन की एक बच्चा नीति एवं कन्या भ्रूण तथा महिला शिशु की हत्या के कारण लिंगानुपात अधिक प्रभावित हुआ है।
- भारत में महिलाओं, मादा शिशुओं एवं भ्रूण हत्या की परंपरा प्राचीन काल से प्रचलित है। वर्तमान समय में भारतीय समाज में सीमित परिवार रखने का प्रचलन तेजी से बढ़ा है, ऐसी स्थिति में लिंग परीक्षण करके मादा भ्रूण के गर्भपात का कार्य पुत्र चाह में अधिक हो रहा है।
- कुछ देशों में स्त्रियों की निम्न सामाजिक दशा, महिलाओं की असुरक्षा, अशिक्षा एवं महिलाओं में अधिक कुपोषण के कारण उनकी मृत्यु दर अधिक देखी जाती है। यही कारण है कि अधिकांश मुस्लिम देशों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अति निम्न दर्ज की जाती है।

10.6 लिंगानुपात का वैश्विक प्रतिरूप

वैश्विक जनसंख्या के लिंगानुपात का वितरण प्रस्तुत करने के लिए तृतीयक लिंगानुपात के आकड़ों का प्रयोग किया जाता है। यह जनगणना के समय प्राप्त होने वाला लिंगानुपात होता है, जो वास्तविक रूप में स्त्री – पुरुष के अनुपात को अभिव्यक्त करता है। विश्व के सभी देशों की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक दशाओं में अन्तर पाए जाने के कारण वहाँ स्त्री एवं पुरुष अनुपात में विभिन्नता देखी जाती है। वर्ष 1990 के दशक में औसत लिंगानुपात 993 स्त्री प्रति 1000 पुरुष था। जनसंख्याविदों का कहना है कि 990 से 1000 स्त्रियाँ प्रति 1000 पुरुष का अनुपात सामान्य होता है। इससे कम या अधिक होना उस स्थान की सामाजिक और आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। महाद्वीपों के अनुसार अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि जहाँ उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं अफ्रीका में स्त्रियाँ की संख्या अधिक है वहीं दक्षिणी अमेरिका, एशिया और आस्ट्रेलिया में पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है। प्रत्येक महाद्वीप में लिंगानुपात के वितरण को निम्नलिखित सारणी के माध्यम से दर्शाया गया है –

सारणी 10.1 महाद्वीपों के अनुसार लिंगानुपात (2001)

क्र. सं.	महाद्वीपों के नाम	लिंगानुपात
1.	यूरोप	1,051
2.	एशिया	960
3.	अफ्रीका	1,017
4.	उत्तरी अमेरिका	1,050
5.	दक्षिणी अमेरिका	995
6.	ओशीनिया	983
7.	पूर्व सोवियत संघ	1,137
8.	सम्पूर्ण विश्व	993

स्त्रोतः संयुक्त राष्ट्र संघ का जनसंख्या विभाग.

विश्व के सभी देशों के लिंगानुपात संबंधी आकड़ों का एक साथ विश्लेषण करना आसान नहीं है, इसलिए इस इकाई में महाद्वीपों के अनुसार उनके वितरण को समझने का प्रयास किया गया है। उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि विश्व के सबसे अधिक विकसित महाद्वीप उत्तरी अमेरिका और यूरोप में स्त्रियों की संख्या पुरुष वर्ग से अधिक दर्ज की गई है। यहाँ पर ऐसी स्थिति पाए जाने का मुख्य कारण पुरुषों की मृत्यु का अधिक होना है। इन महाद्वीपों के सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि यहाँ पुरुषों और स्त्रियों के जीवन स्तर, पोषण, चिकित्सा, शिक्षा एवं रोजगार के समान अवसर प्राप्त हैं फिर भी जैविक कारकों के साथ ही होने वाली विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं से पुरुष वर्ग की मृत्यु अधिक होती है। इन महाद्वीपों में सभी आयु वर्ग में पुरुषों की मृत्यु अधिक होती है। एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में विस्तारित रूस के विशाल भू–भाग में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 1137 महिलाएँ प्राप्त होती है। इसी प्रकार सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए महाद्वीप अफ्रीका पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक दर्ज की जाती है। यहाँ पर भी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 1037 अंकित की गई है।

एशिया एवं दक्षिणी अमेरिका के देशों की अर्थव्यवस्था की प्रकृति विकासशील देशों की है। इन देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आजादी प्राप्त की है। इसके कारण इनके अधिकांश देशों में अशिक्षा, व्यापक निर्धनता, स्वस्थ्य एवं प्रसूति सेवाओं की निम्न गुणवत्ता, कुपोषण, समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति, पितृ सत्तात्मक समाज

आदि के कारण मातृ मृत्यु दर एवं स्त्री मृत्यु दर दोनों अधिक होती है। इसी का परिणाम है कि इन महाद्वीपों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम दर्ज की जाती है। ओशिनिया के विशाल भू–भाग में सम्मिलित आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से विकसित देश हैं परंतु यहाँ भी पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम दर्ज की गई है। यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 989 अंकित की गई है जिसका मुख्य कारण है दूसरे देशों से पुरुष जनसंख्या का अधिक मात्रा यहाँ आगमन। यही कारण है कि इन देशों में लिंगानुपात पुरुषों के पक्ष में पाया जाता है।

10.7 भारत में लिंगानुपात का वितरण

विश्व के अन्य देशों की भांति ही भारत में भी लिंगानुपात के वितरण में असमानता देखी जाती है। इसी प्रकार समयानुसार कभी इसमें वृद्धि हुई है तो कभी ह्रास। भारत के संदर्भ अध्ययन करने पर विदित होता है कि विगत कुछ वर्षों में ह्रास हुआ पुनः वृद्धि हुई है। जो लिंगानुपात वर्ष 1901 ई. में 972 स्त्री/1000 पुरुष दर्ज किया गया था वह निरंतर घटते हुए वर्ष 2001 ई. में 933 स्त्री/1000 पुरुष प्राप्त हुआ। इसके पश्चात कुछ बढ़ कर वर्ष 2011 ई. 943 के स्तर को प्राप्त किया। इसकी प्रवृत्ति का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि यह किसी वर्ष कुछ बढ़ जाता है तथा कभी – कभी कुछ घट जाता है। भारत में लिंगानुपात की प्रवृत्ति को वर्ष 1901 से 2011 ई. के मध्य निम्नलिखित सारणी द्वारा दिखाया गया है –

सारणी 10.2 भारत के लिंगानुपात में परिवर्तन (1901 – 2011)

क्र. सं.	जनगणना वर्ष	लिंगानुपात (स्त्रियाँ / 1,000 पुरुष)
1.	1901	972
2.	1911	964
3.	1921	955
4.	1931	950
5.	1941	945
6.	1951	946
7.	1961	941
8.	1971	930
9.	1981	934
10.	1991	927
11.	2001	933
12.	2011	943

स्त्रोतः जनगणना विभाग, लखनऊ.

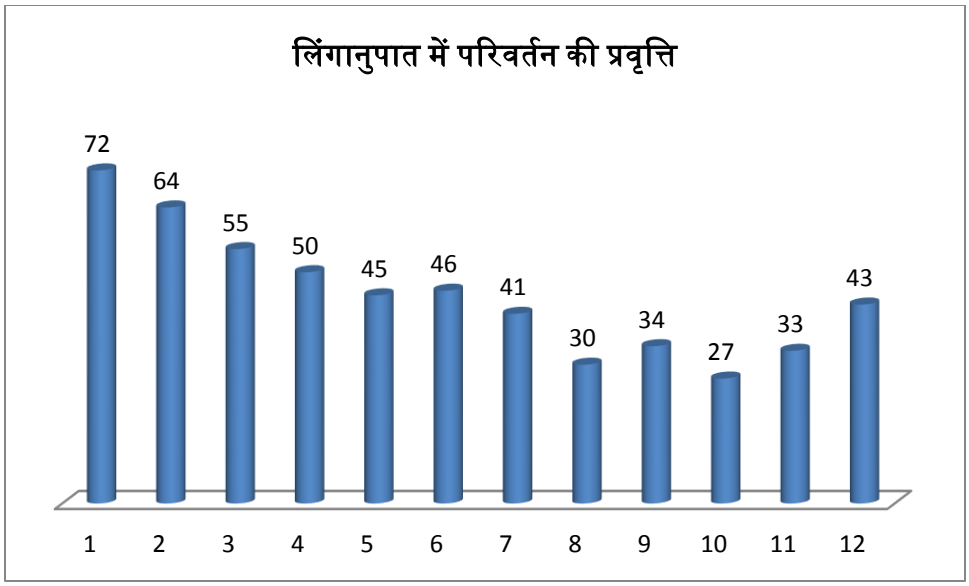

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1901 ई. से 1951 ई. के मध्य लिंगानुपात में निरंतर तीव्र गिरावट आयी है। जो लिंगानुपात वर्ष 1901 ई. 972 था वह घट कर 1951 ई. में 946 हो गया। इसकी प्रवृत्ति में निरंतर परिवर्तन दर्ज हुआ है। कभी यह बढ़ा है तो कभी घटा है। वर्ष 1991 ई. के बाद से लगातार तीन दशकों में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है।

भारत में लिंगानुपात के तीन स्वरूप देखे जाते है –

1) उच्च लिंगानुपात वाले राज्य – 1000 से अधिक

2) मध्यम लिंगानुपात वाले राज्य – 1000 से 900 के मध्य

3) निम्न लिंगानुपात वाले राज्य – 900 से कम

भारत में उच्च लिंगानुपात वाले राज्यों की श्रेणी में केवल दो राज्य केरल (1084) और पांडिचेरी (1038) सम्मिलित है। मध्यम लिंगानुपात वाले राज्यों में वे राज्य सम्मिलित है जिनका लिंगानुपात 1000 से 900 के मध्य दर्ज किया जाता है। इन राज्यों में छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, हिमांचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखण्ड, गोआ, त्रिपुरा, लक्ष्यद्वीप, झारखण्ड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश , उत्तर प्रदेश, आंध्रा प्रदेश आदि राज्यों को सम्मिलित किया जाता है।

सारणी 10.3 भारत में लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष / स्त्रियाँ)

क्र. सं.	राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों के नाम	लिंगानुपात		
		1901	**2001**	**2011**
1.	केरल	1004	1058	1048
2.	पांडिचेरी	––	1001	1038
3.	छत्तीसगढ़	––	989	991
4.	तमिलनाडु	1044	987	995
5.	मणिपुर	1037	974	987
6.	मेघालय	1036	972	986
7.	ओडिसा	1037	972	978

8.	हिमाचल प्रदेश	884	968	974
9.	कर्नाटक	983	965	968
10.	उत्तराखण्ड	––	962	963
11.	गोवा	1085	961	968
12.	त्रिपुरा	874	948	961
13.	लक्ष्यद्वीप	1063	948	946
14.	झारखण्ड	––	941	947
15.	मिजोरम	1113	935	975
16.	पश्चिम बंगाल	945	935	947
17.	असम	919	935	954
18.	राजस्थान	905	921	926
19.	महाराष्ट्र	978	922	925
20.	बिहार	1054	919	916
21.	गुजरात	954	920	918
22.	मध्य प्रदेश	990	919	930
23.	नागालैण्ड	937	900	931
24.	अरुणाचल प्रदेश	––	893	920
25.	जम्मू एवं कश्मीर	882	892	883
26.	उत्तर प्रदेश	937	898	908
27.	आंध्रा प्रदेश	945	878	992
28.	पंजाब	832	876	893
29.	सिक्किम	916	875	889
30.	हरियाणा	867	861	877
31.	अण्डमान एवं निकोबार	318	846	878
32.	दिल्ली	862	821	866
33.	दादरा एवं नगर हवेली	960	812	775
34.	चंडीगढ़	771	777	718
35.	दमन एवं दीव	1085	710	618

स्त्रोतः जनगणना विभाग, लखनऊ.

निम्न लिंगानुपात उन राज्यों में पाया जाता है जहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 900 से कम महिलाएँ पायी जाती है। ऐसे राज्यों में जम्मू और कश्मीर, पंजाब, सिक्किम, हरियाणा, अण्डमान एवं निकोबार, दिल्ली, दादर एवं नगर हवेली, चंडीगढ़ आदि सम्मिलित है।

भारत में लिंगानुपात के वितरण को निम्नलिखित मानचित्र के द्वारा दर्शाया गया है –

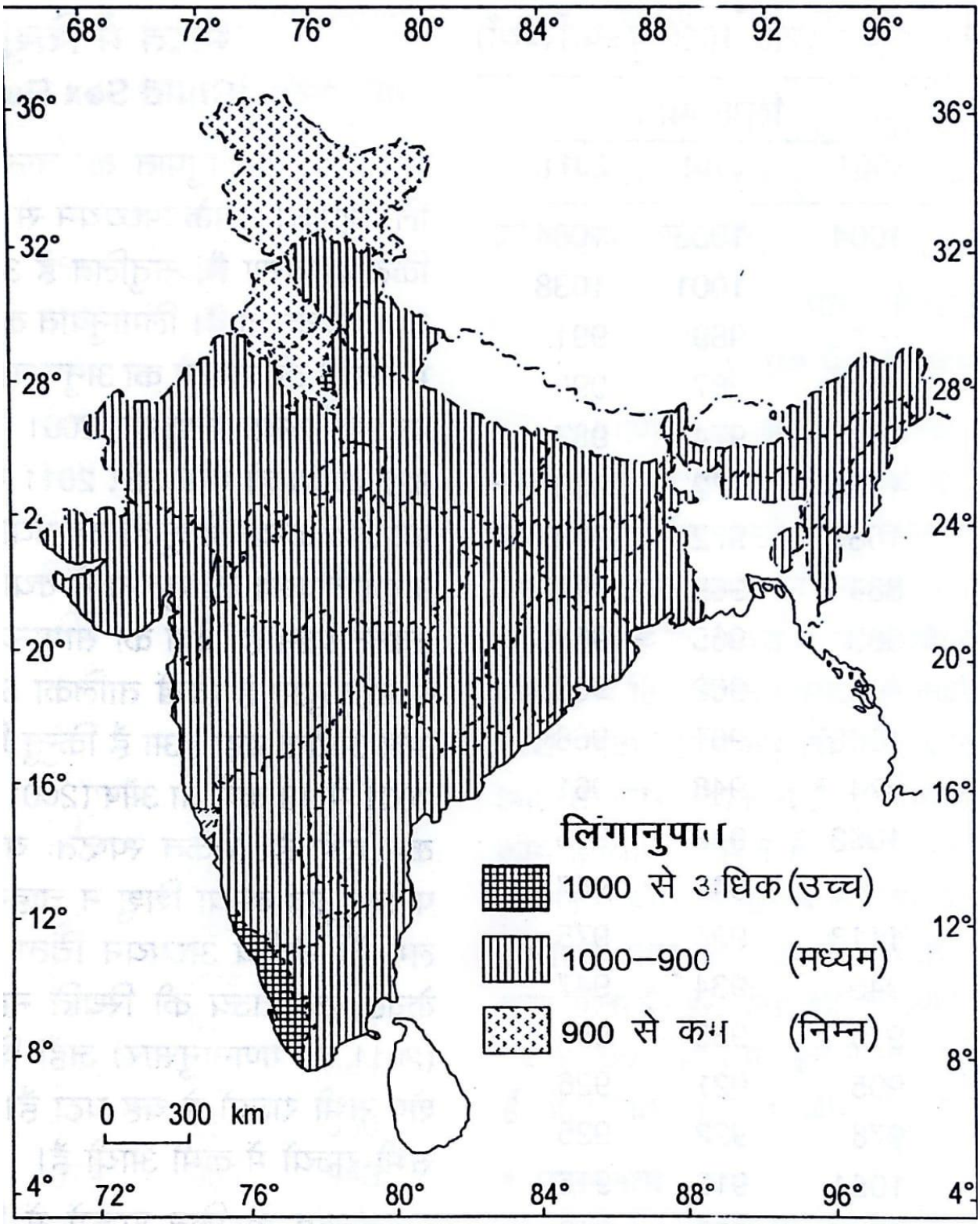

चित्र 10.1 भारत में लिंगानुपात का वितरण.

10.7.1 भारत में शिशु लिंगानुपात का वितरण

शिशु लिंगानुपात का अर्थ होता है 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के मध्य पाया जाने वाला अनुपात। इसके द्वारा समाज में बच्चों की स्थिति, उनका स्वस्थ्य, संतुलित पोषण, भ्रूण लिंग की स्थिति, उनके जन्म एवं मृत्यु दर का पता लगाया जाता है। शिशु लिंगानुपात में भी सामान्य लिंगानुपात के भाति ही समय के साथ परिवर्तन देखा जाता है। वर्ष 1991 ई. में प्रति 1000 पुरुष शिशु पर 945 कन्याएँ थी। उसके पश्चात उसमें तीव्रता से गिरावट आयी है जो वर्ष 2001 ई. एवं 2011 ई. में क्रमशः 927 एवं 914 दर्ज की गई थी। इस प्रकार देखा जाता है कि वर्ष 2001 ई. एवं 2011 ई. के मध्य 13 अंक की कमी आयी है। आकड़ों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि देश में 6 राज्यों में ही शिशु लिंगानुपात में वृद्धि हुई है जबकि अन्य सभी राज्यों में कमी आयी है। इसके कारणों की व्याख्या करने पर स्पष्ट होता है कि लोगों द्वारा कन्या शिशु के प्रति अरुचि तथा सीमित परिवार की मानसिकता कम शिशु लिंगानुपात के लिए जिम्मेदार है।

भारत के जिन राज्यों में शिशु लिंगानुपात में कमी आयी है उनमें जम्मू एवं कश्मीर, लक्ष्यद्वीप, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, झारखण्ड, मणिपुर, मध्य प्रदेश एवं नागालैण्ड सम्मिलित है। इसी प्रकार देश में सात ऐसे भी राज्य है भी हैं जहाँ के शिशु लिंगानुपात वृद्धि दर्ज की गई है। ये राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, मिजोरम, गुजरात, तमिलनाडु एवं अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह।

सारणी 10.4 भारत में शिशु लिंगानुपात (0 – 6 आयु वर्ग)

क्र. सं.	राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों के नाम	शिशु (0 – 6 आयु वर्ग) लिंगानुपात		
		1901	2001	2011
1.	जम्मू और कश्मीर	––	9411	859
2.	हिमाचल प्रदेश	951	896	906
3.	पंजाब	875	798	846
4.	चंडीगढ़	899	845	867
5.	उत्तराखण्ड	949	908	886
6.	हरियाणा	879	819	830
7.	दिल्ली	915	868	866
8.	राजस्थान	916	909	883
9.	उत्तर प्रदेश	927	916	899
10.	बिहार	960	942	933
11.	सिक्किम	965	963	944
12.	अरुणाचल प्रदेश	982	968	960
13.	नागालैण्ड	993	964	944
14.	मणिपुर	974	957	934

15.	मिजोरम	969	964	971
16.	त्रिपुरा	967	966	953
17.	मेघालय	986	973	970
18.	असम	975	965	957
19.	पश्चिम बंगाल	967	960	950
20.	झारखण्ड	979	965	943
21.	ओडिसा	967	953	934
22.	छत्तीसगढ़	984	975	964
23.	मध्य प्रदेश	941	935	912
24.	गुजरात	928	883	886
25.	दमन और दीव	958	926	909
26.	दादर एवं नगर हवेली	1013	979	924
27.	महाराष्ट्र	946	913	883
28.	आंध्र प्रदेश	975	961	943
29.	कर्नाटक	960	946	943
30.	गोवा	964	938	920
31.	लक्ष्यद्वीप	941	959	908
32.	केरल	958	960	959
33.	तमिलनाडु	948	942	946
34.	पांडिचेरी	963	967	965
35.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	973	957	966

स्त्रोतः जनगणना विभाग, लखनऊ.

लगातार शिशु लिंगानुपात में गिरावट आने से देश के सम्मुख निम्नलिखित समस्याएँ उत्पन्न हो सकती है –

1. देश में कन्याओं की संख्या में निरंतर कमी होने से विवाह जैसे संस्कार का फैसला कन्या पक्ष द्वारा लिया जाएगा कहाँ और कैसे विवाह करना है।
2. अंतर्जातीय, अंतरवर्णीय, अंतरक्षेत्रीय विवाहों आदि का प्रचलन बढ़ेगा।

10.6 सारांश

आपने इस इकाई में लिंगानुपात के प्रकार एवं लिंगानुपात के परिकलन की विधियों का अध्ययन किया है। आप समझ गए होगें कि लिंगानुपात किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में स्त्री एवं पुरुष का अनुपात होता है, जिसका घनिष्ट संबंध वहाँ के विकास की अवस्था से होता है। जिन देशों में लिंगानुपात संतुलित पाया जाता है वहाँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक समग्र रूप से देखा जाता है इसके विपरीत जिन देशों में लिंगानुपात असंतुलित होता है, जुआ, शराब, हत्या, बलात्कार जैसी समस्याएँ अधिक पाई जाती है जो एक स्वास्थ्य एवं समृद्ध समाज का परिचायक नहीं होता है। वास्तव में किसी देश की जनसंख्या तथा वहाँ का सबसे बड़ा संसाधन होती है जो उसकी भौगोलिक अवस्थिति, सरकारी नीतियों, सांस्कृतिक संगठन आदि के आधार पर होता है, जिसमें लिंगानुपात की भिन्नता इनकी प्रभाविता से जुड़ी हुई है। विश्व के सभी देशों में लिंगानुपात एक समान नहीं पाया जाता है। कहीं पर अधिक तो कहीं पर कम। लिंगानुपात के परिकलन की विधियाँ भी सभी देशों में एक समान नहीं होती है। कहीं पर इसे पुरुषों के संदर्भ में स्त्रियों की संख्या तो कहीं पर स्त्रियों के संदर्भ में पुरुषों की संख्या से मापी जाती है। उसी प्रकार कहीं पर इसकी गणना प्रति हजार पर की जाती है तो कहीं पर प्रति सौ पर। इस प्रकार लिंगानुपात का वैश्विक स्वरूप बहुत विविधता पूर्ण है।

10.7 स्वमूल्यांकन प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

1. किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में स्त्री एवं पुरुष के अनुपात को कहते है।

   (क) लिंगानुपात (ख) घनत्व (ग) वितरण (घ) सान्द्रण

2. लिंगानुपात की विस्तृत व्याख्या करने वाली पुस्तक मानव आनुवंशिकता के सिद्धान्त किसके द्वारा लिखी गई है।

   (क) चार्ल्स डार्विन (ख) कर्ट स्टर्न (ग) अरस्तू (घ) हटिंगटन

3. द्वितीयक लिंगानुपात क्या होता है।

   (क) गर्भधारण के समय प्राप्त होने वाला लिंगानुपात।

   (ख) जन्म के समय प्राप्त होने वाला लिंगानुपात।

   (ग) जनगणना के समय प्राप्त होने वाला लिंगानुपात।

   (घ) मृत्यु के समय प्राप्त होने वाला लिंगानुपात।

4. भारत में लिंगानुपात की गणना कैसे की जाती है।

   (क) प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या।

   (ख) प्रति सौ पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या।

   (ग) प्रति हजार स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या।

   (घ) प्रति सौ स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या।

5. वर्ष 2011 ई. की जनगणना के अनुसार विश्व में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है।

   (क) 1012 (ख) 894 (ग) 984 (घ) 1002

10.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

Bogue] D- J-] 1969] Principles of Demography] John Wiley] N-Y-

Clarke] John I-] 1973] Population Geography] Pergaman Press] Oxford-

Crook] Nigel] 1997] Principles of Population and Development] Pergaman Press] N- Y-

Garmier] J- B-] 1970] Geography of Population] Longman] London-

Mamoria] C- B-] 1981] India's Population Problem] Kitab Mahal] New Delhi-

Premi] M- K-] 1991] India's Population] Heading Towards a Billion] B- R- Publishing Corporation-

Blassoff] M- and Srinivasan K-] 2001] Population Development Nexus in India : Challenges for the New Millennium] Tata McGraw Hill] New Delhi-

Woods] R-] 1979] Population Analysis in Geography] Longman] London-

Zelinsky] W-] 1966] A Prologue to Population Geography] Prentice Hall-

चन्दना, आर. सी., 2022, जनसंख्या भूगोल – संकल्पना, नियंत्रक व विश्व प्रारूप, कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

चन्दना, आर. सी., 2022, भारत : जनसंख्या (जनसंख्या भूगोल – भाग 2), कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

मौर्या, एस. डी., 2005, जनसंख्या भूगोल, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद.

ओझा, आर. पी., 1984, जनसंख्या भूगोल, प्रतिभा प्रकाशन.

हीरा लाल, 2000, जनसंख्या भूगोल के मूल तत्व, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली.

तिवारी, राम कुमार, 2023, जनसंख्या भूगोल, प्रवालिका पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद.

10.9 अभ्यास प्रश्न (सत्रांत परीक्षा की तैयारी)

1. लिंगानुपात के अर्थ को स्पष्ट कीजिए?
2. लिंगानुपात के प्रकारों की व्याख्या कीजिए?
3. लिंगानुपात के परिकलन की विधियों का वर्णन कीजिए?
4. लिंगानुपात के वैश्विक वितरण का विश्लेषण कीजिए?

इकाई–11 साक्षरता का अर्थ, साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारण

इकाई की रूपरेखा

11.0 प्रस्तावना

11.1 उद्देश्य

11.2 साक्षरता का अर्थ एवं संकल्पना

11.3 भारत में साक्षरता की प्रगति

11.4 साक्षरता मापन की विधि

11.5 साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारण

11.6 जनांकिकीय कारण

11.7 सामाजिक कारण

11.8 राजनीतिक कारण

11.9 आर्थिक कारण

11.10 सारांश

11.11 स्वमूल्यांकन प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

11.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

11.13 अभ्यास प्रश्न (सत्रांत परीक्षा की तैयारी)

11.0 प्रस्तावना

साक्षरता के आधार पर संपूर्ण मानव संस्कृति को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रथम पढ़ने लिखने की कला के विकसित होने के पूर्व की सांस्कृतिक अवस्था। दूसरी पढ़ने एवं लिखने की कला सीखने के पश्चात की अवस्था। प्रसिद्ध विद्वान गोल्डन (1968) लिखते हैं कि साक्षरता पूर्व अवस्था से साक्षरता अवस्था में परिवर्तन आज से लगभग 4000 वर्ष पहले शुरू हुआ। यह अवस्था चित्रकारी विधा से शुरू होकर धीरे – धीरे वर्तमान वर्ण विधा तक पहुंची है। लिखने की कला के विकास के साथ ही सांस्कृतिक प्रगति में साक्षरता का महत्व बढ़ा है। इसी संकल्पना को संदर्भित करते हुए चांदना लिखते हैं कि जनसंख्या भूगोल में साक्षरता सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति का सबसे विश्वसनीय सूचक माना जाता है। साक्षरता का महत्व गरीबी उन्मूलन, मानसिक एकाकीपन की समाप्ति, शांतिपूर्वक वैश्विक बंधुत्व वाले अंतरराष्ट्रीय संबंधों को विकसित करने एवं व्यक्तियों को अपने विचारों को मौलिक रूप में अभिव्यक्त करने में अधिक है।

11.1 उद्देश्य

साक्षरता ही मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करती है। शिक्षा के ही बल पर व्यक्ति आदि मानव से वर्तमान के प्रौद्योगिकी मानव में परिवर्तित हुआ है, इस प्रकार अब शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है। इस इकाई के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है –

1. साक्षरता के अर्थ को समझना।
2. साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारणों की व्याख्या करना।

11.2 साक्षरता का अर्थ एवं संकल्पना

साक्षरता एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्पना है, जिसका तात्पर्य न्यूनतम साक्षरता निपुणता से है। इसका स्तर एक देश से दूसरे देश में भिन्न होता है। निम्नतम साक्षरता स्तर की भिन्नता मौलिक रूप से विचारों के विनिमय से लेकर अनेकों कठिन संकल्पनाओं एवं परिकल्पनाओं तक माना जा सकता है। कुछ विद्वानों द्वारा पाठशाला शिक्षा की अवधि के आधार पर साक्षरता एवं असाक्षरता का निर्धारण किया जाता है। जनसंख्या भूगोल के जनक ट्रिवार्था का मानना है कि विद्यालय शिक्षा की अवधि के आधार पर साक्षरता का निर्धारण नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही उनका यह भी मानना है कि किसी देश में प्रचलित भाषा में पढ़ने एवं नाम लिखने की दक्षता के आधार पर साक्षरता का निर्धारण नहीं हो सकता है। फिनलैंड ने साक्षरता के निर्धारण हेतु वर्ष 1930 ई. में सबसे कठिन मानक को तैयार किया उसके अनुसार केवल उन लोगों को साक्षर माना जा सकता है, जो कठिन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जो लोग इसमें असफल हैं उनके लिए दो श्रेणियां निर्धारित की है –

पहला– अर्द्ध शिक्षित – ऐसे लोग जो पढ़ लिख तो सकते हैं परंतु गणितीय गलतियां करते हैं।

दूसरा– अशिक्षित – ऐसे लोग जो न तो पढ़ सकते हैं और न ही लिख सकते हैं।

वर्ष 1961 ई. में हांगकांग की जनगणना में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो यह कहता है कि वह एक भाषा पढ़ सकता है तथा उसके बारे में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह लिख भी सकता है तो उसे साक्षर माना जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या आयोग के अनुसार किसी भी भाषा में साधारण संदेश को समझ के साथ पढ़ने एवं लिखने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को साक्षर माना जा सकता है। धीरे – धीरे विश्व के अनेकों देशों द्वारा साक्षरता की इस परिभाषा को स्वीकार किया गया है। भारतीय जनगणना ने भी इसे कुछ संशोधनों के साथ अपनाया है।

वैश्विक स्तर पर साक्षरता के स्वरूप की तुलना में अनेकों समस्याएं आती हैं। कुछ ऐसे भी देश हैं जिनमें जनगणना तो नियमित ढंग से की जाती है परंतु साक्षरता संबंधित आंकड़ों का संग्रह ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। वर्तमान समय में शिक्षा एवं साक्षरता के बढ़ते महत्व के कारण ऐसे देश की संख्या दिन – प्रतिदिन कम होती जा रही है। प्रत्येक देश द्वारा भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा एवं साक्षरता के मानक अलग – अलग निश्चित किए हैं। ऐसी स्थिति में वैश्विक स्तर पर साक्षरता की समीक्षा प्रस्तुत करना कठिन होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसके लिए एक मानक आधार एवं परिभाषा देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता की तुलनात्मक व्याख्या की जा सके।

साक्षरता संबंधित आंकड़ों की एक प्रमुख समस्या विविध सारणी पद्धति भी है। कुछ देशों में साक्षरता संबंधित आंकड़ों में पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों को समाहित किया जाता है, तो कुछ देशों में इन्हें अलग रखा जाता है और उन्हें असाक्षर माना जाता है। कुछ राष्ट्रों का मानना है कि पाँच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ही किसी व्यक्ति में पूर्ण निपुणता के साथ साक्षरता का विकास हो सकता है। ऐसी स्थिति में इन देशों द्वारा साक्षरता का विकास हो सकता है। ऐसी स्थिति में इन देशों द्वारा दस वर्ष की आयु वाले बच्चों को भी साक्षर नहीं माना जाता है।

संयुक्त राष्ट्र एवं यूनेस्को ने संयुक्त रूप से साक्षरता के संकल्पना के विकास, प्रसार एवं उपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन प्रयासों का अनेक राष्ट्रों ने समर्थन भी किया है। यूनेस्को ने वर्ष 1957 ई. में 60 देश में सर्वेक्षण करके पढ़ने – लिखने की क्षमता के आधार पर साक्षरता निर्धारण को मौलिक स्वरूप प्रदान किया। वर्ष 1978 ई. में संयुक्त राष्ट्र संघ में यह विचार पारित हुआ कि कार्य क्षमता के आधार पर साक्षरता की संकल्पना की व्याख्या की जा सकती है। अतः इस बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार वह व्यक्ति साक्षर होगा जिसमें वह सभी कार्य करने की क्षमता हो जिसके लिए साक्षरता आवश्यक हो। साक्षरता की संकल्पना में पढ़ना, लिखना गणित के प्रश्नों की समझ, सामाजिक कार्यों की कुशलता आदि अभिन्न अंग हैं। सभ्य समाज द्वारा साक्षरता को सामाजिक संवेदनशीलता, सामाजिक एवं आर्थिक जागरूकता, सामान्य विवेचनात्मकता सामाजिक विकास आदि सभी सुदृढ़ माध्यम माना गया है।

शिक्षा प्राप्ति एवं साक्षरता से एक व्यक्ति एवं समाज को अनेक मानवीय, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। शिक्षा का सबसे अधिक प्रभाव उसकी मानवीय स्वभाव पर पड़ता है। एक शिक्षित व्यक्ति आत्म सम्मान, स्वाभिमान, आत्म सशक्तिकरण, आत्म विश्वास आदि समाज आदि सकारात्मक रूप से परिपूर्ण होता है। इससे उसमें स्वयं पर संपूर्ण विश्वास होता है। उसके द्वारा अपने निर्णय लेना सुगम होते हैं तथा कोई भी ऐसे व्यक्तियों को धोखा नहीं दे सकता है। शिक्षा प्राप्ति के उपरांत एक व्यक्ति सामाजिक मूल्यों से परिपूर्ण हो जाता है तथा उसके जीवन में सकारात्मक सुधार अधिक देखे जाते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से भी साक्षरता बहुत उपयोगी है पुरुषों के साथ ही महिलाओं में इसका प्रभाव ज्यादा देखा जाता है। आर. सी. चांदना लिखते हैं कि एक शिक्षित नारी को स्वयं एवं अपने परिवार के स्वास्थ्य का अधिक ध्यान होता है तथा परिवार नियोजन के लाभ के बारे में वह अधिक जागरूक होती है। परिवार नियोजन को लेकर भारत में किए गए अनेकों शोधों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के सफल संपादन हेतु स्त्रियों में कम से कम 10 वर्ष की शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण पर ध्यान रखने वाले व्यक्तियों का मानना है कि किसी भी क्षेत्र में सतत आर्थिक विकास में शिक्षा की सहभागिता 40% के बराबर होती है। विभिन्न क्षेत्रों की सामान्य आय तथा आर्थिक विकास के साथ शिक्षा का सकारात्मक सहसंबंध पाया जाता है।

11.3 भारत में साक्षरता की प्रगति

भारत प्राचीन काल से ही सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक चिंतन का केंद्र स्थल रहा है। समय – समय पर अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए हैं, जिनमें शिक्षा एवं साक्षरता की अधिक भूमिका रही है। एक साक्षर एवं शिक्षित व्यक्ति ही सशक्त समाज का निर्माण कर सकता है। ऐसी स्थिति में साक्षरता निर्धारण एवं उसके मानक स्तर को लेकर समय – समय पर अनेकों निर्णय लिए गए हैं। इसके लिए संवैधानिक प्रावधान भी किए गए हैं ताकि संपूर्ण देशवासियों तक शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकता का प्रसार आसानी से किया जा सके। इसके लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं –

- भारतीय जनगणना में वर्ष 1901 ई. से लेकर वर्ष 1931 ई. तक केवल दो भागों में विभक्त किया गया है पहला साक्षर एवं दूसरा निरक्षर। साक्षर की परिभाषा में मात्र यह लिखा गया है जो व्यक्ति पढ़ एवं लिख लेते हैं वह साक्षर हैं।

- वर्ष 1961 की जनगणना में बताया गया है कि जो व्यक्ति सामान्य पत्र पढ़ एवं लिख सकता है वह साक्षर है। वह व्यक्ति जो किसी भी भाषा में न तो पढ़ सकता है और न ही लिख पाता है वह असाक्षर है।

- वर्ष 1971 ई. की जनगणना में कुछ परिवर्तन के साथ निम्नलिखित परिभाषा दी गई है वह व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ सकता है उसे लिख एवं पढ़ सकता है उसे साक्षर माना जाता है। वह व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता उसे साक्षर नहीं माना जाएगा।

- वर्ष 1981 ई. की जनगणना में साक्षरता की परिभाषा को कुछ और विस्तृत किया गया और उसमें बताया गया कि वह व्यक्ति जो किसी भाषा को लिख पढ़ सकता है और समझ सकता है साक्षर कहा जाएगा। वह व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है एवं लिख नहीं सकता साक्षर नहीं होगा।

- इस जनगणना में इस बात को भी माना गया कि साक्षर होने के लिए यह आवश्यक नहीं है, कि संबंधित व्यक्ति ने कोई परीक्षा पास की है या किसी प्रकार की औपचारिक शिक्षा ग्रहण की है।

- वर्ष 1991 ई. की जनगणना में साक्षरता को परिभाषित करने के लिए 1981 ई. की जनगणना की बात को स्वीकार किया गया। इसको अधिक सार्थक रूप प्रदान करने हेतु 6 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या को निरक्षर माना गया तथा उसे कुल जनसंख्या से अलग करके साक्षरता की गणना की गई।

इस प्रकार पहली बार आयु सीमा को आधार मानते हुए साक्षरता की गणना की गई। इस गणना में 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया गया।

- वर्ष 2001 ई. की जनगणना में भी 1991 ई. की परिभाषा एवं मानक को स्वीकार किया गया । इस वर्ष भी इसमें थोड़ा विस्तार दिया गया तथा ब्रेल लिपि पढ़ लेने वाले नेत्रहीन व्यक्तियों को भी साक्षर की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया गया ।

- भारतीय संविधान में शिक्षा के प्रसार हेतु अनेक प्रावधान किए गए हैं। जहाँ प्राथमिक शिक्षा को जहाँ मौलिक अधिकार बनाया गया है वहीं नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शिक्षा को जनता के लिए अनिवार्य बताते हुए सरकारों को इसके संपूर्ण प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है।
- भारतीय संविधान के उद्देश्यों को मौलिक स्वरूप प्रदान करने तथा लोगों को साक्षर बनाने हेतु 1988 ई. में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई।
- शिक्षा के सार्वभौम प्रसार को दृष्टिगत करते हुए देश में वर्ष 2001 ई. में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई।

उपरोक्त प्रसंग को दृष्टिगत करते हुए भारतीय जनगणना विभाग द्वारा साक्षरता को निम्नलिखित रूप में स्वीकार किया गया है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग का जो व्यक्ति किसी भी भाषा को समझ सकता है लिख पढ़ सकता है, उसे साक्षर कहा जाता है। ऐसे नेत्रहीन व्यक्ति जो ब्रेल लिपि पढ़ सकते हैं उन्हें भी साक्षर माना गया है। साक्षर होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि व्यक्ति ने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त की है अथवा न्यूनतम परीक्षा पास की हो।

11.4 साक्षरता मापन की विधि

साक्षरता व्यक्ति के लिए आवश्यक मूलभूत अवधारणा है जिसके मापन हेतु अनेकों विधियों और सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। शिवदास मौर्य अपनी पुस्तक जनसंख्या भूगोल में लिखते है कि विश्व के सभी देशों द्वारा इसके मापन हेतु किसी न किसी विधि या सूचकांक का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है किन्तु साक्षरता के परिभाषा और उसके लिए प्रयोग होने वाले आकड़ों के संग्रह की तकनिकियों में अंतर होने के कारण सूचकांकों में भी भिन्नता पाई जाती है। वैश्विक स्तर पर इनका तुलनात्मक अध्ययन करना कठिन हो जाता है। इसके साथ ही यह भी देखा जाता है कि जनगणना में भी अनियमितता पायी जाती है। इस प्रकार जनगणना अंतराल में असमानता होने के कारण उनका तुलनात्मक अध्ययन भी कम ही हो पता है। प्रायः यही देखा जाता है कि विश्व के सभी देशों में जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पर ही सम्पन्न होती है परन्तु कुछ देशों में इसमें भी भिन्नता पाई जाती है। इन सभी समस्याओं एवं बाधाओं को एक साथ संदर्भित करते हुए साक्षरता के मापन हेतु विद्वानों द्वारा निम्नलिखित दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। इन विधियों का प्रयोग सामान्यतः विश्व के सभी देशों द्वारा कुछ अपवादों को छोड़ कर किया जाता है –

अ. अशोधित साक्षरता दर

ब. आयु विशिष्ट साक्षरता दर

अ. अशोधित साक्षरता दर : किसी प्रदेश, क्षेत्र अथवा देश की संपूर्ण जनसंख्या की तुलना में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत संख्या ज्ञात कर लेना ही अशोधित साक्षरता दर या सामान्य साक्षरता दर कहलाती है। इसे ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है –

अशोधित साक्षरता दर = कुल साक्षर संख्या * 100 / कुल जनसंख्या

नोट : * से तात्पर्य गुणा से है.

ब. आयु विशिष्ट साक्षरता दर

आयु विशिष्ट साक्षरता दर = 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की कुल साक्षर जनसंख्या * 100 / 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की कुल जनसंख्या

नोट : * से तात्पर्य गुणा से है.

इस प्रकार की साक्षरता की गणना करने के लिए एक निश्चित आयु वर्ग की जनगणना की तुलना में कुल साक्षर व्यक्तियों की गणना की जाती है। यह गणना इस आयु वर्ग के अनुपात में की जाती है। इससे इस बात का बोध होता है कि किस आयु वर्ग में कितनी जनसंख्या साक्षर है।

11.5 साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारण

पृथ्वी के धरातल पर जनसंख्या की अन्य तत्वों के समान ही साक्षरता के वैश्विक वितरण में भी असमानता पाई जाती है। यदि इसके अध्ययन हेतु संपूर्ण पृथ्वी को अनेक भौगोलिक इकाइयों जैसे देश, प्रदेश, प्रखण्ड आदि भागों में भी विभक्त करके देखें तो सर्वत्र असमानता दिखाई देती है। इस असमानता हेतु एक ही कारण हर जगह पर जिम्मेदार नहीं होते। इसके लिए उन स्थानों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थिति उत्तरदाई होती हैं। सामान्य अवलोकन में यह पाया गया है कि जिन देश या समाज की आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियां काफी विकसित होती हैं वहाँ साक्षरता का वितरण समान है जबकि अल्प विकसित अथवा विकासशील देशों एवं समाज में साक्षरता का असामान वितरण पाया जाता है। ऐसी स्थिति में सामुदायिक वितरण में भी पाई जाती है जो समुदाय आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अधिक सशक्त हैं। उनमें शिक्षा का प्रसार अधिकांश पाया जाता है जबकि इन कारणों से वंचित समुदायों में साक्षरता का स्तर एकदम न्यून पाया जाता है। वैश्विक स्तर पर साक्षरता के वितरण में असमानता हेतु जिम्मेदार कारकों को निम्न अध्ययन निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है –

सारणी : 11.1 साक्षरता के वितरण में असमानता हेतु जिम्मेदार कारक

क्र. सं.	कारण	कारण के उपप्रकार
1.	जनांकिकीय कारण	1. जनांकिकीय संक्रमण
		2. नगरीकरण
2.	सामाजिक कारण	1. शिक्षा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण
		2. समाज में स्त्रियों की दशा
		3. धार्मिक विश्वास
		4. शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता
		5. शिक्षा का माध्यम
3.	राजनीतिक कारण	1. सरकारी नीति
4.	आर्थिक कारण	1. अर्थव्यवस्था का प्रकार
		2. जीवन स्तर
		3. यातायात तथा संचार के साधन
		4. तकनीकी विकास स्तर
		5. शिक्षा में लागत

स्त्रोतः जनसंख्या भूगोल, राम कुमार तिवारी.

11.6 जनांकिकीय कारण

जनांकिकीय कारणों के अंतर्गत उन सभी कारणों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या की विशेषताओं से संबन्धित होते है। किसी भी स्थान पर पायी जाने वाली वर्तमान जनसंख्या एक निश्चित

विकास का प्रतिफल होती है। यह विकास कई अवस्थाओं में सम्पन्न होता है। जब मानव सभ्यता विकास की प्रारम्भिक अवस्था में होती है तब मानव जीवन में कोई स्थायित्व नहीं पाया जाता है। वह यायावर का जीवन व्यतीत करता है ऐसी स्थिति में उसके लिए शिक्षा कोई विशेष आवश्यकता नहीं रह जाती है। बाद के समयों में जैसे – जैसे उसके जीवन मे स्थायित्व आने लगता है वह बस्तियों का विकास करके जब स्थायी रूप से रहने लगता है। तब वह अनेकों विकासात्मक अवदानों को विकसित करता है जिसमें से शिक्षा भी एक है। कालांतर में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ समाज ग्रामीण स्वरूप से नगरीय समाज में परिवर्तित हो जाता है जिससे साक्षरता के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। साक्षरता को प्रभावित करने वाले प्रमुख जनांकिकीय कारण निम्नलिखित है –

11.6.1 जनांकिकीय संक्रमण

जनांकिकीय संक्रमण जनसंख्या के विकास की अवस्था होती है। इसका साक्षरता से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं पाया जाता है, परंतु परोक्ष रूप से यह प्रभावित करती है। जब कोई देश जनसंख्या संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में होता है, तब वहाँ साक्षरता की दर निम्न पाई जाती है और अर्थव्यवस्था अल्प विकास की अवस्था में होती है। ऐसे देशों में अशिक्षा के कारण जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों उच्च स्तर पर पाया जाता है। ऐसी स्थिति में लोगों का ध्यान शिक्षा से हटकर बीमारियों एवं परिवार के पालन पोषण में लगा रहता है। द्वितीय एवं तृतीय अवस्था वाली अर्थव्यवस्थाएँ मुख्यतः विकासशील देशों की होती हैं। इन देशों में बच्चों की संख्या अधिक पाई जाती है जिसके कारण उनके शिक्षा का संपूर्ण प्रबंधन नहीं हो पाता और साक्षरता दर कम पाई जाती है। जनांकिकीय संक्रमण की चतुर्थ एवं पंचम अवस्था वाली स्थिति विकसित देशों में पाई जाती है। इन देशों का सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्तर उच्च होता है। उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थाओं की उपलब्धता के कारण इन देशों तथा समाजों में साक्षरता दर उच्च पाई जाती है।

11.6.2 नगरीकरण

साक्षर एवं शिक्षित व्यक्तियों का सर्वाधिक संकेंद्रण नगरीय क्षेत्रों में देखा जाता है। वहाँ की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियां साक्षरता के उच्च स्तर हेतु जिम्मेदार होती हैं। नगरीय क्षेत्र द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक एवं पंचम क्रियाकलापों के केंद्र होते हैं। इन कार्यों के संचालन हेतु अधिक कुशल एवं शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। आधुनिक शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े संस्थान भी यही स्थिति होते हैं, यही कारण है कि यहाँ निवास करने वाली जनसंख्या में साक्षरता की दर उच्च होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक क्रियाकलापों से जुड़ी अर्थव्यवस्था के साथ गरीबी के अनेकों कारक मौजूद होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण संस्थाओं का समुचित विकास नहीं होता जहाँ नगरीय क्षेत्रों में घर के निकट विद्यालय उपलब्ध होते हैं वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इनका वितरण दूर – दूर पाया जाता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नगरी क्षेत्र की अपेक्षा साक्षरता दर निम्न पाई जाती है। जैसे वर्ष 2001 की जनगणना में नगरीय क्षेत्रमें साक्षरता दर 71% पाई गई तो ग्रामीण क्षेत्रों में यह 44.54% दर्ज की गई है।

11.7 सामाजिक कारण

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वंय नहीं कर सकता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ताने – बने का निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है वही कालांतर में समाज में परिवर्तित होता है। इसलिए कहा जाता समाज सम्बन्धों का जाल है। एक समाज मूल्यों और आदर्शों का संयोजन होता है जिसके सभी कार्यों का संचालन कुछ सामान्य नियमों के अनुसार होता है। इन्हीं का प्रभाव वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ता है। जैसे – जैसे समाज विकास एवं आधुनिकता की ओर अग्रसर होता जाता उसमें शिक्षा का विकास तीव्र गति से होने लगता है। साक्षरता को प्रभावित करने वाले प्रमुख सामाजिक कारण निम्नलिखित है –

11.7.1 शिक्षा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण

भारत जैसे बहु सांस्कृतिक एवं सामाजिक विविधता वाले देश में बहुत ज्यादा विभिन्नता देखने को मिलती है। प्रत्येक समाज की अपनी अलग – अलग विचारधारा, मान्यताएं, विश्वास एवं परंपराएं पाई जाती हैं। इनमें से कुछ के द्वारा समाज में रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों का विकास हुआ है। उदाहरणस्वरूप लड़कियां पराए घर चली जाएगी अतः उन्हें शिक्षा की जरूरत नहीं है। कुछ परिवार बच्चों की शिक्षा को आर्थिक बोझ समझते हैं उन्हें पढ़ाने के बजाय किसी धनार्जन वाले कार्यों में लगाना ज्यादा उचित समझते हैं। ऐसे दृष्टिकोण वाले लोगों के यहाँ बच्चों की संख्या भी ज्यादा होती है परंतु उनमें साक्षरता का स्तर निम्न पाया जाता है।

11.7.2 समाज में स्त्रियों की दशा

वैश्विक तथा विभिन्न देशों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि जिन देशों या समाजों में महिलाओं की दशा उच्च स्तरीय है वहाँ साक्षरता का स्तर भी उच्च है। मुस्लिम जनसंख्या की बहुलता वाले देशों में स्त्रियों की दशा अत्यंत दयनीय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उन्हें बुर्के में रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए तथा सार्वजनिक स्थानों पर भी नहीं जाना चाहिए । ऐसी स्थितियां शिक्षा के प्रसार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि इन समाजों में साक्षरता दर निम्न पाई जाती है। आधुनिकता के प्रसार के कारण ऐसी भावना धीरे – धीरे कम हो रही है और इन देशों की महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक दशाओं में सुधार हो रहा है। उनकी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सहभागिता भी बढ़ रही है। इसके विपरीत पश्चिमी देशों में महिलाओं को पुरुषों के समान ही सभी अधिकार प्राप्त हैं। उनके साथ शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं किया जाता है। यही कारण है कि इन समाजों की साक्षरता दर उच्च दर्ज की जाती है। भारत में भी अधिकांश महिलाएं घरेलू कार्यों में संलग्न है तथा वे सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक अवहेलना का शिकार होती हैं। इसी कारण इनमें साक्षरता दर कम पाई जाती है। उदाहरणस्वरूप वर्ष 2001 की जनगणना में जहाँ पुरुष साक्षरता दर 75.9% है वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 54.02% प्राप्त होती है।

11.7.3 धार्मिक विश्वास

कुछ समाजों के धार्मिक विश्वास, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं मान्यताएं साक्षरता दर को प्रभावित करते हैं। जहाँ मुस्लिम समुदाय में धर्मानुसार नमाज पढ़ने की मौखिक व्यवस्था है तथा यहाँ साक्षर होना आवश्यक नहीं है, वहीं हिंदू एवं ईसाई समुदायों में धार्मिक ग्रंथों के पाठन हेतु शिक्षित होना आवश्यक है। यही कारण है कि मुस्लिम समाजों में साक्षरता की दर कम एवं हिंदू तथा ईसाई वर्ग में यह दर उच्च पाई जाती हैं। ईसाई समाज के लोगों द्वारा भी शिक्षा एवं साक्षरता के विकास पर अधिक जोर दिया जाता है। जिन समाजों में इस वर्ग के लोग अधिक संख्या में निवास करते है वहाँ साक्षरता की दर उच्च पाई जाती है। जहाँ पर इस वर्ग के लोग प्रवास करके जाते हैं वहाँ पहले की तुलना साक्षरता की दर उच्च हो जाती है। जैन एवं बौद्ध समुदायों में भी शिक्षा को महत्त्व दिया है इसलिए जिन जगहों पर इस वर्ग के लोगों का संकेन्द्रण अधिक पाया जाता है वहाँ भी साक्षरता की दर उच्च पाई जाती है। औपनिवेशिक काल में ईसाई धर्म के प्रसार के लिए भी औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा भी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था ।

11.7.4 शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता

शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता का सीधा संबंध साक्षरता दर पर पड़ता है। जिन गांवों के पास विद्यालय उपलब्ध होते हैं, वहाँ के बच्चों की पहुंच विद्यालय तक आसानी से हो जाती है। ऐसी स्थिति में यह पाया जाता है कि ऐसे गाँव जहाँ विद्यालय नहीं उपलब्ध हैं, की तुलना में विद्यालय की उपलब्धता वाले गाँव में साक्षरता दर अधिक पाई जाती है। इसी प्रकार जिन नगरों में कॉलेज की उपलब्धता अधिक होती है उनमें अन्य नगरों की तुलना में शिक्षण हेतु अन्य सुविधाएं अधिक मात्रा में उपलब्ध होती हैं। उनमें साक्षरता दर अधिक पाई जाती है। भारत की तरह अन्य विकासशील देशों में जहाँ गाँव में विद्यालयों की कमी है वहाँ निरक्षरों की संख्या अधिक पाई जाती है। ऐसी स्थिति में सरकारों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है सरकारें जनसंख्या के हिसाब से स्कूलों की संख्या सुनिश्चित करें अथवा निकट पड़ोसी दूरी के आधार पर दो या दो से अधिक गाँव हेतु विद्यालयों की स्थापना करें। ऐसा करने से ही साक्षरता का समुचित प्रसार हो सकता है।

11.7.5 शिक्षा का माध्यम

शिक्षा का माध्यम भी साक्षरता को प्रभावित करता है। यदि प्रारंभिक शिक्षा को मातृभाषा में उपलब्ध कराया जाए तो बच्चों की ग्राह्यता एवं आकर्षक अधिक होगा। अंग्रेजी माध्यम में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के अलग मानक हैं। यह शिक्षा समाज के संभ्रांत लोगों में अधिक देखी जाती है, दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा ही है। किसी एक भाषा के आधार पर संपूर्ण देश में शिक्षा नहीं दी जा सकती। उदाहरणस्वरूप भारत जैसे देश में हिंदी में पढ़ाई होनी चाहिए परंतु आजादी से अब तक मातृभाषा के आधार पर एकरूपता नहीं देखने को मिलती। यहाँ प्रत्येक राज्य की अपनी अलग – अलग भाषा है। कहीं बंगाली, कहीं गुजराती, कहीं तेलुगू तो कहीं तमिल और कन्नड़ भाषाओं में भी शिक्षाएं दी जा रही हैं। कुछ शिक्षण संस्थान ऐसे भी मिलते हैं जो स्थानीय भाषा के साथ ही हिंदी एवं अंग्रेजी में भी शिक्षण कार्य का संपादन करते हैं, परंतु इनकी

संख्या कम है। ऐसी स्थिति में माध्यम की भिन्नता के कारण अधिसंख्यक आबादी शिक्षा से दूर रह जाती है और साक्षरता दर निम्न दर्ज की जाती है।

11.8 राजनीतिक कारण

किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था होती है। इसके द्वारा ही वहाँ के नागरिकों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। किसी भी देश की सरकार किसी निश्चित मान्यता और सिद्धान्त पर कार्य करती है। इन्हीं मान्यताओं एवं सिद्धांतों से प्रेरित सरकार होकर द्वारा नीतिगत निर्णय लिए जाते है। उन्हीं निर्णयों में से एक होता है शिक्षा एवं शिक्षण संस्थानों का विकास । जिन क्षेत्रों में रूढ़िवादी मान्यता से प्रेरित सरकारें पाई जाती वहाँ शिक्षा जैसे मौलिक तत्व पर कम ध्यान दिया जाता है और साक्षरता दर निम्न दर्ज की जाती है। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में उदारवादी मान्यता से प्रेरित सरकारें कार्य करती है उनके द्वारा अपने नागरिकों के सम्पूर्ण विकास हेतु शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। साक्षरता को प्रभावित करने वाले प्रमुख राजनीतिक कारण निम्नलिखित है –

11.8.1 सरकारी नीति

शिक्षा एवं साक्षरता के विकास तथा प्रसार में सरकारी नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वैश्विक स्तर पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो पता चलता है कि अधिकांश देश औपनिवेशिकता के शिकार थे। ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शक्तियों ने उपनिवेशों में शिक्षा के विकास हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किया। यही कारण है कि अधिकांश देशों में साक्षरता का स्तर निम्न पाया जाता है। इसके विपरीत स्वतंत्र देशों में साक्षरता की दर उच्च पाई जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इनमें से अधिकांश देशों ने आजादी प्राप्त की है। इसके पश्चात इन देशों ने अपनी मातृभाषा के साथ अंग्रेजी में आधुनिक शिक्षा हेतु संपूर्ण प्रबंध किया है। इसका परिणाम यह हुआ कि इन देशों में साक्षरता का स्तर उठने लगा है। कुछ समुदाय नगरीय क्षेत्र से अति दूरस्थ स्थानों पर पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकारों ने अनिवार्य एवं निः शुल्क शिक्षा के साथ आवासीय विद्यालय के संचालन पर भी जोर दिया है ताकि साक्षरता दर को उच्च किया जा सके ।

11.9 आर्थिक कारण

वे सभी क्रियाएँ जिनसे वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है आर्थिक क्रियाएँ कहलाती है। इन क्रियाओं के विविध रूप पाए जाते है। प्राथमिक क्रियाकलापों की तुलना में द्वितीयक एवं तृतीयक से युक्त अर्थव्यवस्थाएँ आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक सम्पन्न होती है। इनका सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक विकास संतुलित रूप से होता है। ऐसी स्थिति में विकास के अन्य मानकों के साथ शिक्षा एवं उससे जुड़े अन्य क्रियाकलापों का अच्छी तरह से विकास होता है। इससे साक्षरता दर भी उच्च दर्ज की जाती है। साक्षरता को प्रभावित करने वाले प्रमुख आर्थिक कारण निम्नलिखित है –

11.9.1 अर्थव्यवस्था का प्रकार

देश की अर्थव्यवस्था एवं वहाँ की साक्षरता दर में सकारात्मक सहसंबंध पाया जाता है। विश्व के जिन भागों में विकसित देश एवं अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। वहाँ की साक्षरता दर उच्च दर्ज की गई है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोपीय देश, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि। यहाँ की विकसित अर्थव्यवस्था शिक्षा के प्रसार हेतु अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराती हैं। ऐसे देश जो विकासशील अवस्था में है वहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न होती है। प्रौद्योगिकी विकास का स्तर भी उच्च स्तरीय नहीं होता ऐसी स्थिति में देश की संपूर्ण भाग में शिक्षा का प्रसार समान रूप से नहीं होता और साक्षरता दर विकसित देशों से कम पाई जाती है। अल्प विकसित देशों में यह और निम्नतम स्तर पर पाई जाती है। औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में भी सभी प्रकार की शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होती हैं। वहाँ शिक्षण प्रशिक्षण की तकनीक एवं प्रौद्योगिकी की आसानी से उपलब्ध हो जाती है, ऐसी स्थिति में साक्षरता दर उच्च दर्ज की जाती है।

11.9.2 जीवन स्तर

किसी व्यक्ति की जीवन स्तर का निर्माण अनेक सामाजिक एवं आर्थिक तत्वों का संयोजन होता है। जिनमें आर्थिक आय, रहन – सहन, खान – पान, घर – खेत एवं परिवार – समाज आदि सम्मिलित होते हैं। जिन लोगों

के पास इन समुचित सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था होती है, उनका सामाजिक स्तर उच्च होता है। जीवन स्तर के दृष्टिकोण से समाज मुख्यतः तीन वर्गों में विभक्त होता है। वे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग हैं। सामान्यतः उच्च वर्ग में साक्षरता का स्तर उच्च पाया जाता है क्योंकि ऐसे वर्ग के बच्चे किसी भी विद्यालय में पढ़ सकते हैं। मध्यम वर्ग अभी विकास की संक्रमण अवस्था में है, ऐसी दशा में इनके पास आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता तो हो गई है परंतु इनका सामाजिक एवं राजनीतिक विकास अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। इसी कारण इनमें साक्षरता दर उच्च वर्ग से कम पाई जाती है। निम्न वर्ग के लोग सामाजिक, सांस्कृतिक राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से इतने पिछड़े हैं कि न तो उनके अंदर जागरूकता है और ना ही इतना सामर्थ्य है कि वे अपने बच्चों को आधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से युक्त शिक्षा दे पाए। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचते ही नहीं, ऐसी दशा में इनमें साक्षरता दर निम्न होती है।

11.9.3 यातायात एवं संचार के संसाधनों की उपलब्धता

वर्तमान प्रौद्योगिकी युग में यातायात एवं संचार के साधनों का समुचित प्रसार विकास का एक मानक होता है। जिन देशों या प्रदेशों में इनकी उपलब्धता अधिक है वहाँ साक्षरता दर अधिक तथा जिन समाजों में उनकी कमी है, वहाँ साक्षरता दर न्यून पाई जाती है। साक्षरता दर के समुचित प्रसार के लिए आवास के निकट विद्यालय की उपलब्धता अनिवार्य शर्त है। कुछ ऐसे ग्रामीण परिवेश भी पाए जाते हैं, जहाँ दूर – दूर तक विद्यालय नहीं है। ऐसी स्थिति में बच्चे पढ़ नहीं पाते और साक्षरता की दर निम्न पाई जाती है। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालय हर गाँव में उपलब्ध होना चाहिए, अन्यथा शिक्षा का प्रसार नहीं होगा। इसके साथ ही अगर यातायात के साधनों का सभी जगह विकास कर दिया जाए तो बच्चे घर से दूर जाकर भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आधुनिक संचार के साधनों का विकास एवं प्रसार भी साक्षरता दर को बढ़ाने में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं।

11.9.4 तकनीकी विकास का स्तर

तकनीक की उपलब्धता एवं प्रसार की दृष्टिकोण से संपूर्ण विश्व दो भागों में विभक्त है। पहला तकनीकी रूप से विकसित राष्ट्र, दूसरा अल्पविकसित देश अथवा समाज। जिन देशों अथवा समाजों का तकनीकी रूप से विकास हो गया है, वहाँ शिक्षा के साथ ही प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इनके अभाव में वर्तमान समय में रोजगार का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में इन समाजों में साक्षरता की दर स्वतः ही उच्च हो जाती है। इसके भी विपरित अल्पविकसित एवं विकासशील समाजों की अधिकांश जनसंख्या कृषि, पशुपालन, मत्स्यन एवं खनन जैसे कार्यों में संलग्न है। ऐसी स्थिति में इनमें साक्षरता एवं शिक्षा की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार देखा जाता है कि तकनीकी रूप से विकसित देशों या समाजों में साक्षरता दर उच्च पाई जाती है जबकि अन्य जगहों पर निम्न।

11.9.5 शिक्षा में लागत

शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, इसके अभाव में मनुष्य पशु के समान हो जाता है। शिक्षा एक व्यय आधारित क्रियाकलाप है, जिस पर यदि वर्तमान समय में खर्च के हिसाब से विवरण दिया जाए तो इसके दो स्वरूप सामने आते हैं। पहली सस्ती शिक्षा दूसरी महंगी शिक्षा। भारत सहित विश्व के सभी देशों में दोनों प्रकार की शिक्षा प्रचलित है। समाज की सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों के आधार पर ही निश्चित होता है कि किस समाज के बच्चे कहां पढ़ेंगे। संसाधन संपन्न वर्गों द्वारा अपने बच्चों को निजी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में उच्च गुणवत्तापूर्ण महंगी शिक्षा प्रदान की जा रही है। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पहुंच आधुनिक शिक्षा तक नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में यह देखा जाता है कि शिक्षा की लागत भी साक्षरता दर को प्रभावित करती है।

11.10 सारांश

आपने इस इकाई में साक्षरता का अर्थ और साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारणों का अध्ययन किया है। आप समझ गए होगें कि साक्षरता और उसे प्रभावित करने वाले कारणों में घनिष्ट संबंध होता है। साक्षरता किसी व्यक्ति अथवा समाज के विकास की अनिवार्य आवश्यकता होती है। इसके अभाव में व्यक्ति पशुवत व्यावहार करता है। वास्तव में किसी देश की साक्षर जनसंख्या तथा वहाँ का सबसे बड़ा संसाधन होती है जो उसकी भौगोलिक अवस्थिति, सरकारी नीतियों, सांस्कृतिक संगठन आदि के आधार पर विकसित होती है। साक्षरता का वितरण सम्पूर्ण

विश्व में एक समान नहीं है। कुछ देश पूर्ण साक्षर हैं तो कहीं पर उच्च, मध्यम एवं निम्न साक्षरता पाई जाती है। साक्षरता के इस विविधतापूर्ण वितरण के लिए अनेक कारण उत्तरदायी होते हैं जिनकी प्रभाविता सभी जगह पर एक समान नहीं होती है।

11.11 स्वमूल्यांकन प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

1. साक्षरता के निर्धारण हेतु सबसे कठिन मानक का प्रयोग फिनलैण्ड द्वारा कब किया गया था।

   (क) 1900 ई. (ख) 1930 ई. (ग) 1950 ई. (घ) 1972 ई.

2. किस संस्थान ने वर्ष 1957 ई. में साक्षरता के निर्धारण हेतु 60 देशों का सर्वेक्षण करके पढ़ने – लिखने की क्षमता का उपयोग किया था।

   (क) यूनेस्को (ख) विश्व व्यापार संगठन (ग) संयुक्त राष्ट्र संघ (घ) यूरोपीय संघ

3. भारत में साक्षरता के निर्धारण हेतु न्यूनतम आयु कितनी निश्चित की गई थी।

   (क) 5 वर्ष (ख) 7 वर्ष (ग) 9 वर्ष (घ) 14 वर्ष

4. भारत की किस जनगणना में इस बात को स्वीकार किया गया कि ब्रेल लिपि पढ़ लेने वाले नेत्रहीन व्यक्ति भी साक्षर हैं।

   (क) 1971 ई. (ख) 1981 ई. (ग) 1991 ई. (घ) 2001 ई.

5. शिक्षा के सार्वभौम प्रसार के लिए भारत सरकार द्वारा कब सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी।

   (क) 2001 ई. (ख) 1981 ई. (ग) 1991 ई. (घ) 2001 ई.

11.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

Bogue] D- J-] 1969] Principles of Demography] John Wiley] N-Y-

Clarke] John I-] 1973] Population Geography] Pergaman Press] Oxford-

Crook] Nigel] 1997] Principles of Population and Development] Pergaman Press] N- Y-

Garmier] J- B-] 1970] Geography of Population] Longman] London-

Mamoria] C- B-] 1981] India's Population Problem] Kitab Mahal] New Delhi-

Premi] M- K-] 1991] India's Population] Heading Towards a Billion] B- R- Publishing Corporation-

Blassoff] M- and Srinivasan K-] 2001] Population Development Nexus in India : Challenges for the New Millennium] Tata McGraw Hill] New Delhi-

Woods] R-] 1979] Population Analysis in Geography] Longman] London-

Zelinsky] W-] 1966] A Prologue to Population Geography] Prentice Hall-

चन्दना, आर. सी., 2022, जनसंख्या भूगोल – संकल्पना, नियंत्रक व विश्व प्रारूप, कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

चन्दना, आर. सी., 2022, भारत : जनसंख्या (जनसंख्या भूगोल – भाग 2), कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

मौर्या, एस. डी., 2005, जनसंख्या भूगोल, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद.

ओझा, आर. पी., 1984, जनसंख्या भूगोल, प्रतिभा प्रकाशन.

हीरा लाल, 2000, जनसंख्या भूगोल के मूल तत्व, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली.

तिवारी, राम कुमार, 2023, जनसंख्या भूगोल, प्रवालिका पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद.

11.13 अभ्यास प्रश्न (सत्रांत परीक्षा की तैयारी)

1. साक्षरता के अर्थ एवं संकल्पना की व्याख्या कीजिए?
2. भारत में साक्षरता की प्रगति का मूल्यांकन कीजिए?
3. साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए?

इकाई–12 साक्षरता प्रतिरूप, भारत में साक्षरता, पुरूष तथा स्त्री साक्षरता में अंतर

इकाई की रूपरेखा

12.0 प्रस्तावना

12.1 उद्देश्य

12.2 साक्षरता का वैश्विक प्रतिरूप

12.3 साक्षरता संक्रमण की अवस्था

12.4 भारत में साक्षरता संक्रमण की अवस्था

12.5 भारत में साक्षरता प्रतिरूप

12.6 भारत में पुरुष तथा महिला साक्षरता में अंतर

12.7 सारांश

12.8 स्वमूल्यांकन प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

12.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

12.10 अभ्यास प्रश्न (सत्रांत परीक्षा की तैयारी)

12.0 प्रस्तावना

शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का सार्वभौमिक अधिकार है। इसके अभाव में व्यक्ति पशु के समान हो जाता है। एक अशिक्षित व्यक्ति अज्ञानता, धर्मांधता, रूढ़िवादिता एवं एकाकीपन जैसी नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का अधिक शिकार होता है। अराजक तत्वों द्वारा ऐसे लोगों का प्रयोग आतंकवाद, अराजकतावाद, सांप्रदायिक दंगों को भड़काने हेतु किया जाता है। धर्म, समाज एवं प्रदेश की भावना को भड़काकर अपने निहित स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। शिक्षा तार्किकता पैदा करती है, व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता का विकास करती है। शिक्षा व्यक्ति के स्वाभिमान एवं आत्मसम्मान को बढ़ाने में सहायक होती है। एक शिक्षित व्यक्ति किसी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा संसाधन होता है वह समाज एवं देश को तरक्की की राह पर ले जाता है। नवीन शोध को प्रोत्साहन देकर देश में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है। इससे तकनीकी एवं चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में नवीनता आती है, मानव कल्याण में वृद्धि होती है।

12.1 उद्देश्य

साक्षरता का वैश्विक वितरण बहुत ही असमान है। कुछ देश पूर्ण साक्षरता के स्तर को प्राप्त कर लिए हैं तो कहीं की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित है। ऐसी स्थित में इसका अध्ययन अति आवश्यक हो जाता है। इस इकाई के उद्देश्य निम्नलिखित है –

1. विश्व में साक्षरता प्रतिरूप का अध्ययन करना।
2. भारत में साक्षरता प्रतिरूप का अध्ययन करना।
3. पुरुष तथा स्त्री साक्षरता के अंतर को स्पष्ट करना।

12.2 साक्षरता का वैश्विक प्रतिरूप

शिक्षा का वैश्विक वितरण बहुत ही आसमान है। कहीं पर इसका प्रभाव ज्यादा है तो कहीं पर कम। वैश्विक दृष्टिकोण से यदि शिक्षा के प्रसार का अवलोकन करें तो ज्ञात होता है कि पूरे विश्व की औसत साक्षरता

दर 82% प्राप्त हुई है। इसमें जहाँ पुरुष की साक्षरता दर 82% प्राप्त हुई है वहीं महिला साक्षरता दर 77% है। इन आंकड़ों के विश्लेषण से यह देखा गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर एक वैश्विक समस्या है। इस कम दर की अनेक समस्याएं वैश्विक स्तर पर देखी जाती है।

पुरुषों एवं महिलाओं की साक्षरता दर के वैश्विक स्वरूप में अनेक सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कारक विभिन्नता के लिए जिम्मेदार होते हैं। विकसित देशों की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थितियां उच्च स्तरीय पाई जाती है, इसीलिए इन देशों में साक्षरता दर जैसी समस्या का समाधान आसानी से कर लिया जाता है। ऐसे देशों में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर भी लगभग एक समान होती है। साक्षरता दर एक ऐसा तत्व है जिसके महत्व एवं जरूरत को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके उत्थान एवं पतन में आर्थिक कारकों की भूमिका सर्वाधिक होती है, अतः अर्थव्यवस्था के विकास एवं साक्षरता में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। साक्षरता दर विकसित एवं संपन्न देशों में सर्वाधिक, विकासशील देशों में मध्यम एवं अल्पविकसित देशों में सबसे कम दर्ज की जाती है। वैश्विक स्तर पर साक्षरता के वितरण स्वरूप का अध्ययन करने पर तीन प्रकार के स्वरूप सामने आते हैं जिनका विस्तृत विवरण निम्नवत है –

12.2.1 साक्षरता का उच्च स्वरूप (90% से अधिक)

विश्व के ऐसे देश जिनमें साक्षरता की दर 90% से अधिक पाई जाती है उच्च साक्षरता दर वाले देश कहलाते हैं। आंकड़ों की अधिकता तथा भौगोलिक स्वरूप से जनसंख्या का विश्व में वृहद प्रसार देखते हुए विश्व के सभी देशों के जनसंख्या संबंधी आंकड़े यहाँ प्रस्तुत नहीं किया जा सकते है। ऐसी स्थिति में विश्व के कुछ चुनिंदा देशों के आंकड़ों को लेकर ही समझने का प्रयास किया गया है। पोलैंड एवं नार्वे ऐसे देश हैं जहाँ साक्षरता दर शत – प्रतिशत दर्ज की गई है अर्थात यहाँ कोई भी व्यक्ति निरक्षर नहीं है। नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान ऐसे देश हैं जहाँ साक्षरता दर 99% दर्ज की गई है। इनमें से अधिकांश देश वृहद भौगोलिक विस्तार वाले हैं । यहाँ पर नृजातीय एवं प्रजातीय विविधता अधिक पाई जाती है। यही कारण है कि औद्योगिक विकास का केंद्र होने के साथ ही सेवा क्षेत्र का समुचित विकास होने पर भी यहाँ कुछ जनसंख्या ऐसी रहती है जहाँ तक शिक्षा का प्रसार अभी तक नहीं हो सका है। उच्च साक्षरता दर वाले देशों की तीसरी श्रेणी में ऐसे देश सम्मिलित हैं जिनकी साक्षरता दर 90% से 99% के बीच पाई जाती है। इन देशों में थाईलैंड, फिलिपींस, सिंगापुर, कुवैत, म्यांमार, चीन, इंडोनेशिया इत्यादि सम्मिलित हैं। आंकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि उच्च साक्षरता दर वाले सभी देश विकसित हैं, यहाँ शिक्षा अनिवार्य है तथा सभी बच्चे अनिवार्य रूप से प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि आर्थिक स्थिति की तरह ही शिक्षा का स्तर भी यहाँ उच्च पाया जाता है। इन देशों में नगरीकरण का स्तर भी उच्च पाया जाता है, साथ ही साथ यातायात एवं संचार के साधनों का भी समुचित रूप से विकास हो गया है। एक तरफ जहाँ उच्च आर्थिक व्यवस्था के कारण विद्यालयों, महाविद्यालयों के साथ उच्च शिक्षण संस्थाओं का इन देशों में समुचित प्रसार पाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ उन्नत यातायात व्यवस्था के कारण बच्चे घर से दूर जाकर भी आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। संचार माध्यमों के उच्च स्तरीय विकास के कारण घर से भी शिक्षा प्राप्त करने के अच्छे अवसर प्राप्त हो जाते हैं । इन देशों में महिलाओं को भी लगभग सामान्य के अवसर सभी क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं, जिसके कारण उनमें भी गतिशीलता अधिक पाई जाती है। इन सभी कारकों का संयुक्त प्रभाव यही है कि विश्व के सभी विकसित देशों में उच्च साक्षरता दर पाई जाती है।

12.2.2 साक्षरता का मध्यम स्वरूप (90% से 40% तक साक्षरता)

ऐसे देश जहाँ साक्षरता दर 90% से 40% के बीच पाई जाती है, उन्हें मध्यम साक्षरता वाले देश कहा जाता है। इनमें अधिकांश विश्व के विकासशील देश सम्मिलित हैं। आधुनिक तरीके से विकास की यात्रा का प्रारंभ इन देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आजादी प्राप्त करने के साथ ही शुरू की थी। औपनिवेशिक शक्तियों के शोषण के कारण इन देशों की अर्थव्यवस्था जर्जर थी, जिसके कारण यहाँ विकास की गति तो तीव्र है परंतु असमानता की खाई इतनी बड़ी है कि उसे भरने में कुछ दशकों का समय लगेगा। ऐसी स्थिति में साक्षरता जैसी मूल आवश्यकता का भी उतना सही ढंग से विकास नहीं हो पाया है, जितना की होना चाहिए । यही कारण है कि इन देशों में साक्षरता दर मध्यम स्तरीय पाई जाती है। यह देश भी विभिन्न उपवर्गों में विभक्त हैं। उच्च मध्यम साक्षरता वाले देशों में साक्षरता 80% से 90% के बीच पाई जाती है। इन देशों में ब्राजील, टर्की दक्षिणी अफ्रीका, मलेशिया, लीबिया एवं अरब के कुछ देश सम्मिलित हैं। इन देशों में औद्योगीकरण का स्तर उच्च पाया जाता है। इन देशों की

दूसरी श्रेणी, मध्यम मध्यम साक्षरता वाले देशों का है, जहाँ साक्षरता दर 80% से 50% के बीच पाई जाती है। इन देशों में भारत, ईरान, सऊदी अरब, इराक, सूडान, मिश्र, बुरुंडी एवं मोरक्को जैसे देश सम्मिलित हैं।

मध्यम साक्षरता वाले देशों की तीसरी उपश्रेणी निम्न मध्यम साक्षरता वाले देशों की है, जहाँ साक्षरता दर 50% से 40% के बीच पाई जाती है। इन देशों में बांग्लादेश, नेपाल, मध्य अफ्रीका, माली, इथोपिया, गिनी विशाउ जैसे देशों का नाम उल्लेखनीय है। रामकुमार तिवारी ने अपनी पुस्तक जनसंख्या भूगोल में लिखते हैं कि मध्यम साक्षरता वाले देशों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इन देशों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर अति निम्न दर्ज की जाती है। ये सभी देश अल्प विकास की अवस्था से निकलकर विकासशील अवस्था में आए हैं। विकास की दर अत्यंत कम है। यही कारण है कि इन देशों के आर्थिक संसाधनों का अधिकांश भाग देश के अवसंरचनात्मक विकास एवं विदेशी विनिमय में खर्च हो जाते हैं और अशिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकता पर पर्याप्त मात्रा में धन की उपलब्धता नहीं हो पाती है। कुछ मुस्लिम देशों में धार्मिक रूढ़िवादिता के कारण भी महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है जबकि उनकी अर्थव्यवस्था लगभग विकसित देशों के समान है। वहां आर्थिक संसाधनों की कोई कमी नहीं पाई जाती है फिर भी धार्मिकता के प्रभाव में इन देशों द्वारा महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है और महिलाएं शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। यही कारण है कि इन देशों में साक्षरता की स्थिति निम्न स्तरीय पाई जाती है।

सारणी 12.1 विश्व के प्रमुख देशों में कुल साक्षरता दर के साथ पुरुष और स्त्री साक्षरता दर

देश का नाम	साक्षरता दर (प्रतिशत में)			देश का नाम	साक्षरता दर (प्रतिशत में)		
	कुल	पुरुष	स्त्री		कुल	पुरुष	स्त्री
उच्च साक्षरता दर वाले देश, 90% से अधिक							
नार्वे	100	100	100	रूस	99	100	99
पोलैंड	100	100	100	कोरिया	99	99	99
स्वीडेन	99	99	99	इटली	98	99	98
आस्ट्रेलिया	99	99	99	युरुग्वे	98	98	98
नीदरलैंड	99	99	99	यूनान	96	98	94
संयुक्त राज्य अमेरिका	99	99	99	चिली	96	96	96
कनाडा	99	99	99	पुर्तगाल	95	96	91
जापान	99	99	99	सिंगापुर	93	97	89
डेनमार्क	99	99	99	कुवैत	93	94	91
यूनाइटेड किंगडम	99	99	99	थाईलैण्ड	93	95	91
फ्रांस	99	99	99	फिलीपीन्स	93	93	93

जर्मनी	99	99	99	चीन	92	96	89
न्यूजीलैण्ड	99	99	99	म्यांमार	90	94	87
मध्यम साक्षरता दर वाले देश, 90% से 40% के मध्य							
मलेशिया	89	92	85	सुडान	61	72	51
ब्राजील	89	88	89	बुरुंडी	59	73	48
टर्की	87	25	80	मोरक्को	52	97	52
दक्षिण	86	87	86	यमन	50	65	40
लीबिया	93	92	72	पाकिस्तान	50	63	36
सऊदी अरब	79	85	71	मध्य अफ्रीका	49	65	34
इरान	77	84	70	नेपाल	49	63	35
भारत	74	82	65	माली	47	54	39
ट्यूनिसिया	74	83	65	बांग्लादेश	48	54	41
इराक	74	84	64	इथोपिया	43	50	35
मिश्र	71	83	59	गिनी बिसाउ	42	58	27
निम्न साक्षरता दर वाले देश, 40% से कम							
सेनेगल	39	51	29	नाइजर	29	43	15
वेनिन	35	48	23	अफगानिस्तान	28	43	13
गिनी	30	43	18	सम्पूर्ण विश्व	82	87	77

स्त्रोत : संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विभाग से प्रकाशित आकड़ों के आधार पर परिगणित.

12.2.3 साक्षरता का निम्न स्वरूप (40% से कम साक्षरता)

ऐसे देशों को निम्न साक्षरता वाले देशों की श्रेणी में रखा जाता है, जिनकी साक्षरता दर 40: से कम पाई जाती है। यह देश भी औपनिवेशिक शक्तियों के शोषण का शिकार हुए हैं । इनको भी स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी है परंतु ये धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में पिछड़े हुए है। ऐसी स्थिति में शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकता की अवसंरचना का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। ये देश विकास की अवस्था में सबसे पीछे है, यही कारण है कि इन देशों में साक्षरता दर निम्न कोटि की पाई जाती है। इन देशों की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। आर्थिक रूप से पिछड़ापन ही शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता एवं जिज्ञासा को कम कर देती है। इन देशों में अफ्रीका एवं इस्लामिक देशों को सम्मिलित किया जाता है।

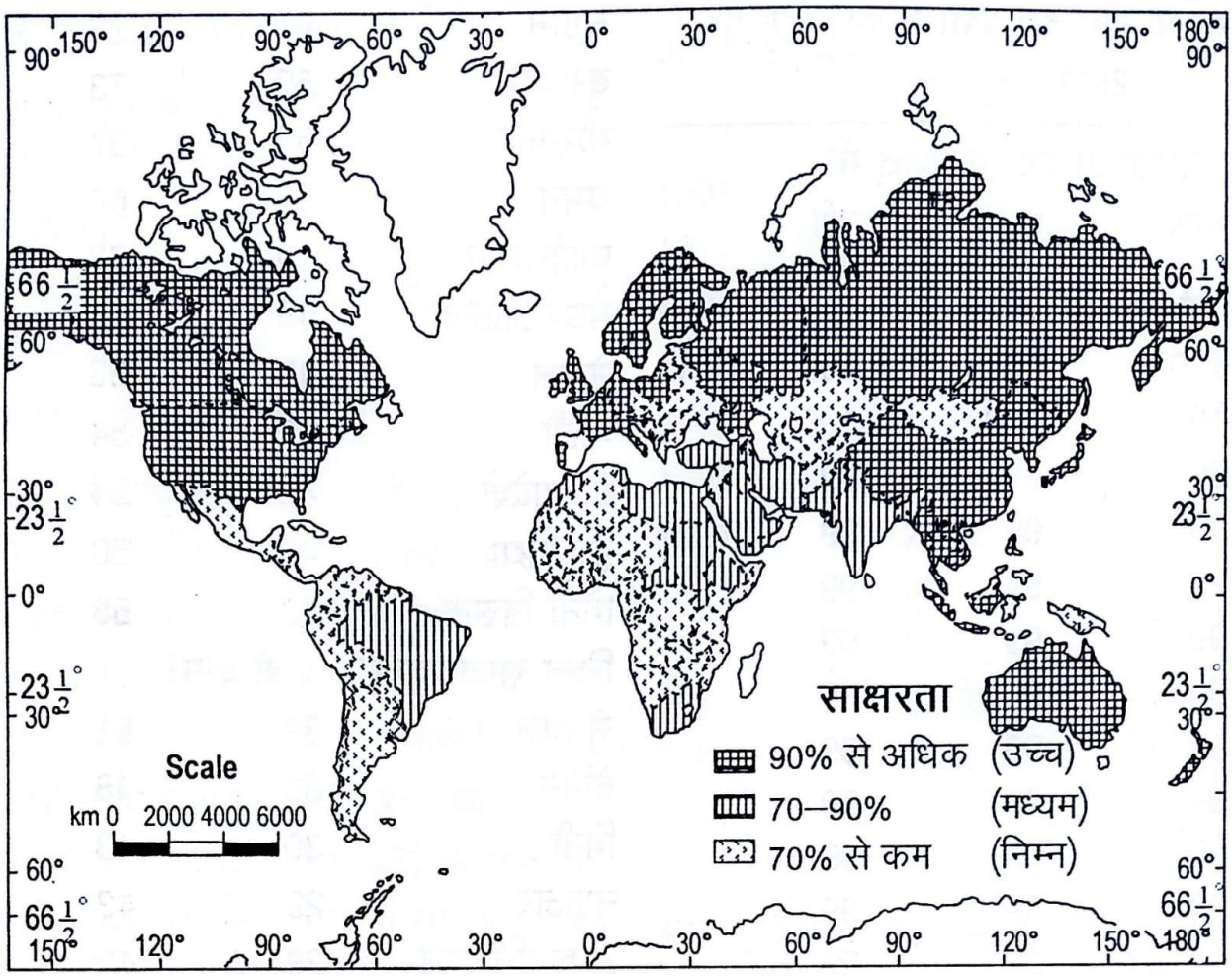

चित्र संख्या 12.1 विश्व में साक्षरता का वितरण.

12.3 साक्षरता संक्रमण की अवस्था

साक्षरता संक्रमण से तात्पर्य परिवर्तन की एक ऐसी अवस्था से है, जिसमें एक असाक्षर समाज का परिवर्तन साक्षर समाज में होता है। इस संकल्पना का प्रारंभ पश्चिमी यूरोप के देशों में हुआ है, वहीं से इसका प्रसरण विश्व के अन्य देशों में हुआ है। जिन देशों की साक्षरता दर 99% या उससे अधिक हो तो ऐसे देश को पूर्ण साक्षरता वाले देश कहा जाता है। अधिकांश विकसित देश इस अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं। साक्षरता संक्रमण की अवस्था के दृष्टिकोण से संपूर्ण विश्व के देशों को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है –

12.3.1 प्रथम अवस्था

इस श्रेणी में ऐसे देश सम्मिलित हैं जिनमें संक्रमण पूर्ण हो चुका है। इनमें साक्षरता सर्व व्याप्त है। यहाँ कोई भी निरक्षर व्यक्ति नहीं है। ये देश प्राचीन औद्योगिक राष्ट्र हैं जहाँ साक्षरता संक्रमण सबसे पहले प्रारंभ हुआ था । इन राष्ट्रों ने अपने यहाँ निरक्षरता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है तथा 20वीं शताब्दी के मध्य अवधि तक इन देशों में साक्षरता संक्रमण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। साक्षरता संक्रमण को पूर्ण करने वाले देशों की इस श्रेणी में उत्तरी अमेरिका के राष्ट्र, पूर्व सोवियत संघ सहित यूरोपीय देश, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड है।

12.3.2 द्वितीय अवस्था

ऐसे राष्ट्र जहाँ अभी साक्षरता मध्यम अवस्था में है संक्रमण क्रिया पर है द्वितीय अवस्था में आते हैं। इन राष्ट्रों में साक्षरता संक्रमण की क्रिया द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शुरू हुई है। मूलतः ये राष्ट्र क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से विशाल हैं तथा कृषि प्रधान भी हैं। जिसके कारण यहाँ संक्रमण की क्रिया बहुत मंद गति से

संपन्न हो रही है। इन देशों में ऐसे असाक्षर लोगों की संख्या भी अधिक पाई जाती है, जो पाठशाला की आयु पूर्ण कर चुके हैं। उन्हें निरक्षरता विरासत में प्राप्त हुई है। इन देशों में जन्म दर उच्च होने के कारण विद्यालय जाने वाली आयु के बच्चों की संख्या अधिक है। ऐसी स्थिति में यहाँ शिक्षा एवं साक्षरता के प्रसार हेतु अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। इनमें से अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था पिछड़ी है तथा कृषि प्रधान अथवा कृषि आधारित है जिसके कारण यहाँ उपलब्ध संसाधनों पर अधिक जनसंख्या का दबाव है। यही कारण है कि इन देशों में साक्षरता संक्रमण विलंब से हो रहा है जबकि इसकी प्रगति विकसित औद्योगिक राष्ट्रों के समान होनी चाहिए। इस वर्ग के राष्ट्रों में भारत, चीन, ब्राजील, मेक्सिको, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ईरान जैसे अनेक देश सम्मिलित हैं।

12.3.3 तृतीय अवस्था

इस अवस्था के अंतर्गत ऐसे राष्ट्र सम्मिलित होते हैं जहाँ साक्षरता संक्रमण अभी हाल में ही प्रारंभ हुआ है। यहाँ साक्षरता दर निम्न पाई जाती है। इन राष्ट्रों की श्रेणी में अफ्रीका एवं पश्चिमी एशिया के इस्लाम धर्मावलंबी वाले राष्ट्र आते हैं। जहाँ साक्षरता प्रसार में अभी गति आनी है। इन देशों में धार्मिक मान्यताओं के प्रभाव के कारण महिलाओं की स्थिति अति दयनीय है। इनमें साक्षरता संक्रमण की गति अभी भी मंद है। यहाँ संक्रमण को गति तब तक नहीं मिलेगी जब तक महिलाओं को समानता का स्तर नहीं प्रदान किया जाएगा।

12.4 भारत में साक्षरता संक्रमण की अवस्था

भारत में भी साक्षरता संक्रमण की सभी अवस्थाएं प्राप्त हुई हैं। चूंकि प्राचीन काल से ही सभ्यता एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। ऐसी स्थिति में यह विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार द्वारा शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु अनेक नीतियां बनाई गई साथ ही साथ अनेकों ऐसे कार्यक्रम भी अपने अथवा लागू किए गए जिनसे नामांकन में वृद्धि हो। इस प्रकार भारत में साक्षरता संक्रमण के तीन चरण निम्नलिखित हैं –

- वर्ष 1971 ई. में की जनगणना में भारत में ऐसा पहली बार हुआ जब साक्षर व्यक्तियों की संख्या निरक्षर व्यक्तियों से अधिक दर्ज की गई। इस प्रकार यह संक्रमण की प्रथम अवस्था थी।
- वर्ष 1991 ई. की जनगणना में भारत के सभी राज्यों में साक्षर व्यक्तियों की संख्या निरक्षर व्यक्तियों से अधिक हो गई। भारत में साक्षरता के इतिहास की यह अवधि द्वितीय संक्रमण अवस्था के नाम से जानी जाती है।
- वर्ष 2011 की जनगणना में भारत साक्षरता संक्रमण के तृतीय अवस्था में प्रवेश किया जब केरल, लक्ष्यद्वीप एवं मिजोरम में साक्षरता दर 90% से अधिक दर्ज की गई। साक्षरता संक्रमण की तृतीय अवस्था तब पूर्ण होगी जब भारत के सभी राज्यों की साक्षरता दर 90% से अधिक प्राप्त होगी। पूर्ण साक्षरता की स्थिति 99% साक्षरता को माना जाता है।

12.5 भारत में साक्षरता प्रतिरूप

साक्षरता दर किसी भी देश के विकास का महत्वपूर्ण मानक होती है। इसकी उपलब्धता एवं अनुपलब्धता के आधार पर ही उसके निवासियों का जीवन स्तर निर्धारित होता है। भारत में साक्षरता दर के वितरण प्रतिरूप का अध्ययन निम्नलिखित दो शीर्षकों के तहत किया जाता है –

1. भारत में साक्षरता में कालिक वृद्धि
2. भारत में साक्षरता का क्षेत्रीय प्रतिरूप

12.5.1 भारत में साक्षरता की कालिक वृद्धि

भारत की संस्कृति की गणना विश्व के प्राचीनतम संस्कृतियों में की जाती है। भारतीय इतिहास में सभ्यता के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त होते हैं परंतु उसके सभी साक्ष्यों को अभी तक पूर्णतःपढ़ा नहीं जा सका है क्योंकि इनमें से अधिकांश का स्वरूप प्रतीकात्मक है। लिखित इतिहास हमें वैदिक कालीन सभ्यता से प्राप्त होते हैं। भारत के वैदिक ग्रन्थों की गणना विश्व के प्राचीनतम ग्रन्थों में की जाती है तथा सभी देशों द्वारा इसे स्वीकार भी

किया जाता है। इससे प्रतीत होता है कि भारत के प्राचीन कालीन लो अशिक्षित थे। इन ग्रन्थों से यह भी जानकारी मिलती है कि प्राचीन काल में स्त्रियां भी शिक्षित थे, उन्हें समाज में समानता का अधिकार प्राप्त था। उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। समाज में वे राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त थी। इन सभी तथ्यों से यही बोध होता है कि उस समय साक्षरता सर्वव्याप्त थी। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि वैदिक काल के पश्चात दो घटनाएं मुख्य रूप से घटित हुई जिससे साक्षरता दर प्रभावित हुई –

- पहली यह कि ऋग्वैदिक काल के पश्चात अनेकों आक्रमण हुए जिसके कारण स्थानीय लोग दासों में परिवर्तित हो गए और उन्हें शिक्षा तथा संपत्ति जैसे अधिकारों से वंचित कर दिया गया।
- दूसरा इसी अवधि में धार्मिकता की भावना का भी उत्थान होने लगा। धर्म को सर्वोच्च माना जाने लगा तथा अलौकिक ईश्वर को संपूर्ण विश्व का निर्माता माना गया। कुछ वर्ग विशेष के लोगों द्वारा सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक निर्णय लिया जाने लगा।

इसका परिणाम यह हुआ कि समाज की एक बड़े तबके को शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकता से दूर कर दिया गया। समाज का एक वर्ग आर्थिक रूप से संपन्न हो गया तो दूसरा इससे पूर्णतःवंचित रह गया। प्राचीन संस्कृतियों को विनष्ट कर दिया गया। समाज में धीरे – धीरे अनेक कुरीतियां व्याप्त हो गई। इन्हीं कुरीतियों का प्रभाव था कि लोगों के बीच साक्षरता की पहुंच धीरे – धीरे कम होती गई। मध्यकाल में भी साक्षरता के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं दिखाई दी। ब्रिटिश काल में शिक्षा का संबंध केवल नौकरी से रह गया। इस समय भी भेदभाव इतना बढ़ा कि शिक्षा सिर्फ धनी एवं संपन्न लोगों तक ही सिमट कर रह गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार द्वारा लोकतांत्रिक विधि से शिक्षा के विकास का प्रयास किया जाने लगा। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा भी समय – समय पर इसे प्रोत्साहन दिया गया। दुरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तथा गरीबों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। इसका प्रभाव यह हुआ कि आज देश में शिक्षा का प्रसार तीव्र गति से हो रहा है।

जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि वर्ष 1901 ई. में देश की साक्षरता दर मात्र 5.34% थी। वर्ष 1931 ई. तक यह बहुत धीमी गति से बढ़ी तथा 1931 ई. में यह 9.50% तक पहुंची। कुछ सुधार के साथ यह दर वर्ष 1941 ई. में 16.67% दर्ज की गई। इसका प्रमुख कारण था देश भर में स्वतंत्रता आंदोलन के तीव्र प्रसार के कारण लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता। स्वतंत्रता प्राप्ति ने इसकी वृद्धि में उत्प्रेरक का काम किया और यह तीव्र गति से बढ़ने लगी। वर्ष 1961 ई. में की जनगणना में जहाँ यह 24.02% दर्ज की गई, वहीं 1971 ई. की जनगणना में 29.48ः प्राप्त हुई। इसके पश्चात देश में सामाजिक, आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी विकास का प्रभाव यह रहा कि वर्ष 1981 ई., 1991 ई. एवं 2001 ई. की जनगणना में साक्षरता दर क्रमशः 36.23ः, 52.5% एवं 65.3% दर्ज की गई है। वर्ष 2011 ई. की जनगणना में साक्षरता दर अब तक के सर्वोच्च स्तर 74.04% अंकित की गई है। इस प्रकार भारत की साक्षरता दर में वृद्धि, स्त्री एवं पुरुष साक्षरता दर को निम्नलिखित सारणी के माध्यम से दिखाया गया है–

सारणी 12.2 भारत में साक्षरता दर में वृद्धि

क्र. सं.	जनगणना वर्ष का नाम	साक्षरता दर (प्रतिशत में)		
		कुल	पुरुष	स्त्री
1.	1901	5.35	9.83	0.69
2.	1911	5.92	10.56	1.05
3.	1921	7.16	12.21	1.81
4.	1931	9.50	15.59	2.93

5.	1941	——	——	——
6.	1951	16.67	24.95	7.93
7.	1961	24.02	36.44	12.95
8.	1971	29.48	39.52	18.70
9.	1981	36.23	46.89	24.82
10.	1991	52.21	64.13	29.29
11.	2001	65.33	75.85	54.16
12.	2011	74.04	82.14	65.46

स्त्रोतः जनगणना विभाग, लखनऊ.

12.5.2 भारत में साक्षरता वितरण का क्षेत्रीय प्रतिरूप

भारत में साक्षरता दर का क्षेत्रीय वितरण बहुत ही आसमान है। कहीं पर यह उच्च पाई जाती है तो कहीं पर निम्न। इस प्रकार देखा जाता है कि संपूर्ण देश में साक्षरता दर में काफी भिन्नता पाई गई है। यह जहाँ अधिकतम केरल में 93.93% दर्ज की गई है, वहीं बिहार में सबसे न्यूनतम 61.5% प्राप्त हुई है। इस प्रकार ज्ञात होता है कि यह अंतर लगभग 32% का है। इस प्रकार साक्षरता के वितरण में असमानता का विश्लेषण निम्नलिखित तीन शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है –

- उच्च साक्षरता वाले प्रदेश (90% से अधिक)
- मध्यम साक्षरता वाले प्रदेश (70% से 90% के मध्य)
- निम्न साक्षरता वाले प्रदेश (70% से कम)

12.5.2.1 उच्च साक्षरता वाले प्रदेश

वर्ष 2001 ई. की जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उच्च साक्षरता वाले राज्यों में उन्हें सम्मिलित किया गया है, जिनकी साक्षरता दर 90% से अधिक है। इस श्रेणी में भारत के मात्र तीन राज्य सम्मिलित होते हैं। केरल (93.9%), लक्ष्यदीप (92.3%) एवं मिजोरम (91.6%)। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ कुल जनसंख्या के साथ ही पुरुष एवं महिला जनसंख्या की साक्षरता दर भी 90% से अधिक है। वहीं शेष दोनों राज्यों की महिला साक्षरता दर 90% से कम अंकित की गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केरल पूर्ण साक्षरता की ओर अग्रसर है। केरल में साक्षरता दर की उच्च पाए जाने के दो कारण है –

1. एक तो इसका नगरीकरण का स्तर उच्च है,
2. दूसरी ओर ईसाई मिशनरियों का प्रभाव यहाँ अधिक है जिसके कारण जनता शिक्षा हेतु प्रेरित होती है।

शेष दोनों राज्यों में नगरीकरण का स्तर उच्च पाया जाता है। नगरीकरण एवं साक्षरता के बीच धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। यही कारण है कि इन राज्यों की साक्षरता दर उच्च दर्ज की गई है।

12.5.2.2 मध्यम साक्षरता वाले प्रदेश

इस वर्ग के अंतर्गत उन राज्यों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी साक्षरता दर 70% से 90% के मध्य दर्ज की गई है। ऐसी साक्षरता दर को प्रदर्शित करने वाले राज्यों की संख्या अधिक है। भारत में सभी राज्यों की साक्षरता दर को निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रस्तुत किया गया है –

सारणी 12.3 भारत के राज्यों में साक्षरता दर का वितरण

क्र. सं.	प्रदेश का नाम	साक्षरता दर (प्रतिशत में)		
		कुल	पुरुष	स्त्री
1.	केरल	93.9	96.0	92.0
2.	लक्षदीप	92.3	96.1	88.3
3.	मिजोरम	91.6	93.7	89.4
4.	त्रिपुरा	87.8	92.2	83.2
5.	गोवा	87.4	92.8	81.8
6.	दमन और दीव	87.0	91.2	79.6
7.	पुडुचेरी	86.6	92.1	81.2
8.	चंडीगढ़	86.4	90.5	81.4
9.	दिल्ली	86.3	91.0	80.9
10.	अंडमान निकोबार	86.3	90.0	81.8
11.	हिमांचल प्रदेश	83.8	90.8	76.6
12.	महाराष्ट्र	82.9	89.8	75.5
13.	सिक्किम	82.2	87.3	76.4
14.	तमिलनाडु	80.3	86.8	73.9
15.	नागालैंड	80.1	83.3	76.7

16.	मणिपुर	79.9	86.5	73.2
17.	उत्तराखंड	79.6	88.3	70.7
18.	गुजरात	79.3	87.2	70.7
19.	दादर व नगर हवेली	77.7	86.5	65.9
20.	पश्चिम बंगाल	77.1	82.7	71.2
21.	पंजाब	76.7	81.5	71.3
22.	हरियाणा	76.6	85.4	66.8
23.	कर्नाटक	75.6	82.9	68.1
24.	मेघालय	75.5	77.2	73.8
25.	ओड़ीशा	73.5	82.4	64.4
26.	असम	73.2	78.8	67.3
27.	छत्तीसगढ़	71.0	81.5	60.6
28.	मध्य प्रदेश	70.6	80.5	60.0
29.	उत्तर प्रदेश	69.7	79.2	59.3
30.	जम्मू और कश्मीर	68.7	78.3	58.0
31.	आंध्र प्रदेश	67.7	75.6	59.7
32.	झारखंड	67.6	78.5	56.2
33.	राजस्थान	67.0	80.5	52.7
34.	अरुणाचल प्रदेश	66.9	73.7	59.7
35.	बिहार	63.8	73.4	53.3
36.	भारत	74.1	82.1	65.5

स्त्रोतः जनगणना विभाग, लखनऊ.

इन राज्यों की साक्षरता संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण से इस बात का बोध होता है कि यहाँ पुरुष साक्षरता दर उच्च पाई जाती है परंतु स्त्री साक्षरता दर निम्न है। इसका मुख्य कारण यहाँ पाई जाने वाली पितृसत्तात्मक समाज, आर्थिक पिछड़ापन एवं महिलाओं की समाज में निम्न स्थिति है।

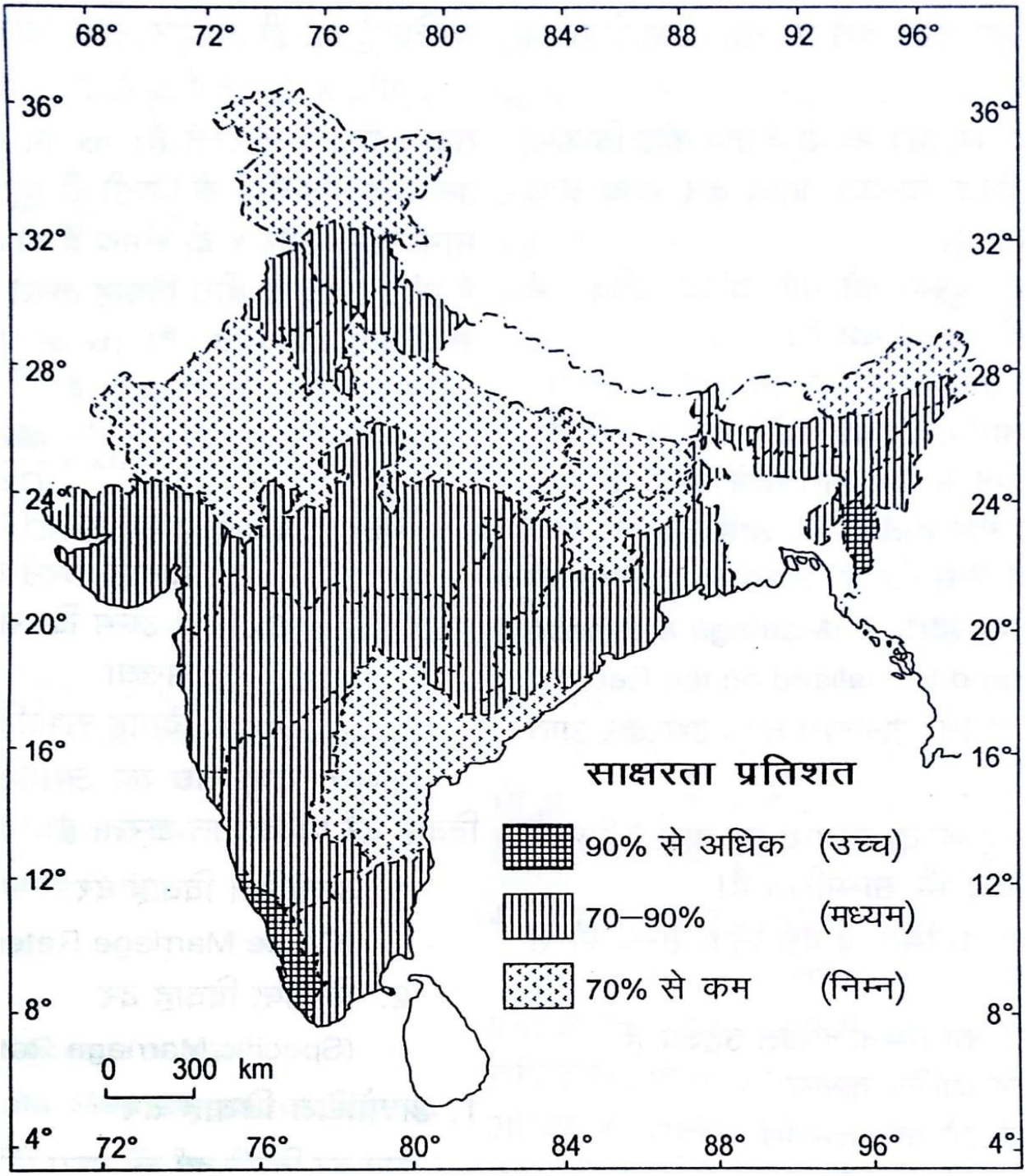

चित्र संख्या 12.2 भारत में साक्षरता का वितरण.

12.5.2.3 निम्न साक्षरता दर वाले राज्य (70% से कम)

भारत में साक्षरता दर की दृष्टिकोण से निम्न दर वाले राज्यों में उन्हें सम्मिलित किया गया है जिनकी साक्षरता दर 70% से कम दर्ज की गई है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश (69.7%), जम्मू कश्मीर (68.7%), आंध्र प्रदेश (67.7%), झारखंड (67.6%), राजस्थान (67%), अरुणाचल प्रदेश (66.9%) के साथ बिहार (61.8%) सम्मिलित हैं।

जनगणना से प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि यहाँ पुरुष एवं महिला साक्षरता दोनों की दर निम्न है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये राज्य अत्यंत पिछड़े हुए हैं जिसके कारण शिक्षा हेतु आवश्यक अवसंरचना का विकास अभी तक नहीं हो पाया है। सामाजिक पिछड़ापन, गरीबी, अंधविश्वास जैसे कारक भी यहाँ निम्न साक्षरता के लिए उत्तरदाई होते हैं।

12.6 भारत में पुरुष तथा महिला साक्षरता में अंतर

वृहद भौगोलिक विस्तार के साथ जनसंख्या की दृष्टि से भारत की गणना विश्व के बड़े देशों में की जाती है। ऐसी स्थिति में यहाँ जनसंख्या के अन्य तत्वों के समान ही साक्षरता के वितरण स्वरूप में असमानता देखने को मिलती है। इस प्रकार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षारता में अंतर को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है –

भारत में पुरुष साक्षरता

देश में अगर पुरुष साक्षरता का अवलोकन किया जाए तो स्पष्ट होता है कि यह जहाँ सर्वाधिक 96.12% है तो 73.39% न्यूनतम प्राप्त होती है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता लक्ष्यद्वीप में प्राप्त होती है। इसके पश्चात क्रमशः केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा आदि का स्थान आता है। इन राज्यों की पुरुष साक्षरता दर 90% से अधिक पाई जाती है। 90% से 80% पुरुष साक्षरता वाले राज्यों के अंतर्गत महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड, गुजरात, तमिलनाडु आदि राज्य आते हैं। इसी प्रकार 80% से कम पुरुष साक्षरता वाले राज्यों में असम, झारखण्ड, मेघालय, आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, एवं बिहार सम्मिलित है।

भारत में महिला साक्षरता

पुरुष साक्षरता की ही भाति महिला साक्षरता में भी देश में असमानता देखी जाती है। केरल ही भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ महिला साक्षरता 90% से अधिक पाई जाती है। 90% से 70% के बीच महिला साक्षरता दर्शाने वाले राज्यों को मध्यम श्रेणी में रखते है। इन राज्यों में मिजोरम, लक्ष्यद्वीप, त्रिपुरा, गोवा, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात आदि सम्मिलित है। इसी प्रकार 70% से कम महिला साक्षरता को व्यक्त करने वाले राज्यों को निम्न श्रेणी में रखा जाता है। इन राज्यों में असम, हरियाणा, दादरा एवं नागर हवेली, ओडिसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, बिहार एवं राजस्थान सम्मिलित है।

12.7 सारांश

आपने इस इकाई में विश्व में साक्षरता प्रतिरूप, भारत में साक्षरता के साथ – साथ पुरुष तथा स्त्री साक्षरता में अन्तर का अध्ययन किया है। आप समझ गए होगें कि साक्षरता के स्तर एवं देश के विकास की अवस्था में घनिष्ट संबंध होता है। जिन देशों का विकास स्तर उच्च स्तरीय होता है वे अपने यहाँ शिक्षा के विकास के समुचित प्रबंधन कर लेते है। प्राथमिक शिक्षा के साथ ही उच्च शिक्षा हेतु गुणवत्ता युक्त विश्वविद्यालय तथा कालेजों की स्थापना कर लेते है, साथ ही इन देशों तथा समाजों का आय स्तर भी उच्च पाया जाता है जिसके कारण शिक्षा पर होने वाला व्यय अधिक पाया जाता है। इसके विपरीत विकासशील एवं अल्प विकसित देशों की न तो आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और न ही सामाजिक – सांस्कृतिक विकास ही उच्च स्तरीय होता है। ऐसी स्थिति में इन देशों में शिक्षा पर व्यय अपेक्षाकृत कम होता है और साक्षरता दर निम्नस्तरीय पायी जाती है। वास्तव में किसी देश की जनसंख्या तथा वहाँ का सबसे बड़ा संसाधन होती है जो उसकी भौगोलिक अवस्थिति, सरकारी नीतियों, सांस्कृतिक संगठन आदि के साथ ही शिक्षा जैसी संकल्पना से पूर्ण होती है। भारत की गिनती भी विकासशील देशों में ही होती है। ऐसी स्थिति में यहाँ भी शिक्षा का स्तर मध्यम स्तरीय पाया जाता है। इसके साथ ही स्त्री एवं पुरुष साक्षरता में भी अंतर पाया जाता है।

12.8 स्वमूल्यांकन प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

1. विश्व की औसत साक्षरता दर कितनी है।

   (क) 75% (ख) 82% (ग) 88% (घ) 95%

2. मध्यम स्तर की साक्षरता विश्व के किन देशों में पाई जाती है।

(क) विकसित देश (ख) विकासशील देश (ग) अल्प विकसित देश (घ) सभी में

3. विश्व के कौन से दो देश हैं जहाँ साक्षरता शत प्रतिशत पाई जाती है।

(क) संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा

(ख) जर्मनी एवं फ्रांस

(ग) ब्रिटेन एवं जापान

(घ) पोलैण्ड एवं नार्वे

4. भारत के किस जनगणना में पहली बार साक्षर व्यक्तियों की संख्या निरक्षर व्यक्तियों से अधिक दर्ज की गई है।

(क) 1951 ई. (ख) 1971 ई. (ग) 1991 ई. (घ) 2001 ई.

5. वर्ष 1901 ई. में भारत की साक्षरता दर कितनी थी।

(क) 8.54% (ख) 7.52% (ग) 5.34% (घ) 6.64%

12.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

Bogue] D- J-] 1969] Principles of Demography] John Wiley] N-Y-

Clarke] John I-] 1973] Population Geography] Pergaman Press] Oxford-

Crook] Nigel] 1997] Principles of Population and Development] Pergaman Press] N- Y-

Garmier] J- B-] 1970] Geography of Population] Longman] London-

Mamoria] C- B-] 1981] India's Population Problem] Kitab Mahal] New Delhi-

Premi] M- K-] 1991] India's Population] Heading Towards a Billion] B- R- Publishing Corporation-

Blassoff] M- and Srinivasan K-] 2001] Population Development Nexus in India : Challenges for the New Millennium] Tata McGraw Hill] New Delhi-

Woods] R-] 1979] Population Analysis in Geography] Longman] London-

Zelinsky] W-] 1966] A Prologue to Population Geography] Prentice Hall-

चन्दना, आर. सी., 2022, जनसंख्या भूगोल – संकल्पना, नियंत्रक व विश्व प्रारूप, कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

चन्दना, आर. सी., 2022, भारत : जनसंख्या (जनसंख्या भूगोल – भाग 2), कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

मौर्या, एस. डी., 2005, जनसंख्या भूगोल, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद.

ओझा, आर. पी., 1984, जनसंख्या भूगोल, प्रतिभा प्रकाशन.

हीरा लाल, 2000, जनसंख्या भूगोल के मूल तत्व, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली.

तिवारी, राम कुमार, 2023, जनसंख्या भूगोल, प्रवालिका पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद.

12.10 अभ्यास प्रश्न (सत्रांत परीक्षा की तैयारी)

1. साक्षरता के वैश्विक प्रतिरूप की व्याख्या कीजिए?
2. साक्षरता संक्रमण क्या होती है। इसकी अवस्थाओं का वर्णन कीजिए?
3. भारत में साक्षरता प्रतिरूप का विश्लेषण कीजिए?

इकाई–13 नगरीयकरण का अर्थ, नगरीयकरण के प्रभाव, भारत में नगरीयकरण

इकाई की रूपरेखा

13.0 प्रस्तावना

13.1 उद्देश्य

13.2 नगरीकरण का अर्थ

13.3 नगरीकरण के दृष्टिकोण

13.4 नगरों के विकास की अवस्था

13.5 नगरीकरण के प्रभाव

13.6 नगरीकरण के सकारात्मक प्रभाव

13.7 नगरीकरण के नकारात्मक प्रभाव

13.8 भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति

13.9 भारत में नगरीकरण की आकारकीय श्रेणी

13.10 भारतीय नगरीकरण की विशेषताएँ

13.11 सारांश

13.12 स्वमूल्यांकन प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

13.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

13.14 अभ्यास प्रश्न (सत्रांत परीक्षा की तैयारी)

13.0 प्रस्तावना

नगर मानव सभ्यता के इतिहास के सभी युगों में संस्कृति एवं सभ्यता के केंद्र स्थल रहे हैं। इनका इतिहास कब से प्रारंभ होता है, के बारे में कोई निश्चित दस्तावेज अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। ऐतिहासिक स्थलों से यह जानकारी मिलती है कि नगरों का इतिहास आज से लगभग 5,000 से 6,000 वर्ष पुराना है। अपने आंकड़ों एवं प्रयोग के आधार पर ग्रिफिथ टेलर तथा डेविड किंग्सले ने भी इसी मत का समर्थन किया है। इन विद्वानों द्वारा प्राचीन काल के नगरों में मेसोपोटामिया को सर्वाधिक प्राचीन नगर माना जाता है। बेबीलोन नगर को भी प्राचीन ही माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन नगर है, जिसके दो प्रमुख नगरी केंद्र हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो हैं। इसके पश्चात विश्व एवं भारत में अनेकों नगरों का विकास हुआ तथा वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ। नगरों को मानवीय सभ्यता का केंद्र माना जाता है, इसीलिए जनसंख्या भूगोल की विषय वस्तु में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। नगर मानव समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्रियाकलापों की विस्तृत जानकारी भी प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक भूगोलवेत्ता द्वारा प्रायःनगरीकरण के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है।

13.1 उद्देश्य

नगरीकरण अपने आप में एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, जो कभी भी स्थिर नहीं रहती है। समय के अनुसार इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इस इकाई के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है –

1. नगरीकरण के अर्थ को समझना।
2. नगरीकरण के प्रभाव की व्याख्या करना।
3. भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करना।

13.2 नगरीकरण का अर्थ

नगरीकरण एक बहुविषयी शब्द है, जिसका प्रयोग सभी विषयों जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, नगर नियोजन एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करने वाले विद्वानों द्वारा किया जाता है। नगरीकरण से तात्पर्य है नगरीय वृद्धि अर्थात किसी जनसंख्या का नगरी हो जाना ही नगरीकरण कहलाता है। रामकुमार तिवारी अपनी पुस्तक जनसंख्या भूगोल में लिखते हैं कि अगर कोई जनसंख्या अपने अनुपात में काफी अधिक बढ़ जाए तो बढ़ी हुई जनसंख्या नगरी है। नगरीकरण को स्पष्ट करते हुए अनेक विद्वानों ने अलग – अलग परिभाषाएं दी हैं जो निम्नलिखित हैं –

जी. टी. ट्रिवार्था के अनुसार कुल जनसंख्या में नगरीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात को ही नगरीकरण कहा जाता है। यह एक प्रक्रिया है जिसका तात्पर्य कुल जनसंख्या में उसे वृद्धि से है जो नगरी क्षेत्र में रहती है। इससे इस बात का बोध होता है कि नगरीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या की अनुपात में कितनी वृद्धि हुई है।

ई. ई. बर्गेल के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें एक ग्रामीण क्षेत्र नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित होता है, नगरीकरण कहते हैं।

डेविस किंग्सले के अनुसार एक निश्चित जनसंख्या में नगरीय बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात या इस अनुपात में वृद्धि को नगरीकरण कहते हैं। नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामाजिक जीवन के सभी प्रारूपों में क्रांतिकारी परिवर्तन करती है। किसी क्षेत्र के तकनीकी विकास एवं आधारभूत अर्थव्यवस्था का नगरीकरण परिणाम होता है।

ग्रिफिथ टेलर ने प्रवास के आधार पर नगरीकरण को परिभाषित करने का प्रयास किया है, उनके अनुसार गांव से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण कहलाता है। इस संदर्भ में टेलर ने दो बातों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है –

- **प्रथम** – यदि किसी नगरीय जनसंख्या में उतनी वृद्धि होती है जितनी ग्रामीण जनसंख्या में होती है, तो ऐसी अवस्था को नगरीकरण में वृद्धि नहीं कहा जा सकता है।
- **दूसरा** – उनका मानना है कि यदि मनुष्य के सामाजिक मूल्य, आचार – विचार तथा चिंतन नगरीय हैं तो वह समाज या व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर भी नगरीकृत कहलाता है। इस विचार में टेलर ने ग्रामीण क्षेत्र की उसे जनसंख्या को भी नगरीय जनसंख्या मान लिया है, जो गैर कृषि कार्यों में संलग्न है।

वी. एल. एस. प्रकाश राव ने नगरीकरण को एक प्रक्रिया के रूप में एकल या बहुत आयामी केंद्र के चारों ओर अकृषित क्रियाकलापों एवं भूमि उपयोग का संकलन बतलाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया तब घटित होती है, जब ग्रामीण क्षेत्र से जनसंख्या का प्रवास नगरीय क्षेत्र की ओर होता है। इस प्रक्रिया में नगरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र दोनों एक – दूसरे पर निर्भर देखे जाते है। एक ओर जहाँ नगरीय क्षेत्र अपने विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों पर निर्भर रहता है, वही आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ ग्रामीण इलाकों को परिवहन एवं संचार जैसी सुविधा नगर ही उपलब्ध कराता है।

बी. एन. घोष ने परिवर्तनीयता के आधार पर नगरीकरण को परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक गांव कस्बा में तथा एक कस्बा नगर में परिवर्तित होता है।

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण वातावरण त्वरित अथवा मंद गति से नगरीय पर्यावरण में परिवर्तित हो जाता है। इसमें जनसंख्या वृद्धि ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में तीव्र गति से होती है। गांव कस्बों में और कस्बा नगरों में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ गैर

कृषि कार्यों की प्रधानता देखी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र से नगरों की ओर प्रवास तीव्र हो जाता है। यह द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलापों की प्रधानता के साथ तकनीक एवं प्रौद्योगिकी का केंद्र बन जाता है।

13.3 नगरीकरण के दृष्टिकोण

नगरीकरण के निम्नलिखित दृष्टिकोणों की पहचान की गई है –

13.3.1 भौतिक दृष्टिकोण

नगरीकरण के भौतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत केवल नगरीय निर्मित क्षेत्र अथवा नगरीय क्षेत्र में वृद्धि दर को सम्मिलित किया जाता है। यह भूमि उपयोग की विस्तार के साथ ऊर्ध्ववर्ती भारती विकास को प्रदर्शित करता है।

13.3.2 सांस्कृतिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण

इसके अंतर्गत सांस्कृतिक एवं सामाजिक पक्ष के घटकों जैसे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, जल आपूर्ति एवं मनोरंजन इत्यादि सम्मिलित होते हैं। जब ग्रामीण क्षेत्रों में इनका विकास धीरे – धीरे बढ़कर उच्च स्तर तक पहुंच जाता है, तब एक ग्रामीण अधिवास नगरी तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या सांस्कृतिक एवं सामाजिक तत्वों को विकसित करके नगरीय जनसंख्या में परिवर्तित होती है।

13.3.3 आर्थिक दृष्टिकोण

नगरीकरण के आर्थिक दृष्टिकोण में नगर के कार्यात्मक व्यवहारों एवं व्यापारिक संरचनाओं के आर्थिक पहलू का अध्ययन किया जाता है। यह नगर गैर कृषि कार्यों के संपादन के कारण केंद्र स्थल के रूप होते हैं, ये प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन जैसे आर्थिक कार्यों के संपादन से विशिष्ट स्थान प्राप्त करते हैं।

13.3.4 जनांकिकीय दृष्टिकोण

नगरीकरण का जनांकिकीय दृष्टिकोण विविध पक्षों का मानक होता है, इसमें इस बात की माप की जाती है कि एक नगरीय जनसंख्या किसी ग्रामीण जनसंख्या से कितना भिन्न है। इसमें एक नगर से दूसरे नगर की भिन्नता का भी अवलोकन किया जाता है कि वहाँ पर उपलब्ध जनसंख्या और उनके पालन पोषण हेतु उपलब्ध संसाधनों के मध्य कितनी समानता पाई जाती है।

13.4 नगरों के विकास की अवस्था

प्रत्येक नगर किसी ग्रामीण भूदृश्य का परिवर्तित रूप होता है। अपने उद्भव से लेकर विकास की चरम अवस्था में प्रत्येक नगर शीघ्र ही नहीं पहुंचता बल्कि उसका क्रमिक विकास होता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि अपने विकास की प्रक्रिया में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरा हुआ यह चरम अवस्था में पहुंच जाता है। प्रारंभ में एक नगर छोटा गांव या बस्ती के रूप में होता है उसके बाद कस्बा में बदलता है। आकार बढ़ने के साथ – साथ उसके कार्यात्मक स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। जहाँ पहले प्राथमिक क्रियाकलाप संपादित होते थे वहाँ आज गैर कृषि कार्यों की अधिकता देखी जाती है। इस प्रकार विकास की विभिन्न चरणों से गुजरा हुआ वह वृहद नगर में परिवर्तित हो जाता है। नगरों के विकास की अवस्था को विभिन्न विद्वानों ने निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया है–

पैट्रिक गिडीज ने नगरीय विकास की तीन अवस्थाओं की पहचान की है–

1. इयोटेक्निक अवस्था – इस अवस्था की अवधि 1000 ई. से 1800 ई. तक है।
2. पोल्योंटेक्निक अवस्था – इस अवस्था की अवध 1800 ई. से लेकर 1899 ई. तक है।
3. नियोटेक्निक अवस्था – इस अवस्था की अवधि 1900 ई. से लेकर अब तक बताई जाती है।

लुईस ममफोर्ड ने नगरीय विकास की पांच अवस्थाओं की व्याख्या की है –

1. इयोटेक्निक अवस्था – 1000 ई. से शुरू।
2. बारोक अवस्था– मध्यकाल एवं आधुनिक काल के मध्य 16वीं शताब्दी में शुरू।

3. पोल्योंटेक्निक अवस्था – 1800 ई. से शुरू।

4. नियो टेक्निक अवस्था – 1900 ई. के बाद शुरू।

5. बायोटेक्निक अवस्थान – नगरीय जनसंख्या की 25,000 से 50,000 तक की अवस्था।

डेविस किंग्सले ने नगरों के विकास की मात्र तीन अवस्थाओं की पहचान की है–

अ. प्राथमिक अवस्था : ऐसी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होती है। इसकी अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होती है यहाँ नगरी जनसंख्या 25% से कम होती है। विश्व के अधिकांश विकासशील एवं अल्प विकसित देश इसी अवस्था में आते हैं।

ब. त्वरण अवस्था : इस अवस्था में नगरीय जनसंख्या 50% से अधिक पाई जाती है। इस अवस्था में कृषि कार्य शिथिल पड़ने लगते हैं तथा गैर कृषि कार्य जैसे प्रशासन, सेवाएं, परिवहन, संचार, व्यापार आदि तीव्र गति से विकसित होने लगते हैं। ऐसी अवस्था में कभी – कभी नगरीय जनसंख्या का अनुपात 70% तक भी चला जाता है। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण – पूर्व यूरोप तथा दक्षिण पश्चिम एशिया के अधिकांश देश इसमें सम्मिलित हैं।

स. अंतिम अवस्था : इसे नगरीकरण की चरम अवस्था कहा जाता है। इसमें नगरी जनसंख्या का अनुपात 70ः से अधिक पाया जाता है। ऐसी अवस्था में नगरीकरण या तो मंद गति से होता है या स्थिर हो जाता है। कभी – कभी नगरीकरण की दर ह्रासोन्मुख भी हो जाती है। इस अवस्था में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, स्वीडेन, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, हॉलैंड एवं जापान जैसे विकसित देश पाए जाते हैं।

जे. पी. गिब्स ने भी नगरीकरण की पांच अवस्थाओं की पहचान की है –

अ. प्रथम अवस्था

ऐसी अवस्था में नगरीय केंद्रों का विकास होता है तथा जनसंख्या वृद्धि ग्रामीण जनसंख्या के समान होती है।

ब. द्वितीय अवस्था

इस अवस्था में नगरीय सुविधाओं से प्रभावित होकर ग्रामीण जनसंख्या का प्रवास नगरों की ओर होता है। इस कारण नगरों का आकार बड़ा हो जाता है । नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर ग्रामीण क्षेत्र से अधिक हो जाती है।

स. तृतीय अवस्था

ग्रामीण क्षेत्रों में इस अवस्था में प्राकृतिक वृद्धि दर तो तीव्र होती है परंतु प्रवास की तीव्रता के कारण ग्रामीण जनसंख्या में कमी आने लगती है। प्रवास की गति अत्यंत तीव्र होती है।

द. चतुर्थ अवस्था

इस अवस्था में नगरों का आकार बड़ा हो जाता है क्योंकि छोटे नगरों से जनसंख्या का बड़े नगरों की और तीव्र गति से प्रवास होता है। इन नगरों में ग्रामीण क्षेत्र से प्रवास कम देखा जाता है। बड़े नगरों में बेरोजगार एवं श्रम विभाजन मुख्य रूप से देखा जाता है।

य. पंचम अवस्था

ऐसी अवस्था में नगरों के परिधि क्षेत्र में उपनगरों का विकास होने लगता है। प्रशासन, सेवाएं, यातायात तथा संचार सेवाओं की उत्तम व्यवस्था के कारण घनत्व अधिक हो जाता है। घने जनसंख्या वाले क्षेत्र से उप नगरीय क्षेत्र की ओर प्रवास होने लगता है।

13.5 नगरीकरण के प्रभाव

प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक नगरों का विकास बहुत सीमित स्थान पर हुआ था। वर्तमान काल में नगरीय विकास का क्षेत्र बढ़ा है। अब यह राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर तक भी देखे जा सकते हैं। प्रत्येक नगर का विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कारणों से प्रभावित होता है। नगर नवाचार के केंद्र होते हैं

जहाँ से प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी का प्रसार ग्रामीण क्षेत्र की ओर होता है। इस प्रकार नगरीकरण के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव होते हैं।

13.6 नगरीकरण के सकारात्मक प्रभाव

रामकुमार तिवारी अपनी पुस्तक जनसंख्या भूगोल में लिखते हैं कि नगर क्षेत्र मानव सभ्यता के केंद्र होते हैं जहाँ नवीनताएं उद्‌भवित होकर बाहर की ओर प्रसारित होती हैं। इस प्रकार नगरों के सकारात्मक प्रभाव की व्याख्या निम्नलिखित उप शीर्षकों के अंतर्गत की जाती है –

13.6.1 सामाजिक सांस्कृतिक प्रगति

ऐसा माना जाता है कि नगरीय क्षेत्र अग्रगामी एवं उन्नतशील होते हैं जबकि ग्रामीण परिवेश पिछड़े अवस्था में हैं। नगरों में सभी प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक सुविधा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं। इसी कारण यहाँ के निवासी ग्रामीण वासियों की तुलना में अधिक कुशल, दक्ष, शिक्षित, प्रशिक्षित, जागरूक, प्रगतिशील एवं महत्वाकांक्षी होते हैं। यहाँ नवीनतम शोध एवं प्रौद्योगिकी अधिक होते हैं। ये क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों को भी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को गतिशीलता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

13.6.2 श्रम विभाजन तथा व्यावसायिक गतिशीलता

नगरों में श्रम विभाजन के आधार पर कार्यात्मक विशिष्टीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। एस. डी. मौर्य लिखते हैं कि श्रम विभाजन से किसी उत्पादन कार्य को कई उपप्रक्रियाओं में बाटकर प्रत्येक उपप्रक्रिया को कुशल एवं विशिष्ट व्यक्तियों और संसाधनों द्वारा संपन्न किया जाता है। इस प्रकार अंत में संपूर्ण साधनों द्वारा किए गए उत्पादन को मिलाकर आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। अर्थव्यवस्था में समस्त उत्पादन कार्य अनेक चरणों में श्रमिकों की योग्यता, रुचि और कुशलता के अनुसार किया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि उत्पादित वस्तुएं गुणवत्ता में उच्च तथा श्रेष्ठ होती हैं। नगरों में कार्यों की विविधता पाई जाती है, जिसके कारण अलग – अलग कौशल विकास को प्रोत्साहन मिलता है। लोग अपनी योग्यता कुशलता तथा क्षमता के अनुसार व्यावसायों का चयन करते हैं। इस प्रकार व्यावसायिक गतिशीलता से सामाजिक एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है जो चेतना एवं बौद्धिकता को प्रश्रय देता है।

13.6.3 रोजगार में वृद्धि हेतु कार्यात्मक विविधता

नगर बहु कार्यात्मकता के कारण बहुधन्धी भी होते हैं यहाँ अनेकों प्रकार के द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलापों का विकास हुआ है। ऐसी स्थिति में रोजगार के अत्यधिक अवसर उत्पन्न हो जाते हैं। जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक क्रियाकलापों के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्यन एवं खनन जैसे कार्य ही संपन्न होते हैं वहीं नगरीय क्षेत्र में इनकी अधिकता होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आय कम होती है जबकि नगरीय क्षेत्र में आय के स्रोत अधिक होते हैं। नगरीय विकास के कारण उद्योग, व्यापार, परिवहन एवं अन्य सेवाओं से रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। यही कारण है कि नगर ग्रामीण क्षेत्र से अधिक मात्रा में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।

13.6.4 तकनीकी विकास

नगरों के विकास से समाज तकनीकी कुशलता से संपन्न हो जाते हैं। नगरों में विकसित तकनीकी के प्रयोग से ग्रामीण क्षेत्र का उत्थान की प्रगति से होता है। आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करके कृषि कार्य को और आसान बनाने के साथ उत्पादन में कई गुना वृद्धि देखी गई है। उन्नत किस्म के बीज एवं खादों का विकास भी नगरीय क्षेत्र की देन है। कम आगत एवं व्यय से अधिक फायदा कमाया जा रहा है। तकनीकी विकास की परिणामस्वरुप यातायात के साधनों एवं संचार माध्यमों के प्रसार से जनसंख्या में गतिशीलता बढ़ी है। साथ ही अनेकों भौतिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सुविधाओं में वृद्धि हुई है।

13.6.5 आर्थिक प्रगति

विकास के मापन के सूचकों में नगरीकरण भी एक है। नगरीकरण का बढ़ता स्तर संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। इसमें वृद्धि से जहाँ बड़े नगरों में अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या का संकेंद्रण होता है वहीं नए – नए नगरों का भी विकास होता है। ऐसे क्षेत्रों में द्वितीय एवं तृतीय क्रियाएं तीव्रता से विकसित होने लगती हैं। इसमें संलग्न

व्यक्तियों की संख्या भी क्रमशः बढ़ने लगती है। प्राथमिक क्रियाकलापों का महत्व कम होने लगता है शिवदास मौर्य लिखते हैं कि शिक्षा, उद्योग, व्यापार, प्रशासन, परिवहन के साथ अन्य सुविधाओं में तीव्रता से वृद्धि होने लगती है जिस देश में संपन्नता आने लगती है। विकसित देशों की लगभग 75% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। विकासशील देशों में यह जनसंख्या संक्रमण अवस्था में है। देश के आर्थिक विकास में नगरीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास एवं नगरीकरण एक दूसरे के सहचर हैं।

13.7 नगरीकरण के नकारात्मक प्रभाव

नगरीकरण के फलस्वरूप जनसंख्या का एक वृहद भाग एक छोटी से भौगोलिक भूमि में निवास करता है जिसके कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र से होने वाले तीव्र प्रवास के कारण यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर भी तीव्र होती है। ऐसी स्थिति में कुछ अराजक एवं असामाजिक तत्वों के कारण अपराध, बेरोजगारी, गंदगी, भीड़भाड़, दुर्घटनाएं एवं राजनीतिक सट्टेबाजी के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो निम्नलिखित हैं –

13.7.1 भूमि की कमी

तीव्र नगरीकरण के कारण नगरों में प्रशासन, वाणिज्य, व्यापार, खेल तथा मनोरंजन हेतु बड़े – बड़े भवनों एवं मैदानों की आवश्यकता होती है। इनके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में जमीन की जरूरत पड़ती है। नगर के प्रारंभिक अवस्था में तो इन संरचनाओं हेतु पर्याप्त भूमि प्राप्त हो जाती है परंतु बाद की अवधियों में भूमि की धीरे – धीरे कमी होने लगती है। इस कारण आधुनिक तकनीक एवं आवश्यकता के अनुरूप नए संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों के निर्माण में संकट खड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में नगर के केंद्रीय भाग से इनका स्थानांतरण नगरीय उपांत की ओर होने लगता है। यही कारण है कि नगरीय विस्तार के समय कारखाने, विश्वविद्यालय, रेलवे, बाईपास, रिंग रोड, हवाई अड्डा इत्यादि नगर से दूर बसाया जाता है।

13.7.2 आवास का संकट

नगरीय क्षेत्र में प्रशासनिक सुविधाओं के साथ दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है। इसी से प्रेरित होकर ग्रामीण क्षेत्र, उप नगरीय क्षेत्र एवं अन्य नगरों से भी अधिक संख्या में लोग इसके तरफ प्रवास करते हैं। नगरों में होने वाला यह प्रवास मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है स्थायी प्रवास एवं अस्थायी प्रवास। अस्थायी प्रवास की भी दो प्रवृत्ति होती है। पहली एक दिन के लिए दूसरी कुछ दिन के लिए। एक दिन के लिए प्रवास करने वाले लोगों को किसी विशेष आवास या आश्रय की आवश्यकता नहीं होती। ये लोग सुबह आते हैं और कार्य संपन्न करने के पश्चात पुनः अपने घर वापस लौट जाते हैं। इसके अतिरिक्त बाकी लोगों के लिए आवास की आवश्यकता होती है। कुछ दिन के प्रवास के लिए करने वाले लोगों के लिए धर्मशाला, होटल या लाज जैसी और संरचनाओं का विकास करना पड़ता है जबकि स्थायी रूप से निवास करने वाले लोगों के लिए स्थायी आवास की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में अधिक मात्रा में आवासीय भूमि की जरूरत पड़ती है। पर्याप्त आवासीय भूमि की उपलब्धता नहीं होने के कारण मलिन बस्तियों का विकास होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही शौचालय, नालियां, पेयजल एवं परिवहन जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं होने के कारण नगरीय क्षेत्रों में प्रदूषण तीव्रता से बढ़ने लगता है।

13.7.3 परिवहन की समस्या

नगर अपने विकास के प्रारंभिक अवस्था में नियोजित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उसकी सड़कें प्रायः सकरी होती हैं। इसके विकास की प्रारंभिक अवस्था में नागरिकों को इस बात का आभास नहीं होता है कि वर्तमान की सकरी गलियां भविष्य के लिए समस्या बन जाएंगी। विकास प्रक्रिया में नगर का केंद्रीय भाग केंद्रीय औद्योगिक जिले में परिवर्तित हो जाता है। सकरी गलियों के कारण यहाँ बड़े वाहन नहीं पहुंच पाते मात्र पैदल चलकर यहाँ पहुंचा जा सकता है। जगह की कमी के कारण वाहनों के सड़क पर खड़े होने से जाम जैसी समस्या प्रतिदिन देखी जाती है। सड़कों का पर्याप्त रख रखाव नहीं होने के कारण अधिक टूट – फूट देखी जाती है जिसकी मरम्मत एवं नई सड़कों का विकास करके परिवहन समस्या का समाधान किया जा सकता है। सकरी गलियां होने के कारण सेवाओं एवं संसाधनों के प्रति व्यक्तियों तक आपूर्ति में भी कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में बड़े –बड़े वाहनों के बाजार क्षेत्र तक नहीं पहुंचने के कारण परिवहन लागत में वृद्धि होने लगती है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को

महंगाई जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ता है। परिवहन के नए स्टेशन को प्रायः नगर से दूर बसाया जाता है। ऐसी स्थिति में लोगों को दूर आने – जाने के लिए स्टेशन तक पहुंचने में भी बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। कभी – कभी यह समस्याएं लूटपाट, उत्पीड़न एवं बलात्कार जैसी घटनाओं में भी परिवर्तित हो जाती हैं, जिसके कारण नगरीय विकास तो हुआ है परंतु वहाँ पर निवास करने वाली जनसंख्या के लिए यह समस्या कभी – कभी घातक भी बन जाती है।

13.7.4 जल आपूर्ति की समस्या

नगरों के विकास के साथ ही जलापूर्ति के साथ जल निकासी की समस्या भी प्रमुख होती है। सामान्यतः देखा जाता है कि नगरों को पानी की आपूर्ति आसपास के उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदी, झील, झरना यदि से कराया जाता है। ऐसा करने से लागत कम आती है। इसके अतिरिक्त कुछ कृत्रिम उपाय जैसे तालाब, नहर, एवं नलकूप आदि के माध्यम से भी जल उपलब्ध कराया जाता है। ये स्तोत्र नगर के निकट होते हैं परंतु इससे दो प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहली यह बहुत खर्चीले एवं मांगे होते हैं जिसका वहन सभी व्यक्तियों द्वारा कर पाना संभव नहीं होता। यह कार्य यदि सरकार द्वारा भी किया जाता है तो उसे पर भारी कीमत आती है जिसके कारण सरकारें ऐसे कार्यों के प्रबंधन में रुचि नहीं लेती। दूसरा अत्यधिक जल दोहन के कारण भूमिगत जल का स्तर लगातार नीचे गिरता चला जाता है। पर्याप्त निकास की व्यवस्था नहीं होने के कारण जगह – जगह पर पानी इकट्ठा होने से गंदगी और अनियमित प्रवाह जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। इस प्रकार नगरीय क्षेत्रों में बहने वाले गंदे पानी तथा अपशिष्ट नगरी क्षेत्र में कई प्रकार की बीमारियों के कारक बनते हैं। गंदे पानियों का समुचित प्रबंधन नहीं होने के कारण इससे दुर्गंध, बीमारी एवं मच्छरों जैसे अनेक घटक आवास स्थल के निकट केन्द्रित हो जाते हैं जिनका नकारात्मक प्रभाव नगर एवं नगर के बाहर क्षेत्र में रहने वाले मलिन बस्तियों के निवासियों पर देखा जाता है। यह भी देखा जाता है की गंदगी एवं मालीनता के कारण इन क्षेत्रों में मृत्यु दर भी अधिक दर्ज की जाती है।

13.7.5 स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मनोरंजन की समस्या

प्रत्येक व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है या नगरी क्षेत्र में सबके लिए स्वास्थ्य एक मूलभूत आवश्यकता है। इसकी उपलब्धता ग्रामीण एवं नगरी दोनों क्षेत्रों में देखने को मिलती है। नगरीय क्षेत्रों में यह अधिक समस्या बन गई है। नगरी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य की समस्या जनाधिक्य का परिणाम होती है। यहाँ जनसंख्या के अनुपात में न तो स्वास्थ्य केंद्र हैं, न ही डॉक्टर और नहीं मरीज के समुचित इलाज के लिए बेड। लगभग यही हाल शिक्षा क्षेत्र का भी है जहाँ बच्चों के संपूर्ण शिक्षण हेतु आवश्यक शिक्षण संस्थाओं का अभाव देखा जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि अधिक संख्या में विद्यार्थियों को कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाता दूसरी तरफ अपर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता के कारण दाखिला प्राप्त कर लेने वाले छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा भी नहीं मिल पाती है। ऐसी स्थिति में वह जनसंख्या जो देश के लिए संसाधन में परिवर्तित हो सकती थी वह जनभा बनकर रह जाती है।

दिन भर कामों की व्यस्तता से होने वाले मानसिक तनाव को दूर करने में मनोरंजन के साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सभी व्यक्तियों के लिए मनोरंजन की आवश्यकता होती है। नगरी क्षेत्र में पाए जाने वाले सिनेमाघर, पार्क, क्लब, खेल के मैदान, पुस्तकालय इत्यादि मनोरंजन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। नगरों की बढ़ती जनसंख्या के कारण इनका अनुपात बिगड़ता जा रहा है। इसके कारण यहाँ के निवासियों में एकाकीपन, तनाव, चिड़चिड़ापन, जुआ, शराब जैसे असामाजिक तत्वों से प्रभाविता बढ़ती जा रही है। मानसिक एकाकीपन जैसी स्थितियां अनेकों प्रकार के असामाजिक कार्यों को भी प्रोत्साहन देती है, जिससे सामाजिक विकास की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है।

13.7.6 विद्युत आपूर्ति की समस्या

विद्युत को नगरीकरण का प्राण वायु कहा जाता है क्योंकि इसकी अनुपस्थिति में नगरीकरण अभिशाप में परिवर्तित हो जाता है। इसके अभाव में कल – कारखाने, ऑफिस, बड़े उद्योग, घरेलू उपकरण, मेट्रो, रेल गाड़ियां एवं अन्य विद्युत चलित वस्तुएं मृतप्राय हो जाती हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण उसकी मांग उत्पादन से अधिक हो जाने के कारण सभी लोगों तक इनकी आपूर्ति नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में लोगों को जीवाश्म इंधनों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कि प्रदूषण का महत्वपूर्ण कारक होते हैं। प्रदूषण की यह समस्याएं नगरी क्षेत्र में दमा, श्वास या अन्य जैसे अन्य बीमारियों के महत्वपूर्ण कारक बनते हैं।

13.7.7 नगरीय अपशिष्टों के निस्तारण की समस्या

नगरी क्षेत्र में अत्यधिक जन जमाव के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। ऐसी स्थिति में कूड़ा – कचरा, मलमूत्र एवं अपशिष्ट पदार्थों का अधिक मात्रा में उत्पादन समस्या का कारण बनता है। यह स्थिति मुख्यतः नियोजन के अभाव में उत्पन्न होती है। नगर पालिका एवं नगर परिषद में एक तो पर्याप्त मात्रा में सफाई कर्मी भी नहीं उपलब्ध हैं, दूसरी तरफ वे अकुशल तथा आयोग्य भी होते हैं जिसके कारण संपूर्ण अपशिष्टों का यथोचित निस्तारण नहीं हो पाता है। वर्तमान समय में प्लास्टिक से निर्मित थैलियाँ एवं बोतलों के प्रयोग का प्रचलन तीव्रता से बढ़ा है। ये पदार्थ प्राकृतिक रूप से अपक्षय भी नहीं होते है। ऐसे पदार्थ नगर में अपशिष्टों के निर्धारण की समस्या को और विकट बना देते हैं, साथ ही सरकारों द्वारा इनके निस्तारण की समस्या को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती है जितनी दी जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में ये पदार्थ अनेकों बीमारियों के कारक बनते हैं।

13.7.8 पर्यावरण प्रदूषण की समस्या

पर्यावरण मानव के वृद्धि एवं विकास हेतु आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण घटक है। जब इसके प्राकृतिक स्वरूप में गिरावट आ जाता है और यह मानव के वृद्धि एवं विकास में बाधक बनने लगता है तब उसे प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के अंतर्गत मुख्यतः जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण सम्मिलित होते हैं। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में प्रदूषण की समस्या अधिक पाई जाती है। आर. पी. तिवारी लिखते हैं कि नगरी क्षेत्रों में मोटर वाहनों एवं कल कारखानों के अत्यधिक संकेंद्रण के कारण तथा अपशिष्ट विसर्जन के लिए पर्याप्त सीवर प्रणालियों का न होना है। बसाव की दृष्टिकोण से घने क्षेत्रों में लकड़ी, कोयला के जलाने एवं खटालों के बनाने से क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि अनेक गंभीर समस्याओं का पाया जाना नगरी क्षेत्र के लिए आम बात होती है। बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के कारण अनिद्रा, सिर दर्द, बहरापन, उच्च रक्तचाप, घबराहट एवं मानसिक अशांति जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। ऐसी स्थिति में प्रदूषण नगरीकरण का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव होता है।

13.8 भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति

भारतीय संस्कृति की गणना विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में की जाती है। देश के आकार की विशालता तथा संस्कृति में विविधता के कारण यहाँ ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासों के प्रतिरूप संयुक्त रूप से मिलते हैं। ऐसी स्थिति में भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या दो शीर्षकों के अंतर्गत की जाती है।

1. नगरीकरण की कालिक प्रवृत्ति
2. नगरीकरण की क्षेत्रीय अथवा स्थानीय प्रवृत्ति

13.8.1 नगरीकरण की कालिक प्रवृत्ति

कालिक प्रवृत्ति से तात्पर्य होता है नगरों के विकास का ऐतिहासिक कालक्रम। इस दृष्टिकोण से भारत का सबसे प्राचीन नगर सिंधु घाटी सभ्यता है, जो 2,000 ई. पू. विकसित होती है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो इसके दो सुनियोजित केंद्र थे । पर्यावरण परिवर्तन तथा विदेशी आक्रमणों के कारण कालांतर में इस सभ्यता का पतन हो गया और इसके अवशेष पर एक ग्रामीण वैदिक सभ्यता पल्लवित हुई। प्राचीन काल में भारत के अन्य प्रमुख नगर हस्तिनापुर, मगध, इंद्रप्रस्थ, मद्र, विराट, द्रुपद एवं द्वारिका थे। ये सभी नगर महाभारत काल के है। प्राचीन भारत में नगरों का नामकरण विकास, उनके आकार एवं कार्य आदि के आधार पर किया जाता था जैसे राजधानी नगर, धार्मिक नगर, सांस्कृतिक नगर एवं दुर्ग नगर। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य प्राचीन नगर जैसे पाटलीपुत्र, कौशांबी, साकेत, काशी, श्रीनगर, जालंधर, उज्जैन, राजगिरी, तक्षशिला इत्यादि भी थे। प्राचीन काल के उत्तरार्ध एवं मध्यकाल के प्रारंभिक अवस्था में राजपूत काल में दुर्ग नगर स्थापित हुए। यह सभी स्थानीय संस्कृति एवं दशाओं से प्रेरित थे।

1200 ई. से लेकर 1700 ई. तक का काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल एवं मुगल काल के नाम से जाना जाता है। इस दौरान राज्य की सीमा विस्तार, प्रशासन के संचालन एवं सैनिक दक्षता में वृद्धि के लिए भी अनेकों नगरों का विकास हुआ। इस समय विकसित प्रमुख नगर दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, फिरोजाबाद, मुगलसराय, जौनपुर, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु एवं बेलरी इत्यादि थे।

वर्ष 1707 ई. में औरंगजेब की मृत्यु के समय भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। इस अवधि में औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा देश के एक विशाल भूभाग पर प्रशासन स्थापित कर लिया गया था। इसी समय प्रशासनिक, व्यापारिक, औद्योगिक , पर्यटन, सैनिक तथा बंदरगाह नगरों का विकास हुआ जो औपनिवेशिक साम्राज्य के नीव थे। इस अवधि में विकसित प्रमुख नगर दार्जिलिंग, शिमला, नैनीताल, पुणे, मद्रास, बनारस, सूरत, कोलकाता, उज्जैन, नागपुर, जोधपुर इत्यादि थे। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति होने के पश्चात नगरीकरण की प्रवृत्ति में तेजी आई जो आज तक भी जारी है। इस प्रकार आधुनिक तरीके से भारत में नगरीकरण के तीन चरण देखे जाते हैं –

1. मंद नगरीकरण का काल 1901 से 1931 तक,
2. मध्यम नगरीकरण का काल 1931 से लेकर 1961 तक,
3. तीव्र नगरीकरण का काल 1961 से प्रारंभ होकर अब तक।

13.8.1.1 मंद नगरीकरण का काल

आधुनिक काल में नगरीकरण की प्रवृत्ति के कालक्रम का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1901 से 1931 ई. के मध्य नगरीकरण के वृद्धि की प्रवृत्ति अत्यंत मंद रही है। इस अवधि के दौरान तीन दशकों में मात्र दो प्रतिशत की वृद्धि दर से नगरीकरण में वृद्धि हुई। जनगणना से प्राप्त होने वाले आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1901 ई. में नगरीकरण की दर 10.8% थी। इसी प्रकार 1911, 1921 एवं 1931 की जनगणना में नगरीकरण की दर क्रमशः 10.5%, 11.17% एवं 11.1% प्राप्त होती है। ब्रिटिश शासन की अवधि में पड़ने वाले अकाल, विभिन्न प्रकार की बीमारियों के प्रकोप तथा लोगों के स्वास्थ्य के प्रति सरकार के नकारात्मक रवैया के कारण मृत्यु दर तीव्र दर्ज की गई। इन्हीं सभी कारणों का संयुक्त परिणाम था कि जनसंख्या वृद्धि दर मंद रही और नगरी क्षेत्र में भी यह वृद्धि दर मंद रही है।

13.8.1.2 मध्यम नगरीकरण का काल

लोगों में बढ़ती जागरूकता, सरकार द्वारा बीमारियों पर नियंत्रण एवं आर्थिक स्तर में वृद्धि के कारण इस अवधि में नगरीकरण की दर तीव्र प्राप्त होई है। 12% से 18% दर तक बढ़ने वाले नगरीकरण को मध्यम नगरीकरण का काल कहा जाता है। इसी समय उद्योगों का विकास, यातायात के साधनों का प्रसार, बाजार का विकास इत्यादि का प्रभाव नगरों के विकास पर पढ़ने लगा। नगर आधुनिक सुविधाओं एवं सेवाओं के प्रमुख केंद्र थे जिससे प्रभावित होकर लोग नगरों की ओर आकर्षित होने लगे। इन्हीं सभी कारकों का प्रभाव था जहाँ पिछले 30 वर्षों में दशकीय वृद्धि दर मात्र दो प्रतिशत प्राप्त हुई थी, वह एक दशक में प्राप्त हो गई और वर्ष 1941 ई. जनगणना में नगरीकरण की दर 13.86% प्राप्त हुई। इसी प्रकार वर्ष 1951 ई. में 17.2%, 1961 ई. में 17.9% अंकित की गई है। इसी प्रकार यह भी देखा गया है कि नगरों की संख्या में भी वृद्धि हुई है जहाँ वर्ष 1931 ई. में नगरों की संख्या 2049 थी वहीं 1941 ई. में इनकी संख्या बढ़कर 2,202 हो गई। इसी प्रकार 1951 ई. में इनकी संख्या 2,844 दर्ज की गई है।

13.8.1.3 तीव्र नगरीकरण का काल

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण आर्थिक विकास की दर बढ़ने लगी। स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर सरकार ने प्राथमिकता दी, इससे इनका भी विकास दर उच्च हो गया। इन सभी का संयुक्त प्रभाव यह था की मृत्यु दर में तीव्रता से कमी आने लगी तथा जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ गई। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटे गांव बड़े गांवों में तथा बड़े गांव नगरों में परिवर्तित होने लगे। नगरीय जनसंख्या में आशा से अधिक वृद्धि दर्ज की गई। ऐसी दशा में नगरी जनसंख्या बढ़कर 1961 ई. में 17.97% हो गई। इस तीव्रता का क्रम आगे भी जारी रहा और वर्ष 1971 ई. में 19.9%, 1981 ई. में 23. 31%, 1991 ई. में 26.13%, 2001 ई. में 27.8% तथा 2011 की जनगणना में 31.02% नगरीय जनसंख्या दर्ज की गई। इस प्रकार उपरोक्त सभी आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वर्ष 1961 ई. से लेकर 2001 ई. के मध्य जितनी नगरीय जनसंख्या में वृद्धि देखी गई थी, उतनी मात्रा एक दशक अर्थात 2001 से 2011 के मध्य दर्ज की गई। इस प्रकार यह अवधि नगरीकरण के दृष्टिकोण से विस्फोटक मानी जाती है।

13.8.2 नगरीकरण का प्रादेशिक अथवा स्थानिक प्रतिरूप

भारत भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं विविधता की दृष्टिकोण से एक विशाल देश है। इन विविधताओं का यहाँ की सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नता पर भी प्रभाव देखा जाता है। आर्थिक विकास की प्रमुख मानक नगरीकरण के वितरण में भी भारत में बहुत असमानता विद्यमान है। यहाँ जहाँ एक ओर दिल्ली एवं चंडीगढ़ जैसे क्षेत्रों में 97% नगरीकरण पाया जाता है, वहीं हिमाचल प्रदेश में यह मात्र 10% दर्ज किया जाता है। इस 97% से 10% के बीच में विद्यमान असमानता प्रतिशत की व्याख्या निम्न तीन भागों में विभक्त करके की जा सकती है –

13.8.2.1 उच्च नगरीकरण दर वाले राज्य (60:%से अधिक)

इस श्रेणी में भारतवर्ष के ऐसे राज्यों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें नगरीकरण की दर 60% से अधिक है। भारत में ऐसे राज्यों की संख्या सात है। इनमें सर्वोच्च नगरीकरण वाला राज्य दिल्ली है जहाँ नगरीकरण की दर 97.50% प्राप्त होती है। दूसरे स्थान पर नगरीकरण की दृष्टिकोण से चंडीगढ़ है यहाँ भी नगरीकरण की दर 97.25 दर्ज की गई है। उच्च नगरीकरण दर वाले अन्य राज्यों को निम्नलिखित सारणी में व्यक्त किया गया है –

सारणी 13.1 भारत के उच्च नगरीकरण वाले राज्य

क्र. सं.	राज्यों के नाम	नगरीकरण (प्रतिशत में)
1.	दिल्ली	97.50
2.	चंडीगढ़	97.25
3.	लक्ष्यद्वीप	78.08
4.	दमन व दीव	75.16
5.	पांडिचेरी	68.35
6.	गोवा	62.17
7.	ओड़ीसा	60.66

स्त्रोतः जनसंख्या विभाग, लखनऊ.

इनमें दिल्ली जहाँ देश की राजधानी है वहीं चंडीगढ़ भी स्वयं केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ – साथ पंजाब एवं हरियाणा राज्य की राजधानी भी है। ऐसी स्थिति में यह अनेक प्रशासनिक भावनाओं के साथ सेवाओं का संकेंद्रण केंद्र पाया जाता है। वर्तमान समय में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के साथ पर्यटन का विकास होने के कारण यहाँ नगरीकरण की दर उच्च पाई जाती है।

13.8.2.2 मध्यम नगरीकरण दर वाले राज्य (60% से 20% के बीच)

मध्यम नगरीकरण का प्रतिशत उन राज्यों में प्राप्त होता है जहाँ नगरीकरण की दर 20% से 60% के मध्य प्राप्त होती है। सामान्य अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह राज्य नगरीकरण की ओर तीव्र गति से बढ़ रहे हैंक्योंकि यहाँ उद्योगों के साथ – साथ कृषि एवं कृषि आधारित अन्य क्रियाकलापों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस श्रेणी में पाए जाने वाले राज्यों को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है –

सारणी 13.2 भारत के मध्यम नगरीकरण वाले राज्य

क्र. सं.	राज्यों के नाम	नगरीकरण (प्रतिशत में)
1.	तमिलनाडु	48.45
2.	केरल	47.72
3.	महाराष्ट्र	45.23
4.	गुजरात	42.58
5.	कर्नाटक	38.57
6.	पंजाब	37.49
7.	हरियाणा	34.79
8.	आन्ध्र प्रदेश	33.44
9.	पश्चिम बंगाल	31.80
10.	मणिपुर	30.21
11.	नागालैण्ड	28.97
12.	मध्य प्रदेश	27.63
13.	जम्मू कश्मीर	27.21
14.	त्रिपुरा	26.18
15.	सिक्किम	24.97
16.	राजस्थान	24.89
17.	झारखण्ड	24.05
18.	छत्तीसगढ़	23.24
19.	उत्तर प्रदेश	22.28
20.	अरुणाचल प्रदेश	22.69
21.	मेघालय	20.08

स्त्रोतः जनसंख्या विभाग, लखनऊ.

13.8.2.3 निम्न नगरीकरण दर वाले राज्य (20% से कम)

20% से कम नगरीय जनसंख्या का प्रतिरूप दर्शाने वाले राज्यों को निम्न नगरीकरण का राज्य कहा जाता है। इन राज्यों में प्राकृतिक अवरोधों के साथ ही मानवीय संसाधनों का भी पूर्णतः विकास नहीं हो पाया है जिसके कारण नगरीकरण में वृद्धि नहीं हुई है। इस श्रेणी में भारतवर्ष के तीन राज्य असम 14.08%, बिहार 11.31% तथा हिमाचल प्रदेश 10.5% सम्मिलित हैं। इनमें असम एवं हिमाचल प्रदेश जहाँ पहाड़ी राज्य हैं वहीं बिहार एक उद्योग विहीन कृषि प्रधान राज्य है (तिवारी 2023)।

13.9 भारत में नगरीकरण की आकारकीय श्रेणी

नगरों का विभाजन कई मानकों के आधार पर किया जाता है। कुछ विद्वानों ने इसका वर्गीकरण कार्यात्मकता या उपयोगिता के आधार पर की है तो कुछ ने जनसंख्या के आधार पर भारत में नगरों के आकारकीय का वर्गीकरण किया है। भारतीय जनगणना विभाग द्वारा जनसंख्या को आधार बनाया गया है। जनसंख्या की आधार पर इसने 6 प्रकार के नगरों की श्रेणियां बताई है –

1. प्रथम श्रेणी के नगर – 100,000 से अधिक जनसंख्या।
2. द्वितीय श्रेणी के नगर – 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या।
3. तृतीय श्रेणी के नगर – 20,000 से 49,999 तक की जनसंख्या।
4. चतुर्थ श्रेणी के नगर – 10,000 से 19,999 तक की जनसंख्या।
5. पंचम श्रेणी के नगर – 5,000 से 9,999 तक की जनसंख्या।
6. षष्टम श्रेणी के नगर – 5000 से कम जनसंख्या।

इन प्रमुख नगरों की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से की गई है

13.9.1 प्राथमिक श्रेणी के नगर

प्राथमिक श्रेणी का नगर ऐसे नगरों को कहा जाता है जिनकी जनसंख्या 100,000 से अधिक होती है। वर्ष 1901 ई की गणना में ऐसे नगरों की संख्या 24 थी, जो वर्ष 1921 में 29, वर्ष 1941 में 49, वर्ष 1961 में 192 हो गई। इसी प्रकार वर्ष 2001 की जनगणना में इस प्रकार के नगरों की संख्या बढ़कर 315 हो गई। निरंतर जनसंख्या वृद्धि के कारण इनका एक वर्ग स्वतः बन जाता है जिन्हें 10 लाखी नगर कहा जाता है। जब किसी नगर की जनसंख्या 100,000 से बढ़कर 10 लाख हो जाती है तो उसे 10 लाखी नगर के नाम से जाना जाता है। जहाँ वर्ष 1901 ई. की जनगणना में मात्र एक 10 लाखी नगर कोलकाता था वहीं वर्ष 1951 ई. की जनगणना में इनकी संख्या बढ़कर चार हो गई जिनके नाम है दिल्ली, कोलकाता, मद्रास एवं हैदराबाद है। इसी प्रकार वर्ष 2001 ई. की जनगणना में ऐसे नगरों की संख्या 35 प्राप्त होती है जबकि वर्ष 2011 ई. की जनगणना में इनकी संख्या बढ़कर 53 हो गई।

13.9.2 द्वितीय श्रेणी के नगर

द्वितीय श्रेणी के नगरों की जनसंख्या एक लाख से कम परंतु 50,000 से अधिक प्राप्त होती है। नगरीकरण की गति का यदि अवलोकन किया जाए तो इनकी गति सबसे तीव्र है। ऐसे नगरों की संख्या वर्ष 1901 ई. में जहाँ 45 थी वहीं 1951 ई. की जनगणना में इनकी संख्या दो गुनी हो गई। वर्ष 2001 ई. की जनगणना में पुनः इनकी संख्या बढ़कर 375 प्राप्त होती है।

13.9.3 तृतीय श्रेणी के नगर

तृतीय श्रेणी के नगरों की जनसंख्या 50,000 से कम तथा 20,000 से अधिक होती है । वर्तमान समय में इन नगरों में भी तीव्र वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जा रही है परंतु इनके नगरीकरण की गति द्वितीय श्रेणी के नगरों से कम है। वर्ष 2001 ई. की जनगणना में संपूर्ण देश में ऐसे नगरों की संख्या 893 दर्ज की गई थी। वर्ष 1901 ई. की जनगणना में इनकी संख्या वर्ष उनकी संख्या जहाँ 130 थी वहीं अगले चार दशकों में इनकी संख्या पुनः दोगुनी हो

जाती है। पुनः अगले चार दशक अर्थात 1981 ई. में इनकी संख्या तीन गुना बढ़कर 738 प्राप्त होती है। इस प्रकार सामान्य अवलोकनों से यह क्या होता है कि वर्ष 1901 से 2001 ई. के बीच इनकी संख्या में वृद्धि 8 गुना से अधिक हुई है।

13.9.4 चतुर्थ श्रेणी के नगर

इस श्रेणी के नगरों की जनसंख्या 10,000 से अधिक तथा 20,000 से कम होती है। ऐसे मध्यम श्रेणी के नगरों की वृद्धि की गति अपेक्षाकृत कम होती है। ये नगर विकासशील अर्थव्यवस्था की बोधक होते हैं। वर्ष 1901 ई. की जनगणना से प्राप्त आंकड़ों में इनकी संख्या 390 प्राप्त हुई थी, जो बढ़कर वर्ष 2001 ई. की जनगणना में 1076 हो गई।

13.9.5 पंचम श्रेणी के नगर

इन नगरों में जनसंख्या का आकार 5,000 से 10,000 के मध्य दर्ज किया जाता है। ऐसे छोटे नगरों की वृद्धि दर अत्यंत मंद होती है। आंकड़ों से ज्ञात होता है कि जहाँ वर्ष 1901 ई. में इन नगरों की संख्या 744 दर्ज की गई थी वहीं 100 साल बाद भी वर्ष 2011 ई. की जनगणना में इनकी संख्या मात्र 745 प्राप्त होती है।

13.9.6 षष्टम श्रेणी के नगर

नगरीकरण का यह सबसे छोटा स्वरूप है। इनकी जनसंख्या 5,000 पाई जाती है। इन्हें जनगणना नगर के नाम से भी जाना जाता है। जनगणना में उनके लिए निम्नलिखित तीन मानक बताए गए हैं –

- इनकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो।
- यहाँ जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो।
- कार्यशील पुरुष जनसंख्या का 75% भाग गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो।

ऐसे नगरों की संख्या निरंतर घट रही है। जहाँ इनकी संख्या वर्ष 1901 ई. की जनगणना में 479 थी वहीं वर्ष 1931 ई. की जनगणना में बढ़कर 509, वर्ष 1951 ई. की जनगणना में इनकी संख्या बढ़ कर 569 हो गई। इसके पश्चात निरंतर ह्रास की प्रवृत्ति देखी जा रही है। वर्ष 2001 ई. की जनगणना में इनकी संख्या घटकर मात्र 177 रह गई है। ग्रामीण जनसंख्या का तीव्र गति से बड़े नगरों की ओर प्रवास के कारण इनकी जनसंख्या निरंतर घटती जा रही है।

13.10 भारतीय नगरीकरण की विशेषताएँ

उपरोक्त अध्ययन के पश्चात भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति की निम्नलिखित विशेषताएं देखी गई है –

1. भारतीय नगरीकरण का इतिहास लगभग 4,000 वर्ष पुराना है। प्राचीन काल में भी भारत में विकसित नगर के साथ मिलते हैं।
2. भारत में नगरीकरण की दर वर्ष 1931 ई. तक तो धीमी थी, परंतु इसके पश्चात तीव्र गति से बढ़कर आधुनिक स्तर तक पहुंची है।
3. भारत के नगरों में जनसंख्या की वृद्धि प्राकृतिक वृद्धि का परिणाम नहीं है बल्कि ग्रामीण क्षेत्र से जनसंख्या का तीव्र गति से नगरों की ओर प्रवास का प्रतिफल है।
4. पश्चिमी देशों की तरह भारत का नगरीकरण औद्योगिक विकास का अनुसरण नहीं करता है। यहाँ औद्योगिक करण नहीं होने की दशा में भी तृतीय एवं चतुर्थक क्रियाकलापों के उत्प्रेरण से तीव्रता से नगरीकरण हो रहा है। ऐसे कारकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, परिवहन, व्यापार एवं मनोरंजन इत्यादि देखे जाते हैं।
5. भारत में कस्बा गांव बनते जा रहे हैं। प्रत्येक जनगणना के दौरान उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। साथ ही जनसंख्या के जुड़ने से नगरों की श्रेणी में भी परिवर्तन हो रहा है।

6. भारत में महानगरीकरण की प्रवृत्ति में तीव्रता देखी जा रही है। ऐसी स्थिति में लोग छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहरों की ओर तीव्रता से प्रवास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में छोटे नगरों की वृद्धि मंद गति हो रही है जबकि बड़े नगरों की तीव्र गति से।

7. रामकुमार तिवारी लिखते हैं कि नगरों में जनसंख्या का संकेंद्रण नगरीय सुविधाओं एवं कार्यों की उपलब्धता के साथ श्रम की मांग नहीं है क्योंकि ऐसा होता तो वहाँ बेरोजगारी नहीं होती बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त निर्धनता एवं बेरोजगारी का परिणाम होती है।

13.11 सारांश

आपने इस इकाई में नगरीयकरण का अर्थ, नगरीयकरण के प्रभाव एवं भारत में नगरीयकरण का अध्ययन किया है। आप समझ गए होगें कि नगरीयकरण किसी देश के विकास का बोधक होता है और नगरीयकरण तथा किसी देश की विकास की अवस्था में घनिष्ट संबंध होता है। नगरीयकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो प्राचीन काल से अब तक अनवरत रूप से चल रही है। नगरीयकरण की अनेक अवस्थाएँ होती है, जिसमें कुछ नगरों का उद्‌भव होता है तो कुछ का पतन। वास्तव में किसी देश का नगरीयकरण उसकी भौगोलिक अवस्थिति, सरकारी नीतियों, सांस्कृतिक संगठन एवं विकास की अवस्था आदि का परिणाम होती है। भारत में नगरीकरण का इतिहास बहुत प्राचीन है जिसके साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते है। उसके पश्चात अनेक प्राचीन एवं मध्यकालीन समय के नगर प्राप्त होते है। आधुनिक काल में स्वतंत्रता से पूर्व नगरीयकरण की प्रवृत्ति बहुत ही मंद थी। स्वतंत्रता के पश्चात नगरीयकरण की गति तेज हुई है और वर्तमान समय में देश में दसलाखी जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 53 हो गई है।

13.12 स्वमूल्यांकन प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

1. लुईस ममफोर्ड ने नगरीय विकास की कितनी अवस्थाएँ बताई है।

   (क) 5 (ख) 4 (ग) 7 (घ) 6

2. पैट्रिक गिडीज ने नगरीय विकास की कितनी अवस्थाएँ बताई है।

   (क) 4 (ख) 5 (ग) 3 (घ) 7

3. भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन है।

   (क) सिंधु घाटी सभ्यता (ख) काशी (ग) पाटलिपुत्र (घ) कांधार

4. आधुनिक भारत में मंद नगरीकरण की अवधि कब देखी गई है।

   (क) 1901 से 1931 (ख) 1931 से 1951 (ग) 1961 से 1981 (घ) 1991 से 2011

5. नगरीकरण के आकारकीय की श्रेणी के आधार पर भारत में नगरों के कितने प्रकार पाए जाते है।

   (क) 4 (ख) 5 (ग) 6 (घ) 7

13.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

Bogue] D- J-] 1969] Principles of Demography] John Wiley] N-Y-

Clarke] John I-] 1973] Population Geography] Pergaman Press] Oxford-

Crook] Nigel] 1997] Principles of Population and Development] Pergaman Press] N- Y-

Garmier] J- B-] 1970] Geography of Population] Longman] London-

Mamoria] C- B-] 1981] India's Population Problem] Kitab Mahal] New Delhi-

Premi] M- K-] 1991] India's Population] Heading Towards a Billion] B- R- Publishing Corporation-

Blassoff] M- and Srinivasan K-] 2001] Population Development Nexus in India : Challenges for the New Millennium] Tata McGraw Hill] New Delhi-

Woods] R-] 1979] Population Analysis in Geography] Longman] London-

Zelinsky] W-] 1966] A Prologue to Population Geography] Prentice Hall-

चन्दना, आर. सी., 2022, जनसंख्या भूगोल – संकल्पना, नियंत्रक व विश्व प्रारूप, कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

चन्दना, आर. सी., 2022, भारत : जनसंख्या (जनसंख्या भूगोल – भाग 2), कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

मौर्या, एस. डी., 2005, जनसंख्या भूगोल, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद.

ओझा, आर. पी., 1984, जनसंख्या भूगोल, प्रतिभा प्रकाशन.

हीरा लाल, 2000, जनसंख्या भूगोल के मूल तत्व, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली.

तिवारी, राम कुमार, 2023, जनसंख्या भूगोल, प्रवालिका पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद.

13.14 अभ्यास प्रश्न (सत्रांत परीक्षा की तैयारी)

1. नगरीकरण को स्पष्ट कीजिए तथा उसके दृष्टिकोण को बताइए?
2. नगरों की विकास की अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए?
3. नगरीकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए?
4. भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए तथा आकारकीय के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए?

इकाई–14 माल्थस का जनसंख्या सिद्धान्त, नव माल्थसवाद, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त

इकाई की रूपरेखा

14.0 प्रस्तावना

14.1 उद्देश्य

14.2 जनसंख्या सिद्धान्त

14.3 माल्थस का जनसंख्या सिद्धान्त

14.4 नव माल्थसवाद जनसंख्या सिद्धान्त

14.5 अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त

14.6 सारांश

14.7 स्वमूल्यांकन प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

14.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

14.9 अभ्यास प्रश्न (सत्रांत परीक्षा की तैयारी)

14.0 प्रस्तावना

यद्यपि अध्ययन के क्षेत्र में जनसंख्या की समस्या नवीनतम नहीं है। मानवीय सभ्यता के विकास के साथ – साथ यह विविध स्वरूपों में समय – समय पर अध्ययन का विषय रही है। प्राचीन काल से विभिन्न विद्वानों ने तत्कालीन समय से जोड़ कर इसके प्रभाव की व्याख्या करने का प्रयास किया है । माल्थस ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आकड़ों के आधार पर जनसंख्या से संबन्धित सिंद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने जनसंख्या की समस्याओं का वैज्ञानिक विश्लेषण भी प्रस्तुत किया था। इसके पश्चात अनेक समाज वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों एवं उत्तरवर्ती विचारकों ने अपनी मान्यताओं एवं विचार के आधार पर आलोचनाएँ की तथा संशोधित विचार भी दिए। जनसंख्या अध्ययन के इतिहास में प्लेटो ने सर्वप्रथम जनसंख्या एवं संसाधन के संबंध पर विचार प्रकट किया था। इसके पश्चात अनेकों विद्वानों ने अलग – अलग समयों पर अपने विचार प्रकट किए तथा तत्कालीन समाज के लिए उपलब्ध संसाधनों और समस्याओं को प्रकट करने का प्रयास किया।

14.1 उद्देश्य

जनसंख्या में वृद्धि होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों की वहन क्षमता से अधिक हो जाती है तब अनेक समस्याएँ उत्पन्न होने लगती है। इसी परिप्रेक्ष्य में विभिन्न विद्वानों द्वारा समय – समय पर जनसंख्या का अध्ययन किया गया। उसके पश्चात जनसंख्या से संबन्धित कुछ नियम भी प्रतिपादित किए गए हैं। इस इकाई के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है –

1. माल्थस के जनसंख्या सिद्धान्त की व्याख्या करना।
2. नव माल्थसवाद जनसंख्या सिद्धान्त की विवेचना करना।
3. अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त की प्रासंगिकता का वर्णन करना।

14.2 जनसंख्या सिद्धान्त

अतः ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि जनसंख्या संबन्धित जो भी सिद्धान्त प्रकट किए गए हैं उन्हें तीन प्रमुख एवं नौ गौण वर्गों में विभक्त कर अध्ययन किया जाता है –

अ) माल्थस से पहले जनसंख्या सिद्धान्त

1. जनसंख्या पर प्राचीन विद्वानों के विचार
2. जनसंख्या पर वणिकवादी विद्वानों के विचार
3. जनसंख्या पर निर्वाधवादी विद्वानों के विचार

ब) माल्थस के समकालीन जनसंख्या सिद्धान्त

4. माल्थस का जनसंख्या सिद्धान्त
5. नव माल्थसवादी जनसंख्या सिद्धान्त

स) माल्थस के पश्चात जनसंख्या पर सिद्धान्त

6. अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धान्त
7. जनसंख्या का जैविक सिद्धान्त
8. जनसंख्या का सामाजिक सिद्धान्त
9. जनांकिकीय संक्रमण सिद्धान्त

उपरोक्त सिद्धांतों में से माल्थस का जनसंख्या सिद्धान्त एवं नव माल्थसवादी जनसंख्या सिद्धान्त अध्ययन की प्रासंगिकता की दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।

14.3 माल्थस का जनसंख्या सिद्धान्त

राबर्ट माल्थस एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री एवं इतिहासकर थे। इनका जन्म 14 फरवरी 1766 ई. में ब्रिटेन में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा 18 वर्ष की आयु तक घर से ही प्राप्त की थी, इसके पश्चात उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कैम्ब्रिज के जेसस कालेज में दाखिला लिया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने इसी कालेज में वर्ष 1793 ई. में अध्यापन कार्य शुरू किया और प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। कुछ दिन तक अध्यापन करने के पश्चात वर्ष 1804 ई. में उन्होंने हैलबरी कालेज में प्रोफेसर पद पर कार्यभार ग्रहण किया तथा वर्ष 1834 ई. में अपनी मृत्यु तक बने रहे।

माल्थस के जनसंख्या सिद्धान्त पर तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों एवं उनसे जुड़ी मान्यताओं और लेखों का अधिक प्रभाव पड़ा। सम्पूर्ण यूरोप में 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में खाद्यान्नों के मूल्य में निरंतर वृद्धि, भुखमरी, निर्धनता एवं बेरोजगारी आदि की भीषण स्थितियाँ देखी गई। इंग्लैंड समेत यूरोप के सभी देश युद्ध में लगे थे जिसके कारण तत्कालीन समय में अकाल एवं भुखमरी की स्थिति भयंकर होती जा रही थी। औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप जहाँ पूंजीपति वर्ग की प्रभुता बढ़ती जा रही थी वहीं दूसरी ओर निम्नवर्गीय जनसंख्या एवं श्रमिकों में निर्धनता एवं बेरोजगारी का चक्र बढ़ता चला जा रहा था। माल्थस के चिंतन एवं लेखनी पर तत्कालीन लेखकों राबर्ट वेलास, वाल्टर रैले, मैथ्यू हेल, जोसेफ टाऊनसेंड एवं विलियम गाडविन आदि के लेखों एवं विचारों का प्रभाव देखा गया। सर वाल्टर रैले ने अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में वर्णित किया है कि यदि युद्ध और बीमारियाँ नियंत्रण नहीं लगाती तो उस समय जनसंख्या इतना अधिक बढ़ जाती की उनका भरण – पोषण हो पाना ही कठिन था। मैथ्यू हेले ने अपनी प्रसिद्ध कृति मानवता की आदिम उत्पत्ति में लिखा है कि सामान्यतः जनसंख्या में वृद्धि मृत्यु कि संख्या से ज्यादा होती है एवं यदि इस पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो जनसंख्या बढ़ती ही जाएगी। उन्होंने जनसंख्या में गुणोत्तर दर से वृद्धि की मान्यता को स्वीकार किया तथा बताया कि आने वाले प्रति 34 वर्षों में जनसंख्या दो गुनी हो जाती है। विलियम गाडविन ने वर्ष 1793 ई. में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'Enquiry Concerning Political Justice and its influence on Morals and Happiness' में वर्णन किया है कि जनता की

दरिद्रता तथा दुःखों के लिए सरकार की नीतियाँ उत्तरदायी होती हैं। वह जनसंख्या वृद्धि को उचित ठहराता है तथा उसकी मान्यता है कि मानवजाति स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर है तथा जनसंख्या वृद्धि से हानि की अपेक्षा लाभ की संभावना है।

माल्थस जिस समय में अध्यापन कार्य में संलग्न थे तथा हैलबरी कालेज में थे उस समय उन्होंने महसूस किया कि पूरे विश्व में जनसंख्या का भार दिन – प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। आयरलैण्ड में उसी समय भयंकर अकाल पड़ा था जिसके कारण खाद्यपदार्थों के मूल्य में काफी वृद्धि होती जा रही थी। आर्थिक दशाएँ लगातार बिगड़ती जा रही थी जिससे सम्पूर्ण समाज बदहाल था। लोगों की भीड़ बेकार, भूखी एवं आर्थिक तंगी से बदहाल थी। बीमारी, महामारी, निर्धनता के साथ युद्ध के माहौल चारो तरफ दिखाई दे रहे थे। समाज श्रमिक वर्ग एवं पूंजीपति वर्ग में विभक्त था। पूंजीपति वर्ग के शोषण से समाज तड़प रहा था। ऐसे समय एवं परिस्थितियों से प्रभावित होकर माल्थस ने इसका समाधान ढुढ़ने का प्रयास किया। इसी पृष्टभूमि में जून 1798 ई. में उसका एक निबंध प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था 'essay on Principle of Population : As its Affects the Future Improvement of Society'- इस निबंध में उन्होंने तत्कालीन जनसंख्या के समक्ष पाई जाने वाली समस्याओं का तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत किया जिसने लोगों को बहुत प्रभावित किया। लोगों की स्वीकार्यता तथा प्रेरणा से प्रेरित होकर माल्थस ने 1803 ई. में अपना दूसरा निबंध लिखा जो 'An Essay on the Principles of Population : or a View of its Past and Future Effects on Human Happiness' शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस निबंध में उन्होंने जनसंख्या वृद्धि एवं परिवर्तन तथा सामाजिक – आर्थिक समस्याओं से जुड़े तथ्यों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उनके अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मानवतावादी दृष्टिकोण था तथा जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं के लिए अनुभववादी परंपरा का अनुसरण किया। इस प्रकार माल्थस ने सर्वप्रथम जनसंख्या और उससे जुड़ी समस्याओं के लिए एक तार्किक सिद्धान्त प्रस्तुत किया।

14.3.1 सिद्धान्त की प्रमुख मान्यताएँ

राबर्ट माल्थस ने इंग्लैण्ड समेत यूरोप के अन्य देशों से प्राप्त आकड़ों, अनुभव तथा पर्यवेक्षण के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकाला उसे माल्थस का जनसंख्या सिद्धान्त के नाम जाना गया। माल्थस ने जनसंख्या संबंधी अपने निबन्ध में निम्नलिखित मान्यताओं का अनुसरण किया –

1) मनुष्य की कामवासना यथास्थिर एवं स्थायी होती है। इसकी संतुष्टि भी आवश्यक होती है, जिसका प्रतिफल संतानोत्पत्ति होती है।

2) मनुष्य में संतान उत्पन्न करने की क्षमता अपरिमित होती है।

3) आर्थिक संपन्नता और संतानोत्पत्ति में सीधा संबंध पाया जाता है। संपन्नता से संतानोत्पत्ति में वृद्धि होती है।

4) मानव जाति के लिए खाद्यान्न एक आवश्यक वस्तु है।

5) कृषि में उत्पत्ति ह्रास का नियम लागू होता है।

14.3.2 सिद्धान्त की व्याख्या

इन मान्यताओं को आधार मानते हुए माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। उनका काहना था कि एक निश्चित अवधि उत्पादन पद्धति कि नियत दशा के तहत आजीविका के साधनों की अपेक्षा जनसंख्या में तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति देखी जाति है। नियंत्रण के अभाव में जनसंख्या ज्यामितीय (गुणोत्तर) अनुपात में बढ़ती है, वहीं जीवन निर्वाह क्षमता में वृद्धि समांतर (अंकगणितीय) रूप में होती है। इस प्रकार जनसंख्या की वृद्धि दर निर्वाह क्षमता की वृद्धि दर से अधिक देखी जाती है। इसके फलस्वरूप वह शीघ्र ही जीवन निर्वाह क्षमता की तुलना में अधिक हो जाति है। इस प्रकार माल्थस द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त की व्याख्या निम्न शीर्षकों के अंतर्गत की जाती है –

14.3.2.1 जनसंख्या वृद्धि की गुणोत्तर दर

माल्थस का मानना था कि मानव में विपरीत लिंगों में काम भावना बनी रहती है, जिसके कारण संतानोत्पत्ति होना स्वाभाविक है। यदि जनसंख्या पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया तो उसमें ज्यामितीय अनुपात में वृद्धि होती रहेगी जो कि खाद्य सामाग्री की तुलना में अधिक तीव्र होगी। इसकी तीव्रता इतना अधिक होती है कि

वह लगभग 25 वर्षों में ही दोगुनी हो जाती है। उनका मानना है कि यदि इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ती रही तो आने वाले 200 वर्षों में जनसंख्या में 256 गुना वृद्धि भी हो सकती है। माल्थस के अनुसार ज्यामितीय वृद्धि निम्न प्रकार से होती है –

1 : 2 : 4 : 8 : 16 : 32 : 64 : 128 : 256

14.3.2.2 खाद्य पदार्थों में अंकगणितीय वृद्धि

माल्थस का मानना था कि खाद्य समग्रियों की वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि के विपरीत होती है। खाद्यान्न की आपूर्ति जनसंख्या की तुलना में धीरे – धीरे होती है। खाद्य संसाधन जनसंख्या की तरह ज्यामितीय दर से नहीं बढ़ते बल्कि उनमें वृद्धि गणितीय दर से होती है। गणितीय वृद्धि का अर्थ निम्नलिखित है –

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10

माल्थस के अनुसार खाद्य आपूर्ति का संबंध फसलों के उत्पादन से है। कृषि उत्पादन में ह्रास का नियम लागू होता है । कृषि उत्पादन में घटोत्तरी की प्रवृत्ति देखी जाती है। इसके बढ़ने की एक निश्चित सीमा होती है परंतु जनसंख्या वृद्धि की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। वे लिखते हैं कि जब जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ कर 256 के स्तर पर पहुँच जाएगी तब तक खाद्यान्नों की अंकगणितीय वृद्धि केवल 9 तक होगी।

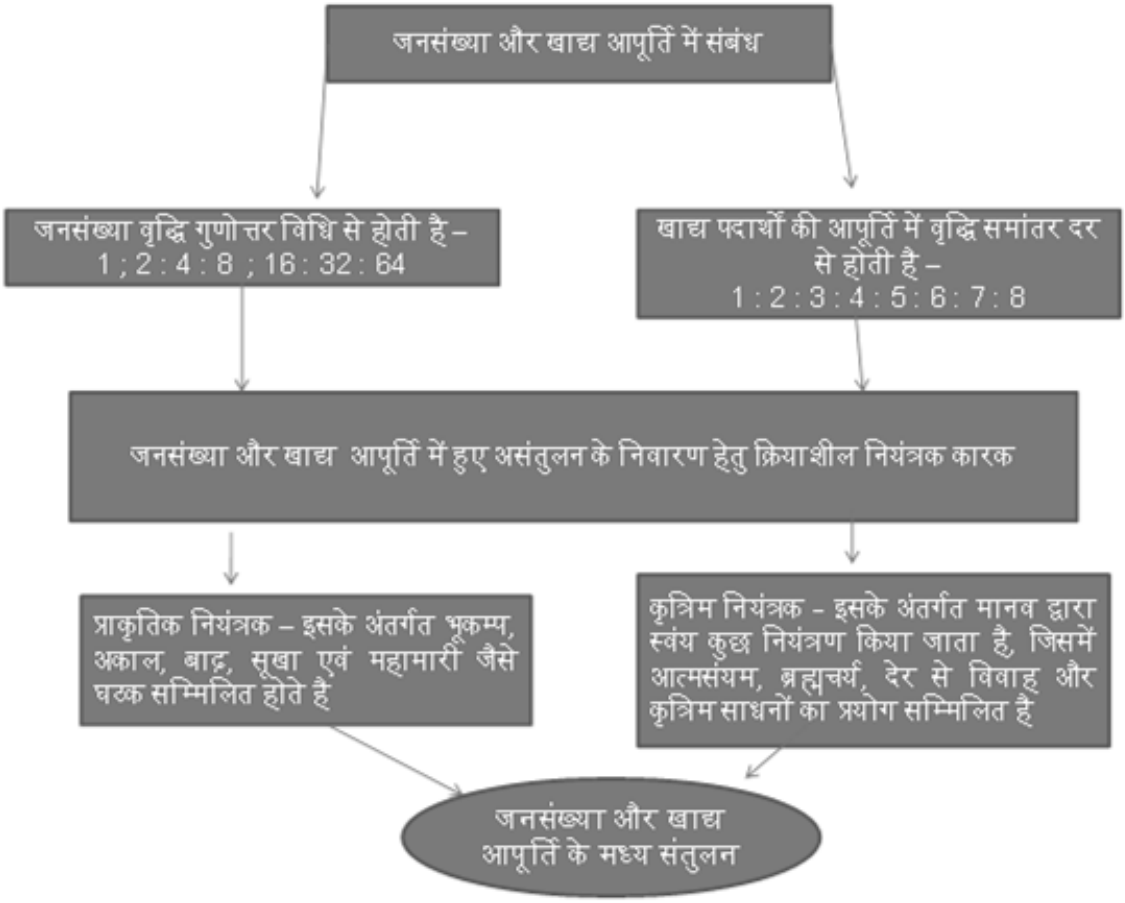

चित्र संख्या 14.1 माल्थस के जनसंख्या सिद्धान्त का आरेखीय प्रदर्शन.

14.3.2.3 जनसंख्या एवं खाद्य पदार्थों के मध्य असंतुलन

माल्थस ने बताया है कि मानव कि खाद्य सामग्री में वृद्धि धीरे – धीरे अंकगणितीय दर से होती है जबकि जनसंख्या में तीव्रता से ज्यामितीय दर वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में खाद्यान्नों की वृद्धि दर तथा जनसंख्या के वृद्धि

में अंतर के कारण दोनों में अंतराल बढ़ता जाता है। इसके फलस्वरूप जनसंख्या और आजीविका के साधनों के मध्य असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि 200 वर्षों के पश्चात खाद्यान्नों की आपूर्ति और जनसंख्या के मध्य अनुपात 9:256 होगा जबकि 300 वर्षों के बाद यह 13:4096 हो जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि माल्थस एक निराशावादी व्यक्ति थे जो मानते थे कि जनसंख्या की स्वभाविक वृद्धि में अवरोध या नियंत्रण यदि नहीं उपस्थित हुआ तो जनसंख्या खाद्यान्न पदार्थों की तुलना तीव्रता से बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप भुखमरी, निर्धनता, गरीबी, बेरोजगारी, एवं भ्रष्टाचार जैसी कष्टकारी दशाएँ उत्पन्न हो जाती है। इसी को संदर्भित करते हुए माल्थस ने कहा है कि प्रकृति की खाने की मेज सीमित अतिथियों के लिए है अतः बिना निमंत्रण आने वालों को अवश्य ही भूखा मरना पड़ेगा।

14.3.2.4 जनसंख्या वृद्धि पर प्रतिबंध

माल्थस का मानना है कि बढ़ती जनसंख्या को यदि समय रहते रोका नहीं गया तो निश्चित ही यह जनसंख्या खाद्यसामग्रियों की वहाँ की क्षमता से अधिक हो जाएगी। सामान्य स्थिति का तो मानना है जनसंख्या उतनी ही रह सकती है जितनी खाद्यसामाग्री की उपलब्धता है। ऐसी अवस्था में संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रकृति की ओर से स्वंय जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाए जाने की कोशिश की जाती है। माल्थस का इस विषय पीआर मानना है कि ईश्वर स्वंय जनसंख्या एवं खाद्यान्न के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। ईश्वर जनसंख्या को संतुलित करने के लिए भुखमरी, महामारी, बाढ़, अकाल, अनावृष्टि जैसे उपकरणों का प्रयोग करता है। प्रकृति द्वारा जनसंख्या नियंत्रण को माल्थस ने नैसर्गिक अवरोध का नाम दिया है, इसके विपरीत जनसंख्या नियंत्रण हेतु मानव जाति द्वारा जो नियंत्रण लगाया जाता है उसे प्रतिबंधक अवरोध कहते हैं।

प्रतिबंधक अवरोध में जनसंख्या पर नियंत्रण मनुष्य अपनी बुद्धि एवं विवेक की श्रेष्ठता के कारण अपनाता है क्योंकि मानव एक चिंतनशील एवं विवेकशील प्राणी है। वह जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण दो प्रकार से लगाता है –

अ) माल्थस नैतिक अवरोध की संकल्पना को जनसंख्या नियंत्रण का प्रमुख आयाम मानते है। इसके अंतर्गत तीन उपायों को प्रमुखता से स्वीकार किया जाता है जो हैं – विवाह नहीं करना, विवाह में विलम्ब और वैवाहिक जीवन को संयमित व्यतीत करना। ये अवरोध सामाजिक एवं नैतिक दृष्टिकोण से अच्छे होते है तथा इनमें कहीं भी कुरीति एवं अवांछनीयता नहीं होती है।

ब) माल्थस का मानना है कि जनसंख्या में नियंत्रण का उपाय संयम भी है। वे स्वीकार करते है कि संयम से कुरीतियों का जन्म होता है क्योंकि संयम का अर्थ होता है अनियमित सहवास, अप्राकृतिक समागम, गर्भ समागम अथवा वेश्यावृत्ती। ये सभी जनसंख्या नियंत्रण के प्रतिबंधात्मक उपाय है। मानव संस्कृति में इन कुरीतियों को अवांछनीय रीति भी कहा जाता है (तिवारी, 2022)।

14.3.3 माल्थस के जनसंख्या सिद्धान्त की आलोचना

माल्थस द्वारा प्रस्तुत सिद्धान्त को कुछ विद्वानों से समर्थन प्राप्त हुआ तो कुछ ने इसकी कटु आलोचना भी की है। जहाँ समर्थन करने वाले विद्वानों मार्शल, एली, कोसा, कार्वर, पैटन तथा टाजिंग सम्मिलित थे वहीं आलोचना करने वालों में कैनन, इग्राहम, ओमनहोम एवं मार्क्स शामिल हैं। इनकी प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित है –

1) जनसंख्या वृद्धि हेतु यह नियम बनाना कि जनसंख्या ज्यामितीय ढंग से बढ़ती है सही नहीं है क्योंकि इसके कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई नहीं देते है।

2) माल्थस का यह मानना है कि प्रत्येक प्राणी में में अपनी जनसंख्या में वृद्धि करने की असीमित चाहत होती है जो कि ठीक नहीं होती है क्योंकि जिन प्राणियों में जितनी अधिक मात्रा में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। उनका विनाश भी तीव्रता से होता है। अपने एक शोध पत्र में स्मिथ लिखते हैं कि स्वीट्जरलैण्ड के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या की स्त्रियों के 20 बच्चे पैदा होते है परंतु युवावस्था तक जाते – जाते इनकी संख्या मात्र दो ही बचती है।

3) माल्थस ने तर्क दिया कि जीवन निर्वाह के साधन अथवा खाद्यान्न पदार्थ गणितीय अनुपात में बढ़ते है, उचित नहीं प्रतीत होते है क्योंकि खाद्य सामग्री के अंतर्गत वनस्पतियों के साथ जीव – जन्तु भी सम्मिलित होते है। माल्थस ने खाद्य पदार्थों में केवल कृषि उत्पादों को स्वीकार किया है जबकि मछलियों एवं जंतुओं

की वृद्धि पर गणितीय अनुपात नियम लागू नहीं होता है। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र के उत्पादन में भी अत्यधिक वृद्धि देखी जा रही है।

4) माल्थस ने मानव में कामेच्छा की पूर्ति एवं संतानोत्पत्ति को एक साथ जोड़ कर देखा है, वे मानते हैं कि मानव इसके बिना नहीं रह सकता है। उनका कहना है कि जब कामेच्छा की पूर्ति होगी तब जनसंख्या में वृद्धि स्वाभाविक है, जबकि व्यावहारिक जीवन में ऐसा नहीं होता है। संतान उत्पत्ति पर व्यक्ति की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं अन्य कारकों का अधिक प्रभाव देखा जाता है।

5) प्रसिद्ध विद्वान कैनन का मानना है कि जनसंख्या वृद्धि एवं खाद्य सामग्री की आपूर्ति में कोई सीधा संबंध नहीं पाया जाता है। उन्होंने इंग्लैण्ड का उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया है कि वहाँ की मात्र 1/6 भू–भाग ही सम्पूर्ण जनसंख्या के भरण – पोषण हेतु सक्षम है।

6) माल्थस की एक मान्यता यह है कि बच्चे बिना बुलाए मेहमान होते है जो प्रकृति की मेज पर भूखे मरेंगे इसके प्रतिउत्तर में कैनन लिखते है कि माल्थस शायद यह भूल गए हैं कि को बच्चा धरातल पर आता है वह न सिर्फ एक मुह लेकर आता है बल्कि दो हाथ भी लेकर आता है। वह अपने कर्मों के आधार पर जितना खाता है उससे अधिक उत्पादन की क्षमता भी रखता है।

7) माल्थस के कुछ आलोचकों का मानना है कि इनके द्वारा जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि का उत्तरदायित्व गरीबों का है पूरी तरह से गलत है। माल्थस एक जगह लिखते हैं कि जो लोग जनसंख्या वृद्धि का पोषण नहीं कर सकते हैं अर्थात गरीब वर्ग के लोगों को विवाह नहीं करनी चाहिए। इसके विरोध में मार्क्सवादी आलोचकों का मानना है कि अधिक जनसंख्या निर्धनता का कारण नहीं होती है बल्कि संसाधनों का आसमान वितरण ही निर्धनता का मुख्य कारण होता है।

8) कुछ आलोचकों का मानना है कि जिस नियंत्रण, संयम एवं आत्म नियंत्रण की बात माल्थस करते हैं व्यावहारिक जीवन में उन्हें अपनाने में मानव समुदाय कठिनाई का अनुभव करता है। ये बातें सैद्धान्तिक रूप में जितनी आदर्श लगती हैं व्यवहार में लाना उतना ही कठिन है।

14.3.4 माल्थस द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या सिद्धान्त की प्रासंगिकता

तत्कालीन यूरोप की जनसंख्या से जुड़ी समस्याओं के प्रेक्षण पर आधार पर प्रतिपादित यह सिद्धान्त अनेक आलोचनाओं के बावजूद भी इसने काफी समर्थन प्राप्त किया है। इस सिद्धान्त की प्रमुख प्रासंगिकताएँ निम्नलिखित है –

1) कुछ विद्वानों का मानना है कि यदि सम्पूर्ण विश्व के खाद्य संसाधनों के वितरण एवं उत्पादन का अवलोकन किया जाए तो स्पष्ट होता है कि इनका उत्पादन सीमित क्षेत्र में होता है और निश्चित मात्रा में में ही होता है। इनके द्वारा एक निश्चित जनसंख्या का ही पालन – पोषण हो सकता है।

2) माल्थस के जनसंख्या सिद्धान्त की सर्वाधिक प्रासंगिकता विकासशील एवं अल्पविकसित देशों में ही देखी जाती है। इन देशों में खाद्य समग्रियों की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि दर कभी – कभी तीव्र हो जाती है, जो इस सिद्धान्त की मान्यताओं और संकल्पना को पुष्ट करती है।

3) इस सिद्धान्त की मूल भावना आज भी मूर्त रूप में देखी जा सकती है। जनसंख्या की वृद्धि तीव्र है तथा खाद्यान्नों की वृद्धि दर धीमी है। जनसंख्या के पालन – पोषण में सहायक औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने की एक सीमा होती है उससे अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

4) अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के नेतृत्व में एक अभियान वर्ष 2000 ई. 'Global Two Thousand Study' चलाया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था विश्व की जनसंख्या एवं संसाधनों का अध्ययन करना। इस दल ने जनसंख्या एवं खाद्यान्न दोनों की उत्पादन प्रवृत्तियों का अध्ययन किया तथा भविष्य में उनके सहसंबंध को प्रकट किया।

14.4 नव माल्थसवाद

जनसंख्या और खाद्यान्न आपूर्ति के संबंधों के विषय में प्रचलित वह विचारधारा जो माल्थस के मान्यताओं का तो अनुसरण करती है परंतु उसमें कुछ व्यवहारिक संशोधन भी प्रस्तुत करती है नव माल्थसवाद कहलाती है। नव माल्थसवादी आधुनिक संतति नियमन आंदोलन के प्रबल समर्थक हैं साथ ही वे स्वयं को माल्थस के उत्तराधिकारी भी मानते हैं। इस आंदोलन का शुभारंभ माल्थस के अनुयायियों द्वारा सन्तति निग्रह के साथ अन्य प्रतिबंधों एवं उपाय द्वारा जनसंख्या को कम करने हेतु शुरू किया गया था। यह आंदोलन मुख्यतः माल्थस के अनुयायियों द्वारा पाश्चात्य देशों में जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रारंभ किया गया था। यह समुदाय संतति निग्रह हेतु रासायनिक और यांत्रिक गर्भनिरोधकों के उपयोग को अपनाने का समर्थन करता है। इंग्लैंड की श्रीमती मेरी स्टांप्स एवं अमेरिका की मारग्रेट स्ट्रेंजर इस आंदोलन की प्रमुख समर्थक रही हैं। इस आंदोलन ने तत्कालीन समय में सभी देश विचारकों, चिकित्सकों, समाजशास्त्रियों, मानव विज्ञानियों एवं अर्थशास्त्रियों को अपनी ओर आकर्षित किया। इन सभी लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण की बात का पूरा समर्थन किया। नव माल्थसवादी संकल्पना के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण भारत में देखने को मिलते हैं जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर सरकार ने परिवार नियोजन के उद्देश्य को स्वीकार किया। कृत्रिम उपायों से संतति निग्रह हेतु जनता को विविध प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की गई तथा उन्हें अपनाने हेतु लोगों को प्रोत्साहित भी किया गया है।

माल्थस ने कामेच्छा तथा संतान उत्पत्ति को जहाँ एक माना और उसमें कोई भेद नहीं किया वहीं नव माल्थसवादी दोनों में अंतर करते हैं। इन लोगों ने माल्थस की विचारधारा एवं सोच में संशोधन किया। वे मानते हैं कि कामेच्छा वयस्कों की एक सामान्य आवश्यकता है और उसका दमन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके दमन से मानव में मानसिक विकृतियां उत्पन्न होती हैं। दूसरी तरफ इनका मानना है की संतान उत्पन्न करने की इच्छा व्यक्तियों में मुख्यतः सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से प्रेरित होती है। मानव के अंदर कामेच्छा की इच्छा होने का मतलब यह नहीं है कि वह संतान उत्पन्न करना चाहता है। इन विचारकों ने यह मत व्यक्त किया है कि यदि कोई पति – पत्नी अतिरिक्त संतान का भार उठाए बिना अपनी कामेच्छा की तृप्ति करना चाहते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए वह गर्भ निरोधक, रासायनिक तथा यांत्रिक उपायों का प्रयोग करके अपनी कामेच्छा की पूर्ति कर सकता है। वह मानते हैं कि यदि वर्तमान समय में माल्थस जीवित होते तो वह भी उनकी मान्यताओं को स्वीकार करते क्योंकि उनके समय एवं वर्तमान समय की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में काफी परिवर्तन हो चुका है।

14.4.1 कृत्रिम विधि से संतानोत्पत्ति पर रोक के पक्ष में तर्क

नव माल्थसवादियों ने जनसंख्या नियंत्रण हेतु कृत्रिम साधनों के प्रयोग पर बल दिया है, इसके पक्ष में इन लोगों ने निम्नलिखित तर्क दिए है –

1. किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधनों की वहन क्षमता से अधिक यदि जनसंख्या पाई जाती है तो उससे अनेक सामाजिक – आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में भूमि एवं अर्थव्यवस्था पर लोगों का भार कम करने के लिए जन्म एवं जनसंख्या नियंत्रण दोनों आवश्यक है।
2. कामेच्छा का दमन करके परिवार के आकार को नियंत्रित करना लाभदायक नहीं होता है क्योंकि परिवार के आकार को सीमित करने में जन साधारण आत्म संयम करने में अधिकांश असफल रहता है। कामेच्छा के दमन से व्यक्तियों में मानसिक विकृति आ जाती है, जो एक सुखमय जीवन हेतु बहुत ही कष्टदायक स्थिति होती है। इससे व्यक्ति के सम्मुख अनेक समस्याएँ उत्पन्न होने लगती है। अतः ऐसी स्थिति में कृत्रिम साधनों के प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए।
3. इस विचारधारा के समर्थक संतति निग्रह अथवा जन्म नियंत्रण को अप्राकृतिक कहते हुए अनुचित भी मानते है। इनका मानना है कि जिस प्रकार व्यक्ति के वस्त्र पहनना एवं घर में रहना आवश्यक है उसी प्रकार संतान उत्पन्न करना भी उसकी एक जैविक प्रक्रिया है। इसका दमन नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में लोगों एवं सरकारों को जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्या के लिए अलग से प्रावधान करना चाहिए। मौर्या (2021) अपनी पुस्तक जनसंख्या भूगोल में लिखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से होने वाली हानियों से बचने तथा मानव समुदाय के कल्याण के लिए संतति अप्राकृतिक होते हुए भी आवश्यक है।

4. नव माल्थसवादी विचारधारा के समर्थक संतति नियंत्रण के लिए कृत्रिम उपायों के प्रयोग को अनुचित मानते है तथा उनका कहना है कि इससे समाज में अनैतिक कार्यों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है जिसके कारण समाज पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। इसके साथ ही इनका यह भी मानना है कि नैतिक नियम मानव द्वारा ही निर्मित किए जाते है जो काल एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित भी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आधुनिक काल में सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से मानव के लिए लाभदायक तथा कल्याण उत्पन्न करने वाले कार्यों को भी नैतिक माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि मानव के सम्मुख उत्पन्न होने वाली भूखमरी, अकाल, बीमारी, महामारी, निर्धनता, युद्ध आदि से बचाने के लिए कृत्रिम साधनों का प्रयोग अनैतिक होते भी नैतिक माना जाता है।

उपरोक्त बातों से स्पष्ट होता है कि नव माल्थसवादी वैचारिक दृष्टिकोण से माल्थस के विरोधी नहीं हैं बल्कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु कृत्रिम साधनों के प्रयोग को प्रोत्साहन देते है। जहाँ माल्थस के समर्थक नियमों के प्रति ज्यादा उग्र होते हैं वहीं नव माल्थसवादी उदार दृष्टिकोण का अनुसरण करते है। ऐसी स्थिति का लाभ यह होगा कि कृत्रिम साधनों के प्रयोग व्यक्ति की कामेच्छा पूर्ण होने के साथ ही जनसंख्या में वृद्धि भी नहीं होगी तथा समाज अनेक प्रकार की कुरीतियों से भी मुक्त रहेगा।

14.5 अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त

किसी प्रदेश की वह अधिवासित जनसंख्या जिसे वहाँ उपलब्ध संसाधनों के अनुसार उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त होता है अभीष्ट या अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धान्त का आधार मूलतः आर्थिक है परन्तु यह सामाजिक दशाओं तथा समाज की तत्कालीन प्रौद्योगिकी के विकास स्तर से सम्बद्ध होती है। जनसंख्या एवं संसाधनों के मध्य पूर्ण संतुलन की अवस्था की प्राप्ति की दशा अत्यंत कठिन है। सामाजिक विकास एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए साम्यावस्था प्राप्त की जा सकती है। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धान्त उसी साम्यावस्था का बोध कराता है। साहित्यिक दृष्टिकोण से अनुकूलतम एक सापेक्षिक शब्द है जिसका अर्थ देश काल के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। यदि अनुकूलतम जनसंख्या का निर्धारण जीवन की गुणवत्ता और जीवन के स्तर के आधार पर करें तो किसी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों का वर्तमान ज्ञान तथा उपलब्ध तकनीकी के अनुसार उसके पूर्ण विकास के साथ उसके उपयोग के लिए सुनिश्चित जनसंख्या जिसे उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त होता है, अनुकूलतम जनसंख्या कही जाती है।

आर्थिक एवं सामाजिक अवधारणाओं के आधार पर किसी प्रदेश में निवासित जनसंख्या के उस भाग को अनुकूलतम माना जाता है, जिससे वहाँ उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है और वहाँ की जनसंख्या का जीवन स्तर उच्चतम होता है। अनुकूलतम जनसंख्या किसी प्रदेश की जनसंख्या तथा संसाधनों के मध्य सम्बन्धों की एक आदर्श स्थिति होती है, जो सामान्यतः सभी प्रदेशों में सुगमता से प्राप्त नहीं होती है। अभी तक ऐसा कोई भी प्रामाणिक मापदण्ड विकसित नहीं हो सका है जिसके सहयोग से विश्व के किसी भी देश में उपलब्ध सम्पूर्ण संसाधनों का मूल्यांकन किया जा सके और उसकी प्रभाविता का सहसंबंध वहाँ की उपलब्ध जनसंख्या से स्थापित किया जा सके। अतः यह ज्ञात करना मुश्किल है कि किसी क्षेत्र में संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो रहा है या नहीं। सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से उच्चतम जीवन स्तर से अभिप्रायः केवल अधिकतम प्रतिव्यक्ति आय से नहीं है बल्कि इसमें प्रतिव्यक्ति पर्याप्त भोज्य पदार्थ, शुद्ध जल, शुद्ध वायु, उच्चस्तरीय आवास, पूर्ण विकसित परिवहन के साधन, मनोरंजन एवं स्वास्थ्य की पूर्ण सुविधा, सर्वोत्तम व्यापारिक दशा और सांस्कृतिक विकास के पूर्ण अवसर आदि की पर्याप्त उपलब्धता से है। इसके अभाव में उच्चतम जीवन स्तर की कल्पना नहीं की जा सकती है (मौर्या, 2005)।

किसी प्रदेश में उपलब्ध संसाधन तथा वहाँ की निवासित जनसंख्या के मध्य आदर्श साम्य की अवस्था का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में कैंटीलोन ने अनुकूलतम जनसंख्या शब्दावली का प्रयोग किया था। अनुकूलतम जनसंख्या एक आदर्श आकार होता है जिससे अधिक या कम होने पर जनसंख्या एवं संसाधनों के मध्य संतुलन बिगड़ जाता है। इस कारण क्षेत्र विशेष में अति जनसंख्या या अल्प जनसंख्या की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अनुकूलतम जनसंख्या के सैद्धान्तिक पक्ष की परिभाषा विभिन्न भूगोलविदों, समाज विज्ञानियों एवं अर्थशास्त्रियों द्वारा समय – समय पर दी गई है जो निम्नलिखित है –

कार साऊडर्स के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो अधिकतम कल्याण उत्पन्न करती है।

पीटर्सन के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या व्यक्तियों की वह संख्या है, जो किसी दिए हुए प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण में अधिकतम आर्थिक प्रतिफल उत्पन्न करने में सक्षम है।

बोल्डिंग के शब्दों में वह जनसंख्या जिस पर किसी क्षेत्र विशेष के लोगों का जीवन स्तर उच्चतम हो अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है।

डाल्टन के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रतिव्यक्ति अधिकतम आय देती है।

मानव भूगोल का शब्दकोश जिसका सम्पादन जानसन एवं अन्य लोगों द्वारा किया गया है के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या की परिभाषा व्यक्तियों की वह संख्या जो किसी दी हुई आर्थिक, सैन्य या सामाजिक लक्ष्यों के संदर्भ में अधिकतम प्रतिफल को प्राप्त कराती है अनुकूलतम जनसंख्या होती है।

प्रसिद्ध विद्वान सावी के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग एवं पूर्ण रोजगार, दीर्घ जीवन संभाव्यता, उत्तम स्वस्थ्य, ज्ञान और संस्कृति, सामाजिक सामंजस्य तथा पारिवारिक दायित्व की प्राप्ति होती है।

वर्ष 2003 में आर. एन. सिंह और एस. डी. मौर्या के सम्पादन में प्रकाशित भौगोलिक पारिभाषिक शब्दकोश की परिभाषा के अनुसार किसी प्रदेश या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की वह आदर्श संख्या जो उस क्षेत्र के संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए सक्षम होती है और जिससे सामान्य जीवन स्तर यथासंभव उच्चतम हो सकता है अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है।

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जब किसी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत निवास करने वाली सम्पूर्ण जनसंख्या को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक दृष्टिकोण से सक्षम बनाने में उपलब्ध संसाधन पर्याप्त होते है तो ऐसी जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। ऐसी जनसंख्या अधिकतम आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करती है तथा संसाधनों के पूर्ण उपयोग और उच्चतम जीवन स्तर के लिए आवश्यक आधार प्रदान करती है।

अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त के मूल तथ्य

अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त मुख्य रूप से किसी क्षेत्र के संसाधन एवं वहाँ की जनसंख्या के संबंध को अभिव्यक्त करते है । इसी कारण जनसंख्या भूगोल में इसका विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त के मूल तथ्य निम्नलिखित है –

1) इसके समर्थकों का मानना है कि यह सिद्धान्त उत्पादन के नियमों पर आधारित है। किसी भी क्षेत्र की वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या से कम होने पर उत्पत्ति वृद्धि नियम एवं अधिक होने पर उत्पत्ति ह्रास नियम नियम लागू होता है। अतः अनुकूलतम जनसंख्या के निर्धारण हेतु उत्पादन के नियम प्रयोग किए जाते है।

2) विश्व के किसी भी देश की जनसंख्या स्थिर नहीं पाई जाती है बल्कि उसमें गतिशीलता देखी जाती है। देशों के उत्पादन संसाधनों में गुणात्मक अथवा मात्रात्मक परिवर्तन होने से अनुकूलतम जनसंख्या के स्वरूप में परिवर्तन होता है। मौर्य (2022) लिखते हैं कि उत्पादन के साधनों की मात्र, तकनीकी एवं वैज्ञानिक ज्ञान, कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होने के कारण अनुकूलतम जनसंख्या का आकार बढ़ जाता है साथ ही साथ इनके स्तर में कमी होने पर अनुकूलतम जनसंख्या के आकार में ह्रास हो जाता है।

3) अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना एक आदर्श स्थिति होती है जिसका सैद्धान्तिक महत्त्व अधिक होता है।

14.5.1 अनुकूलतम जनसंख्या के निर्धारण के तत्व

अनुकूलतम जनसंख्या का आकार क्या होगा इसका निर्धारण करना आसान काम नहीं है। किसी क्षेत्र विशेष में उच्चतम जीवन स्तर या अधिकतम आर्थिक उत्पादन या अधिकतम सामाजिक कल्याण का सीमांकन करना कठिन काम है। किसी क्षेत्र विशेष हेतु अनुकूलतम जनसंख्या के अधिकतम आर्थिक उत्पादन, सैन्य शक्ति, सामाजिक कल्याण के अलग – अलग मानक हो सकते है। इन मानकों के आधार पर अलग – अलग उद्देश्य निर्धारित किए जाते है। इस प्रकार अनुकूलतम जनसंख्या के निर्धारण के प्रमुख तत्वों में सकल घरेलू उत्पाद, प्रतिव्यक्ति आय, पूर्ण

रोजगार, उच्चतम जीवन स्तर, संसाधनों का पूर्ण उपयोग, संतुलित जनांकिकीय संरचना, प्रदूषण रहित विकास आदि प्रमुख है।

14.5.1.1 सकल राष्ट्रीय उत्पाद

समाज में अधिकतम आर्थिक उपयोगिता के आकलन के मापकों में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का महत्त्वपूर्ण स्थान है। जिन देशों का सकल राष्ट्रीय उत्पाद अधिक होता है वहाँ प्रतिव्यक्ति आय भी अधिक होता है। प्रतिव्यक्ति आय की अधिकता की स्थिति में जनसंख्या में आर्थिक समृद्धि का वितरण अधिक पाया जाता है। लोगों के पास अधिक धन संचय होने प्रतिव्यक्ति व्यय एवं क्रय क्षमता बढ़ जाती है। इससे समाज मे आर्थिक साधनों का प्रवाह अधिक देखा जाता है। चूंकि प्रतिव्यक्ति आय औसत आय को प्रकट करती है, अतः जिन समाजों में यह अधिक पाई जाती है वहाँ उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग की संभावना अधिक होती है।

14.5.1.2 उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग

किसी भी देश में किसी निश्चित कालावधि में यदि तत्कालीन प्रौद्योगिक एवं तकनीकी के प्रयोग से समस्त ज्ञान संसाधनों के पूर्ण प्रयोग वाली संकल्पना अनुकूलतम जनसंख्या से साम्य रखती है। समय में परिवर्तन के साथ ही नई प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के विकास से नवीतम संसाधनों की खोज होती है तथा पूर्व के उपलब्ध संसाधनों की गुणवत्ता में वृद्धि होती रहती है। अतः इसके आधार पर भी किसी देश काल की अनुकूलतम जनसंख्या के मानक में परिवर्तन होता रहता है।

14.5.1.2 देश की जनांकिकीय संरचना

किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या का संबंध वहाँ की जनांकिकीय संरचना में भी देखा जाता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या में लिंग, आयु आदि तत्वों में संतुलन होने पर निर्भरता अनुपात सामान्य बना रहता है। जन्मदर तथा मृत्युदर में अंतर भी धीरे – धीरे कम होने लगता है और दोनों अपने निम्नतम स्तर पर पहुँच जाते है, जिससे जनसंख्या स्थिर हो जाती है इस प्रकार उपलब्ध संसाधनों एवं वहाँ की जनसंख्या की आवश्यकताओं के साम्य की स्थिति प्राप्त हो जाती है।

14.5.1.3 पूर्ण रोजगार की अवस्था

यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में उसके सभी नागरिकों को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं तो इससे आय के वितरण की असमानता कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में आश्रित जनसंख्या का स्तर भी अपने निचले पायदन पर पहुँच जाता है। वहाँ के उपलब्ध सम्पूर्ण संसाधन वहाँ की जनसंख्या के भरण – पोषण में सक्षम हो जाते है।

14.5.1.4 जीवन का उच्च स्तर

जीवन के उच्चतम स्तर की अवधारणा एक सामाजिक संकल्पना है। यह उच्चतम आय एवं पूर्ण रोजगार के साथ – साथ उच्चतम स्वस्थ्य और सुखमय जीवन हेतु आवश्यक सुविधाओं की पूर्ण उपलब्धता पर निर्भर होती है। जिन समाजों ने इस स्तर को प्राप्त कर लिया है वहाँ अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना सार्थक हो जाती है।

14.5.1.5 प्रदूषण रहित सतत विकास

अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना मात्र आय के उच्चतम स्तर एवं आर्थिक उत्पादन से नहीं जुड़ी हुई है। इसमें पर्यावरणीय तत्वों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। अधिकतम आर्थिक लाभ क प्राप्त करने के लिए पर्यावरण की निरंतर क्षति नहीं पहुंचायी जा सकती है। पर्यावरणीय अवनयन से मृदा अपरदन, निर्वनीकरण, जल एवं वायु प्रदूषण में निरंतर वृद्धि होती जाती है जो वर्तमान एवं भविष्य के लिए गंभीर पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कर सकते हैं। प्रसिद्ध विद्वान जी. आर. टेलर के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या का अधिकतम वह है जो पर्यावरण अथवा समाज को या पोषण की कमी से व्यक्ति के स्वस्थ्य को क्षति पहुंचाए बिना अनिश्चित काल तक स्थिर रह सके।

अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना को लेकर जनसंख्याविदों एवं अन्य मानवशास्त्रियों में विवाद के अनेक पक्ष देखे जाते है। इस संकल्पना के उदय के साक्ष्य प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के देशों में देखे जाते हैं। इसके सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षों की आलोचना के अनेक आधार मिलते है। बहुत से

भूगोलविदों एवं जनसंख्याविदों का मानना है कि वर्तमान संसार में अर्थव्यवस्था और समाज की गतिशीलता के साथ लगातार प्रौद्योगिकी का विकास एवं नवीन प्रकार के संसाधनों की खोज, अनवीकरणीय संसाधनों के वैकल्पिक खोज के कारण संतुलन की अवस्था की प्राप्ति अत्यंत कठिन है। ऐसी स्थिति में अनुकूलतम जनसंख्या का निर्धारण अत्यंत कठिन हो जाता है।

15.5.2 माल्थस का जनसंख्या सिद्धान्त एवं अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त का तुलनात्मक अध्ययन

काल एवं परिस्थितियों के अनुसार अनेकों विद्वानों ने जनसंख्या से संबन्धित सिद्धांतों का प्रतिपादन समय – समय पर किया है। इन लोगों ने अपने तरीके से किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का आध्यान किया है और वहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल जनसंख्या सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। इन्हीं सिद्धांतों में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त दो सिद्धान्त माल्थस का जनसंख्या सिद्धान्त एवं अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त भी हैं। इन दोनों में जनसंख्या जुड़े तथ्यों की व्याख्या की गई है फिर भी दोनों में कुछ असमानताएँ पाई जाती है, जो निम्नलिखित है –

1. माल्थस द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त की प्रकृति निराशावादी है तथा वह जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को हानिकारक मानता है इसके विपरीत अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धान्त किसी क्षेत्र की जनसंख्या के अनुकूलतम से कम होने पर लाभकर एवं अधिक होने पर हानिकर मानता है।
2. माल्थस का सिद्धान्त जनसंख्या एवं खाद्यान्न आपूर्ति के मध्य संबंध अध्ययन करता है जबकि अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धान्त किसी देश की जनसंख्या और उसके राष्ट्रीय आय के मध्य संबंध का विश्लेषण करता है।
3. माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि के लिए गुणोत्तर सिद्धान्त एवं खाद्यान्न उत्पादन के लिए के सामान्य दर के नियम का निर्धारण किया है वहीं अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त में इन दरों की उपयोगिता की बात कहीं नहीं की गई है।
4. जहाँ माल्थस का सिद्धान्त केवल जनाधिक्य वाले देशों के लिए उपयोगी है वहीं अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धान्त जनाभाव एवं जनाधिक्य दोनों प्रकार के देशों के लिए उपयोगी है।
5. माल्थस का मानना है कि जनाधिक्य की अवस्था में प्राकृतिक प्रकोप, अकाल, भुखमरी एवं युद्ध जैसे कारक स्वतः सक्रिय हो जाते है किन्तु अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त के अनुसार जनाधिक्य होने पर ऐसे कारकों की सक्रियता अनिवार्य नहीं है।
6. मौर्या लिखते हैं कि माल्थस का सिद्धान्त जनसंख्या वृद्धि को अति चिंताजनक एवं भयावह मानता है तथा जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन देता है इसके विपरीत अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धान्त देश कि सामाजिक – आर्थिक स्थितियों के अनुसार देश के लिए उचित जनसंख्या नीति के निर्माण पर जोर देता है।

14.6 सारांश

आपने इस इकाई में माल्थस का जनसंख्य सिद्धांत, नव माल्थसवाद एवं अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का अध्ययन किया है। आप समझ गए होगें कि जनसंख्या भूगोल के इन सिद्धांतों ने जनसंख्या से जुड़ी अवधारणाओं को अपने तरीके से व्यक्त करने का प्रयास किया है। वास्तव में किसी देश की जनसंख्या वहाँ का सबसे बड़ा संसाधन होती है जो उसकी भौगोलिक अवस्थिति, सरकारी नीतियों, सांस्कृतिक संगठन आदि के आधार पर विकसित होती है। माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि तथा खाद्यान्न की आपूर्ति के सहसंबंध को जोड़कर सिद्धान्त प्रस्तुत प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। बाद में कुछ विद्वानों द्वारा इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठाया गया जिसके कारण इसकी काफी आलोचना भी हुई। नव माल्थसवादी माल्थस के अनुयायी थे तथा उन्होने इसकी कमियों को दूर करके सिद्धान्त प्रस्तुत किए। बाद के वर्षों में अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, जिसमें इस बात को स्वीकार किया गया कि किस प्रकार वहाँ उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जाए ताकि सर्वोत्तम कल्याण की प्राप्ति हो सके।

14.7 स्वमूल्यांकन प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

1. माल्थस ने अपना जनसंख्या संबंधी सिद्धान्त कब दिया था।
   (क) 1775 ई. (ख) 1798 ई. (ग) 1808 ई. (घ) 1905 ई.
2. माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को बताया था।
   (क) धनात्मक (ख) ऋणात्मक (ग) गुणोत्तर (घ) अंकगणितीय
3. माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को बताया था।
   (क) अंकगणितीय (ख) ऋणात्मक (ग) धनात्मक (घ) गुणोत्तर
4. नव माल्थसवादी विचारक थे।
   (क) माल्थस के विरोधी (ख) माल्थस के समकालीन (ग) माल्थस अनुयायी (घ) माल्थस समर्थक
5. अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है।
   (क) उपलब्ध संसाधनों की वहन क्षमता से अधिक
   (ख) उपलब्ध संसाधनों की वहन क्षमता से कम
   (ग) उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए जिनका जीवन स्तर उच्च बनाया जा सके
   (घ) उपरोक्त सभी

14.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

Bogue] D- J-] 1969] Principles of Demography] John Wiley] N-Y-

Clarke] John I-] 1973] Population Geography] Pergaman Press] Oxford-

Crook] Nigel] 1997] Principles of Population and Development] Pergaman Press] N- Y-

Garmier] J- B-] 1970] Geography of Population] Longman] London-

Mamoria] C- B-] 1981] India's Population Problem] Kitab Mahal] New Delhi-

Premi] M- K-] 1991] India's Population] Heading Towards a Billion] B- R- Publishing Corporation-

Blassoff] M- and Srinivasan K-] 2001] Population Development Nexus in India : Challenges for the New Millennium] Tata McGraw Hill] New Delhi-

Woods] R-] 1979] Population Analysis in Geography] Longman] London-

Zelinsky] W-] 1966] A Prologue to Population Geography] Prentice Hall-

चन्दना, आर. सी., 2022, जनसंख्या भूगोल – संकल्पना, नियंत्रक व विश्व प्रारूप, कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

चन्दना, आर. सी., 2022, भारत : जनसंख्या (जनसंख्या भूगोल – भाग 2), कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

मौर्या, एस. डी., 2005, जनसंख्या भूगोल, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद.

ओझा, आर. पी., 1984, जनसंख्या भूगोल, प्रतिभा प्रकाशन.

हीरा लाल, 2000, जनसंख्या भूगोल के मूल तत्व, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली.

तिवारी, राम कुमार, 2023, जनसंख्या भूगोल, प्रवालिका पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद.

14.9 अभ्यास प्रश्न (सत्रांत परीक्षा की तैयारी)

1. माल्थस के जनसंख्या संबंधी सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए?
2. नव माल्थसवादी विचारकों ने माल्थस के सिद्धान्त में जो संशोधन किया था उन्हें स्पष्ट कीजिए?
3. अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए तथा अनुकूलतम जनसंख्या के निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए?

इकाई–15 जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएँ, भारत में जनसंख्या की समस्याएँ

इकाई की रूपरेखा

15..0 प्रस्तावना

15.1 उद्देश्य

15.2 विकसित देश में जनसंख्या की समस्याएँ

15.3 विकासशील देशों की जनसंख्या संबंधित समस्याएँ

15.4 भारत में जनसंख्या की समस्या

15.5 सारांश

15.6 स्वमूल्यांकन प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

15.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

15.8 अभ्यास प्रश्न (सत्रांत परीक्षा की तैयारी)

15.0 प्रस्तावना

वर्तमान समय में विश्व के समक्ष उपस्थित समस्याओं में जनसंख्या वृद्धि एक प्रमुख समस्या है। प्रत्येक देश की अपनी स्थान, काल एवं परिस्थिति के अनुसार संसाधनों की उपलब्धता होती है जिससे एक निश्चित जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यदि किसी देश के संसाधन वहाँ उपलब्ध जनसंख्या की आवश्यकताओं से अधिक हैं तो ऐसी अवस्था अल्पसंख्यक कहलाती है, जबकि संसाधनों की उपलब्धता से अधिक मात्रा में उपयोग की अवस्था अधिसंख्यक जनसंख्या के रूप में जानी जाती है। जब संसाधन की उपलब्धता एवं जनसंख्या द्वारा प्रयोग की क्षमता के मध्य संतुलन स्थापित हो जाता है तब ऐसी अवस्था को अनुकूलत जनसंख्या की अवस्था कहा जाता है। बदलती जीवन शैली के कारण व्यक्ति की आवश्यकताएँ एवं महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही है, जिनकी पूर्ति करना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए आसान नहीं होता है।

15.1 उद्देश्य

जनसंख्या में वृद्धि होने से अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती है। ये समस्याएँ अलग – अलग देश के लिए अलग – अलग प्रकार की होती है। इनके समाधान के लिए अलग – अलग प्रकार के नियोजन की आवश्यकता होती है। इस इकाई के प्रमुख उद्देश्य निम्न है –

1. जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं का विश्लेषण करना।
2. भारत में जनसंख्या की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करना।

वैश्विक स्तर पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो ज्ञात होता है कि आर्थिक विकास सभी जगह पर समान रूप से नहीं हुआ है। कुछ देशों की अर्थव्यवस्थाएं विकसित अवस्था में हैं तो अधिकांश देशों के अर्थव्यवस्थाएं विकासशील अथवा अल्पविकसित अवस्था में है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या और उससे जुड़ी समस्याएँ दोनों के लिए अलग – अलग होती है। इस प्रकार इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं में जनसंख्या से जुड़ी समस्याओं का विश्लेषण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है –

15.2 विकसित देश में जनसंख्या की समस्याएँ

विकसित देश आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत संपन्न है जिसके कारण यहाँ मानव जाति के विकास हेतु आवश्यक संपूर्ण जरूरतों की आपूर्ति आसानी से हो जाती है। व्यक्तिगत स्तर पर भी इन राष्ट्रों के लोग काफी संपन्न होते हैं, ऐसी स्थिति में जीवन हेतु आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध वे आसानी से कर लेते है। वर्तमान समय में विश्व के लगभग 40 देश ऐसे हैं जिन्हें विकसित वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। विकसित देशों की श्रेणी में मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोपीय, आंग्ल अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया, रूस, न्यूजीलैण्ड, पैराग्वे, अर्जेंटीना एवं जापान सम्मिलित है। इन देशों में आर्थिक विकास का स्तर उच्चतम पाया जाता है। यहाँ जनसंख्या के जीवन यापन हेतु संपूर्ण सुविधा उपलब्ध होते हैं, फिर भी जनसंख्या से संबंधित अनेक समस्याएँ विद्यमान होते हैं जिनका विवरण निम्नवत है –

15.2.1 जनसंख्या ह्रास एवं वृद्धि की समस्या

आर्थिक दृष्टिकोण से विकसित देशों में संपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग संग्रहित है परंतु इन देशों में संपूर्ण विश्व की मात्र 25% जनसंख्या ही निवास करती है, शेष 75% जनसंख्या विकासशील एवं अल्पविकसित देशों में रहती है। दोनों प्रकार के देश में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति में अंतर पाया जाता है। जहाँ विकसित देश जनसंख्या ह्रास की समस्या से ग्रसित हैं वहीं विकासशील एवं अल्प विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि की समस्या प्रमुख है। अधिकांश विकासशील देशों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है इसके विपरीत कुछ विकसित देशों में यदि जनसंख्या बढ़ भी रही है तो उसकी दर अत्यंत मंद है। कुछ देशों में ऐसा भी देखा जा रहा है कि उनकी जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हो गई है। विकसित देशों में तो कुछ जनांकिकीय संक्रमण की अवस्था में पहुंच गए हैं जिसके कारण वहां जनसंख्या वृद्धि लगभग शून्य हो गई है। इन्हीं सब कारकों का परिणाम है कि इन देशों की जन सांख्यिकी की स्थिति धीरे – धीरे कम होती जा रही है।

अध्ययन की अनुकूलतम अवस्था में जनसंख्या एवं भूमि का अनुपात तथा जनसंख्या एवं संसाधन के मध्य संतुलन होना चाहिए। विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 44 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है। यह अनुपात विकसित देशों के संदर्भ में 19 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है। वैश्विक राष्ट्रीय उपज के संदर्भ में भी यही परिदृश्य देखने को मिलता है। विश्व के संपूर्ण राष्ट्रीय उपज का 85% भाग इन्हीं देशों में ही संग्रहित है जबकि यहाँ मात्र 25% जनसंख्या ही निवास करती है। यूरोप के कुछ देशों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है जिसका मुख्य कारण औद्योगिक क्रांति है। विश्व के अन्य देशों में भी जनसंख्या घनत्व एवं संसाधन अनुपात बिगड़ता जा रहा है।

15.2.2 प्रजननता की समस्या

विकसित देशों की प्रजननता दर में निरंतर गिरावट की प्रवृत्ति देखी जा रही है। वर्ष 1990 ई. के प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से इस बात का पता चलता है, कि विश्व में औसतन प्रति स्त्री प्रजनन दर 4.3 थी जबकि उसी समय विकसित देशों में यह मात्र 1.8 बच्चे प्रति स्त्री है। इन देशों में जनसंख्या संक्रमण की अवस्था लगभग पूर्ण हो चुकी है। रामकुमार तिवारी अपनी पुस्तक जनसंख्या भूगोल में लिखते हैं कि विकसित देशों में जनसंख्या संक्रमण की अवधि पूर्ण हो चुकी है। यह सामान्य स्तर से काफी नीचे आ गई है। इन देशों में अब प्रजनन दर को नीतियों द्वारा भी उठाया नहीं जा सकया। पश्चिमी यूरोप के कुछ देशों में जन्म संबंधी व्यवहार, भ्रूण हत्या एवं परिवार नियोजन जैसे कानून के प्रतिबंध को काम करना शुरू कर दिया है। पहले चर्च द्वारा जन्म दर पर नियंत्रण के लिए आह्वान किया जाता था परंतु अब इन व्यवहारों में परिवर्तन आया है। पश्चिमी यूरोप सहित अन्य विकसित देशों में बच्चों के पैदाइश, उनका पालन – पोषण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाएँ महंगी होती जा रही है। ऐसी स्थिति में लोगों में कम बच्चा पैदा करने की प्रवृत्ति घर कर गई है। आर. सी. चंद्रा लिखते हैं कि विकसित देशों में उत्पादकता स्तर एवं प्रजनन स्तर तब तक पुनः स्थापना स्तर पर बना रहेगा जब तक अधिक मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में ह्रास होकर उनके श्रम बाजार को नकारात्मक रूप में प्रभावित न करें । इन देशों में प्रजनन दर को बढ़ाने के लिए सरकारों द्वारा कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

15.2.3 अवैध गर्भ एवं गर्भपात की समस्या

विकसित देशों की प्रमुख समस्याओं में एक परिवार नियोजन भी है। यहाँ की खुली संस्कृति में शारीरिक संबंध आम बात होती है, जिसके कारण गर्भ निरोधक दवाइयां एवं अन्य उपकरण खुलेआम सामान्य दुकानों पर भी

मिल जाते है। शादी से पूर्व ही इन देशों में शारीरिक संबंध के प्रचलन के कारण अमेरिका जैसे देश में प्रति वर्ष आधे गर्भ अनिश्चित तथा कुल गर्भधारण के एक तिहाई गर्भ का गर्भपात से समाप्त हो जाता है। विकसित देशों में अवैध बच्चों की बढ़ती संख्या प्रमुख समस्या है। विवाह हुए बगैर पैदा होने वाले बच्चे अवैध बच्चे कहलाते है। विकसित देशों में अवैध बच्चों की संख्या दिन – प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसको अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक कारक प्रोत्साहित करते है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या आयोग से प्राप्त एक आंकड़े से स्पष्ट हुआ है कि स्वीडन में वर्ष 1975 में 20 से 24 वर्ष आयु वर्ग की जितनी महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया उनमें से 37% अवैध थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1970 से 77 के मध्य हुए एक सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया कि इस अवध में यहाँ 83% लोग बिना विवाह के सहवास में रह रहे है। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1991 ई. में 10.21 लाख बच्चों को जन्म अविवाहित महिलाओं ने दिया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों की कुल संख्या का 30% है। प्रजातीयता के आधार पर भी अवैध बच्चों की संख्या में अंतर देखा जाता है। सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में अंतर के कारण अश्वेत लोगों में ज्यादा अवैध बच्चे पैदा होते हैं वहीं श्वेतों में इनकी संख्या कम दर्ज की गई है। एक आंकड़े से ज्ञात हुआ है कि अवैध बच्चों का अनुपात अश्वेतों में जहाँ 68% है वहीं श्वेतों में 22% है।

विश्व जनसंख्या आयोग से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि संपूर्ण विश्व में 25% गर्भपात होता है तथा प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ भ्रूण हत्याएं भी होती है। इन दोनों प्रक्रियाओं में सम्मिलित लगभग 50 लाख महिलाओं में 15 से 19 वर्ष की युवतियां सम्मिलित होती है। इनमें से भी लगभग 50% गैर कानूनी होता है क्योंकि इनका कोई पंजीकरण नहीं होता है। इनमें से अधिकांश असुरक्षित व्यवस्था एवं अर्द्ध प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। फ्रांस एवं इटली में कैथोलिक मान्यता वाले लोगों में गर्भपात की अनुमति होती है जबकि पोलैंड जैसे देश में परिवार नियोजन एवं गर्भपात पर पूर्णतः रोक है।

15.2.4 लिंगानुपात में अंतर

लिंगानुपात पुरुष के संदर्भ में महिलाओं एवं महिलाओं के संदर्भ में पुरुषों के अनुपात को व्यक्त करता है। विकसित एवं विकासशील दोनों प्रकार के देशों में यह प्रमुख समस्या के रूप में सामने आया है। दोनों में अंतर यही है कि जहाँ विकसित देशों में पुरुषों की संख्या कम है वही विकासशील देशों में महिलाओं की संख्या कम है। यूरोपीय देशों सहित रूस में पुरुषों की संख्या कम है। विद्वानों द्वारा इसका प्रमुख कारण औपनिवेशिक प्रवृत्ति एवं दोनों विश्व युद्ध में पुरुषों का अधिक संख्या में मर जाना बताया जाता है। अमेरिका में भी पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम पाई जाती है। इसका कारण पुरुषों की जीवनशैली एवं दुर्घटनाओं द्वारा अधिक मृत्यु होना बताया जाता है। जैविक रूप से भी महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक प्रतिरोधकता पाई जाती है, जिसके कारण वह मजबूत होती हैं फिर भी विकासशील देशों में इनकी संख्या कम पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण वहां स्वास्थ्य, पोषण एवं देखभाल की उचित व्यवस्थाओं का अभाव बताया जाता है।

15.2.5 जीवन प्रत्याशा में अंतर

जीवन प्रत्याशा से तात्पर्य होता है किसी व्यक्ति की जन्म के समय संभावित आयु। विकसित देशों की जीवन प्रत्याशा विकासशील देशों से अधिक पाई जाती है। प्राप्त आंकड़ों एवं शोधों से ज्ञात होता है कि लगभग सभी विकसित देशों में जन कल्याण की उत्तम प्रणाली, जन स्वास्थ्य में सुधार, सुदृढ़ जीवन स्तर, उच्च रहन –सहन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के समुचित प्रसार के कारण इन देशों की जनसंख्या निराश्रित, अभाव एवं संक्रामक रोगों से मुक्त होती है। वर्ष 2011 में जनसंख्या आयोग से प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि विकसित देशों में जीवन प्रत्याशा जहाँ 70 वर्ष है, वही विकासशील एवं अल्पविकसित देशों में यह मात्र 59 वर्ष है। विकसित देशों में सामान्यतः जीवन प्रत्याशा उच्च पाई जाती है परंतु वहां निवास करने वाली प्रजातियों में भी यह भिन्न होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1978 की जनगणना से प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट हुआ है कि अश्वेतों की तुलना में श्वेतों की जीवन प्रत्याशा 5 वर्ष के लगभग अधिक होती है। इस प्रकार एक ही देश में निवास करने वाली प्रजातियों में अंतर का पाया जाना एक प्रमुख समस्या है।

15.2.6 उच्च नगरीकरण की समस्या

विकसित देशों की अर्थव्यवस्था उन्नत प्रकार की है जिसके कारण यहाँ औद्योगीकरण का स्तर उच्च पाया जाता है। इसी औद्योगिकरण का परिणाम होता है कि उच्च नगरीकरण का उच्च पाया जाना। वर्तमान समय में

विकसित देशों की लगभग 75% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है। इसी कारण नगर बहुत बड़े हो गए है। उनके विस्तार की गति भी काफी मंद है। इनकी अधिकांश नगरों की जनसंख्या एक करोड़ से अधिक पाई जाती है, जिसके कारण यह नगर मेगा सिटी में परिवर्तित हो चुके है। इन नगरों की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पाया जाने वाला प्रदूषण है। प्रदूषण के सभी स्वरूप चाहे जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण सभी विकराल रूप में विद्यमान होते है। अधिक जनसंख्या के कारण संरचनात्मक सुविधाओं में कमी पाई जाती है, जिसके कारण नगर के चतुर्दिक मलिन बस्तियों का पाया जाना आम बात होती है। इसके अतिरिक्त अपराध, महंगाई, जुआ एवं शराब इत्यादि से जुड़ी समस्याएँ यहाँ प्रचुर मात्रा में विद्यमान होती है।

15.3 विकासशील देशों की जनसंख्या संबंधित समस्याएँ

विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था अभी विकास की ओर अग्रसर है। यहाँ जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है जिसके कारण सभी लोगों तक विकास, रोजगार, अवसर एवं समानता की पहुंच नहीं हो पाती है। दूसरी तरफ यहाँ संसाधनों का वितरण भी असमान पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विकासशील देशों में जनसंख्या के संबंध में निम्न समस्याएँ उत्पन्न होते हैं –

15.3.1 जनसंख्या का असमान वितरण

विकासशील देशों में संपूर्ण विश्व जनसंख्या का लगभग 75ः भाग निवास करता है जबकि यहाँ आर्थिक संसाधनों का मात्र 15% भाग वितरित पाया जाता है। दूसरी तरफ विकसित देशों में जहाँ 25% जनसंख्या निवास करती है वहीं 85% आर्थिक संसाधन भरे पड़े है। ऐसी स्थिति में आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर संपूर्ण विश्व को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, संसाधन सम्पन्न एवं संसाधन विपन्न। इसके कारण उनके रहन – सहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना, रोजगार के अवसर, क्षेत्रीयता एवं जनांकिकीय इत्यादि दशाओं में काफी अंतर पाया जाता है। ऐसी स्थिति में इन देशों में अधिक ग्रामीण जनसंख्या, उच्च घनत्व एवं गरीबी का पाया जाना आम बात है। भुखमरी, अज्ञानता, अंधविश्वास जैसी कुरीतियां अपने चरम पर होती हैं, जिनकी जंजीरों को तोड़ पाना इन अर्थव्यवस्थाओं के लिए मुश्किल काम होता है।

15.3.2 प्रति व्यक्ति आय की कमी

एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के देशों में प्रजातीय, सांस्कृतिक, जातीय एवं भाषाई आधार पर काफी भिन्नता पाई जाती है। आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़ा होने के कारण इन देशों की प्रति व्यक्ति आय अत्यंत कम पाई जाती है। विश्व बैंक से प्राप्त आंकड़ों से विदित होता है कि अफ्रीका महाद्वीप के मोजांबिक एवं रवांडा जैसे देशों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 3,000 से भी कम है, वहीं दूसरी तरफ विकसित देशों में यह काफी अधिक पाई जाती है। विकासशील देशों के निवासियों की आय काफी कम होती है तथा उनमें एक देश से दूसरे देश में काफी भिन्नता पाई जाती है। इससे इस बात का बोध होता है कि ऐसी स्थिति में जिन समाजों में पूंजीपति एवं गरीब एक साथ रहते हैं, वहां पूंजीपतियों द्वारा गरीबों का अत्यधिक शोषण होता है। इसी शोषण का परिणाम होता है कि कभी – कभी यहाँ वर्ग संघर्ष भी हो जाते है।

15.3.3 खाद्यान्न की समस्या

विश्व के सभी विकासशील देश जनांकिकीय संक्रमण की द्वितीय अथवा तृतीय अवस्था से गुजर रहे है। ऐसी स्थिति में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों नियंत्रित हुई है, परंतु मृत्यु दर में गिरावट तीव्रता से आई है। इसके फलस्वरुप इन देशों की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। जिस तीव्रता से जनसंख्या में वृद्धि हुई है इस तीव्रता से खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। दूसरे तरफ इन देशों में उद्योगों का विकास उतना नहीं हो सका है कि रोजगार के माध्यम से लोगों को पर्याप्त आय प्राप्त हो सके। ऐसी स्थिति में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग खाद्यान्न की समस्या से जूझ रहा है। कुछ देशों में 1950 के पश्चात हरित क्रांति का प्रसार हुआ है। इसका प्रभाव देश के संपूर्ण भाग पर समान रूप से नहीं पड़ा है, जिसके कारण सामाजिक असमानता एवं आर्थिक विषमता में वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में पूंजीपति एवं बड़े भूमि धारक जहाँ अधिक संपन्न हुए हैं, वहीं बहुत बड़ी जनसंख्या या तो भूमिहीन है या खेतीहर मजदूर में परिवर्तित हो गई है। यह स्थिति भी खाद्यान्न की समस्या को और विकट कर देती है।

जनसंख्या के क्षेत्रीय स्वरूप पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो विदित होता है कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 74% भाग एशिया में निवास करता है, 17% जनसंख्या अफ्रीका में, जबकि शेष 9% जनसंख्या विश्व के अन्य भाग में पाई जाती है। एशिया के अधिकांश देश कृषि प्रधान है। यहाँ गहन कृषि के साथ विस्तृत कृषि भी की जाती है। इसके बावजूद भी ग्रामीण इलाकों में श्रमिकों का एक बड़ा भाग बेरोजगार है। किसी भी देश की ऐसी अवस्था को गुप्त बेरोजगारी कहा जाता है। दूसरी तरफ अफ्रीकी महाद्वीप में भाषायी, जातीय एवं सांस्कृतिक भिन्नताएं भी उच्च स्तर पर पाई जाती है। इस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व निम्न पाया जाता है परंतु मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र है। दक्षिण अमेरिका में भी विस्तृत खेती की जाती है परंतु प्रति एकड़ अथवा प्रति हेक्टेयर उत्पादन यहाँ भी विकसित देशों की तुलना में बहुत कम पाया जाता है। यहाँ का सामाजिक – सांस्कृतिक संगठन एशिया एवं अफ्रीका के देशों से भिन्न है। इस प्रकार इन सभी देशों में खाद्यान्न का संकट एक प्रमुख समस्या है।

15.3.4 संसाधनों की कमी

विकासशील देशों के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण चुनौती संसाधनों कि कमी है। यहाँ के संसाधनों के संबंध में विद्वानों द्वारा दो मत प्रकट किए जाते हैं पहले मत की समर्थकों का मानना है कि इन क्षेत्रों में संसाधनों की बहुत कमी है जिसके कारण यहाँ विकास नहीं हो पाया है। इसके विपरीत दूसरा वर्ग आशावादी है और उसका मानना है कि इन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया है जिसके कारण यहाँ संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाया है और ये देश विकास की यात्रा में पीछे रह गए है।

कुछ विद्वानों का समूह इस बात को भी स्वीकार करता है कि विकासशील देशों में इतनी गतिशीलता है कि इनका समुचित विकास खाद्यान्न एवं अन्य संसाधनों के उत्पादन को चार से पांच प्रतिशत तक बढ़ा सकता है। इस बढ़े हुए खाद्यान्न से विदेश के साथ असंतुलित व्यापार को भी ठीक किया जा सकता है। साथ ही साथ विदेशी मुद्रा अर्जित करके देश के विकास की गति को और तीव्र किया जा सकता है।

विकासशील देशों के सम्मुख एक प्रमुख समस्या वित्तीय संसाधनों की भारी कमी भी है। इसे पूरा करने के लिए इन देशों को या तो दूसरे देशों से उच्च ब्याज पर ऋण लेना पड़ता है या अपने नागरिकों पर भारी करारोपण करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में विकसित देशों द्वारा कठोर शर्तें भी रखी जाती हैं जिसका उनके विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन सभी विकासशील देशों की आर्थिक समस्या बहुत विकट है, जिसके कारण यह देश संकट के मकड़ जाल में फंसे हुए है।

15.3.5 आवास की समस्या

रोटी कपड़ा के साथ ही आवास भी मानव की आधारभूत आवश्यकता है जिसकी अनुपस्थिति में मानव का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। विकासशील देशों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, यही कारण है कि यहाँ जनसंख्या के अनुपात में आवासों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाती है। यह विकासशील देशों के सम्मुख प्रमुख विकट समस्या है। ग्रामीण परिवेश में गरीबी एवं निर्धनता के कारण जनसंख्या पर आर्थिक दबाव अधिक रहता है, जिसके कारण वह अपने हेतु आवश्यक घरों का निर्माण नहीं कर पाते । ऐसी स्थिति में झुग्गी –झोपड़ी, कच्चे मकान एवं तंबुओं में रहने के लिए विवश होते है। आर्थिक अभावों के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार हेतु जब वे नगरी क्षेत्र की ओर प्रवास करते हैं, तब वह या तो महंगे किराए के घरों में रहने के लिए विवश होते हैं या सरकारी जमीनों पर झोपड़ियां डालकर रहते है। ऐसी स्थिति में नगरीय क्षेत्र के चतुर्दिक मलिन बस्तियों का विकास होता है। यह भी विकासशील देशों की प्रमुख समस्या है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता हो जाती है कि सरकारें प्रत्येक परिवार हेतु एक अच्छे मकान की व्यवस्था करें क्योंकि ऐसी मलिन बस्तियां भविष्य में गंदी बस्तियों में परिवर्तित हो जाती हैं।

15.4 भारत में जनसंख्या की समस्या

जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। वर्ष 2011 की जनगणना से प्राप्त आकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,21,08,54,977 थी, जिसमें पुरुषों की संख्या 62,32,70,258 तथा महिलाओं की संख्या 58,75,84,719 थी। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. है। ऐसी स्थिति में इसके सभी नागरिकों तक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित कर पाना सरकारों के लिए आसान नहीं होता है।

आजादी के पश्चात विभिन्न सरकारों द्वारा अधिकतम प्रयास भी किए गए फिर अनेक समस्याएँ अभी भी विद्यमान हैं जिंका समाधान करना अति आवश्यक है। वे समस्याएँ निम्नलिखित है –

1. **जनसंख्या का असमान वितरण** : कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। देश के आंतरिक भाग में भी जनसंख्या का वितरण बहुत आसमान है। कहीं पर इसका संकेन्द्रण अधिक पाया जाता है तो कहीं विरल है, कुछ क्षेत्र ऐसे भी पाए जाते है जो एकदम से जनशून्य है। देश के मैदानी भागों का उच्चावच समतल है जिसके कारण कृषि के साथ जीवन के लिए आवश्यक अन्य सुविधाएँ आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इन क्षेत्रों में यातायात के साधनों एवं मार्गों का विकास आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पर कृषि उत्पादों, औद्योगिक उत्पादों तथा सेवाओं की आपूर्ति प्रत्येक स्थान तक आसानी से हो जाती है। ये क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि प्रधान जिसके कारण अधिक से अधिक जनसंख्या के पोषण में यह सक्षम है। यही कारण है कि मैदानी भाग में अधिक जनसंख्या निवास करती है।

   पर्वतीय एवं पठारी भागों में कम जनसंख्या निवास करती है इसका मुख्य कारण वहाँ का उच्चावचीय स्वरूप है। इन क्षेत्रों के समतलीय भाग मानव निवास, कृषि कार्य के लिए एवं अन्य अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करते है जिसके कारण यहाँ अधिक जनसंख्या पाई जाती है। दूसरी तरफ पर्वतीय एवं पठारी ढलानों पर कम जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाकलापों का सम्पादन होता है। यहाँ आजीविका का मुख्य साधन कृषि एवं मजदूरी होती है। वह भी सभी नागरिकों को वर्षभर रोजगार नहीं प्रदान कर पाती है, इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव होता है। इसके विपरित शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक क्रियाकलापों के अतिरिक्त कार्यों का सम्पादन होता है। इसी कारण उद्योगों एवं सेवाओं में यहाँ रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होते है, जिसके कारण स्थानीय लोगों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से भी अधिक संख्या में लोग आ जाते है। आधुनिक तरीके से विकास के अन्य घटकों का यहाँ उन्नत विकास होता है, इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार जैसी आवश्यकताएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। इनके कारण भी ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक लोग शहरों की ओर प्रवास करते है। शहरी क्षेत्रों में दिन – प्रतिदिन लगातार जनसंख्या का घनत्व बढ़ता जा रहा है।

2. **तीव्र जनसंख्या वृद्धि** : विश्व के अन्य विकासशील देशों की भांति भारत में भी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। भारत भी अभी जनसंख्या संक्रमण की अवस्था से गुजर रहा है इसका प्रभाव भी यहाँ की जनसंख्या पर देखा जा सकता है। संक्रमण अवस्था के दौरान प्रारम्भिक समय में तो जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों उच्च स्तर पर थी बाद के समयों में जिस गति से मृत्यु दर में कमी आयी है उस दर से जन्म दर में कमी नहीं दर्ज की गई जिसका परिणाम विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि के रूप में सामने आता है। आजादी से लेकर वर्तमान समय तक के जनसंख्या से प्राप्त आकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि पूर्व में जो जन्म दर 37 प्रति हजार थी घटकर 25 हो गई उसी अवधि में मृत्यु दर भी 40 प्रति हजार से घटकर 8 प्रति हजार प्राप्त हुई है। इस प्रकार जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों के परिवर्तन में अंतर होने के कारण जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है। जनसंख्या के आकड़ों से विदित होता है कि जो जनसंख्या वर्ष 1901 में 23.8 करोड़ थी वह बढ़कर 1951 ई. में 36.11 करोड़, 2001 में 102.8 करोड़ तथा 2011 में 121.01 करोड़ दर्ज की गई है। इस प्रकार नियोजन काल भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है। भारतवर्ष में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारकों में कृषि एवं उद्योग का तीव्र गति से विकास, स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं में सुधार, जीवन स्तर में सुधार, आर्थिक क्षेत्र का विकास, जन्म दर में आवश्यकता के अनुरूप कमी का नहीं होना आदि है।

3. **प्रति व्यक्ति आय में कमी** : भारत की अर्थव्यवस्था का स्वरूप विकासशील का है। तीसरी दुनिया के अन्य विकासशील देशों की भांति भारत भी औपनिवेशिकता का शिकार रहा है तथा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्वतन्त्रता प्राप्त की है। जिस अनुपात में यहाँ जनसंख्या में वृद्धि हुई है उस अनुपात में अर्थव्यवस्था तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हुई है। कृषि सहित विकास के अन्य क्षेत्रों से भी अधिक आय नहीं हो पायी जितनी होनी चाहिए । उत्पादन के सभी क्षेत्रों के साथ ही सेवाओं के क्षेत्र से पर्याप्त आय होने के कारण

देश की राष्ट्रीय आय के साथ प्रति व्यक्ति आय भी कम है। इन्हीं सभी कारणों का परिणाम है कि देश की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है।

4. **खाद्यान्न की समस्या** : व्यक्ति के जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता भोजन है। भारत सहित सम्पूर्ण विश्व के लिए खाद्यान्न की समस्या गरीबों के समक्ष मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। भारत जैसे देशों में धनाभाव तथा खाद्य सामाग्री की कम उपलब्धता होने के कारण गरीब व्यक्तियों की क्रय शक्ति कम होती है, जिसके कारण खाद्यान्न की समस्या और विकट हो जाती है। देश में खाद्य सामाग्री की उपलब्ध मात्रा अनेक सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक विफलता के कारण सभी वर्गों तक एक समान रूप उपलब्ध नहीं हो पाती है। आजादी के पश्चात भारत सरकार के साथ ही अनेक राज्य सरकारों ने भी खाद्यान्न आपूर्ति के प्रयास किए । इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए गरीबी मिटाने तथा लोगों तक खाद्य औपूर्ति सुनिश्चित हो सके के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई । इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ दशकों में ही देश खाद्यान्न आयातक से खाद्यान्न निर्यातक में परिवर्तित हो गया। इससे खाद्यान्न की समस्या का कुछ सीमा तक तो समाधान किया गया परंतु तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के कारण सभी लोगों तक नहीं हो पाया। देश की विशालतम जनसंख्या तक खाद्य आपूर्ति करने के लिए विदेशों से खाद्यान्न का आयात भी करना पड़ता है जिससे देश की अधिक विदेशी मुद्रा व्यय हो जाती है।

5. **संसाधनों की कमी** : वे सभी वस्तुएँ जो व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम होती है संसाधन कहलाती है। अगर कोई वस्तु किसी व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है तो वह संसाधन नहीं कही जा सकती है। संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते है। प्राकृतिक संसाधन एव मानवीय संसाधान। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति प्रदत्त होते है जबकि मानवीय संसाधन व्यक्तियों की कुशलता, तकनीकी, प्रद्योगिकी, विकास की अवस्था आदि के आधार पर विकसित होते है। जनसंख्या एवं संसाधनों की उपलब्धता एवं संभाव्यता के आकड़ों का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि हुई है उस अनुपात से संसाधनों का न तो उपत्पादन हुआ है नहीं वृद्धि हुई है। देश में जो संसाधन उपलब्ध भी है उनका वितरण सम्पूर्ण देश में एक समान नहीं है। कहीं पर ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं तो कहीं विरल । छोटा नागपुर का क्षेत्र जहाँ खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की दृष्टिकोण से अधिक सम्पन्न है वहीं मरुस्थलीय एवं पहाड़ी क्षेत्र संसाधनों की दृष्टि से विपन्न है। इस प्रकार देश में जनसंख्या और संसाधन का सहसंबंध नकारात्मक प्रवृत्ति है।

6. **आवास की कमी का** : तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के कारण भारत में आवास की समस्या गंभीर होती जा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि जिस अनुपात में ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात में आवासों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। भारत में आवासीय समस्या का मुख्य कारण धन का असमान वितरण तथा निर्धनता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिक, निर्धन और कम आय वर्ग वाले लोग कच्चे घरों एवं झोपड़ियों मेन रहते है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों, पठारी एवं पहाड़ी भागों में निवास करने वाले लोग इतने निर्धन हैं कि वे अपनी झोपड़ी बनाने में सक्षम नहीं होते है। घास – फूस एवं पत्तियों से वे अपनी झोपड़ियाँ और अस्थायी घरों का निर्माण करते हैं जो अधिक समय तक टिकते नहीं है। निर्धनता एवं धनाभाव के कारण ये लोग अपने घरों और टूटी झोपड़ियों का निर्माण एवं मरम्मत नहीं कर पाते है। पहाड़ी एवं पठारी भागों में निवास करने वाले गरीब लोग आवास के अभाव में पेड़ों के नीचे, गुफाओं और खुले में निवास करने को विवश होते है।

   आवासीय समस्या का सबसे भयंकर एवं जटिल स्वरूप नगरीय क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक संख्या में लोगों का नगरों की ओर प्रवास के कारण नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। जिस अनुपात से इनके आगमन से नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ रही है उसी अनुपात घरों एवं भवनों का निर्माण नहीं हो पाता है। अधिक संख्या में लोगों के आने जो आवासीय संकट उत्पन्न होता है उसका प्रतिफल मलिन बस्तियों के रूप में सामने आता है। इन मलिन बस्तियों में जनसंख्या का दबाव अधिक होता है जबकि जनसंख्या के अनुपात में वहाँ सुविधाएँ नगण्य हो जाती है। ऐसी स्थिति इन मलिन बस्तियों में निवास करने वाले लोगों का जीवन बद से बदतर हो जाता है।

7. **स्वस्थ्य की समस्या** : किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता एवं वृद्धि – विकास का सबसे बड़ा बोधक स्वास्थ्य होता है। कोई भी व्यक्ति तब तक अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता है जब तक वह पूरी तरह

से स्वस्थ न हो । यह भी कहा जाता है कि स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का विकास होता है। जब कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है तब वह अपनी पुरी क्षमता से विभिन्न प्रकार के कार्यों का सम्पादन करता है और उसका परिणाम भी उच्च स्तरीय होता है। इसके विपरीत जब एक व्यक्ति विविध प्रकार की बीमारियों एवं व्याधियों से ग्रसित होता है तब स्वतः ही उसकी कार्य क्षमता का ह्रास हो जाता है और उसके द्वारा सम्पन्न कार्य अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करते है।

स्वस्थ्य की समस्या भारत में जनसंख्या से जुड़ी प्रमुख समस्याओं में से एक है। भारत की अधिक जनसंख्या तक उच्च गुणवत्ता वाली स्वस्थ्य सुविधाओं की पहुँच नहीं हो पाती है। जिस अनुपात से देश में जनसंख्या वृद्धि हुई है उस अनुपात से देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास नहीं हुआ है। देश में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा भी स्वस्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में व्यय नहीं किया जाता है। जिसके कारण सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों एवं अस्पतालों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का गुणवत्ता पूर्ण विकास हुआ है परंतु ये सुविधाएँ इतनी महँगी है कि सामान्य और गरीब व्यक्तियों की इन तक पहुँच ही नहीं हो पाती है। देश के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों एवं समाज के अंतिम वर्ग के लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं के समुचित प्रसार नहीं होने के कारण ये लोग नीम – हकीम के जाल में फस जाते है। इससे छोटी – छोटी बीमारियां विकराल रूप धारण कर लेती हैं साथ ही अत्यधिक जन एवं धन की हानि होती है जिसका देश एवं अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

8. **शिक्षा की समस्या** : शिक्षा किसी भी व्यक्ति के सम्मानपूर्ण जीवन यापन का प्रमुख माध्यम है। शिक्षा विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है। शिक्षा से ही व्यक्ति के सोचने, समझने, उचित व्यवहार करने, निर्णय लेने जैसी कुशलताओं का विकास होता है साथ ही साथ व्यक्ति का सर्वांगीण विकास भी होता है। भारत जैसे विशाल देश में शिक्षा की समृद्ध परंपरा प्राचीन काल से ही देखी जा रही है। प्राचीन काल से वर्तमान तक भारत में शिक्षा के विविध आयाम देखे जाते है और वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली विश्व के प्रमुख देशों के ही समान है। इतना होने के बावजूद भी भारत में तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या और इसके विशाल आकार होने पर भी शिक्षा की समस्या बनी हुई है। देश में जिस अनुपात से जनसंख्या बढ़ी है उस अनुपात में न तो शिक्षा का अवसंरचनात्मक ढाँचा बढ़ा है नहीं नए विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है। कक्षाओं में शिक्षक एवं विद्यार्थी का जो अनुपात होना चाहिए उससे काफी नीचे है। राज्य एवं केंद्र सरकारों द्वारा भी बजट का बहुत कम हिस्सा शिक्षा पर व्यय किया जाता है। केंद्र के साथ ही कुछ राज्य सरकारें भी शिक्षा बजट में लगातार कटौती कर रहीं है। पाठ्यक्रम का निर्धारण, बच्चों के नामांकन, पुस्तकों एवं कापियों का वितरण, परीक्षाओं के सम्पादन की अनियमितता आदि के कारण बच्चों में शिक्षा के प्रति अरुचि पैदा हो रही है। इन सभी संयुक्त प्रभाव यह है कि देश में शिक्षा की दर निम्न स्तरीय पायी जा रही है।

9. **कुपोषण** : किसी व्यक्ति के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों की आपूर्ति नहीं हो पाने की स्थित कुपोषण कहलाती है। खाद्यपदार्थों की अपर्याप्तता, निर्धनता, अज्ञानता, विपणन सेवाओं की विफलता आदि के कारण देश के विशाल जनसंख्या तक गुणवत्ता युक्त खाद्यसामाग्री की उपलब्धता नहीं होने के कारण अधिक संख्या में लोग कुपोषण के शिकार हो जाते है। कुपोषण के कई प्रकार होते हैं (अ) अल्प पोषण, (ब) अति पोषण, (स) असंतुलित पोषण एवं (द) विशिष्ट अभाव । भारतीय परिस्थितियों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि यहाँ मुख्य रूप से अल्प पोषण अधिक व्यापक एवं प्रधान है। यहाँ की आवश्यकता के अनुसार स्वस्थ्य रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है किन्तु विभिन्न अवलोकनों से ज्ञात हुआ है कि भारत में एक व्यक्ति को मात्र 1950 कैलोरी ही प्राप्त हो रही है। एक अन्य सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि सम्पूर्ण देश की जनसंख्या के 30% गरीब लोगों को मात्र औसतन 1700 कैलोरी, 40% लोगों को 1700 से 2300 कैलोरी के मध्य तथा शेष 30% लोगों को ही 2300 कैलोरी से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। किसी भी व्यक्ति के लिए तिलहन, दलहन, प्रोटीनयुक्त पदार्थ एवं चर्बी युक्त पदार्थों की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में बढ़ती हुई जनसंख्या तथा कम खाद्यपदार्थों की आपूर्ति के कारण कुपोषण की समस्या बढ़ती जा रही है और अधिक संख्या में लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार होते जा रहें है।

10. **जल की समस्या** : जल ही जीवन है की उक्ति आज भी सार्थक है साथ ही इसके महत्त्व को प्राचीन काल से लेकर आज तक स्वीकार किया गया है। जल के बिना मानव सभ्यता की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। विश्व की सभी संस्कृतियाँ जल स्त्रोतों या नदियों के किनारे ही विकसित हुई है मिश्र की सभ्यता नील नदी, हड़प्पा की सभ्यता सिंधु नदी आदि । आधुनिक समय का अवलोकन करने पर भी स्पष्ट होता है प्रमुख औद्योगिक एवं व्यापारिक नगर या तो बड़ी नदियों के तट पर स्थित हैं या समुद्र के तटवर्ती इलाकों में । ऐसी स्थिति में बिना जल के मानव सभ्यता की कल्पना नहीं की जा सकती है। जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है उसके पश्चात उद्योग एवं घरेलू उपयोग आते है। जल विज्ञान से प्राप्त आकड़ों में बताया जाता है कि विश्व कि सम्पूर्ण जलराशि का 97% भाग महासागरों एवं सागरों में संचित है जोकि खारा है और मानव के लिए अनुपयुक्त है। शेष 3% में से 2% ध्रुवों एवं पर्वतों के शिखरों पर हिम के रूप में संचित है और मात्र 1% जलराशि ही मानव के उपयोग के लिए बची हुई है।

    भारत का विशाल आकार एवं अधिक जनसंख्या के संदर्भ में जल की समस्या यहाँ अब गंभीर होती जा रही है। देश में जल की उपलब्धता एवं वितरण भी बहुत ही असमान है कहीं पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है तो कहीं एकदम नहीं । तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या ने जल संकट को और विकट कर दिया है। अधिक लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने, घरेलू एवं औद्योगिक जरूरतों की पूर्ति हेतु अधिक जल का दोहन हो रहा है, इसका परिणाम यह हो रहा है कि भूमिगत जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या की खाद्य को पूर्ण करने के लिए लायी गई हरित क्रांति ने जहाँ एक तरफ खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ा कर खाद्य समस्या का समाधान करके देश को आत्म निर्भर बनाया वहीं अधिक से अधिक मात्रा में जल का दोहन करके पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल संकट को खड़ा कर दिया है। आधुनिक तरीके की जीवन शैली ने भी जल समस्या को और अधिक बढ़ा दिया है।

11. **यातायात की समस्या** :किसी भी देश या अर्थव्यवस्था के विकास के मानकों में यातायात एवं परिवहन तंत्र का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन्हीं के माध्यम से व्यक्तियों, वस्तुओं एवं सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाया जाता है। जिन देशों में यातायात पूर्ण विकसित है उच्च स्तरीय वहाँ वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से हो जाती है। सभी व्यक्तियों तक वस्तुओं एवं सेवाओं की समुचित आपूर्ति होने के कारण नागरिकों का सर्वांगीण विकास होता है। इसके जिन स्थानों पर यातायात के साधनों का अभाव है या आंशिक विकास हुआ है, वहाँ वस्तुओं एवं सेवाओं की समय से आपूर्ति नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में मूलभूत आवश्यकताओं के अभाव में कल्याण के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नहीं हो पता है। ऐसी स्थिति में ये क्षेत्र विकास के दौड़ में पीछे छुट जाते है। परिवहन के विविध स्वरूप पाए जाते है जैसे सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन एवं जल परिवहन ।

    परिवहन के इन माध्यमों के विकास हेतु अलग – अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ पाई जाती है। भौगोलिक उच्चावच की अनुकूल परिस्थितियाँ इनके निर्माण एवं विकास को प्रोत्साहन मिलता है। प्रतिकूल दशाओं में जहाँ एक ओर इनके निर्माण में अनेक कठिनाई आती है वहीं अधिक मात्रा धन भी खर्च करना पड़ता है। जाम की समस्या भी प्रमुख है जिससे वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति में देरी होती है। कुछ जल्दी खराब होने वाली वस्तुएँ नष्ट भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में जहाँ कुछ लोग आवश्यक वस्तुओं के उपभोग से वंचित हो जाते हैं वहीं आर्थिक हानि भी होती है।

12. **बेरोजगारी की समस्या** : जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात में रोजगार के अवसरों का उपलब्ध नहीं हो पाने की स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। दूसरे शब्दों में जब कोई व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य हो तथा वह कार्य भी करना चाहता हो परंतु उसे कार्य उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो तो ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहते है। भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में बेरोजगारी सबसे गंभीर समस्या है। बेरोजगारी ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है है परंतु दोनों जगह इसका स्वरूप भिन्न – भिन्न होता है। भारत में विद्यमान बेरोजगारी के प्रमुख स्वरूप निम्नलिखित है –

    - **सामान्य बेरोजगारी** – व्यक्ति की सक्रिय आयु वर्ग में जब लोगों को उनकी योग्यता एवं इच्छा के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो उसे सामान्य बेरोजगारी कहते है।

- **प्रच्छन्न बेरोजगारी** – किसी रोजगार में संलग्न ऐसे व्यक्ति जिन्हें उस वस्तु या सेवा के उत्पादन से हटा भी दिया जाए तो उस वस्तु या सेवा के उत्पादन के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ऐसे व्यक्तियों को ही प्रच्छन्न बेरोजगार कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय कृषि में देखा जा सकता है, जहाँ कार्याभाव के कारण आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कृषि कार्य में संलग्न है। यदि इन्हें कृषि कार्य से हटा दिया जाए तो कृषि उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

- **मौसमी बेरोजगारी** – मौसमी बेरोजगारी से तात्पर्य ऐसी स्थिति से जिसमें व्यक्ति को साल के कुछ महीनों में रोजगार अवसर उपलब्ध हो जाते है, शेष समय में वे बेरोजगार ही रहतें है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत में कृषि मजदूर है। कृषि कार्य कुछ निश्चित समय में ही संपादित होते है इसलिए फसलों की बुआई, निराई एवं गुड़ाई के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है। इन्हीं समयों में उन्हें रोजगार मिल जाते है बाकी समय वे खाली बैठते है।

- **शिक्षित बेरोजगारी** – शिक्षित बेरोजगारी उस समय उत्पन्न होती है जब एक पढ़े – लिखे, कुशल, प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप रोजगार नहीं मिल पता है। इस प्रकार की अधिकांश बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है।

- **औद्योगिक बेरोजगारी** – औद्योगिक बेरोजगारी की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब औद्योगिक इकाइयों में स्वचालित मशीनों एवं संगणकों आदि के प्रयोग से श्रमिकों की छटनी होने लगती है और अधिक मात्रा में लोग बेरोजगारी के शिकार हो जाते है। इस प्रकार की बेरोजगारी अधिक मात्रा में नगरीय एवं उपनगरीय क्षेत्रों में मिलती है।

13. **कृषि योग्य भूमि की समस्या** :सभी व्यक्ति के लिए भोजन मूलभूत आवश्यकता है, बिना इसके मानव अस्तित्व की कल्पना नही की जा सकती है। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के लिए अधिक से अधिक खाद्य पदार्थो की आवश्यकता होती है। इन खाद्य पदार्थों की आपूर्ति का एकमात्र स्त्रोत कृषि ही है। अधिक खाद्यान्नों के उत्पादन के अधिक से अधिक मात्रा में कृषि भूमि की आवश्यकता होती है। बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि भूमि लगातार संकुचित होती जा रही है। अधिक जनसंख्या के लिए अधिक मात्रा में अधिवास योग्य भूमि, औद्योगिक ईकाइयाँ, परिवहन के मार्ग, कार्यालय, शिक्षण संस्थान, बाजार एवं मनोरंजन स्थलों की आवश्यकता होती है। इन सभी को बनाने के लिए कृषि योग्य भूमि का अधिक से अधिक मात्रा में कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। इस प्रकार इन विविध कार्यों के लिए लगातार भूमि अधिग्रहण से कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है।

14. **सेवाओं के समावेसित वितरण की समस्या** : भारत की लगभग 68% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। उसका वितरण देश के सभी भागों में एक समान नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही वह दूर – दराज के क्षेत्रों में निवास करती है, इसके साथ ही कुछ जनसंख्या पर्वतीय, पठारी, दलदलीय एवं अगम्य क्षेत्रों में भी रहती है। आधुनिक तरीके से विकसित सेवाएँ नगरीय और उससे संलग्न क्षेत्रों में अधिक प्रसारित होती है। जैसे – जैसे नगरीय क्षेत्रों से दूर जाते है वैसे – वैसे लोगों तक इनकी पहुँच कम होती है। कुछ चुनिन्दा लोगों को ही इससे फायदा होता है जबकि अधिसंख्यक जनसंख्या तक इन सेवाओं की आपूर्ति नहीं हो पाती है। इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव गरीब जनता पर पड़ता है, जो देश के विकास में बाधक बनता है।

15. **औद्योगीकरण की समस्या** : उद्योगों को आधुनिक विकास की धुरी कहा जाता है। अध्ययन में यह पाया गया है जिन देशों का औद्योगिक विकास स्तर जितना उच्च होता है वहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक विकास की दर अधिक पायी जाती है। आधुनिक काल में भारत औपनिवेशिक शक्तियों का शिकार रहा है जिसके कारण यहाँ उद्योगों के विकास पर कम ध्यान दिया गया है। प्राचीन काल एवं मध्य काल में भारत के विभिन्न राज्यों में कुटीर एवं लघु उद्योगों के प्रमाण मिलते है। भारत में आधुनिक तरीके से उद्योगों के विकास की नीव दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा रखी गयी थी। उसके पश्चात देश में विभिन्न चरणों में उद्योगों का विकास हुआ है। भारत में उद्योगों के वितरण का स्वरूप बहुत ही असमान है। यह कुछ क्षेत्रों में ही सीमित है। इससे मुख्य रूप से दो प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होती है, एक तो इनमें रोजगार प्राप्त करने के लिए लोगों को अधिक दूरी तय करनी

पड़ती है दूसरी ओर इनसे प्राप्त उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुचानें अधिक व्यय के साथ अधिक समय भी लगता है।

16. **सामाजिक एवं सांप्रदायिक दंगों की समस्या** :भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में विविध धर्म एवं मान्यताओं के लोग एक साथ रहते है। उनके रहन – सहन, विश्वास, धार्मिक मान्यताएँ एवं परम्पराएँ अलग – अलग होती है। इसी के अनुसार उनके विविध कार्यक्रम एवं आयोजन भी होते है। कभी – कभी दो विपरीत मान्यताओं वाले लोगों के बीच विवाद हो जाते है। कुछ परिस्थितियों में इनका स्वरूप हिंसक होता जाता है। ऐसी स्थिति में अधिक मात्रा में जन एवं धन की हानि होती है। इसका देश एवं अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

यदि सरकारों द्वारा इन समस्याओं का समुचित प्रबंधन कर दिया जाए तो भारत की यह विशाल जनसंख्या संसाधन में परिवर्तित हो सकती है। इस मानवीय संसाधन का उपयोग करके भारत विश्व की महाशक्ति बन सकता है और विकसित देशों की श्रेणी में आ सकता है।

15.5 सारांश

आपने इस इकाई में जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएँ एवं भारत में जनसंख्या की समस्याओं का अध्ययन किया है। आप समझ गए होगें कि जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या के अन्य तत्वों के साथ ही उसकी समस्याओं का भी अध्ययन करना अत्यंत जरूरी है। वास्तव में किसी देश की जनसंख्या तथा वहाँ का सबसे बड़ा संसाधन होती है जो उसकी भौगोलिक अवस्थिति, सरकारी नीतियों, सांस्कृतिक संगठन आदि का प्रतिफल होती है। सम्पूर्ण विश्व में जनसंख्या की समस्या एक समान नहीं है। जहाँ विकसित देशों में अल्प जनसंख्या पाई जाती है वहीं विकासशील देश अधिक जनसंख्या का सामना कर रहें है। इस तरह दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाएँ किसी न किसी प्रकार की समस्या का सामना अवश्य ही कर रही है।

15.6 स्वमूल्यांकन प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

1. विकसित देशों में सम्पूर्ण विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है।

   (क) 20% (ख) 25% (ग) 40% (घ) 52%

2. विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है।

   (क) 88 (ख) 62 (ग) 44 (घ) 36

3. विकसित देशों की लगभग कितनी जनसंख्या नगरों में निवास करती है।

   (क) 50% (ख) 58% (ग) 75% (घ) 86%

4. विकासशील देशों में लगभग विश्व के सम्पूर्ण आर्थिक संसाधनों का कितना भाग वितरित पाया जाता है।

   (क) 5% (ख) 15% (ग) 22% (घ) 36%

5. अफ्रीका महाद्वीप में विश्व सम्पूर्ण विश्व की लगभग कितनी जनसंख्या निवास करती है।

   (क) 15%ss (ख) 17% (ग) 21% (घ) 24%

15.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

Bogue] D- J-] 1969] Principles of Demography] John Wiley] N-Y-

Clarke] John I-] 1973] Population Geography] Pergaman Press] Oxford-

Crook] Nigel] 1997] Principles of Population and Development] Pergaman Press] N- Y-

Garmier] J- B-] 1970] Geography of Population] Longman] London-

Mamoria] C- B-] 1981] India's Population Problem] Kitab Mahal] New Delhi-

Premi] M- K-] 1991] India's Population] Heading Towards a Billion] B- R- Publishing Corporation-

Blassoff] M- and Srinivasan K-] 2001] Population Development Nexus in India : Challenges for the New Millennium] Tata McGraw Hill] New Delhi-

Woods] R-] 1979] Population Analysis in Geography] Longman] London-

Zelinsky] W-] 1966] A Prologue to Population Geography] Prentice Hall-

चन्दना, आर. सी., 2022, जनसंख्या भूगोल – संकल्पना, नियंत्रक व विश्व प्रारूप, कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

चन्दना, आर. सी., 2022, भारत : जनसंख्या (जनसंख्या भूगोल – भाग 2), कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

मौर्या, एस. डी., 2005, जनसंख्या भूगोल, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद.

ओझा, आर. पी., 1984, जनसंख्या भूगोल, प्रतिभा प्रकाशन.

हीरा लाल, 2000, जनसंख्या भूगोल के मूल तत्व, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली.

तिवारी, राम कुमार, 2023, जनसंख्या भूगोल, प्रवालिका पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद.

15.8 अभ्यास प्रश्न (सत्रांत परीक्षा की तैयारी)

1. जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्याओं की व्याख्या कीजिए?
2. विकसित देशों की जनसंख्या की समस्याओं का वर्णन कीजिए?
3. विकासशील देशों में जनसंख्या से जुड़ी समस्याओं का उल्लेख कीजिए?

इकाई–16 जनसंख्या नीति का अर्थ, आवश्यकता एवं उद्देश्य, भारत की जनसंख्या नीति, नई जनसंख्या नीति

इकाई की रूपरेखा

16.0 प्रस्तावना

16.1 उद्देश्य

16.2 जनसंख्या नीति की परिभाषा

16.3 जनसंख्या नीतियों की विशेषताएं

16.4 जनसंख्या नीतियों के उद्देश्य

16.5 विकसित देशों की जनसंख्या नीति

16.6 विकासशील देशों की जनसंख्या नीति

16.7 भारत की जनसंख्या नीति

16.8 सारांश

16.9 स्वमूल्यांकन प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

16.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

16.11 अभ्यास प्रश्न (सत्रांत परीक्षा की तैयारी)

16.0 प्रस्तावना

जनसंख्या नीति किसी देश की सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और इसका लक्ष्य देश की जनसंख्या को बढ़ाकर या घटाकर प्रभावित करना है। जिस देश की जनसंख्या अधिक है उसके जनसंख्या वृद्धि के आकार को कम करना और जिन देशों में जनसंख्या कम है, उसके जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाना जनसंख्या नीति कहलाती है।

16.1 उद्देश्य

जनसंख्या किसी भी देश का सबसे महत्त्वपूर्ण संसाधन होती है। जब किसी देश की जनसंख्या और वहाँ उपलब्ध संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित हो जाता है तब उसे अनुकूलतम जनसंख्या कहते है। अनुकूलतम जनसंख्या से कम या अधिक होने की दोनों स्थितियाँ समस्याएँ उत्पन्न करती है। ऐसी स्थिति में सभी देशों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप जनसंख्या नीतियों की घोषणा की जाती है। इस इकाई के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है –

1. जनसंख्या नीति के अर्थ, आवश्यकता एवं उद्देश्य को स्पष्ट करना।
2. भारत में जनसंख्या नीति और नई जनसंख्या नीति – 2000 की आवश्यकता एवं उद्देश्य का वर्णन करना।

16.2 जनसंख्या नीति की परिभाषा

किसी देश का एक प्रमुख पहलू उसकी जनसंख्या का आकार है। अधिक जनसंख्या के कारण किसी देश में अत्यधिक संसाधनों का उपयोग होता है। स्वास्थ्य, शासन व्यवस्था, शिक्षा, संसाधनों और सेवाओं पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं दूसरी ओर एक आबादी कम आबादी वाली हो सकती है, जो अक्सर अस्थिर होती है। ऐसी स्थिति के कारण आर्थिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि आबादी में कामकाजी उम्र के कम वयस्क होते है। इसीलिए कई

सरकारें अधिक जनसंख्या और कम जनसंख्या से निपटने के लिए जनसंख्या नीति का उपयोग एक औजार के रूप में करते है।

यूनेस्को के अनुसार जनसंख्या नीति के अंतर्गत वे सभी कौशल, उपाय और कार्यक्रम सम्मिलित किए जाते हैं, जो विशिष्ट जनांकिकीय चरों जैसे जनसंख्या आकर, जनसंख्या विश्लेषण, जनसंख्या वृद्धि, भौगोलिक वितरण एवं जनांकिकीय विशेषताओं को प्रभावित करते हुए आर्थिक, सामाजिक, जनांकिकीय राजनीतिक एवं अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योगदान हेतु प्रयुक्त किए जाते है।

उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि जनसंख्या नीति किसी सरकार की वह दस्तावेज है जिसमें देश के संसाधन एवं जनसंख्या के बीच संतुलन बना रहे इस बात पर ज़ोर दिया जाता है। इसीलिए किसी भी देश को जनसंख्या नीति की आवश्यकता पड़ती है।

16.3 जनसंख्या नीतियों की विशेषताएं

भविष्य की जनसांख्यिकी प्रवृत्तियों एवं परिवर्तनों की भविष्यवाणी करने के लिए एक सरकार अपने अतीत एवं वर्तमान जनसंख्या की जनसांख्यिकी जांच करेगी। किसी भी देश के पास मौजूद संसाधनों में इष्टतम जनसंख्या आकर निर्धारित करने में सहयोग करता है। इससे देश के लिए सबसे उपयुक्त जनसंख्या नीतियां चुनी जाएगी। विभिन्न जनसंख्या नीतियों के भिन्न – भिन्न घटक होते हैं, इसलिए जनसंख्या नीतियों के निर्णय लेते समय तीन मुख्य तत्वों पर विचार किया जा सकता है। एक तत्व निम्नलिखित हैं –

- प्रजननता
- मृत्यु दर
- प्रवास

16.3.1 प्रजनन क्षमता

प्रजनन क्षमता जनसंख्या नीतियों के मुख्य तत्वों में से एक है। उदाहरण के लिए जन्मों को प्रोत्साहित करके जनसंख्या के आकार को बढ़ाना या जन्मों को हतोत्साहित करके जनसंख्या के आकार को सीमित करना । यह कार्य अधिकतर प्रचार एवं प्रोत्साहन के माध्यम से किया जाता है। विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से होती है तो ऐसे देश में जनसंख्या नीति होगी, प्रजननता को कम करने की । इसके लिए सरकार द्वारा अनेकों योजना कार्यक्रम एवं प्रचार चलाए जाते है। इन कार्यक्रमों के द्वारा सरकार प्रजननता को नियंत्रित करती है, जैसे – चीन, भारत, बांग्लादेश इत्यादि। विकसित देशों में जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड में परिवार को सफलतापूर्वक सीमित कर दिया गया है। अब वहां जनसंख्या में भारी कमी आ गई है तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि की नीति बनाई जा रही है। वर्तमान समय में अधिक बच्चों वाले दंपत्ति को आर्थिक मदद दी जा रही है।

16.3.2 मृत्यु दर

विकसित देशों में मृत्यु दर कम होती है जबकि इसके विपरीत विकासशील देशों में मृत्यु दर अधिक होता है। संपूर्ण विश्व के सभी देश मृत्यु दर को कम करना चाहते हैं क्योंकि यही मानवीयता होगी। इसकी वृद्धि कोई भी देश नहीं चाहता। मृत्यु दर का कम और अधिक होना निर्भर करता है, उस देश की चिकित्सकीय व्यवस्था पर। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त हैं तो मृत्यु दर कम होगी। अतः सभी देश अपने यहां स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए नीति बनाने एवं क्रियान्वित करने के लिए तत्पर रहते है। जिस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होगी वहां की जीवन प्रत्याशा उच्च होती है।

16.3.3 प्रवास

जनसंख्या नीतियों का एक और तत्व प्रवासन है जिसका उपयोग जनसंख्या को विनियमित करने के लिए किया जाता है। यदि यह आंतरिक प्रवास (जो आंतरिक या बाहरी हो सकता है) के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से या सीमा नियंत्रण के माध्यम से प्रवास को सीमित करने के माध्यम से किया जाता है। प्रवासन के लिए प्रेरणाओं में कर प्रोत्साहन, सब्सिडी, निवेश और प्रवासियों के लिए परमिट शामिल हो सकते है।

16.4 जनसंख्या नीतियों के उद्देश्य

अलग – अलग जनसंख्या आकर के लिए उद्देश्य अलग – अलग होते है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि नीति किस परिणाम को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के आकार को बढ़ाना या जनसंख्या के आकार को कम करना है।

16.5 विकसित देशों की जनसंख्या नीति

विकसित देशों की जनसंख्या संक्रमण की अंतिम अवस्था में है। इस कारण जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अत्यधिक निम्न स्तर पर आ गए हैं या जनसंख्या वृद्धि दर काफी मंद हो गया है या लगभग स्थिर हो गया है। विकसित देशों के श्रेणी में संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, जापान, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड इत्यादि आते है।

16.5.1 संयुक्त राज्य अमेरिका

इसकी कोई निश्चित जनसंख्या नीति नहीं है, परंतु यहां प्रवास नियंत्रण के लिए बहुत से नियम है जिनका जनसांख्यिकी महत्व अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता, मजबूत परिवार, बच्चों की देखभाल और सुरक्षा सभी जोड़ों और व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से और जिम्मेदारी से अपने बच्चों की संख्या, अंतर और समय तय करने और जानकारी एवं साधन रखने का अधिकार शामिल है। भेदभाव, जबरदस्ती या हिंसा से मुक्त, साथ ही परिवार नियोजन गतिविधियां जो स्वैच्छिक पसंद के सिद्धांत का पालन करती है।

16.5.2 फ्रांस

वर्ष 1939 ई. में फ्रांस ने कोड डेला फैमिले नामक एक जन्म पूर्व जनसंख्या नीति लागू की । यह देश उम्रदराज जनसंख्या से पीड़ित था जिसमें उपर्युक्त कामकाजी उम्र के लोग कम थे, इसलिए इस नीति का उद्देश्य देश की जनसंख्या का आकार बढ़ाना और अधिक श्रम प्राप्त करना था । इस नीति के प्रोत्साहन में निम्नलिखित शामिल थे –

- अपने बच्चों के साथ घर पर रहने वाली माताओं को आर्थिक सहायता की पेशकश की गई ।
- गर्भ निरोधकों पर प्रतिबंध (जो यौन संचारित रोगों के प्रचार को रोकने के लिए वर्ष 1967 ई. में फिर से लागू कर दिया गया था)
- भुगतानशुदा मातृत्व अवकाश
- बच्चों वाले परिवारों के लिए निःशुल्क छुट्टियां

16.5.3 स्वीडन

स्वीडन में वर्तमान में एक खुले दरवाजे वाली आप्रवासन नीति है। इस नीति का उद्देश्य देश को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना है क्योंकि अप्रवासी करों और श्रम के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे। इसके अतिरिक्त देश में जन्म दर कम है।

स्वीडन की अप्रवासन नीति के प्रभाव

अप्रवासन नीति के कारण स्वीडन में बहुत से प्रवासी है। हालांकि इससे राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे पैदा हो गए है। हिंसक दंगों में वृद्धि हुई है और अप्रवासियों के लिए बेरोजगारी बढ़ रही है जिससे देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ रहा है।

16.5.4 सिंगापुर

सिंगापुर ने जन्म समर्थक और जन्म विरोधी दोनों नीतियां पेश की है।

- वर्ष 1960 और 1970 के दशक में उच्च प्रजनन दर और बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रतिरोध में प्रसव विरोधी नीतियां बनाई गई थी। गर्भ निरोधकों को कम कीमतों पर पेश किया गया था और विज्ञापनों के

माध्यम से छोटे परिवारों को बढ़ावा दिया गया। साथ ही परिवार नियोजन पर वित्तीय प्रोत्साहन और शिक्षा भी छूट दी गई।

- वर्ष 1987 ई. में देश में जन्म समर्थक नीति पेश की गई थी। इस नीति ने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए वित्तीय लाभ और प्रचार के माध्यम से प्रोत्साहन की पेश की। इसे पहले की जन्म विरोधी नीति के कारण कम हुई जनसंख्या से निपटने के लिए लागू किया गया था।

16.6 विकासशील देशों की जनसंख्या नीति

एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका एवं मध्य अमेरिका के सभी देश विकासशील देशों के अंतर्गत आते है। सभी विकासशील देशों की जनसंख्या वृद्धि बहुत तीव्र है। कई देशों में तो विस्फोटक वृद्धि देखने को मिलती है। इन देशों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि एक विकट समस्या का रूप धारण कर लिया है। इस समस्या से निजात पाने के लिए ये देश जनसंख्या नीति को बना रहे हैं और उन्हें लागू भी कर रहे है। विकासशील देशों द्वारा बनाई गई जनसंख्या नीतियाँ निम्नवत है –

16.6.1 एशिया

एशिया में जहाँ विश्व की आधे से अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसके देशों की जनसंख्या नीति में अनेक विविधता देखने को मिलती है, जैसे – चीन, भारत, श्रीलंका, हांगकांग, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड में जहाँ जबरन परिवार नियंत्रण कार्यक्रमों के साथ – साथ परिवार नियोजन और सामाजिक एवं आर्थिक उपायों पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन देशों की उत्पादकता दर में पर्याप्त ह्रास हुआ है। सऊदी अरब में तो कृत्रिम गर्भनिरोधक उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी गई है। वहीं अफगानिस्तान, इराक, जॉर्डन, तुर्की, ईरान, लेबनान और सीरिया केवल स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण की भावना से परिवार नियोजन के लिए अभिरुचि ले रहे है। इजराइल में तीव्र जनसंख्या वृद्धि की नीति अपनी गई है।

16.6.2 चीन

वर्ष 1980 और 2016 के बीच चीन ने एक बच्चे नीति की शुरुआत की। देश की तेजी से बढ़ती जनसंख्या वृद्धि, जो देश की आर्थिक प्रगति पर दबाव पैदा कर रही थी, से निपटने के लिए नीति ने कानून के माध्यम से परिवारों को एक – एक बच्चे तक सीमित कर दिया। परिवारों को एक से अधिक बच्चा पैदा करने से रोकने के लिए विभिन्न प्रवर्तन लागू किए गए। इनमें शामिल है –

- अनुपालन न करने वालों पर जुर्माना,
- नीति का पालन करने वालों को वित्तीय प्रोत्साहन,
- निरोधकों की पर्याप्त उपलब्धता,
- जबरन नसबंदी,
- जबरन गर्भपात

इन सभी तत्वों का उपयोग करके चीन ने अपने यहां बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करके जनसंख्या एवं संसाधन की उपलब्धता में सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया ।

16.6.3 बांग्लादेश

बांग्लादेश की पहली जनसंख्या नीति वर्ष 1976 ई. में बनाई गई थी, जब जनसंख्या वृद्धि दर लगभग तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष थी। तब से बांग्लादेश ने प्रजनन क्षमता को मध्यम स्तर तक कम करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान समय तक बांग्लादेश की जनसंख्या नीति दो अलग – अलग चरणों में विकसित हुई है। पहला चरण 1997 ई. तक चला और 1976 की जनसंख्या नीति में उल्लिखित उद्देश्यों और रणनीतियों द्वारा निर्देशित था। दूसरा चरण 1998 ई. में शुरू हुआ और वर्तमान समय तक जारी है। बांग्लादेश

जनसंख्या नीति 2004 का मुख्य उद्देश्य 2007 तक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करने के लिए वर्ष 2010 ई. तक शुद्ध प्रजनन दर 1 प्राप्त करना था।

16.7 भारत की जनसंख्या नीति

जनसंख्या नीति का तात्पर्य ऐसी सरकारी घोषणा से है जिसमें जनसंख्या वृद्धि की जाए अथवा जनसंख्या नियंत्रित की जाने से होता है। आर्थिक विश्लेषण में जनसंख्या नीति से तात्पर्य किसी देश की उस जनसंख्या से है, जिसमें देश की जनसंख्या का आकार और संरचना निश्चित की जाती है क्योंकि भारत गर्म जलवायु एवं आर्थिक समस्याओं से ग्रसित देश है। जहाँ जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो चुकी है फलतरू देश में श्रमिकों का आधिक्य, बेकारी एवं गरीबी जैसी गंभीर समस्याएं है। अतः भारत की जनसंख्या नीति निश्चय ही जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित होगी।

16.7.1 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति

भारतवर्ष जनांकिकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की जन्म दर 1.95% वार्षिक है। यह जन्म दर विश्व में सबसे ऊंची जन्म दरों में से एक है। स्थायी आर्थिक विकास, सामाजिक विकास एवं पर्यावरण सुरक्षा की आवश्यकता अनुसार 2045 ई. तक स्थिर जनसंख्या दर प्राप्त करने हेतु दीर्घकालीन रूपरेखा प्रस्तुत की है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में कुल प्रजनन दर 2010 ई. तक 2.1% लाना है। यद्यपि देश में 1991 से 2001 तक 180.6 मिलियन व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। इस प्रकार जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर जो वर्ष 1991 ई. में 2. 14% थी उसे 2001 ई. तक घटाकर 1.93% पर लाया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में योजना आयोग ने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि को एक अवधि तक स्थिर करना आयोजित विकास का एक केंद्र बिंदु है।

16.7.2 स्वतंत्रता पश्चात सरकार की जनसंख्या नीति

स्वतंत्रता के बाद सन् 1951 ई. में योजना आयोग की स्थापना के बाद आयोग ने भारतीय आर्थिक विकास एवं संरचनात्मक तथ्यों को आर्थिक नियोजन के माध्यम से हल करने की व्यवस्था की है। दुर्भाग्य है कि भारतीय जनसंख्या नीति परिवार नियोजन एवं नसबंदी में फंस कर रह गई है। इसलिए जनसंख्या नीति में इस समस्या का जनसांख्यिकी के सीमाओं से आगे बढ़कर देखना चाहिए क्योंकि आर्थिक विकास से स्वत आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।

योजनाकाल में जनसंख्या नियंत्रण हेतु किए गए प्रयास

आजादी के पश्चात देश के रणनीतिकारों के समक्ष प्रमुख चुनौती यह थी कि देश का विकास किस प्रकार किया जाए। बहुत सोच विचार करने के पश्चात इस बात पर सहमति बनी कि रूस की समाजवादी विचारधारा का अनुसरण करते हुए देश का विकास किया जाए। इसी से प्रेरित होकर पंचवर्षीय योजना की संकल्पना को स्वीकार किया गया था। वर्ष 1951 ई. में प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ ही नियोजन काल की शुरुआत हुई। देश के विविध पक्षों के लिए अलग – अलग योजना काल में अनेक लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इन्हीं लक्ष्यों में से एक है जनसंख्या नीति। विविध योजना काल में जनसंख्या नियंत्रण लागू की गई नीतियाँ निम्नलिखित सारणी में उल्लिखित है –

सारणी 16.1 विभिन्न योजना काल में क्रियान्वित प्रमुख जनसंख्या नीतियाँ

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना की अवधि	क्रियान्वित प्रमुख प्रमुख नीतियाँ
1.	प्रथम पंचवर्षीय योजना	1951 – 1956	1. परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रभाव की समीक्षा तथा उससे जुड़े आकड़ों का एकत्रीकरण ।

			2. परिवार नियोजन कार्यक्रम पर सामाजिक, आर्थिक एवं जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन ।
			3. परिवार नियोजन की विविध विधियों की जनता तक पहुँच कैसे सुनिश्चित की जाए तथा किस प्रकार उन्हें प्रशिक्षित किया जाए ।
			4. समाज के विभिन्न वर्गों के कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से उस वर्ग के परिवार का आकार, प्रजनन की प्रवृत्ति एवं परिवार नियोजन के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है से जुड़ी जानकारी को एकत्र करना ।
			5. प्रजननता के चिकित्सकीय एवं मनोवैज्ञानिक पक्ष के विविध आयामों पर शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा ।
2.	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	1956 – 1961	1. परिवार नियोजन की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए जनता में शिक्षा का प्रसार ।
			2. इससे जुड़े व्यक्तियों को पूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करना ।
			3. परिवार नियोजन पर शोध, अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देना ।
			4. नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों पर नसबन्दी की सुविधा एवं कर्मचारियों की व्यवस्था करना ।
3.	तृतीय पंचवर्षीय योजना	1961 – 1966	1. इस अवधि में जनसंख्या नियंत्रण हेतु कोई विशेष नीति नहीं बनाई गई थी ।
			2. इस अवधि तक देश की जनसंख्या काफी बढ़ गई थी जिससे अनेक समस्याएँ स्वतः उत्पन्न हो चुकी थी ।
			3. इस समय जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रचार – प्रसार पर विशेष ध्यान दिया गया ।
			4. इसी समय लूप के प्रयोग हेतु लोगों को विशेष रूप से जागरूक किया गया ।
4.	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	1969 – 1974	1. इस योजना में भी तीसरी काल योजनाकाल के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर बल दिया गया ।
			2. इस अवधि में नसबन्दी पर विशेष ध्यान दिया गया तथा लोगों को परिवार नियोजन की सभी विधियों से अवगत कराया गया ।
5.	पंचम पंचवर्षीय योजना	1974 – 1980	1. वर्ष 1972 ई. में गर्भ समापन को वैध घोषित किया गया । कानून की इस व्यवस्था के अनुसार 20 हफ्ते के गर्भ को समाप्त किया जा सकता है।
			2. वर्ष 1976 ई. से विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर लड़कियों के

			लिए 15 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष की गई।
			3. चौथी पंचवर्षीय योजना की जन संख्या नीति के तहत लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया । जनांकिकी का नियम यह कहता है कि बाल मृत्यु दर एवं रुग्णता दर बढ़ने से प्रजनन दर में वृद्धि होती है।
			4. इस अवधि में यह शिकायत आयी कि परिवार नियोजन के क्षेत्र में जो राज्य उत्कृष्ट प्रदर्शन किए है संसद में उनका प्रतिनिधित्व घटने लगता है। इसके पश्चात ही यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 1971 ई. की जनगणना के आधार पर ही संसद एवं विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाएगी ।
			5. प्रोत्साहन और हतोत्साहन की नीति को अपना करके वर्ष 1976 ई. के पश्चात जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया ।
6.	छठी पंचवर्षीय योजना	1980 – 1985	1. इस योजना की अवधि में परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा 1078 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे परंतु खर्च 1478 करोड़ रुपए किए गए ।
			2. इस दौरान बनाई गई नीति के दो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जिसमें पहले तहत जन्म दर को 30 प्रति हजार से घटाकर 25 प्रति हजार तक लाना तथा दूसरे के अनुसार 24 मिलियन लोगों की नसबन्दी की जानी थी जबकि मात्र 17 मिलियन लोगों की ही नसबन्दी की जा सकी ।
7.	सातवीं पंचवर्षीय योजना	1985 – 1990	1. इस योजना अवधि में वर्ष 1985 ई. में श्री अरुण सिंह के नेतृत्व में एक संसदीय दल का गठन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी द्वारा किया गया था । इसका गठन हिन्दी भाषी क्षेत्र में परिवार नियोजन के मार्ग में आने वाली बाधाओं का अध्ययन करने के लिए किया गया था ।
			2. इसी योजना काल में ही कहा गया था शुद्ध प्रजनन को 1 तक लाना है जबकि बाद में स्वीकार किया गया कि यह लक्ष्य 2000 से पहले नहीं प्राप्त हो सकता है।
			3. इस योजना काल में परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कुल 3121 करोड़ रुपए खर्च किए गए जो सम्पूर्ण योजना काल के व्यय का 1.4% था ।
8.	आठवीं पंचवर्षीय योजना	1992 – 1997	1. इस अवधि परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाने वाले दम्पतियों को नगद धनराशि एवं कुछ भूमि प्रदान करने का प्रलोभन भी दिया गया ।
			2. एक लक्ष्य यह भी रखा गया कि शिशु मृत्यु दर को 70 प्रति हजार तक लाया जाए ।

9.	नौवीं पंचवर्षीय योजना	1997 – 2002	1. वर्ष 1994 ई. में गठित डॉ एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाली समिति के प्रतिवेदन के आधार पर 1 फरवरी 2000 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 को घोषित किया था । इस नीति के अनेकों तथ्य हैं –
			2. उपरोक्त समिति ने बताया था कि जनसंख्या में 20ः वृद्धि जन्म नियंत्रण उपकरणों के अभाव में हुई है अतः जहाँ तक इनकी उपलब्धता नहीं हो पाई है उस परिवार तक इन उपकरणों की पहुँच सुनिश्चित करना ।
			3. इस अवधि में उन लोगों की पहचान की गई थी जो परिवार नियोजन उपकरणों के अभाव या कमी के कारण अनचाहे गर्भ से ग्रस्त है।
			4. इस योजना के प्रमुख लक्ष्य थे शिशु मृत्यु दर को 56 – 60 प्रति हजार तक लाना, अशोधित जन्म दर को 24 – 23 प्रति हजार तक लाना है और कुल प्रजनन दर को भी 2.9 से 2.6 के बीच लाना है।
10.	दसवीं पंचवर्षीय योजना	2002 – 2007	1. इस अवधि में परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 27,125 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे ।
			2. इस काल में शिशु मृत्यु को 45 प्रति हज़ार लाने के साथ ही वर्ष 2012 तक 28 प्रति हज़ार लाने का प्रस्ताव रखा गया था, जो प्राप्त नहीं हो सका ।
			3. 2001 – 2011 के दशक की वृद्धि दर को 16.2% पर लाने का लक्ष्य रखा गया था परंतु यह अनंतिम आँकड़ों में 17.63% दर्ज की गई है।

स्त्रोतः भारत, 2024.

16.7.3 भारतीय जनसंख्या नीति, 1976

भारत में इस जनसंख्या नीति की घोषणा अप्रैल 1976 ई. में तत्कालीन स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री डॉ. कर्ण सिंह ने किया था। उन्होंने जनसंख्या नीति में राष्ट्रीय विचार विमर्श के बाद एक दीर्घकालीन नीति में कहा है कि भारत के उज्जवल भविष्य के निर्माण में गरीबों के लिए जनसंख्या वृद्धि की समस्या से निपटना आवश्यक है।

16.7.3.1 जनसंख्या नीति का लक्ष्य

भारत की नई जनसंख्या नीति के विभिन्न लक्ष्य संबंधी मापदंड घोषित हुए। इस जनसंख्या नीति का लक्ष्य जन्मदर 35 प्रति हज़ार से घटाकर 25 प्रति हज़ार करना है, इसलिए चिकित्सा सुविधाएँ, बंध्याकरण, प्रशिक्षित कर्मचारी व उपकरण आदि की उपलब्धता का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। वर्ष 1976 ई. की जनसंख्या नीति में उत्तरदयी दृष्टिकोण की पहल हुई ताकि लोग स्वेच्छा से जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रमों को अपनाए।

16.7.3.2 जनसंख्या नीति के प्रमुख कार्यक्रम

जनसंख्या नीति 1976 ई. के सफल क्रियान्वयन हेतु कुछ निश्चित कार्यक्रम चलाए गए जो निम्नलिखित है–

- बंध्याकरण की अनिवार्यता

भारत सरकार के नई जनसंख्या नीति में बंध्याकरण को अनिवार्य करने की राज्य सरकारों से अपील की गई लेकिन यह भी कहा गया कि भारत सरकार बंध्याकरण एवं नसबंदी के साधनों के अभाव में अनिवार्य घोषित नहीं कर सकती है।

- विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने की आवश्यकता

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों की 15 से बढ़कर 18 वर्ष व लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़कर 21 वर्ष करने का प्रावधान किया गया।

- वित्तीय सहायता

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता देने का एक मापदंड बनाया कि राज्यों को केंद्रीय आर्थिक सहायता का 8% परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर व्यय करना होगा।

- जनसंख्या शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम

जनसंख्या शिक्षा को पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाए, इसलिए शिक्षा में जनसंख्या संबंधी मूल्यों के ज्ञान के लिए ऐसी पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाएं, जिनसे लड़के – लड़कियों को जनसंख्या की समस्या संबंधित व्यवहारिक सामग्री प्राप्त हो सके।

- छोटे परिवार के सिद्धांत संबंधी नियम

जनसंख्या नीति में छोटे परिवार सिद्धांत पर बल दिया गया है। सरकार ने कहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को परिवार नियंत्रण करने होंगे।

- बंध्याकरण के लिए पुरस्कार

जनसंख्या नीति में बंध्याकरण के लिए पुरस्कार घोषित किए गए जिसमें दो बच्चों के बाद बंध्याकरण में ₹ 1000, तीन बच्चों के बाद बंध्याकरण में ₹ 100, चार बच्चों के बाद बंध्याकरण करने पर ₹ 70 पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी।

- दान पर छूट एवं व्यापार प्रचार

सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए ध्यान देने वाली संस्थाओं, व्यक्तियों या कंपनी आदि को आयकर में छूट देने की घोषणा की है, जिससे परिवार नियोजन के लिए दान से धन की व्यवस्था हो सके।

16.7.4 संशोधित जनसंख्या नीति, 1977

भारत सरकार ने जनसंख्या नीति 1977 में निम्नलिखित संशोधन किया है –

- सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम किया गया क्योंकि भारतीय जन मानस परिवार नियोजन शब्द से घृणा करने लगा था।
- परिवार कल्याण कार्यक्रम में बंध्याकरण अथवा नसबंदी की अनिवार्यता को समाप्त कर ऐच्छिक किया गया।
- विवाह योग्य आयु को बढ़ाने पर विचार किया गया जिससे जन्म दर कम हो सके।
- छोटे परिवार का संदेश घर – घर पहुंचाया जाए जिससे जन भावना छोटे परिवार – सुखी परिवार एवं हम दो हमारे दो की बन सके।
- जन्म दर घटाने के लिए कृत्रिम उपायों में वृद्धि की गई, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए।
- परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाए। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि प्रत्येक परिवार कल्याण केंद्र पर प्रशिक्षित कार्यक्रम चलाया जाए।

16.7.5 नई जनसंख्या नीति – 2000

केंद्र सरकार ने अपनी नई जनसंख्या नीति की घोषणा 15 फरवरी 2000 को कर दी है। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 को तीन मुख्य उद्देश्यों के परिपेक्ष्य में देखा जाता है। पर्याप्त मात्रा में गर्भनिरोधकों की उपलब्धता, स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचा और वह स्वास्थ्य कर्मियों की आपूर्ति करना है। जबकि मध्यकालीन उद्देश्य सन् 2010 ई. तक कुल प्रजनन दर को 2रू1 के प्रतिस्थापन स्तर तक लाना है। नई जनसंख्या नीति का दीर्घ कालीन उद्देश्य सन् 2045 तक स्थिर जनसंख्या को ऐसे स्तर तक स्थिर बनाने की बात की गई है, जो आर्थिक दृष्टिकोण से सामाजिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के अनुरूप हो।

15 फरवरी 2000 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई जनसंख्या नीति की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि छोटे परिवार (प्रति दंपति एक बच्चे) का मानक अपनाने के लिए प्रोत्साहन एवं प्रेरणा प्रदान करने के लिए इसमें 16 उपायों को शामिल किया गया है। इनमें ग़रीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वालों को 21 वर्ष निर्धारित आयु के पश्चात विवाह करने, दो बच्चों के मानक को अपनाने तथा दो बच्चों के पश्चात नसबंदी कराने पर यथोचित पुरस्कार दिए जाने के उपाय शामिल है।

छोटे परिवार के मानक को अपने को प्रोत्साहित करने के लिए शामिल किए गए प्रयासों में निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय है –

- केंद्र सरकार ऐसे पंचायत और जिला परिषदों को पुरस्कृत करेगी, जो अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के उपाय को अधिकाधिक अपने के लिए प्रेरित करेगी।
- नई नीति के तहत बाल – विवाह निरोधक अधिनियम तथा प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण तकनीकी निरोधक अधिनियम को कड़ाई के साथ लागू किया जाएगा।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उन परिवारों को ₹ 5000 की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जाएगी जिनके सिर्फ दो बच्चे थे और दो बच्चों के जन्म के बाद उन्होंने बंध्याकरण कर लिया होगा।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उन लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा, जो निर्धारित उम्र में विवाह करने के बाद पहले बच्चे को तब जन्म दिया जब माँ की उम्र 21 वर्ष हो जाए और वे छोटे परिवार के सिद्धान्त में विश्वास रखते हुए दो बच्चों को जन्म देने के बाद बंध्याकरण करा लें।
- ग्रामीण क्षेत्रों में एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उदार शर्तों पर ऋण तथा आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी।
- गर्भपात सुविधा योजना को और मजबूत किया जाएगा।
- गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं को इस कार्य से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

नई जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने एवं उसकी समीक्षा के लिए 11 मई 2000 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय 100 सदस्य वाले राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया है।

नई जनसंख्या नीति – 2000 को सफल बनाने की रणनीति

फरवरी 2000 में लघु होने वाली जनसंख्या नीति 2000 को सफल बनाने के कई रणनीतियाँ बनाई गई ताकि वह अपने लक्ष्य को पूर्णता के साथ प्राप्त कर सके । इसके लिए बनाई गई रणनीतियाँ निम्नलिखित है –

1) उन स्थानों तक परिवार नियोजन के कार्यक्रम एवं सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित करना जहाँ तक अभी नहीं हो सकी है।
2) शिशु मृत्यु दर को 30 प्रति हजार तक लाने पर विशेष बल देना।
3) प्रसव के दौरान होने वाले मातृत्व मृत्यु दर को 100 प्रति लाख जीवित प्रसव के स्तर तक नीचे लाना।
4) विभिन्न प्रकार की बीमारियों से गर्भवती महिला एवं नवजात शिशु की मृत्यु को रोकने के लिए टीकाकारण को प्रोत्साहन देना।

5) प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क करना जिससे 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो सके। साथ ही बीच में पढ़ाई छोडने वाले बच्चों के पुनः नामांकन की व्यवस्था करना।

6) जनता में इस बात की जागरूकता को बढ़ाना कि लड़कियों की शादियाँ 20 वर्ष की उम्र के पश्चात ही करें तथा पहला बच्चा शादी के दो वर्ष पश्चात ही करें।

7) अधिकांश प्रसव स्वास्थ्य केन्द्रों में ही सम्पन्न कराएँ। शत प्रतिशत करने के लिए लोगों को प्रेरित करें।

8) प्रजननता के उपकरणों के बारे में लोगों को अवगत कराएँ तथा उनके उपयोग के निर्णय को उपभोक्ताओं पर ही छोड़ दें।

9) गर्भधारण, जन्म, मृत्यु एवं विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बना देना चाहिए।

10) संक्रामक बीमारियों से बचाव की जानकारी एवं टिकाकरण को अधिक से अधिक लोगों तक प्रसारित करना।

11) एड्स और अन्य यौन जनित के प्रति जनता में जागरूकता पैदा करना।

12) प्रजनन केन्द्रों में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं भारतीय दवाइयों के प्रयोग को बढ़ावा देना।

13) परिवार नियोजन कार्यक्रमों को जनकेन्द्रित बनाया जाए ताकि अधिक से

14) महिला सशक्तिकरण, पौष्टिक आहार एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं को नगरीय क्षेत्र के साथ – साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंचाने के अच्छे प्रयास किया जा रहे है।

15) पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाकर जनसंख्या नीति को सफल बनाया जा सकता है। इसके माध्यम से पंचायत और उसके सदस्यों को उससे जुड़ी जानकारी को आसानी से अवगत कराकर लोगों में जागरूकता पैदा की जा सकती है।

16.8 सारांश

आपने इस इकाई में जनसंख्या नीति का अर्थ, जनसंख्या नीति आवश्यकता एवं उद्देश्य के साथ भारत की जनसंख्या नीति और नई जनसंख्या नीति – 2000 का अध्ययन किया है। आप समझ गए होगें कि जनसंख्या नीति एवं किसी देश के विकास में घनिष्ट संबंध होता है। जनसंख्या नीति के माध्यम से सरकारें अपने देश में उपलब्ध संसाधनों के द्वारा अपने नागरिकों का सर्वोत्तम कल्याण करने का प्रयास करती हैं। वास्तव में किसी देश की जनसंख्या तथा वहाँ का सबसे बड़ा संसाधन होती है जो उसकी भौगोलिक अवस्थिति, सरकारी नीतियों, सांस्कृतिक संगठन, जनसंख्या नीति आदि के आधार पर संगठित होती है। जिन देशों की जनसंख्या कम हो रही है वे जनसंख्या वृद्धि के प्रोत्साहन हेतु नीतियाँ बना रहें है। दूसरी तरफ ऐसे भी देश हैं जहाँ जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है और संसाधनों पर भार बढ़ता जा रहा है, ऐसे देश अपने यहाँ जनसंख्या नियंत्रण की नीतियाँ बना रहे है। भारत भी तीव्र जनसंख्या वृद्धि की अवस्था से गुजर रहा है। यहाँ जनसंख्या संसाधनों की वहन क्षमता से बहुत अधिक है। ऐसी स्थित में भारत सरकार द्वारा आजादी के बाद बनने वाली पहली सरकार से ही जनसंख्या नियंत्रण पर कार्य कर रही है। इसके लिए समय – समय पर अनेक जनसंख्या नीतियों की घोषणा की गई। सबसे नवीनतम जनसंख्या नीति 2000 की है, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण करने वाले लोगों के लिए प्रोत्साहन की भी घोषणा की गई है।

16.9 स्वमूल्यांकन प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

1. विकसित देश जनसंख्या संक्रमण की किस अवस्था में है।

   (क) प्रथम अवस्था (ख) द्वितीय अवस्था (ग) तृतीय अवस्था (घ) चतुर्थ अवस्था

2. निम्नलिखित में वह कौन सा देश है जिसने 20वीं सदी में जन्म समर्थक एवं जन्म विरोधी दोनों प्रकार की नीतियाँ पेश की है।

   (क) स्वीडेन (ख) सिंगापुर (ग) फ्रांस (घ) संयुक्त राज्य अमेरिका

3. बांग्लादेश ने अपनी पहली जनसंख्या नीति कब बनाई थी।

(क) 1972 ई. (ख) 1976 ई. (ग) 1988 ई. (घ) 1995 ई.

4. भारत की जनसंख्या नीति 1976 की घोषणा तत्कालीन स्वस्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री ने की थी, उस समय स्वस्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री कौन थे।

(क) डॉ कर्ण सिंह (ख) इन्दिरा गाँधी (ग) जय प्रकाश नारायण (घ) मुलायम सिंह यादव

5. भारत की नई जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा कब की गई थी।

(क) 26 जनवरी, 2000 (ख) 15 फरवरी, 2000 (ग) 26 मार्च, 2000 (घ) 15 अगस्त, 2000

16.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

Bogue] D- J-] 1969] Principles of Demography] John Wiley] N-Y-

Clarke] John I-] 1973] Population Geography] Pergaman Press] Oxford-

Crook] Nigel] 1997] Principles of Population and Development] Pergaman Press] N- Y-

Garmier] J- B-] 1970] Geography of Population] Longman] London-

Mamoria] C- B-] 1981] India's Population Problem] Kitab Mahal] New Delhi-

Premi] M- K-] 1991] India's Population] Heading Towards a Billion] B- R- Publishing Corporation-

Blassoff] M- and Srinivasan K-] 2001] Population Development Nexus in India : Challenges for the New Millennium] Tata McGraw Hill] New Delhi-

Woods] R-] 1979] Population Analysis in Geography] Longman] London-

Zelinsky] W-] 1966] A Prologue to Population Geography] Prentice Hall-

चन्दना, आर. सी., 2022, जनसंख्या भूगोल – संकल्पना, नियंत्रक व विश्व प्रारूप, कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

चन्दना, आर. सी., 2022, भारत : जनसंख्या (जनसंख्या भूगोल – भाग 2), कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

मौर्या, एस. डी., 2005, जनसंख्या भूगोल, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद.

ओझा, आर. पी., 1984, जनसंख्या भूगोल, प्रतिभा प्रकाशन.

हीरा लाल, 2000, जनसंख्या भूगोल के मूल तत्व, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली.

तिवारी, राम कुमार, 2023, जनसंख्या भूगोल, प्रवालिका पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद.

16.11 अभ्यास प्रश्न (सत्रांत परीक्षा की तैयारी)

1. जनसंख्या नीति को परिभाषित कीजिए तथा उसकी विशेषताओं को बताइए?
2. विकसित देशों एवं विकासशील देशों की जनसंख्या नीति को स्पष्ट कीजिए?
3. भारत में लागू की गई अब तक की जनसंख्या नीतियों का विस्तार से विश्लेषण कीजिए?